

सोवियत संघ का आर्थिक विकास

डा० देवेन्द्र प्रताप सिंह

एम० ए०, एम० काम०, एल० एल० बी०, पी० एच० डी०
वाणिज्य विभाग—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

प्रो० हीरालाल तिवारी

एम० ए०

प्राग्ज्योतिष कालेज, गुवाहाटी



इंडियन प्रेस

प्रयाग

प्रकाशक
स्टूडेंट्स फ्रॉण्ड्स
२, हीवेट रोड
इलाहाबाद—३

प्रथम संस्करण

सर्वाधिकार सुरक्षित १९६२

प्रकाशक के लिखित अनुमति के बिना समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में समीक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में प्रस्तुत पुस्तक के किसी अंश को उद्धृत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है ।

मूल्य
२.५० नया पैसा

मुद्रक
बी० एन० बूंस,
दि डोमोनियन प्रेस (प्रा०) लि०
११७, हीवेट रोड, इलाहाबाद ।

अपनी बात

आर्थिक विकास के अध्ययन की दिशा में प्रस्तुत पुस्तक हमारा दूसरा प्रयास है। 'संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक विकास' समाप्त कर लेने पर स्व० श्री बिजन बिहारी सामन्त ने इस ओर हमारा ध्यान आकषिप्त किया था, दुःख है कि वे इस समय अपने आग्रह का परिणाम देखने के लिए हमारे बीच नहीं हैं।

हमने सोवियत संघ के आर्थिक विकास को तटस्थ दर्शक के निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। तथ्यों और आंकड़ों के चयन में परस्पर विरोधी मान्यताओं के कारण हमें कठिनाई अवश्य हुई, समाधान के लिए न हमने मध्यम मार्ग ग्रहण किया, न निराधार निष्कर्ष पर पहुँचने का दावा। इस दिशा में हमने सोवियत लेखकों और विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह मास्को से प्रकाशित बुलेटिनों को प्रमाणिक माना है और जहाँ अधिक मतभेद दीख पड़ा है वहाँ विरोधी विचारकों के तथ्य और आंकड़े पूरी सूचना के साथ उद्धृत कर दिए गए हैं।

छब्बीस अक्षरों की असमर्थ भाषा को अध्ययन का माध्यम बनाने के कारण हम देश-विदेश के विभिन्न व्यक्तियों और स्थानों के नामों को गलत ढंग से लिखने और उनका उच्चारण करने के अभ्यस्त से हो गए हैं। ज्ञातव्य है—रूसी वर्णमाला में 'ट' और 'ड' वर्ण नहीं होता, रूसी 'त', 'द' और 'त्स' वर्णों के स्थान पर अंग्रेजी में क्रमशः T, D और Ts वर्ण प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी की असमर्थता हमने हिन्दी के सिर नहीं मढ़ी है।

हम आभारी हैं अपने सोवियत बन्धु विक्रतर बालिन (प्राध्यापक हिन्दी विभाग, लेनिनग्राद विश्वविद्यालय) के जिनके निकट सम्पर्क के कारण हमें सोवियत जन-जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला। काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के डा० एस० के० आर० भण्डारी (अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग),

(२)

डा० आनन्द शरण रतूड़ी (अध्यक्ष, अर्थ-शास्त्र विभाग), डा० गौरी शंकर लवानिया (प्राध्यापक, कृषि अर्थ-शास्त्र), प्राग्ज्योतिष कालेज के प्रधानाचार्य श्री तीर्थनाथ शर्मा, विदेशी भाषा प्रकाशन ग्रह मार्को और सोवियत दूतावास नई दिल्ली से हमें समय-समय पर उपयोगी सुझाव और सूचनाएँ प्राप्त होती रहीं हैं ।

आशा है पाठक हमारी इस पुस्तक को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास की भाँति ही अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाएँगे ।

लेखक द्वय

हीरालाल तिवारी

देवेन्द्र प्रताप सिंह

सूचिका

अपनी बात

पृष्ठ संख्या

अध्याय १-२ पूर्व पीठिका-प्राकृतिक साधन-कोयला-मिट्टी का तेल, पीट-गैस-जल विद्युत शक्ति-खनिज पदार्थ—लट्टा और काष्ठ-धागा, खाद्यान्न-भूमि-पशु समुद्र ।	१ - ६ ७-१०
अध्याय ३ जार युग (१९०५ तक)-जनसंख्य-उद्योग-श्रम सम्बन्धी अधिनियम-वृहत स्तर उत्पादन की ओर-मोमबत्ती-चमड़ा. तेल-व्यापार-यातायात-कृषि ।	११-१६
अध्याय ४-राज्य क्रान्ति (१९०५-१७)-भूमि-सरकार की नीति-राजनीतिक दल-रूसी जनसंघ-प्रथम विश्व युद्ध-युद्ध और कम्युनिस्ट अर्थ-व्यवस्था-उद्योग-कृषि-सामाजिक अवस्था मार्च क्रान्ति-इन्कलाब के ८ महीने	२०-२८

लेनिन युग

(१९१७-१९२४)

अध्याय ५-युद्धत साम्यवाद (War Communism 1917-21) अराजकता-श्वेतसेना और विदेशी आक्रमणकारी-देश के गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दल-स्वतन्त्र बाजार और स्पर्धा की समाप्ति-विदेशी व्यापार-वितरण-नारकम्प्रोद (पूर्ति आयोग)-गैज़वाइन उपावेलिना (Glavki)-मुद्रा-क्षति अवसाद के कारण-सर्वोच्च राष्ट्रय अर्थ-व्यवस्था-उद्योग धन्धों का राष्ट्रीय करण-श्रम-कृषि ।	२९-४०
अध्याय ६-नई आर्थिक नीति-कृषि उत्पादन-मूल्य में असंतुलन-राष्ट्रीय आर्थिकयोजना-न्यास तथा अभिषद-श्रमिक-व्यापार ।	४१-५२

अध्याय ७ — आर्थिक पुनर्गठन और कैची संकट—आशा की
किरण—चर्वोन्नेज पत्र मुद्रा—कैची संकट कैची या दरार । ५३—६१

स्तालिन युग

(१९२४—५४)

अध्याय ८ — योजना प्रणाली का संघटन—औद्योगीकरण की
कठिनाइयाँ—विशिष्टीकरण (Specialisation)—
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । ६२—६४

अध्याय ९ — प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८—३२)—
उद्योग—कृषि—श्रम—आन्तरिक व्यापार—सिंहावलोकन ६३—७४

अध्याय १० — द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना (१९३२—३७)— ७५—८०

अध्याय ११ — तृतीय पञ्चवर्षीय योजना (१९३८—४२)—
मूल योजना । ८१—८५

अध्याय १२—द्वितीय विश्व युद्ध—तीसरी योजना का उत्तरार्द्ध
—युद्ध जनित क्षति—योजना का नया मोड़—युद्ध कालीन
अर्थ-व्यावस्था । ८३—९२

अध्याय १३—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना - योजना के उद्देश्य
—उद्योग—लोहा और इस्पात—लोहेतर उद्योग—कोयला
—पीट—गैस—पेट्रोल और मिट्टी का तेल—बिजली—
मशीन निर्माण रसायनिक उद्योग—रबर—गृह-निर्माण—
काष्ठउद्योग—कपड़ा और हलके उद्योग—खाद्य पदार्थ—
कृषि—यातायात—रेल—जल यातायात—वायुयान—
योजना की सफलता । ९३—१०७

अध्याय १४ — पंचम पंचवर्षीय योजना (१९५१ - ५५)
कृषि—उन्नत जन-ज वन—योजना की सफलता । १०८—११५

पूर्व साम्य की ओर

अध्याय १५—षष्ठम् पञ्चवर्षीय योजना—मूल योजना—बड़े
उद्योग—कोयला—तेल और गैस स्वचालित मशीने

(Automatic Machine) विद्युत शक्ति—कृषि—नये
उद्योग स्वास्थ्य और संस्कृति—योजना की विफलता

११६—१२३

अध्याय १६—सप्त वर्षीय योजना—देश की प्राकृतिक सम्पत्ति
का उपयोग—प्रावैधिक विकास—समाजवादी उद्योग धन्धों
का विकास क—वर्ग बड़े उद्योग—लोहैतर धातु उद्योग
(Non-ferrous metals industry) रसायनिक
उद्योग (Chemical industry) ईंधन उद्योग (Fuel
Industry) विद्युत शक्ति (Electrification) मशीन
बनाने के उद्योग, लछा, कागज तथा काष्ठ उद्योग—
ख-वर्ग उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन—खाद्य उद्योग
(Food Industry) समाजवादी कृषि का विकास—
योजना का लक्ष्य—फसलों का उत्पादन पशुपालन—कृषि
उत्पादन—राजकीय फार्मों का विकास—कृषि के विकास
में विद्युत शक्ति का प्रयोग—जंगल—यातायात और
परिवाहन के साधनों का विकास—सामुद्रिक यातायात—
नदी यातायात—रेल—स्थल यातायात—वायुयान—
योजना में व्यय की जाने वाली धन राशि, सिंहावलोकन—
सप्तवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अमेरिकी दृष्टि कोण—
अनुमान और तथ्य ।

१२४—१४१

अध्याय १७—उद्योग—भारत उद्योग—धातु—औद्योगिक ईंधन
(Fuel)—प्राकृतिक गैस—मशीन निर्माण—रसायनिक
उद्योग—विद्युत शक्ति—उपभोग की वस्तुएँ—खाद्य उद्योग
(Food Industry)—चीनी—मांस—दूध—मछलियाँ
—टिन और वितन्तुत रंग—वनस्पति तेल ।

१४२—१५६

अध्याय १८ यातायात—रेल—जल यातायात ।

१६०—१६३

अध्याय १९—मजदूर; मजदूर संघ और मजदूरी—मजदूर
संघ के कार्य—मजदूर संघ का संगठन, सोवियत मजदूर

संघ का क्रमिक विकास—हड़ताल—मजदूर संघ की सदस्यता के लाभ—मजदूरी।

१६४—१७१

अध्याय २०—कृषि—बेगारी—दास प्रथा का उन्मूलन—कृषि की समस्याएँ अक्टूबर क्रान्ति—स्वाधीनता के पहले चरण—सहकारिता की आवश्यकता—‘कोलखाज’ सहकारी खेती—सामूहिक खेती के प्रकार—कम्यून—खेती की संयुक्त समितियाँ—सामूहिक खेती—सामूहिक खेतों की आय का बटवारा—सामूहिक फार्मों का प्रबन्ध—सामूहिक खेती ने कृषकों को क्या दिया ?—सोवोखज सरकारी खेती—राज्य फार्म के भेद—राज्य फार्मों का संगठन और कार्य प्रणाली—खाद्यान्न उद्योग (Food Industry)—कृषि उत्पादन में वृद्धि—निकेता खुश्चेव का भाषण।

१७२—१६२

अध्याय २१—वित्तव्यवस्था : योजना और पद्धति—मुद्रा और योजना—मुद्रा स्फीति (१६१७—२४) घाटे का बजट—मुद्रा की मांग में वृद्धि—विदेशी मुद्रा से रूबल का सम्बन्ध—१६४७ के मौद्रिक सुधार—स्वर्णमान रूबल—सौवियत आय व्ययक—आय के साधन—लाभ कर (Profit Tax)—आयकर (Income Tax) सरकारी बांड—व्यव के प्रमुख स्रोत—बैंक—राज्य बैंक (State Bank)—अल्प बचत बैंक (Saving Bank)।

१६३—२०६

अध्याय २२—व्यापार—(Trade) राजकीय व्यापार—त्राग-सहकारी व्यापार (Co-operative Trade)—मूल्य—उपसंहार—विदेशी व्यापार (Foreign Trade) विदेशी व्यापार का संगठन।

२१०—२१४

अध्याय २३—साम्यवाद—कार्ल मार्क्स—कम्यूनिस्ट सिद्धान्त—द्वन्द्वीयकम्यूनिकवाद—साम्यवाद को लेलिन की देन—आन्तरिक व्यवस्था—स्तालिन—खुश्चेव।

२१५—२२०

अध्याय १

पूर्व पीठिका

सोवियत भूमि के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी मान्यताएँ हैं। इसकी आर्थिक प्रगति को न अतिशय श्रद्धा की दृष्टि से देखने वालों की कमी है न अतिशय घृणा की। वस्तु स्थिति यह है कि सोवियत संघ के आर्थिक विकास का प्रत्येक अध्येता राजनीति से प्रभावित है। अर्थशास्त्र में जान-बूझ कर राजनीति को घसीटा गया है और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अपनी विचार धारा के अनुकूल बना लिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाय उसके सिद्धान्तों, मान्यताओं और कार्य प्रणाली के प्रति अध्येता की आस्था हो ही। आस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। महत्व आस्था का नहीं, उस देश की सफलता का है। साधन का नहीं, साध्य का है। साधन के सम्बन्ध में दृष्टिकोण की भिन्नता हो सकती है किन्तु साध्य के सम्बन्ध में नहीं।

१९०४ में जापान से पराजित होने वाले इस महादेश ने यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग न लिया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। बरसाती नदी के समान अबाध गति से बढ़ने वाली नाजी सेनाओं के सामने चञ्चल बनकर आने वाला यही देश था। १४ सितम्बर १९५६ में जिसने सोवियत राकेट ल्युनिक तृतीय के चांद पर रूसी झंडा गाड़ने का समाचार पढ़ा होगा वह कठिनता से इस सत्य पर विश्वास करेगा कि २५ वर्ष पहले वहाँ केवल ४ प्रकार के ट्रैक्टर बनाएँ जाते थे। सोवियत संघ की सफलताओं को अनदेखा करने वाले भ्रम में हैं।

सोवियत सङ्घ का विकास निर्वाध गति से नहीं हुआ है। मार्ग में अगिनत रुकावटें आई हैं। उसका ५० वर्षों का आर्थिक इतिहास राजनीतिक हलचलों से भरा है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने दो-दो महायुद्ध फ़ैलकर इतने अल्प समय में इतनी अधिक प्रगति की हो। यदि सोवियत देश

युद्ध के नाश से बचा होता, यदि प्रकृति ने इसके साथ सौतेले पुत्र जैसा बर्ताव न किया होता तो आज यह न जाने कहाँ होता ।

सोवियत सङ्घ जितनी सराहना और आदर के योग्य है उतना आदर और प्रशंसा इसे पश्चिमी देशों से नहीं मिली । उन्होंने इसे सर्वदा भय, आशंका और घृणा की दृष्टि से देखा । संभव है इसका कारण पर्याप्त जानकारी का अभाव हो । द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों को विश्वास नहीं था कि सोवियत सङ्घ नाजी आक्रमण का सामना कर पाने में समर्थ होगा । पांच बड़ों में ने एक ने तो नाजी सेना के आगे बिना लड़े ही हथियार डाल दिया, एक युद्ध का तमाशाई था "जो हो इसकी सैनिक शक्ति का यथार्थ ज्ञान युद्ध के अन्तिम वर्षों में ही हो सका था ।

सांविगत सङ्घ के विषय में इतना अधिक भ्रम फैलाया जा चुका है और फैलाया जा रहा है कि वस्तु स्थिति का अभ्ययन असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । पं० नेहरू के शब्दों में — "रूस के बारे में जो सवाल मुझसे अक्सर पूछा गया वह यह था कि क्या वहाँ की स्त्रियाँ राष्ट्र की जायदाद बना ली गई हैं ।" ^१ यह संस्मरण १९२८ का है । सत्य यह है कि भारत के बाद यही एक ऐसा देश है । जहाँ सबसे कम तलाक होता है । अपनी इसी संस्मरण पुस्तक में नेहरू जी ने न्यूयार्क के 'नेशन' अखबार के सम्वाददाता के एक लेख का उद्धरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार उक्त सम्वाददाता लन्दन में बैठकर बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रीगा के सम्वाददाता के रूप में भूठी खबरें छुपवाया करता था । सम्वाददाता के शब्दों में — "जब कभी रीगा का विचार मेरे मन में आता है तो मेरे सामने शहर की तस्वीर नहीं आती है, बल्कि इसके बदले समाचार पत्रों के दफ्तरों की तस्वीर मेरे सामने खड़ी हो जाती है । पुराने डेस्कॉ, लेई की शीशियों, कैंचियों, टाइप राइटर्स और रद्दी कागजों की तस्वीरें नजर आती हैं । यहाँ से कृषि सम्बन्धी उपज और खासकर ओट (जई) इंग्लैण्ड को भेजा जाता है । निःसन्देह इन-साइक्लोपीडिया का संस्करण बहुत पुराना होगा । आजकल रीगा से और सब चीजों की बनिस्वत भूठी अफवाहें कहीं ज्यादा भेजी जाती हैं ।"

^१ रूस की सैर—पं० जवाहर लाल नेहरू

इस गलत फहमी के लिए सोवियत सरकार भी कुछ कम उत्तरदायी नहीं है। तथा कथित लोहे की दीवार को दूर करने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया और गैर कम्युनिस्ट देशों के बीच की खाई पाटने की दिशा में वे सर्वदा उदासीन रहे। दूसरों ने उन्हें गलत समझा उन्होंने गलत समझने दिया। चुपचाप काम करते रहे। क्रमशः आगे बढ़ते रहे। उनका बाल चन्द्र धरती का चक्कर लगाने लगा। उनका अग्नि ब्राण चांद पर पहुँच गया। काम पूरा होने के समाचार हमें मिले, काम की तैयारी के नहीं। एक घटना का बरबस स्मरण हो आता है। अस्थायी सरकार की स्थापना (मार्च १९१७) के बाद राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए थे। जनता फूल माला लिए स्वागत को खड़ी थी पर स्तालिन कब जेल से छूटकर प्रबन्दा (सत्य) के सम्पादकीय विभाग में पहुँच कर लेख लिखने लगा किसी ने न जाना। बिना हो हल्ला मचाए काम करते रहना रूसी चरित्र की अद्भुत विशेषता है। किसी रूसी से राजनीतिक चर्चा कीजिए। आपकी पूरी बात वह सुन लेगा। उससे कुछ पूछिए चुप रह जायगा। बहुत आग्रह कीजिए उत्तर मिलेगा “पता नहीं... शायद ऐसा होता है... शायद नहीं... शायद...”। विगत दो वर्षों में विभिन्न दूतावासों से पत्र व्यवहार करने का हमें अवसर मिला है सबसे संतुलित और संक्षिप्त उत्तर सोवियत दूतावास के रहे हैं।

यूरोप की लगन और साहसिकता के साथ एशिया की कष्ट सहिष्णुता और लक्ष्य के प्रति अटूट आस्था उनके पल्ले पड़ी है। सोवियत सङ्घ की वर्तमान प्रगति हमारे आकर्षण का कारण हो सकती है पर युद्धत सांभवाद के चार वर्षों की दारुण परिस्थितियों से होकर आगे बढ़ने का साहस शायद ही कोई देश कर सके। परिस्थितियों के आगे वे झुके पर टूटे नहीं—यही उनकी सफलता का रहस्य है।

आर्थिक विकास के लिए न उन्हें बिना जोती-बोई उर्वर धरती मिली, न विदेशी औद्योगिक सहायता और कच्चा माल और न ही औद्योगिक उत्पादन की खपत के लिए उपनिवेश। सब और से उनका रास्ता बन्द था। उनके साधन सीमित थे। लक्ष्य महान था। एक नितान्त नवीन और पूर्णतः अव्यावहारिक अर्थ-व्यवस्था का वे प्रयोग कर रहे थे और वह भी भूल और प्रयोग के

सिद्धान्त के आधार पर। आश्चर्य है उस अर्थ-व्यवस्था के प्रारूप के निर्माण में किसी अर्थशास्त्री का नहीं, दार्शनिक का हाथ था। मार्क्स का दर्शन परियों की कहानी के राजा द्वारा सपने में देखे गए मोती के पेड़ जैसा था, लेलिन ने सातवें राजकुमार की तरह उस पेड़ में पानी दिया। गैर कम्प्यूनिष्ट विचारकों ने इसे पागलपन समझा किन्तु स्तालिन ने मोती तोड़कर हमें दिखा दिया।

मार्क्स का स्वप्न लेलिन के हाथों संवारा गया, स्तालिन ने उसे साकार बनाया। स्वप्न अपने में बहुत बड़ा है। सोवियत देश उसे सर्वांग पूर्ण बनाने की दिशा में प्रयत्न शील है। विश्व में विचारकों की कमी नहीं है पर किसी विचारक के सिद्धान्तों को ऐसा व्यावहारिक रूप नहीं मिला। उनके मार्ग में अनगिनत बाधाएँ आईं। ठोकरे अच्छी हैं, गिरना अच्छा है बशर्ते की चलने का आगे बढ़ने का हौसला न टूट जाय।

पंचवर्षीय योजनाओं में शक्ति के श्रोत, साधन और लगाई जाने वाली पूँजी के सम्बन्ध में की जाने वाली जिज्ञासाओं के उत्तर प्रायः नहीं मिलते। प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े अध्येता के सम्मुख प्रश्न वाचक चिह्न बनकर खड़े हो जाते हैं। योजना की सफलता के लिए पूँजी के आधारीक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता पर पूँजी ही सब कुछ नहीं है। पूँजी उत्पत्ति का एक साधन भर है। कितनी पूँजी लगाई जा रही है यही जानना आवश्यक नहीं है यह भी जानना आवश्यक है कि वह पूँजी समाज के किस वर्ग से आ रही है ? उसके आगम का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास है अथवा संचय और परिग्रह ? व्यक्तिगत पूँजी का विनियोग आर्थिक विषमता को जन्म देता है और आर्थिक विषमता असन्तोष को। लोकतांत्रिक भावना के अभाव में राजकीय पूँजीवादी भी व्यक्तिगत पूँजी विनियोग की भांति कोढ़ की खाज बन सकता है। आर्थिक विकास के अध्येता को प्रत्येक प्रवृत्ति का विश्लेषण करना आवश्यक है।

विगत दस वर्षों में विभिन्न राष्ट्रों की समृद्धि और ऐश्वर्य शीलता में महत्व पूर्ण उलट-फेर हुआ है। एक समय था जब राष्ट्रों की समृद्धि का अनुमान उनकी जनसंख्या विस्तार, और अधिकृत उपनिवेशों से लगाया जाता था। कालान्तर में औद्योगिक प्रगति और कच्चे माल की उपलब्धि समृद्धि का माप

पूर्व पीठिका

दशक बनी। बीसवीं शती के द्वितीय चरण तक रूई, लोहा, पेट्रोल और कोयला समृद्धि के आवश्यक और अनिवार्य अंग थे। जब औद्योगिक ईंधन (fuel) के रूप में जल-विद्युत का प्रयोग होने लगा तो कोयले का महत्व पर्वतीय नदियों ने लिया। यह स्थिति भी अधिक दिन चल न सकी। बांध बनाकर कृत्रिम रूप से जल विद्युत बनाई जाने लगी। १९५६ में सोवियत सङ्घ विश्व के जल-विद्युत उत्पादन का १२% पैदा कर रहा था। (विश्व का कुल उत्पादन १२५० अरब किलोवाट था।) इस समय वाष्पीय यंत्रों से पैदा की जाने वाली बिजली कुल परिमाण की ६७% पूर्ति करती है। अनुमान है कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने पर कालान्तर में अफ्रीका ४१% और भारत तथा चीन २२% का उत्पादन करेंगे। सम्पूर्ण विश्व के तेल उत्पादन (८३,२७ लाख टन) का १०% इस्पात (३०,८० लाख टन) का १६%, ताम्बा (२७.५ लाख टन) का १०% सोवियत देश में होता है।

आज सम्पत्ति की परिभाषा भी बदल चुकी है। मोटे तौर पर कुछ कच्ची सामग्रियों की उपलब्धि, खाद्यान्न, शक्ति के स्रोत और औद्योगिक विकास को सम्पत्ति का माप दशक माना जाता है किन्तु विगत वर्षों के वैज्ञानिक आविष्कारों ने कुछ अत्यन्त नवीन पदार्थों को अत्यधिक मूल्यवान प्रामाणित कर दिया है। आज का युग कोयला, पेट्रोल और विद्युत को बहुत पीछे छोड़ आया है। आज का महत्वपूर्ण ईंधन है—आणविक शक्ति सर्वाधिक बहुमूल्य पदार्थ है, यूरेनियम और थोरियम। १९५७ में सोवियत सङ्घ आणविक शक्ति के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर (विश्व के कुल उत्पादन का ४०—४० प्रतिशत) था। सात वर्षीय योजना का लक्ष्य बहुत अधिक है।

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्लास्टिक और नाइलान का महत्व पूर्ण स्थान है। काठ और हाथी दांत का स्थान प्लास्टिक और सैल्युलाइड ले रहा है। संभव है भविष्य में नाइलान के कृत्रिम रेशे रूई, रेशम और जूट का महत्व घटा दें। यदि रसायन विज्ञान ने सचमुच खाद्य समस्या का हल ढूँढ़ निकाला तो कृषि उत्पादनों पर आ बनेगी। रसायन विज्ञान के लिए सर्वाधिक उपादेय सल्फरिक एसिड का १२% भाग सोवियत सङ्घ में उपलब्ध है। धात्विक उत्पादन में एल्युमिनियम की उपयोगिता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। विश्व

के कुल एल्युमिनियम उत्पादन में १२% रूस का हिस्सा है। औद्योगिक आवश्यकताएँ भी बहुत बढ़ गई हैं।

सम्प्रति हमें कहना यही है कि आज के बदलते युग में आर्थिक विकास के मूल्यांकन का दृष्टिकोण भी बदलना होगा। औद्योगीकरण, उत्पत्ति के साधन, व्यापारिक फसलें, पूँजी का विनियोग अब समृद्धि और ऐश्वर्य के माप इण्ड नहीं रहे।

विश्व के अर्थ-शास्त्री किसी देश के आर्थिक विकास का अध्ययन करते समय उसकी मांग और पूर्ति तथा आयात और निर्यात के संतुलन से उसकी आर्थिक समृद्धि के सम्बन्ध में अपना मत निर्धारित करते हैं। सोवियत सङ्घ के सम्बन्ध में उन्हें दूसरा दृष्टिकोण अपनाना होगा। यहाँ विकास के प्रथम चरण में ही आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति आ गई थी। फल यह हुआ कि आयात और निर्यात के आधार पर इसकी समृद्धि का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका। उत्पत्ति के साधनों के राष्ट्रीय कारण के कारण मांग और पूर्ति के संतुलन से क्रेता और विक्रेता की स्वतंत्र स्पर्धा के लिए अवकाश नहीं रह गया।

हमारा अभिप्राय मात्र इतना है कि पाश्चात्य अर्थ-शास्त्रियों के चश्मे से सोवियत सङ्घ की सर्वतोमुखी प्रगति नहीं देखी जा सकती। इसके लिए हमें उदार दृष्टिकोण अपना कर यहाँ की कम्यूनिस्ट अर्थ-व्यवस्था और 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के सिद्धान्त के कार्यान्वयन और उसकी सफलताओं का मूल्यांकन करना होगा।

अध्याय २

प्राकृतिक साधन

सोवियत समाजवादी लोकतंत्र मानव की समता के विश्वासी पन्द्रह राज्यों का सङ्घ है। ये राज्य हैं - रूस, उक्रेन, बेलोरूसी, उजबक, कजाकस्तान, जार्जिया, अज़र्बैजान, लिथूनियाँ, मोल्डाविया, लटाविया, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अर्मनी, तुर्कमानस्तान और इस्थोनिया। सोवियत सङ्घ पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल भू भाग में फैला हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल ३२० लाख वर्ग किलोमीटर (८५ लाख वर्ग मील) और जन संख्या २०,०२,००,००० (१९५६ की जन गणना के अनुसार) है।

औद्योगिक दृष्टि से सोवियत सङ्घ आत्मनिर्भर देश है। आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुएँ यहाँ उपलब्ध हैं।

कोयला

उद्योग धन्धों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन का प्रायः दो तिहाई भाग कोयला है। उक्रेन में बहने वाली दोनेत्स नदी की तराई में उपलब्ध कोयले की खानों से निकाला जाने वाला कोयला दक्षिण यूरोपीय रूस, बोलगा की तराई और यूक्रेन के औद्योगिक संस्थानों में धातु गलाने के काम आता है। करनगंदा (कजाकस्तान) की खानों से क्रान्ति पूर्व काल से २५ गुना अधिक कोयला निकाला जाता है। पीचोरा, क्रिजेल और चेल्याबिन्स्क अपेक्षया नए क्षेत्र हैं। इस समय ५९३० लाख टन का वार्षिक उत्पादन है। कजाकस्तान और साइबेरिया में कोयले की नई खानों का पता चला है।

मिट्टी का तेल

काकेशिया मिट्टी के तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वाकू, प्रेजनी और कुबान तीन अन्य बड़े क्षेत्र हैं। यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में, बोलगा और इम्बा नदी की तराई में तथा मध्य एशिया में भी मिट्टी के तेल के कुएँ हैं। १९५५ ई० में लगभग १३५० लाख टन तेल साफ किया गया था।

पीट (Peat)

पीट बिजली का तार बनाने में प्रयुक्त होता है। सोवियत सङ्घ में यह सर्वाधिक उपलब्ध है। यह मास्को, आइवेनो, यारोस्लेब्ल और लेलिनग्राद में मिलता है।

गैस

ट्रांस काकेशिया, उत्तरी काकेशिया, मध्य एशिया, उत्तरी और मध्य यूराल तथा पीचोरा में अधिकता से उपलब्ध है। १९५६—६० में गैस का उत्पादन दार्ढ़ गुना हो जायगा।

जल विद्युत शक्ति

दनीपर जल विद्युत केन्द्र सबसे बड़ा है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (१९५१—५५) द्वारा विज्ञान के अनुनातन साधनों से युक्त निम्नलिखित जलविद्युत केन्द्र खोले गए हैं— त्सम्लेनेस्कया जलविद्युत केन्द्र (लेलिन बोल्गा-दान नहर पर), ग्यूस केन्द्र (अर्मनी में) वेरखने स्विस् केन्द्र (लेलिनग्राद क्षेत्र में), मिनगेच्योर केन्द्र (अजर्बैजान में), कामा और काखोव्का केन्द्र (दनीपर पर), गोर्की केन्द्र (वोल्गा नदी पर) नार्वा केन्द्र आदि।

३२,००,००० किलो० क्षमता वाले दो जल-विद्युत केन्द्र इरकुत्स्क (अंगारा नदी पर) और बर्क शीघ्र ही कार्य करने लगेंगे और इतनी ही क्षमता का दूसरा केन्द्र क्रानोयारस्क बनाया जा रहा है।

१९६० में ३० लाख किलो० बिजली कोयले से उत्पन्न की जायगी।

खनिज पदार्थ

लेलिनग्राद, मास्को, एलेक्ट्रोस्ताल, वेक्सा, ओमुत्निन्स्क, ज्लातोत्स, ज्दानोव, पित्रोवास्क-जावेकात्स्की, कोम्सोमोलस्क में इस्पात, राग, तुला, लिपेत्स्क आदि में कच्चा लोहा, वोल्खोव में अल्यूसुनियम, बेमाक, मेदनागोर्स्क अलवर्दी में ताँबा, मिलता है। जस्ता, शीशा और निकल भी आवश्यकता भर उपलब्ध है।

भवन-निर्माण के कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री ग्रेनाइट, संगमरमर,

पत्थर और चूना यूराल और स्तेलिनोगोरास्क में पाये जाते हैं। उत्तरी काकेशिया और वोल्गा क्षेत्र में सिमेंट मिलता है।

लट्टा और काष्ठ

७०% जंगल पूर्वी यूराल और साइबेरिया में हैं। अधिकांश लट्टे श्रमिक काटते हैं। आजकल लट्टा काटने और चीरने का काम मशीनों से लिया जाने लगा है। सोवियत सङ्घ में प्रायः २०० लकड़ी चीरने की मिलें हैं।

प्लाइवुड और कागज बनाने के केन्द्र लेलिनग्राद, स्तालिनग्राद, इकार्गो, अर्खान्गोल्स्क आदि हैं।

धागा (Textile)

मास्को, लेलिनग्राद, मध्य एशिया पश्चिम साइबेरिया, ट्रांस काकेशस औद्योगिक केन्द्र हैं।

सिल्क के उद्योग वोल्गा क्षेत्र, मध्य एशिया, कजाकस्तान और साइबेरिया में हैं। आज कल सिल्क का प्रचार बढ़ रहा है।

खाद्यान्न

गेहूँ, जौ, जई, आलू और चुकंदर की चीनी बहुतायत से उत्पन्न होती है। भोजन में अम्लीय पदार्थ नहीं होते। खाना मीठा, फीका और नमकीन होता है।

यूक्रेन, मोल्डेवियन, उत्तरी काकेशस, दक्षिणी-पश्चिमी कुवान में जाड़े का और वोल्गा क्षेत्र, यूराल, पश्चिमी साइबेरिया, उत्तरी कजाकस्तान में बसन्त ऋतु का गेहूँ उत्पन्न होता है। यूक्रेन, कुस्क, बेलगोराद् तथा वोरिनेज में चुकन्दर होता है।

भूमि

जंगलों को छोड़कर ३ भाग जोत के अन्दर है। देश के क्षेत्रफल का प्रायः ३ भाग अविकसित भूमि है जो अधिकांश टंड्रा, रेगिस्तान या पहाड़ पर है। कृषि भूमि में यूरोपीय रूस की अधिक उन्नति हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है।

पशु

खेती, सवारी और खाने योग्य पशु अधिक हैं।

यूरोपीय रूस में दूध देने वाले पशु अधिक हैं। उक्रेन और उत्तरी काकेशस में सूअर, स्टेप्स में घोड़ा और टंड्रा में रेन्डियर तथा सफेद भालू अधिक मिलते हैं। कैस्पियन सागर, वोल्गा, ओबी, यनसी और लीना तथा अन्य छोटी नदियों में मछलियाँ मिलती हैं।

समुद्र

औद्योगिक दृष्टि से काला सागर प्रमुख है। देश का प्रायः ५०% व्यापार इसी से होता है। तेल, आनाज और कोयला बाहर भेजा जाता है। ओडेसा, निकोलवेयो, जान्दोनोव, रोस्तोव-आन-दान, वास्तुयी, नेवोरोसिस्क प्रमुख बन्दरगाह हैं। कैस्पियन सागर के तट पर बाकू और अस्तरखान के बन्दरगाहों द्वारा मिट्टी का तेल बाहर भेजा जाता है। बाल्टिक सागर के तट पर लेलिन ग्राद, तल्लिन और रिगा बन्दरगाह हैं। उत्तरी सागर वर्ष के ६ महीने जमा रहता है, मुरमास्क और अरर्वन्गोल्स्क से थोड़ा बहुत व्यापार होता है।

एशियायी रूस में जापान सागर के तट पर ब्लादीवोस्तक प्रमुख बन्दरगाह है।

अध्याय ३

जार युग

(१९०५ तक)

सोवियत सङ्घ के जार कालीन आर्थिक विकास का अध्ययन करते समय निरपेक्ष दृष्टिकोण अपेक्षित है। यह सत्य है कि इस युग के आर्थिक विकास की गति तत्कालीन पश्चिमी यूरोप जैसी न थी किन्तु देश की प्रगति का मार्ग अवरूढ़ न था, वह क्रमशः विकास की ओर बढ़ रहा था। गति के धीमेपन के लिए अनेकानेक भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं, अकेला जार ही दोषी न था।

औद्योगिक क्रान्ति और वैज्ञानिक अनुसंधानों से पूर्व विश्व के अन्य देशों के साथ सोवियत सङ्घ का सम्बन्ध घनिष्ट न था। उसके पास न तो अमेरिका की भांति प्रचुर मात्रा में उर्वर भूमि थी, न इंग्लैंड को भांति उपनिवेश। जनता में कुंठा और अवसाद छाया था। प्रकृति भी सद्य न थी। अपने ही बल पर प्रगति के पथ पर बढ़ना था। यदि जार को जनता का सहयोग मिला होता, यदि उसे वे सभी सुविधाएँ मिली होती जो पश्चिमी देशों को उपलब्ध थीं तो उसे और अधिक सफलता मिली होती। हाँ, विकास की दिशा आज जैसी न होकर कुछ और होती।

प्रथम पीतर ने पश्चिमी यूरोप के ढंग पर देश के विकास की कामना की थी। अपने उद्देश्य में वह बहुत अंशों में सफल भी रहा। १७०३ ई० में वर्ग नदी के किनारे उसने पीतरबुर्ग नगर बसाया जो १७२४ ई० में इस देश की राजधानी बना [१६९८ ई० तक यह नगर राजधानी था। १६२४ ई० में इसका नाम बदल कर लेलिनग्राद रख दिया गया।] भवन निर्माण की कला में विशेष प्रगति हुई।

जार के सपनों के प्रारूप और उनके कार्यान्वय के साधन पूँजीवाद और सामन्तवाद के मिश्रण थे। यही कारण है कि जार युग में एक ओर तो शरद प्रासाद (१७६२) और कजांस्की सवोर का गिर्जाघर (१८११) बना दूसरी ओर

कल कारखानों की स्थापना हुई। अन्य देशों की भांति विकास केवल उद्योग और कृषि तक ही सीमित न रहा। कला, स्थापत्य और साहित्य भी उसी अनुपात में फूला-फला। पुश्किन, लेर्मन्तोफ्, तालस्ताय, क्रोपत् किन्, चेरवब और गोर्की की लेखनी तथा शिल्पी मोत्फरॉ, रास्त्रेली, रोसी और बोरोनिखिन् की छेनी और हथौड़ी अबाध गति से चलती रही। जार शिल्पियों के प्रति जितना सदय था साहित्यकारों के प्रति उतना ही निर्मम। यदि जार भारत के श्रुंग, नाग था गुप्त सम्राट्टों की भांति सहृदय होता तो वहाँ कालीदास और भवभूति पैदा होते किन्तु जार की निरंकुशता और सामाजिक कुंठा ने पैदा किया तालस्ताय और गोर्की को। जार निकोलस के मुद्रण कानून द्वारा तनिक से अविश्वास पर लेखक साइवेरिया में घुट-घुटकर मरने के लिए भेज दिये जाते थे। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान की पुस्तकों में भी अनैतिक बातों की चर्चा अपराध थी किन्तु गोर्की ने 'चकला' लिखा ही। सोवियत सङ्घ के विकास में लेर्मन्तोफ्, तालस्ताय और गोर्की का योग लेलिन और स्तालिन से कम नहीं हैं।

अपनी भौतिक समृद्धि के बावजूद भी जार शाही आन्तरिक दुर्बलता की शिकार थी। देश की जनसंख्या १८२० लाख और क्षेत्रफल ८४५.०११८ वर्ग मील था।

वेस्ट लॉन्टोवास्क की संधि के फलस्वरूप पोलैण्ड, फिनलैण्ड, लेटेविया, लूथेनिया, एस्थोनिया अलग हो गए। देश का ३.८% क्षेत्रफल और १७.१% जनसंख्या कम हो गई। जार शाही की दुर्बलता इस संधि, जापान युद्ध (१९०४—०५) तथा अवसाद के एकाध अवसरों पर ही प्रकट हुई।

जनसंख्या

जार युग में देश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रही।

१७२५—१३० लाख । १७९६—३६० लाख । १८५१—६७० लाख
१८५८—७४० लाख । १८९५—१२५६ लाख । १८९७—१२९० लाख
१९१२—१७८० लाख ।

जनसंख्या वृद्धि के साथ एक और बात ध्यान देने योग्य है और वह है आर्थिक असमानता। देश की समृद्धि का उपभोग केवल मुट्टी भर सरमायेदार

करते थे। अधिकांश जनता अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए तरसती रहती थी। १८६५ ई० की जनसंख्या का विस्तृत विवरण निम्न है—

धनिक और सभ्रान्त वर्ग	— ३० लाख
धनी उद्योगपति	— २३१ लाख
मध्यम वर्गीय उद्योगपति	— ३५८ लाख
मजदूर-किसान	— ६३७ लाख

योग १२५६ लाख

उद्योग

१८८० ई० तक लघु स्तर पर देश का औद्योगिक विकास होता रहा। कृषि के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। आगे चलकर मंदी की एकाध छोटी अवधियों के अतिरिक्त देश निरन्तर आगे बढ़ता रहा। स्मरणीय है सोवियत सङ्घ के आर्थिक विकास में पूँजी और पूँजीपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। विकास के प्रथम चरण में ही उद्योगपतियों का विरोध प्रारंभ हो गया।

औद्योगीकरण के बाधक तत्वों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं—

१—सामान्य जनता की निष्क्रियता

जनता ने औद्योगीकरण में विशेष दिलचस्पी नहीं ली। संभवतः इसका कारण जनता की मानसिक कुंठा थी। बलात् मजदूर बनाये जाने की सरकारी नीति से भी विशेष लाभ न हुआ। १८६१ ई० में दास प्रथा समाप्त कर दी गई और प्रायः २०० लाख दास मुक्त हो गए। गांव के कठोर श्रम से ऊबे दास नगरों की ओर आकर्षित अवश्य हुए पर वे अकुशल श्रमिक थे।

२ जमीदारों का विरोध

आश्चर्य की बात तो यह है कि उद्योगपतियों के सबसे बड़े विरोधी मजदूर किसान न थे वरन् जमीदार थे। जार युग में जमीदारों का प्रभुत्व था। पीतर प्रथम ने बनियों को प्रमुखता दी। औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक भी था। जमीदारों ने बनियों की प्रमुखता को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझा। जमीदारों का विरोध अलेक्सन्द्र प्रथम के शासन काल में दिसम्बरी विद्रोह

(१८२५ ई०) के रूप में प्रकट हुआ। जमींदारों का यह विद्रोह कुचल दिया गया। ५ जमींदार नेताओं को फांसी दे दी गई और १०० अन्य नेता या तो पदच्युत कर दिए गए या साइबेरिया में निर्वासित कर दिए गए।

श्रम सम्बन्धी अधिनियम

समय-समय पर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कानून बनाये गए। बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती थी (१८२२)। औरतों और बच्चों से रात में काम नहीं लिया जा सकता था (१८८५)। दुर्घटना बीमा द्वारा आपत्ति काल में श्रमिकों को निःसहाय होने से बचाया गया (१९०३)। १९०५ में हड़ताल करना अवैधानिक घोषित कर दिया गया किन्तु हड़तालें होती रहीं।

वृहत स्तर उत्पादन की ओर

अठारहवीं शती से ही उद्योगों की दिशा वृहत् स्तर उत्पादन की ओर उन्मुख हुई। व्यक्तिगत स्तर पर चलाये जाने वाले उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होती रही पर उनकी वृद्धि का अनुपात राजकीय उद्योगों जैसा न था।

वर्ष	राजकीय कारखाने	व्यक्तिगत कारखाने	योग
१७४१-४३	६३,०५४	२४,१९९	८७,२५३
१७६२	९९,३३०	४३,१८७	१,४२,५१७
१७८१-८२	२,०९,५५४	५४,३४५	२,६३,८९९
१७९४-९६	२,४१,२५३	७०,९६५	३,१२,२१८

आँकड़ों से स्पष्ट है कि आगे चलकर उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके नींव की ईंट जार युग में ही रखी जा चुकी थी।

लघु स्तर उद्योग दिनों दिन कम होते गए। अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ विशिष्ट उद्योगों के आँकड़े दिए जा रहे हैं।

सन् उद्योग के हाथ करवे १८६६ में ४३६ तथा १८७९ में ४४१ और १८९० में ३११ थे। इसके विपरीत शक्ति से चलने वाले करघों की संख्या में वृद्धि हुई। शक्ति-करघों की संख्या जो १८६० में ११,००० थी बढ़कर १८९० में ८७,००० हो गई।

मोमबत्ती

१८६६-३८ ई० में १३६ लाख रूबल की मोमबत्ती बनाई गई थी किन्तु १८६० ई० में यह संख्या घटकर ५० लाख रूबल हो गई। मोमबत्ती उद्योगों की हासो-मुखता का कारण तेल के नये कृत्रों की जानकारी थी। प्रकाश के लिए मोमबत्ती के स्थान पर मिट्टी का तेल प्रयुक्त होने लगा था।

अन्य रासायनिक पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होती गई—

वर्ष	रासायनिक पदार्थों का मूल्य
१८५७	१४० लाख रूबल
१८८०	३६२.५ लाख रूबल
१८६०	४२० लाख रूबल

चमड़ा

चमड़े के उद्योग गृहों की संख्या में तो कमी हुई किन्तु मजदूरों की संख्या और निर्मित माल के मूल्य में वृद्धि हुई।

वर्ष	उद्योग गृह	मजदूर	निर्मित माल का मूल्य लाख रूबल में
१८६६	२३०८	११४६३	१४६
१८६०	१६२१	१५५६४	२७७

अधिकांश कल कारखाने यूरोपीय रूस में ही थे।

१८६० के आँकड़ों के अनुसार वहाँ १११२४ कारखाने और ८७५७६४ मजदूर थे जो १५०१० लाख रूबल के मूल्य का सामान्य तैयार करते थे।

खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग भी निरंतर प्रगति करते रहे। आनाज की सफाई करने और भूसी निकालने वाले उद्योग लघु स्तर पर देश भर में बिखरे थे। आटा पीसने की पवन चक्कियों की संख्या में वृद्धि हुई—

वर्ष	पवन चक्कियां
१८६५	८५७
१८६६	२१७६
१८८५	३६४०
१८६०-६१	५२०१
१८६४-६५	५०४१

ल

तेल पेरने के उद्योगों और उनमें काम करने वालों की संख्या में कमी अवश्य हुई किन्तु उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। जब देश लघु स्तर उत्पादन से वृहत् स्तर उत्पादन की ओर अग्रसर होता है तो प्रायः यही स्थिति होती है—

वर्ष	कारखाने	श्रमिक	उत्पादन रूबल में
१८७६	२४५०	७२०७	६४८६०००
१८९०	३८३	४७४६	१२२३२०००

कारखानों और श्रमिकों की संख्या में कमी का आशय देश में बेकारी की वृद्धि नहीं है। विकासोन्मुख देशों में ऐसा होना स्वाभाविक है। अल्प कारखानों के बन्द होने पर दूसरे कारखाने खुल जाते हैं और श्रमिकों को काम मिल जाता है। निम्न आँकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो जायगी—

वृहत् स्तर उद्योग (काम करने वाले हजारों में)

वर्ष	कारखानों में	खनिज उद्योगों में	रेलों में	योग
१८६५	५०६	१७५	३२	७०६
१८९०	८४०	३४०	२५२	१४३२

१९०५ ई० में लोहा और इस्पात के उत्पादन में इसका चौथा स्थान था। १९०६ ई० में यह विश्व के ६ प्रमुख व्यापारिक देशों में एक था। खनिज, चातु कार्मिक (Metallurgical) और तेल उद्योगों में इंग्लैण्ड और फ्रान्स आदि पश्चिमी देशों की भी पूँजी लगी थी। अधिकांश उद्योग देशी पूँजी से चलाए जा रहे थे।

औद्योगिक क्षेत्र में मिश्रण आन्दोलन (Combination Movement) प्रारंभ हो गया था। विभिन्न उद्योगों ने समय-समय पर अपने न्यास (Trust) और अभिषद (Syndicate) बनाये। यह प्रवृत्ति सबसे पहले लोहा और इस्पात के उद्योगों में आई। कालान्तर में चीनी और पेट्रोल आदि अन्य उद्योगों के भी अनेक न्यास और अभिषद बने।

देश के कल कारखानों, श्रमिकों तथा उत्पादक की निरन्तर वृद्धि होती रही—

वर्ष	कारखानों की संख्या	श्रमिकों की संख्या हजार में	वार्षिक उत्पादन लाख रुबल में
१८५०	६,४८३	३१७.७	१,६६०
१८६३	१६,६५६	४१६.६	३,५१८
१८७०	२६,३७७	४३५.८	५,००१
१८७६	३४,७७४	८६१.०	१२,६०३
१८८०	३२,२५४	१,४२४.८	१५,०२६
१९००	३८,१४१	२,३७३.४	३४,३८६
१९०८	३६,८६६	२,६७६.६	४६,०८६
१९१२	२६,६६५	२,६३१.३	५७,३८१

व्यापार

१९१४ ई० के पूर्व व्यापार का संतुलन देश के पक्ष में था। १९१४ ई० से २० तक व्यापार का संतुलन विपक्ष में रहा। संतुलन बिगड़ने का मूल कारण आन्तरिक अव्यवस्था थी।

(लाख रुबल में)

वर्ष	निर्यात	आयात	सन्तुलन
१९०४	१०,०६३	६,५१४	+ ३,५४९
१९०५	१०,७७३	६,३५०	+ ४,४२३
१९०६	१०,६४८	८,००६	+ २,६४२
१९०७	१०,५३०	८,४७३	+ २,०५७
१९०८	६,६८२	६,१२६	+ ५६६
१९०९	१४,२७६	६,०३६	+ ८,२४०
१९१०	१४,४६०	१०,८४४	+ ३,६१६

वर्ष	निर्यात	आयात	सन्तुलन
१९११	१५,९१४	११,६१६	+ ४,२९८
१९१२	१५,१८७	११,७१७	+ ३,४७०
१९१३	१५,२०१	१३,७४०	+ १,४६१
१९१४	८,३५०	११,०६०	- २,७४४
१९१५	२,७४०	८,७००	- ५,९६०
१९१६	२,३७०	८,६२०	- ६,२५०
१९१७	१,३७०	८,०२०	- ६,६५०
१९१८	७५	६११	- ५३६
१९१९	१	३०	- २९
१९२०	१४	२८७	- २७३

यातायात

यातायात के साधनों की दृष्टि से देश बहुत पीछे था। इतने बड़े देश में केवल ४५,००० मील लम्बी रेल थी (१९१५) अधिकांश आवागामन नदियों द्वारा होता था जो शीत ऋतु में बर्फ से जम जाती थीं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का सामना न कर पाने का एक कारण यातायात के साधनों का अभाव भी था।

कृषि

कृषि के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। किसान पुराने विचार के थे। यद्यपि ८०% जनसंख्या की आजीविका कृषि ही थी किन्तु भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में बड़ा अन्तर था। जार शाही के अंतिम वर्षों में देश भर में प्रायः १७० लाख खेत थे। आधी कृषि योग्य भूमि बड़े भूपतियों, मठों और शाही परिवार की थी, बीस प्रतिशत भूमि बड़े किसानों की थी और शेष ३० प्रतिशत पर देश की दो तिहाई जनता का स्वामित्व था। श्री लेनिन के शब्दों में १९०५ ई० में—

गरीब किसान — १०५ लाख

मध्यम वर्ग — १० लाख

सम्पन्न किसान—१५ लाख

बड़े जमींदार—३ लाख

योग १३०.३ लाख

भूमि पर स्वामित्व न रहने और कृषि उत्पादन का मन चाहा उपभोग न कर पाने के कारण किसान खेती में मन नहीं लगाते थे। १८६१ ई० में दासों को मुक्त कर देने पर विकास के लक्षण प्रगट हुए थे पर सरकारी नीति के कारण आशा जनक सफलता न मिल सकी। दासों को आधे समय जमींदार के खेत पर काम करना पड़ता था और आधे समय अपने खेत पर। खेत उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न थे, ४६ वर्ष में उन्हें क्रमशः मूल्य चुकाना था।

१८८२ ई० में कृषकों की आर्थिक समस्या सुलभने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना हुई। १९१४ ई० में देश भर में ३३००० समितियां कार्य कर रही थी जिनमें १२,००० उपभोक्ता समितियां, १३००० साख समितियां और ८००० बहुद्वेशीय समितियां थीं। १९१० ई० में जार ने भूमि के सामूहिक स्वामित्व को व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार कर लिया।

अध्याय ४

राज्य क्रान्ति

(१९०५—१७)

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग युद्ध के सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं पर सोवियत भूमि का आर्थिक और राजनीतिक इतिहास मार्क्स के अनुमानित तथ्यों और घटनाओं के समान्तर चल रहा था इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। १९०५ से रक्त क्रान्ति तक यहाँ के आर्थिक इतिहास में यदि कोई समस्या थी तो वह वितरण की थी। औद्योगिक पूँजीवाद के विकास के लिए वहाँ अवकाश न था। कारण स्पष्ट है। पश्चिमी यूरोप में सामन्तवाद की जड़े सोवियत भूमि इतनी गहरी नहीं थी। औद्योगिक पूँजीवाद के आरंभिक चरण में ही यूरोपीय देशों को अतिरिक्त उत्पादन की खपत के बाजार मिल गए—ये बाजार थे, अविकसित उपनिवेश। फलतः सामन्तवाद और औद्योगिक पूँजीवाद दोनों को एक साथ प्रसार का अवसर मिला, दोनों परस्पर विरोधी बनकर नहीं, मित्र बनकर आए।

सोवियत संघ की परिस्थिति भिन्न थी। यहाँ की औद्योगिक पूँजी का प्रायः तीन चौथाई भाग विदेशी था। यदि रक्त क्रान्ति विफल हुई होती तो बहुत सम्भव था कि औद्योगिक पूँजीवाद जार शाही ही से साठ-गांठ करके आर्थिक विकास को किसी दूसरी दिशा में ले जाता। हमारे इस अनुमान का आधार तत्कालीन औद्योगिक अवस्था है। सोवियत उद्योग विदेशी पूँजी और व्यवस्था के अन्तर्गत आगे बढ़ रहे थे। करोड़ों रूबल की विदेशी पूँजी यूरोपीय रूस में लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत बैंकों का तीन चौथाई भाग यूरोपीय पूँजीपतियों का था। कोयला उद्योग में पेरिस के बैंकों की पूँजी लगी थी। फ्रान्स और इंग्लैंड के बैंक मिट्टी के तेल उद्योग पर हावी थे। बाकू के तेल का ४०% भाग इंग्लैंड और फ्रान्स के हाथ में था। बिजली उद्योग में जर्मनी की पूँजी लगी थी।

विदेशी पूँजी पर आधारित उद्योगों के प्रसार का मुख्य कारण यूरोपीय रूस का सस्ता श्रम था। बीसवीं शती के आरम्भिक वर्षों में अकुशल श्रम का भी औद्योगिक महत्व था। स्वतंत्र स्पर्द्धा में लागत का महत्वपूर्ण स्थान होता था। यूरोपीय रूस में किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादन की लागत कम पड़ती थी।

भूमि

भूमि की समस्या ज्यों की त्यों बनी थी। जारशाही ने इसमें हस्तक्षेप करना उचित न समझा। आश्चर्य तो यह है कि भूमि की समस्या-क्रमशः अपने आप सुलभती जा रही थी। जमींदार दिन प्रति दिन भूमि बँच रहे थे और धनी किसान उसे खरीद रहे थे। १९०५—९ तक के चार वर्षों में बड़े जमींदारों ने अपनी भूमि का दसवां भाग धनी किसानों के हाथ बँच दिया था।

भूमि से जीविका पाने वालों के तीन वर्ग थे—

१—गाँव के मुखिया— इनके हाथ में कुल भूमि का $\frac{१}{५}$ भाग था। ये लोग अपनी सारी भूमि पर खेती नहीं करते थे। इनकी भूमि का ७५% माला गुजारी या अधिया पर दूसरे धनी किसान या भूमि हीन किसान जोतते थे।

२—धनी किसान— शेष $\frac{१}{५}$ भूमि के स्वामी।

३—भूमि हीन किसान मजदूर।

सरकार की नीति

आरम्भ में सरकार मुखियों को नाराज नहीं करना चाहती थी। मुखियों की सहायता के बिना लगान की वसूली नहीं हो सकती थी। धनी किसान इन्हीं की सहायता से साधारण किसानों पर अत्याचार कर पाते थे। किन्तु ये मुखिये संख्या में बहुत थोड़े थे और जन-उभाड़ को रोकने में असमर्थ थे। धनी किसान भी इनसे असन्तुष्ट थे। समर्थकों की संख्या बढ़ाने और किसान मजदूर आन्दोलन को कुचलने के लिए यह आवश्यक था कि धनी किसानों को अपेक्षित सुविधाएँ दी जाती और यदि मुखिया इस कृत्य से नाराज होते तो उन्हें नाराज होने दिया जाता।

जार शाही के प्रमुख अधिकारी स्तोलिपिन ने अपने कृषि सम्बन्धी सुधारों द्वारा इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर २२ लाख किसानों को मुखियों के चंगुल से मुक्त कराया फलतः प्रायः ६ लाख किसानों के पास निजी सम्पत्ति के रूप में भूमि हो गई। इस सुधार से लाभ उठाने वाले जार शाही के समर्थक बन गए।

राजनीतिक दल

संक्रमण कालीन युग में राजनीतिक दलों की जैसी अवस्था प्रायः रहती है यहाँ भी थी। किसान-मजदूरों के आन्दोलन बुरी तरह कुचल दिए गए थे। १९०३-४ में जनतंत्रक समाजवादी दल (Social Democratic Party) में दो दल हो गए। गर्म दल जिसका नेता लेनिन था बहुमत में था। श्री लेनिन के दल का नाम इसी कारण बोल्शेविक (बहुमतीय) पड़ा।

दूसरा दल सुधारवादी मेन्शेविक (अल्पमतीय) था। मेन्शेविक दल वस्तुतः आराम कुर्सी के शिक्षित राजनीतिज्ञों का संघटन था। इन्हें कमकरो की शक्ति की अपेक्षा अपनी बुद्धि पर अधिक भरोसा था।

पारस्परिक फूट के कारण कमकरो की शक्ति का हास देखकर प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सक्रिय हो उठीं। व्यापारी तथा घनी किसानों ने १९०५ की विफल क्रान्ति के बाद रूसी जनसंघ (Union of the Russian People) नामक संस्था बनाई।

रूसी जनसंघ

रूसी जनसंघ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मारकोव थे। यह अभिजात वर्ग तथा पुलिस के एजेंटों का दल था। इनका मुख्य उद्देश्य निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए सरकार का साथ देना और कमकरो की सहानुभूति पाने के लिए समय असमय जैसा तैसा आन्दोलन चलाते रहना था। ये चमगादड़ी प्रवृत्ति के नेता एक ओर तो सरगर्मी दिखाकर जनता की सहानुभूति पाने के इच्छुक थे दूसरी ओर जन-शक्ति का दुरुपयोग कर आन्दोलन विफल बनाते थे। सरकारी सूचनाओं के अनुसार १९०७ में १६६२, १९०८ में १६५६ और १९०९ में १४३५ व्यक्तियों को राजद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी।

बोलशेविक दल ने सरकार के सम्मुख तीन मांगे रखीं—

- १—प्रशासन का ढांचा लोकतांत्रिक हो ।
- २—जमींदारी का अंत किया जाय ।
- ३—मजदूरों से ८ घंटे से अधिक काम न लिया जाय ।

१९१० से अक्टूबर क्रान्ति तक अनेक विफल हड़तालें हुईं । हड़ताल में भाग लेने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई । सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल 'लेना के रक्त स्नान' (Lena Bloodbath अप्रैल १९१२) के बाद हुई । लेना (साइबेरिया) की सोने की खानों में काम करने वाले निहत्थे मजदूरों पर गोली चलाई गई थी । मजदूरों के खून से वहां की धरती लाल हो जाने के कारण इस घटना को 'लेना का रक्त स्नान' की संज्ञा मिली ।

प्रथम विश्व युद्ध

आस्ट्रिया का राजकुमार सरविया में खेर करते समय मारा गया—इस छोटी सी चिनगारी ने सम्पूर्ण यूरोप महाद्वीप को युद्ध की लपटों में भून दिया । युद्ध, युद्ध के कारण और उसके प्रभाव पर आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी, करें क्यों ? क्या युद्ध का यही कारण था ? क्या इसके मूल में राजकुमार की ही प्रतिहिंसा थी ?

जार का युद्ध से कोई सीधा सम्बन्ध न था । वस्तु स्थिति यह थी कि रूस के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर मित्र राष्ट्रों के बैंकों का प्रभाव था । चूँकि इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के पूँजीपतियों का स्वार्थ निहित था इस कारण रूस को भी इसमें भाग लेना पड़ा । युद्ध में भाग लेने का एक और कारण था, रूस और जर्मनी में कृषि सम्बन्धी प्रतियोगिता । जर्मनी ने रूस के गल्ले पर बहुत अधिक कर लगा दिया था । जार निकोला जर्मनी के इस व्यवहार से अप्रसन्न था ।

युद्ध में भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सम्राज्ञी जारीना थी । जार निकोला उसके हाथ की कठपुतली था । जारीना इतिहास प्रसिद्ध सुन्दरी और महत्वाकांक्षिणी स्त्रियों की भांति मूर्ख और घमंडी थी । स्त्रैण होने के कारण जार में उसकी बात टालने की सामर्थ्य न थी । मजे की बात तो यह है कि

जारीना जर्मन रक्त से सम्बन्धित थी। जार के कुछ बड़े सैनिक अफसर जर्मनी से घन पाते थे। आक्रान्ता विजय की नहीं, जनता के उभाड़ की दिशा बदलने की थी। राजनीति के प्रति जागरूक और आर्थिक विषमता से आक्रान्त जनता को युद्ध का भूत ही बहला सकता था; पेट की आग देश भक्ति के धूप छाही अवगुंठन से ही काबू में की जा सकती थी। जारीना ने यही किया।

१९१३ ई० तक प्रायः सभी कुशल मजदूर सेना में भर्ती किए जा चुके थे और रेल का इंजन बनाने के कारखानों में युद्ध सामग्री उत्पन्न की जाने लगी थी। प्रायः डेढ़ करोड़ नए रंगरूट बनाए गए। कृषि और उद्योग के क्षेत्र से एक तिहाई जनता सेना में भेज दी गई थी।

युद्ध सामग्री का यह हाल था कि सैनिक आवश्यकता की एक तिहाई राइफलें देश में थीं। जिस प्रकार बूचड़ खाने में बकरे भेजे जाते हैं जार ने युद्ध में सैनिक भेजे। खाद्य सामग्री इन बलि के बकरों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी—सामान्य जनता की बात और है।

यातायात की सुविधाओं के अभाव में आयात सामग्री स्टेशनों पर ही पड़ी रहती थी। देश में वस्तु विनियम प्रणाली प्रचलित थी। कृषि उत्पादन दिनों दिन गिरता जा रहा था। सामान्य जनता को आवश्यक आवश्यकताओं के लिए भी तरसना पड़ता था। १९१६ की शीत ऋतु में कृषकों को जो कष्ट सहने पड़े उसका अनुमान करना भी कठिन है।

युद्ध और कम्युनिस्ट

सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट युद्ध-विरोधी होते हैं। वर्ग युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य युद्ध में उनकी आस्था नहीं होती। साम्राज्यवादियों की विजय या पराजय का मजदूर किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके पास खोने के लिए केवल पैरों की बेड़ी होती है। गोलियां-मोलियां हैं चाहे वे बर्लिन की हो या पेन्नोप्रद की। युद्ध घोषणा के बाद ही बोल्शेविक दल ने तीन बातों के लिए प्रयत्न आरम्भ किया—

१—साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध में परिवर्तित करना।

२—साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की सरकार की हार की क मना करना।

३—अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना ।

स्टेट ड्यूमा में बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने युद्ध के विरुद्ध मत दिया । इस अपराध के लिए ५ बोल्शेविक प्रतिनिधियों को साइबेरिया में आजीवन देश निकाला दे दिया गया ।

जब राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता एक दूसरे से टकरा जाती है तो कम्युनिस्ट बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं । विजय प्रायः राष्ट्रीय भावनाओं की होती है । युद्ध काल में कम्युनिस्टों के पग प्रायः डगमगा जाते हैं । प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय (Second International) का अंत कर दिया । उन्होंने युद्ध के विरुद्ध प्रस्ताव तो पास कर लिया, अपनी-अपनी सरकारों को जी भर कोसकर उनकी हार की कामना कर ली किन्तु युद्ध छिड़ते ही केचुल बदल ली । जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के कम्युनिस्टों ने अपनी अपनी सरकार का समर्थन किया । प्रत्येक का विश्वास था कि उनकी सरकार आत्म-रक्षार्थ युद्ध कर रही है ।

अर्थ-व्यवस्था

प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस औद्योगिक दृष्टिकोण से एशिया का ही एक भाग था । अत्यधिक पिछड़ी शान्ति कालीन अर्थ-व्यवस्था को युद्ध कालीन अर्थ-व्यवस्था में परिणत कर देना मूर्ख निकोलस अथवा महत्वाकांक्षिणी जारिना के बस की बात नहीं थी । औद्योगिक पोलैंड, कृषि क्षेत्र उक्रेन, बाल्टिक और काला सागर के बन्दरगाह खोकर जार शाही जमीन पर के कछुए जैसी निरीह और पंगु हो गई थी । उसका सैनिक व्यय प्रायः २४० लाख रूबल प्रतिदिन था ।

सुधार की धुन में जार ने १९०६ ई० में मद्य निषेध कानून पास कर दिया था । आबकारीकर, कर द्वारा प्राप्त आय का प्रायः २०% था । इस ७९१८ लाख रूबल वार्षिक घाटे को पूरा करने और रीढ़ तोड़ डालने वाले सैनिक व्यय के लिए अप्रत्यक्ष करों और मुद्रा प्रसार का सहारा लिया गया । यदि जार ने सामन्तवादी कर पद्धति न अपना कर लोकतांत्रिक कर पद्धति अपनाई होती तो वह सफल रहता पर उसने ऐसा न किया ।

मुद्रा प्रसार के कारण रूबल की क्रय शक्ति १९१५ से ही गिरने लगी थी। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि सरकारी छाप खाना प्रतिदिन ३०० लाख रूबल के नोट छाप सकता था और देश में ७५० लाख रूबल के नोटों की आवश्यकता थी। १९१४ में १६३ करोड़ रूबल के नोट चलन में थे। १९१७ में कागजी मुद्रा १७१७.५ करोड़ रूबल हो गई। १९१७ के मूल्य युद्ध पूर्व वर्षों के साठ गुने थे।

देश विदेशी ऋण के भार से दिनो दिन दबता जा रहा था। क्रान्ति के समय देश पर प्रायः ४३६१ लाख रूबल का कर्ज था।

उद्योग

युद्ध से विदेशी व्यापार को बड़ा धक्का पहुँचा। निर्यात के लिए बनाए गए माल परिवहन के साधनों के अभाव में देश में ही रह गए। उद्योगपतियों को देशी बाजार पर ही निर्भर रहना पड़ा। मुद्रा की क्रय शक्ति के ह्रास के कारण देशवासियों की आवश्यकताएँ सीमित हो गईं। उद्योगों का सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाने का यह भी एक कारण था। ईंधन और कच्चे माल की कमी, अनुभव के अभाव और कुप्रबन्ध के कारण औद्योगिक विकास उतना न हो सका जितना युद्ध काल में प्रायः होता है। युद्ध काल में उद्योग क्रमशः उन्नति करते गए —

वर्ष	कारखानों की संख्या	कुल उत्पादन करोड़ रूबल में
१९१३	१३,४८५	५६२*१
१९१४	१३,८५८	५६६
१९१५	१२,६४६	६३६
१९१६	१२,४६२	६८३*१

देश की तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उत्पादन की २०% वृद्धि अपर्याप्त थी। स्मरणीय है कि परेशानी जार को थी, जनता को थी। उद्योगपतियों के लाभांश पर देश के आर्थिक असन्तुलन का प्रभाव नहीं पड़ा। १९१३—१५ में उद्योगपतियों का लाभांश प्रायः दूना हो गया था। कुछ विशिष्ट उद्योगों ने अपनी पूँजी का २५.०% तक लाभांश बाँटा था।

कृषि

कृषि प्रधान देश में कृषि की उपेक्षा आश्चर्य का विषय हैं। युद्ध काल में कृषि उत्पादन क्रमशः गिरने लगा और सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयास के बावजूद १९२१ तक कोई उल्लेखनीय प्रगति न हो सकी। यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति के बहुत दिन बाद यहाँ भी कृषि क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग होने लगा पर उनका आयात होता था। देश में मशीनों के निर्माण की कोई व्यवस्था न थी। युद्ध के कारण आयात असंभव हो जाने पर मशीने दुर्लभ हो गईं।

सरकार ने सैनिक आवश्यकतओं को ध्यान में रखते हुए घोड़े जन्त कर लिए। घोड़ा रूसी किसान का मुख्य पशु है। किसानों को भी सैनिक बनने के लिए बाध्य किया गया। युद्ध काल में अनाज की उपज में प्रायः एक तिहाई की कमी हुई।

राजकीय नियंत्रण की शिथिलता के कारण कृषि उत्पाद के मूल्य विभिन्न स्थानों पर विभिन्न थे। जिले के अधिकारी स्वेच्छा से मूल्य निर्धारित करते थे। किसान अधिक मूल्य वाले जिलों में कृषि उत्पादन बेचना पसन्द करते थे। अधिकांश उत्पादन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सेना के लिए खरीद लिया जाता था। सट्टेबाजी और चोर बाजारी का बोल बाला था। खुले बाजार में बहुत कम चीजें बिकती थीं।

सामाजिक अवस्था

समाज के प्रत्येक वर्ग में असन्तोष व्याप्त था। आरम्भ में तो केवल नगर मजदूर हड़तालें करते रहे कालान्तर में सेना से भागे सिपाहियों ने भी उनका साथ देना प्रारम्भ किया। विजित प्रदेशों से भागे नागरिकों और सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था न की जा सकी। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि उदार विचारधारा के मॅनशेविक कर्रेंस्की भी दूमा में गर्म बातें करने लगे।

मार्च की क्रान्ति •

जार निकोला ने परिस्थितियों से तंग आकर २ मार्च १९१७ को त्याग-पत्र दे दिया। उसके अपने शब्दों में 'भेरे (जार के) चारों ओर कायरता, धोखाबाजी और विश्वासघात' था।

रानियों ने जब भी देश की राजनीति में सक्रिय भाग लिया, राज्य का पतन हुआ—इतिहास के इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। काश, जार समय से पहले इसे समझ सका होता।

इन्कलाब के ८ महीने

२ मार्च से ८ नवम्बर तक

२ मार्च १९१७ को एक बजे सबेरे जार निकोला ने सिंहासन छोड़ दिया। एक काम चलाऊ अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। कहने को क्रान्ति सफल रही किन्तु शासन सत्ता जार के ताड़ से गिर कर धनिक वर्ग के खजूर पर अटक गई। क्रान्ति में रक्त बहा जनता का किन्तु शक्ति मिली बोलुश्वा वर्ग को।

म्यूलिकांब के निर्देशन में भूमि सुधार योजना बनाई गई किन्तु धनी किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निश्चय न किया जा सका। जुलाई में अस्थायी सरकार में पुनः परिवर्तन हुआ और करैस्की के नेतृत्व में नई सरकार बनी। करैस्की ने बिना मुआवजा दिए भूमि का बटवारा करने का निश्चय किया। लेनिन से करैस्की का विरोध क्रमशः बढ़ता गया। पेत्रोग्राद सोवियत का प्रधान करैस्की नवम्बर क्रान्ति के पक्ष में नहीं था। ७ नवम्बर १९१७ (पुराने रूसी पंचांग के अनुसार २५ अक्टूबर) को लाल क्रान्ति सफल रही। कवि सुलेमान स्ताल्स्की के शब्दों में, “बोलशेविक भूकम्प ने पुराने संसार को तर-ऊपर कर दिया। हमारे चिरकालीन दुख के पहाड़ ढह गए और हमारी अंधकार-पूर्ण घाटी को अक्टूबर के महान प्रकाश ने आलोकित कर दिया।”^१

^१सोवियत भूमि—राहुल सांकृत्यायन पृ० ३४१

लेनिन युग

(१९१७-१९२४)

अध्याय ५

युद्धत साम्यवाद

(War Communism 1917—21)

लेनिन युग का उत्तरार्द्ध सोवियत संघ के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। जार की प्रतिस्पर्द्धी पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व से आंतकित हो उठी थीं। देश के सामन्त और पूँजीपति खोई प्रभुता पाने के लिए सचेष्ट थे। कुंठित और हीन भावनाओं से ग्रसित जनता साम्यवाद के लिए तैयार न थी। अपने साहस लगन और निष्ठा से लेनिन ने सोवियत संघ की इस संक्रमण काल में रक्षा की। यह सत्य है कि लेनिन को अपने जीवन काल में अपेक्षित सफलता न मिली किन्तु सोवियत संघ की वर्तमान सफलतायें (और उज्वल भविष्य) उस महामहिम के अध्यवसाय की नींव पर खड़ी हैं।

१९१८ ई० में पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ को चारों ओर से घेर लिया उनका प्रयत्न यह था कि आवश्यकता की कोई वस्तु देश के भीतर बाहर से न जाने पाये। औषधियाँ और बच्चों के लिए दूध तक न आ पाता था। कर्बला की कहानी दुहराने में मित्र राष्ट्रों ने कोई कसर नहीं उठा रखी। बोलशेविकों को दबाने के लिए पोलों को भड़काया गया और उन्हें सहायता दी गई। जार को दिये गए कर्जे के प्रश्न पर भगड़ा आरम्भ हुआ। जार युग के जमींदारों और पूँजीपतियों ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की। जहाँ कहीं भी मित्र राष्ट्रों की विजय हुई पुरानी जार शाही की स्थापना की गई किन्तु विरोधी शक्तियों की विजय क्षणिक थी। कालान्तर में उन्हें भुक्ना पड़ा।

अराजकता

क्रान्ति के पश्चात् अराजकता की स्थिति स्वाभाविक है पर सोवियत संघ को अपने शैशव में ही जिस संक्रमण काल का सामना करना पड़ा वह अभूत-पूर्व है। लेनिन और नवजात बोलशेविक सरकार के सम्मुख एक साथ तीन शत्रु आए—

- १—जार की श्वेत सेना, नड़े अधिकारी, सामन्त तथा पूँजपति।
- २—विदेशी आक्रमणकारी।
- ३—देश के गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दल।

श्वेत सेना और विदेशी आक्रमणकारी

श्वेत सेना मणि खोये नाग के समान भयानक हो उठी थी। दक्षिण में कुबान और उत्तर में काकेशिया उसके केन्द्र थे। जर्मनी के साथ जब से वेस्त लितोवास्क की सन्धि हुई थी तभी से उक्रइन जर्मनी के अधिकार में था। अक्टूबर १९१८ में श्वेत सेनाओं ने जनरल दंकिन के तत्वावधान में अजो और ओल्गा के क्षेत्र अधिकृत कर लिए थे। अगस्त में जेक शक्तियों ने श्वेत सेना के साथ साइबेरिया से कजाखस्तान तक अधिकार जमा लिया। अमेरिका, कनेडी, फ्रांसीसी तथा जापानी सेना की सहायता से एडमिरल कोलचक ने यूराल से साइबेरिया तक का विशाल भू भाग हस्तगत कर लिया। सेमिनोव और होरवत को जापान की मदद मिल रही थी। उत्तर में ब्रिटिश सेनायें बढ़ अवश्य रही थीं पर उन उनकी प्रगति धीमी थी। शासन सूत्र ग्रहण करते ही प्रायः दो तिहाई भाग लाल सेना (बोलशेविक) के हाथ से जाता रहा।

बीसवीं शती का दूसरा दशक लोक-तांत्रिक सिद्धान्तों के प्रसार का युग था। अधनंगी और भूखी जनता अपनी शक्ति और अधिकारों से परिचित हो रही थी। नींद की तंद्रा का कुहासा एशिया के आकाश से उठ रहा था। भारत, चीन, टर्की, ईरान जंग लगी जंजीरों को तोड़ डालना चाहते थे। स्वाभाविक था कि सोवियत सङ्घ पूर्वोक्त देशों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता। हुआ भी यही किन्तु देशी पिस्तौल और हथ गोले सोवियत सङ्घ की क्या सहायता करते ? और वह भी तब जब चलाने वाले हाथों में बेड़ी पड़ी हो।

लेनिन युग—युद्धत साम्यवाद

देश के गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दल

लाल क्रान्ति से पूर्व देश में लोकतांत्रिक भावनाओं का उदय हो रहा था। जार निरंकुश स्वेच्छाचारी सम्राट् नहीं था। उसके मंत्रिमंडल में जन प्रतिनिधियों को स्थान मिला था। लाल क्रान्ति की मूलभूत भावना न समझ पाने के कारण गैर कम्युनिस्ट नेता और उनकी समर्थक जनता बोलशेविक दल की अप्रत्याशित सफलता से आतंकित हो उठी।

जनता का विश्वास खोने का दायित्व साम्यवादी छुट मैयों को भी है। मार्क्स के वर्ग युद्ध का सिद्धान्त समझे बिना ही उन्होंने तथाकथित वर्ग युद्ध आरंभ कर दिया। प्रत्येक सफेदपोश संभ्रान्त नागरिक, अनुभवी कर्मचारी, कुलक (जमींदार) और शिक्षित उनकी दृष्टि में बोर्जुआ और शोषक था। वैयक्तिक मतभेद पर भी राजनीतिक रंग चढ़ाया गया। फलतः इस वर्ग के लोग नए सामाजिक अछूत बनाए गए और इन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

१४ मई १९१८ को सोवियत की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (TISK, Central Executive Committee of the Soviets) ने घोषणा की कि खेतों की अतिरिक्त उपज न देने वाले देश द्रोही समझे जायेंगे और उन्हें दण्ड दिया जायगा। कृषकों से अन्न प्राप्त करने के लिए कमेटियों बनाई गई। अतिरिक्त उपज बलात् छीनने के प्रश्न पर बोलशेविक और वामपक्षी समाजवादी क्रान्तिकारियों में मतभेद हुआ। मास्कों में सर्वप्रथम वद्रोह हुआ और नये इन्कलब के नारे लगाए जाने लगे। कुलक (ग्रामीण जमींदार) और केरेदून्याक (मध्यवर्गीय कृषक) बोलशेविक सरकार से रुष्ट होकर श्वेत सेना की सहायता करने लगे और स्वतः श्वेत सेना में भरती हुए। विद्रोही नेताओं में मेखानो (दक्षिणी यूक्रेन) और एन्तानो (ताम्बो प्रदेश) प्रमुख थे।

पुराने अधिकारी दकिया नूसी विचार के थे और नए अनुभव हीन। बाजार समाप्त हो जाने के कारण उद्योग और कृषि की पारस्परिक सम्बद्धता की कड़ी टूट गई। किसान व्यापारिक फसलों की ओर से उदासीन थे। स्वाभाविक ही था कि वे ऐसा अन्न क्यों बोएँ जिसके बदले में उन्हें कुछ न मिले। शहरी

जनता, राज्य और साम्यवादी दल में अलगाव था। संघीय और प्रांतीय सरकारों में भी वैमनस्य था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशृङ्खलता, अलगाव और असम्बद्धता नजर आ रही थी। प्रशासनिक ढांचा ढीला पड़ता जा रहा था।

मजदूर सङ्घ और उसकी कार्य प्रणाली से मजदूर असन्तुष्ट थे। मोत्स्की ने मजदूर सङ्घों का नए सिरे से संगठन किया और लाल सेना के कुछ लोगों को उत्पादक कार्यों में लगाया।

१९१८ में ही लेलिन ने गांव समितियों तोड़ दीं।

१९१९ में मध्यमवर्गीय किसानों से समझौता कर लिया गया।

स्वतन्त्र बाजार और स्पर्द्धा की समाप्ति

स्वतंत्र बाजार और स्पर्द्धा पूर्णतः समाप्त कर दी गई और उनके स्थान पर राजकीय एकाधिकार की स्थापना हुई। राजकीय उद्योगों में मुद्रा को चलन का माध्यम नहीं माना गया। पूर्ति आयोग (नारकम्पोद) को उपभोग की वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी अधिकार मिले। सहकारी समितियों ने धीरे-धीरे राज्य से सम्बन्ध स्थापित कर लिया। १९१९ में सहकारी थोक बिक्रय समिति (सेनत्रोस्वायस Co-operative Wholesale Society) राज्य के अधिकार में चली गई। मजदूरों को इसका सदस्य बनाया गया। फुटकर व्यापार का पुनर्गठन हुआ। आर्थिक ढाँचे का कठोर अनुशासन सैनिक व्यवस्था जैसा था।

कृषि उत्पादन और राजकीय क्रय के विभिन्न रूप थे—

- १—वे वस्तुएँ जिन्हें अनिवार्य रूप से राज्य ले लेता था।
- २—वे वस्तुएँ जो राज्य के द्वारा एकाधिकृत होने पर भी राज्य द्वारा ली नहीं जाती थी।
- ३—व्यक्तिगत व्यवसाहयों अथवा राज्य द्वारा खरीदे जा सकने योग्य वस्तुएँ।

प्रायः सभी मुख्य वस्तुएँ पहले और दूसरे वर्ग के अन्तर्गत थी। औद्योगिक उत्पादन आनाज के ही बदले दिया जाता था। मजदूरों को मजदूरी के बदले टिकट दिया जाता था जिसे दिखाकर वे सहकारी समिति से आवश्-

यकता की वस्तुएँ लेते थे। टिकट पर मजदूर के षावने का स्पष्ट निर्देश रहता था।

विदेशी व्यापार

देशी व्यापार पर जितनी सरलता से नियंत्रण कर लिया गया उतनी सफलता विदेशी व्यापार के क्षेत्र में नहीं मिली। दिसम्बर १९१७ से विदेशी व्यापार करने वालों को लाइसेंस दिये गए। सरकार को लाइसेंस प्रथा से संतोष न था। अप्रैल १९१८ में राज्य सरकार ने विदेशी व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। सोवियत राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति से विदेशी बैंक और व्यवसायी पहले ही चिढ़े हुए थे। राजकीय एकाधिकार की घोषणा के बाद उन्होंने सोवियत मुद्रा और साख को अस्वीकार कर दिया। फलतः विदेशी व्यापार एक प्रकार से समाप्त प्राय हो गया।

सोवियत देश पश्यों की भुगतान में सोना और बहुमूल्य रत्न देता था। १९१६-२० में स्वीडन, डेनमार्क, स्विटजरलैंड से थोड़ा बहुत व्यापार होता था। नकद भुगतान के लालच से जर्मनी ने सोवियत सङ्घ से १९२० में पुनः व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया। इंग्लैंड और अमेरिका के विचारों में परिवर्तन हुआ। आर्थिक घेरा बन्दी टूट गई। अब सोवियत संघ दूसरे देशों से पुनः व्यापार करने लगा किन्तु जैसे जैसे वह आत्म निर्भरता की ओर बढ़ता गया। विदेशी व्यापार कम होता गया।

वितरण

भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने के बाद वितरण की समस्या को जितनी जटिल होना चाहिए था उतनी न हुई।

किसानों के तीन वर्ग थे—

- १—कुलक - सम्पन्न जमींदार जो वैतनिक नौकरों द्वारा काम करवाते थे।
- २—केरेद्व्याक्—मध्यम वर्गी किसान।
- ३—बेद्व्याक्—गरीब किसान। इनकी संख्या ३५% थी। शासन इनके प्रति सदय था। ये कर मुक्त किसान थे।

क्रान्ति के समय ही कुलकों को समाप्त करके किसानों ने सरकार की मदद के बिना ही भूमि का जैसा-तैसा बटवारा करके सरकार को बहुत बड़ी परेशानी

से बचा लिया। स्थिति अनुकूल होने पर सरकार ने जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जिसे संशोधित रूप में ८ वीं कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। सैद्धान्तिक रूप से पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार भूमि के वितरण का सिद्धांत निश्चित किया गया था। कृषि पर आश्रित परिवारों की सदस्य संख्या के आधार पर भूमि, पशु और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजारों का वितरण हुआ। किसानों के व्यक्तिगत अधिकार की मान्यता स्वीकार करते हुए भी उन्हें भूमि बेचने का अधिकार नहीं दिया गया।

सब कुछ हुआ किन्तु आवश्यकता के अनुसार भूमि के समान वितरण का सिद्धांत समस्या का एक मात्र समाधान न बन सका। एक तो कृषि योग्य भूमि वैसे ही कम थी, दूसरे बड़े कुलकों के खेत, किसानों को न देकर सरकारी फार्म बना लिए गए थे।

नारकम्प्रोद (पूर्ति आयोग Commissariat of supply)

अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्राप्त करने और उसे केन्द्रीय व्यवस्था के अंतर्गत वितरित करने के उद्देश्य से नारकम्प्रोद की स्थापना की गई। इस आयोग को पूर्ति संबंधी सभी अधिकार मिले थे। इससे लाइसेंस प्राप्त किए बिना व्यापार नहीं किया जा सकता था।

गैलवाइन उपावेलिना (Glavki)

औद्योगिक उत्पादन के वितरण के लिए यह संस्था बनाई गई थी। राष्ट्रीयकरण के साथ इसका महत्व बढ़ता गया किन्तु यह संस्था औद्योगिक उत्पादन की वितरण संबंधी सभी समस्याओं का समाधान न ढूँढ़ सकी इस कारण औद्योगिक प्रशासन में सहायता पहुंचाने वाली एक अन्य संस्था वेसेंखा का निर्माण किया गया।

मुद्रा

मुद्रा स्फोटि रोकने के सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। बहुत अधिक परिमाण में कागजी मुद्रा जारी की गई थी। मुद्रा प्रसार के लिए तत्कालीन सरकार को दोषी नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि मुद्रा प्रसार के अतिरिक्त सरकार के सामने कोई दूसरा चारा न था।

१ नवम्बर १९१७ को देश की चालू मुद्रा २२'४ मिलियार्ड रूबल थी जो बढ़ते-बढ़ते मार्च १९१८ में ३० मिलियार्ड रूबल, १ जून को ४०'३ मिलियार्ड रूबल और १ जनवरी १९१९ को ६८'८ मिलियार्ड रूबल हो गई। इसके पश्चात् प्रसार की गति और तीव्र हो गई। गिरणामतः १९२० में रूबल की क्रय शक्ति १९१७ की अपेक्षा केवल ०'१ रह गई।

स्फीति का प्रभाव पूँजी व्यवसायी और कृषक वर्ग पर बहुत बुरा पड़ा। स्फीति रोकने के लिए १९१८-२० में अधिक संख्या में पत्र मुद्रा का निर्गम हुआ पर कोई उल्लेखनीय सफलता न मिल सकी।

क्रमशः मुद्रा की चलन कम की गई। वेतन वस्तुओं के रूप में दिया जाने लगा। यहाँ यह निर्देश कर देन अपेक्षित है कि मुद्रा को विनियम के माध्यम के रूप में स्वीकार न करना कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है।

युद्ध में सोवियत संघ को पर्याप्त हानि उठानी पड़ी। सोवियत संघ के पास १०% कोयला, २५% लोहा, ५% खाद्यान्न, १% चीनी के क्षेत्र बच रहे थे। पीतर बुर्ग और मास्को की सड़कों पर अकाल नाच रहा था। विदेशी पूँजी और व्यवस्था पर आधारित उद्योगों को बन्द कर देना पड़ा। ग्रेजनी और बाकू से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने के कारण मिट्टी का तेल न मिल पाता था। दोनेत्स से कोयला नहीं आ पाता था। इस्पात बनाने वाली आधी से अधिक भट्टियाँ बुभ चुकी थीं। रूई के अभाव में सूती कपड़े के उद्योग बंद पड़े थे। मिलों की चिमनियाँ शान्त पड़ी थीं और देश के भाग्य पर धुआँ छा रहा था।

यातायात के साधनों का नितान्त अभाव था। रेल और बसें वैसे भी कम थीं, कोयले और तेल की कमी के कारण उनकी संख्या और कम हो गई। सैनिक और युद्ध सामग्री ले जाने भर को भी वे नहीं थीं। १९१९ में ५०% रेलें सेना और युद्ध सामग्री ढो रही थीं। १९१७ में ३०% इंजन मरम्मत के लिए पड़े थे। १९२० में केवल ४००० इंजन ही काम दे रहे थे शेष या तो नष्ट हो गए थे या वेकार पड़े थे।

क्षति—युद्ध में प्रायः ३६०० पुल और ३६० इंजन रखने के घर टूटे थे। १२०० मील रेलवे लाइन, ५०,००० मील टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार

टूट गए थे। देश के विभिन्न भागों से सम्बन्ध टूट जाने और जन भावना सरकार के विपक्ष में हो जाने के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों उत्पन्न हो गईं थीं। भुख-मरी के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता में हास हो रहा था। अपराध की भवना बढ़ रही थी। अनुशासन की भावना का नितन्ता अभाव था प्रायः ६०% मजदूर अनुपस्थित रहते थे—और वे काम करते भी किस लिए ? १९२० में मजदूरों को जितनी मजदूरी मिलती थी वह ११-१२ दिन के लिए ही पर्याप्त होती थी और महीने के शेष दिन उन्हें किसी अन्य वैध या अवैध तरीके से पेट भरना पड़ता था। मॉरिस डाब के शब्दों में— At the worst period the meagre daily bread ration of on eighth of a pound for workers was issued only one alternate days. It is hardly surprising that the towns should have lost between a quarter and a third of their population, largely by migration to the village, and Moscow as much as a half of its population.

लेनिन युग के पूर्वाद्ध में सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः असंतुलित थी। बोलशेविक दल की दृष्टि साम्यवाद के आकाश कुसुम की ओर थी। वे सभी प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं को मिटा कर अभिनव समाज की रचना में सचेष्ट थे। एक ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्तियों को योग्यतानुसार काम और आवश्यकतानुसार वेतन दिया जा सके। उत्पादन, विनिमय और वितरण के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। उद्योग धन्धों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग का अधिकार पूँजीपतियों के हाथ से छिन कर सर्वहारा वर्ग के हाथ में आया किन्तु जन नेताओं में सुव्यवस्थित रूप से उद्योग चलाने की क्षमता न थी। आदर्श था कि सबको काम मिले, वास्तविकता थी कि जिन्हें काम मिला था। वे भी बेकाम हो रहे थे।

अवसाद के कारण

क्रान्ति पूर्व युग में सोवियत संघ में अनेक न्यास (Trust) और अभिषद (Syndicate) उद्योग धन्धों का संचालन करते थे। देशी पूँजीपतियों के

अतिरिक्त फ्रांस, इंग्लैंड और बेलजियम के पूँजीपतियों की भी पूँजी उद्योग धन्वों में लगी थी। उद्योग धन्वों का राष्ट्रीय करण हो जाने पर देशी पूँजी-पतियों को अपने हाथ खींच लेने पड़े। विदेशी पूँजीपतियों की मनमाने लाभोश की आशा तो जाती ही रही उनकी पूँजी भी असुरक्षित थी। बृहद् स्तर उत्पादन में पूँजी का महत्व निःसंदिग्ध है। उत्पादन गिरना या ठप्प हो जाना स्वाभाविक ही था।

अधिकांश उद्योग धन्वे उक्रइन में थे। जो पश्चिमी यूरोप के निकट है। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से घिर जाने के कारण न तो बाहर से कच्चा माल आ पाता था और न उत्पादन बाहर भेजा जा सकता था। कोयले और कच्चे माल की बेहद कमी थी। मुद्रा स्फीति के कारण आन्तरिक बाजार समाप्त हो गया था।

उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण मात्र कर लेने से आर्थिक समस्यायें नहीं सुलभतीं। मध्यस्थों के अभाव में उनका लाभोश मजदूरों को बांटा जा सकता है किन्तु यह तब संभव है जब उत्पादन हो। क्रान्ति के समय देखे गए सपनों के प्रसाद ढहने लगे। क्रान्ति के समय इकट्ठा किया गया खाद्यान्न और दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ समाप्त हो जाने पर मजदूरों में असंतोष बढ़ा। आये दिन हड़तालें होने लगीं। हड़तालों का प्रभाव उत्पादन पर और बुरा पड़ा।

मिलों से निराश मजदूर कारखानों को छोड़ कर खेतों की ओर लौटने लगे। जनवरी १९१८ में २५० लाख मिल मजदूर थे जिनकी संख्या क्रमशः घटते-घटते ४ लाख से भी कम हो गई। उत्पादन ६ भाग से भी नीचे गिर गया। जो मजदूर कारखानों में काम कर भी रहे थे उनकी उत्पादन क्षमता केवल २८% थी। ऐसी स्थिति में अवसाद न आना ही आश्चर्य का विषय होता।

सर्वोच्च राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था

संक्रमण कालीन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था परिषद की स्थापना की गई। इसके दो मुख्य कार्य थे—

१ — बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना।

२—सरकार को कृषि, यातायात, व्यापार और अर्थ सम्बन्धी सलाह देना।

उद्योग धन्वों का राष्ट्रीयकरण

कौंसिल आफ पीपुल्स कमीसार (सोव्नाकर्म R. S. F. S. R.) ने बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया। २६ मई ४ जून १९१८ की N. E. C. की बैठक में बय हुआ कि लोहा, इस्पात, रसायन, तेल और वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। २६ दिसम्बर १९२० को उन सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया जिनमें ५ या उससे अधिक व्यक्ति काम करते थे।

राष्ट्रीयकरण का परिणाम देश के लिए बड़ा भयावह सिद्ध हुआ। एक एक करके कारखाने बन्द होने लगे।

वर्ष	भारी उद्योग	हलके उद्योग	योग
आधार वर्ष १९१३	१००	१००	१००
१९१६	११६.१	८८.२	१०६.४
१९१७	७४.८	७८.४	७५.७
१९१८	३३.८	७३.५	४३.४
१९१९	१४.९	४९.०	२३.१
१९२०	१२.८	४४.१	२०.४

कुछ पदार्थों का उत्पादन तो इतना कम हुआ कि आँकड़ों पर विश्वास करना कठिन है। सोवियत संघ के इन आँकड़ों से विकासशील राष्ट्र प्रेरणा ले सकते हैं। उसकी वर्तमान प्रगति को देखते हुए शायद ही कोई विश्वास करे कि १९२० में १९१३ की अपेक्षा लोहा १.६% कच्चा लोहा २.४%, इस्पात ४% सूती वस्त्र ५% और चोनी का उत्पादन ५.८% हुआ था। १९१२ ई० में प्रति व्यक्ति १८.२ स्वर्ण रूबल के मूल्य की अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं उत्पादित की गईं थीं जो १९२० ई० में घट कर केवल २.४ स्वर्ण रूबल रह गईं और उपभोग की अन्य वस्तुओं का मूल्य २०,६६० लाख स्वर्ण रूबल से गिर कर २,६२० लाख स्वर्ण रूबल रह गया।

इस रोमांचकारी अबसाद का जो प्रभाव जनसंख्या और निवासियों के रहन-सहन के स्तर पर पड़ा वह कल्पनातीत है ।

श्रम

श्रमिकों की दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया गया । ११ नवम्बर १९१७ को काम के ८ घंटे निर्धारित किए गए । महिलाएं और १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों से रात में काम नहीं कराया जा सकता था । १४ नवम्बर से बीमा योजना लागू कर दी गई । बेरोजगारी, बीमारी और गर्भावस्था के बीमों की व्यवस्था की गई । दिसम्बर में अधियोजन विभाग की स्थापना हुई ।

कृषि

१३ करोड़ की जनसंख्या में प्रायः १० करोड़ किसान थे । मिल मजदूर सिद्धांतः साम्यवाद के समर्थक थे यद्यपि महंगाई और बेकारी के कारण उनकी आस्था भी ढिग रही थी । किसानों का मानसिक स्तर और सामाजिक चेतना मिल मजदूरों जैसी न थी । वे समाज के नाम पर अपने निजी और पारिवारिक स्वार्थों की बलि नहीं देना चाहते थे । २६ अक्टूबर १९१७ को बिना मुआवजा दिये भूमि पर से व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया गया । आरम्भ में किसानों ने सोचा था कि केवल बड़े भूपति ही कानून की चपेट में आयेंगे किन्तु जब १६ फरवरी १९१८ को सोवियत सरकार ने भूमि का राष्ट्रीयकरण कर लिया तो किसानों के कान खड़े हो गए । छोटे किसानों की शक्ति का प्रयोग बड़े किसानों की शक्ति के विरुद्ध न किया जा सका । कोई भी स्वामित्व त्यागने को राजी न था ।

१९१८ में खाद्य नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना की गई । इस बोर्ड को किसानों से अतिरिक्त खाद्यान्न ले लेने का अधिकार मिला । बोर्ड अपने प्रयास में विफल रहा । किसानों ने सरकारी निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाई, छुट-पुट संघर्ष भी हुए । जब किसानों को विद्रोह में सफलता न मिली तो उन्होंने शान्ति प्रिय अहिंसावाद या हठवादिता का सहारा लिया । वे खेती से उतना ही अन्न पैदा करते थे जितने में उनका परिवार जीवित रह सके । फलतः कृषि के अतिरिक्त अन्य साधनों से जीविका उत्पन्न करने वालों को खाद्यान्न देने की समस्या जटिल हो गई ।

अतिरिक्त पशुओं को इसलिए मार डाला गया कि सरकार उन पर अधिकार न कर ले। आंकड़े कह रहे हैं कि स्वार्थाघ जनता राष्ट्रीयता की भावना भूल चुकी थी—

वर्ष	जोती गई भूमि लाख देसियातिन में	उत्पादन लाख पूड में	बोड़े लाख में	अन्य पशु लाख में	भैंड़े लाख में
१९००-१३	८३१	३८५०	—	—	—
१९१६	७६०	३४८२	३१५	४६६	८०६
१९१७	७६४	३३५०	—	—	—
१९२०	६२६	२०८२	२५४	३६१	४६८
१९२१	५८३	१६७६	२३३	३६८	४८४

क्रय शक्ति में ह्रास होने के कारण मूल्य इतने बढ़ गए थे कि चाहते हुए भी किसान चारे के अभाव में पशु जीवित रख सकने में असमर्थ थे। किसानों के सामने दो ही मार्ग थे या तो वे एक मेरिना भैंड़ को वर्ष भर पालें, १७०० रुबल का चारा खिलायें और वर्ष के अंत में उससे ५०० रुबल का ऊन प्राप्त करें अथवा उसे मार कर खा जाय। उन्होंने दूसरा मार्ग ही अधिक श्रेयस्कर समझा।

अध्याय ६

नई आर्थिक नीति

६ मार्च १९२१ को मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्त के विरुद्ध विद्रोह हुआ। बोल्गा तथा साइवेरिया के किसानों ने विद्रोहियों का साथ दिया। देश भर में साम्यवादी नेताओं और उनके सिद्धान्तों के प्रति अविश्वास प्रगट किया जा रहा था। लेनिन और उनके साथियों ने अपनी भूल स्वीकार की किन्तु साम्यवाद के प्रति उनकी आस्था अडिग रही।

किसान भूमि के राष्ट्रीय करण के पक्ष में न थे। वे चाहते थे कि चर्च और बड़े जमींदारों से छीनी गई भूमि पर उनका स्वामित्व स्वीकार कर लिया जाय। अतिरिक्त आनाज किसानों से ले लेने के अधिनियम ने उन्हें और विद्रोही बना दिया। किसान अपने पसीने की कमाई शहरों में नहीं जाने देना चाहते थे। परिस्थिति ने क्रान्ति के समय कंधे से कंधे मिला कर चलने वाले किसानों-मजदूरों को एक दूसरे के आमने-सामने खड़ा कर दिया। दोनों एक दूसरे को शोषक और अपने को शोषित समझते थे।

त्रात्स्की शक्ति के केन्द्रीकरण का समर्थक न था। विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था में आस्था रखते हुए वह सैनिक शासन का हामी था। लेनिन के बाद इतना सुलभा मस्तिष्क किसी का न था। बोलशेविक अपने देश की भांति ही इंग्लैंड और जर्मनी में भी क्रान्ति का स्वप्न देख रहे थे। उनका विश्वास था कि क्रान्ति के पश्चात् इन देशों के जनवादियों से उन्हें सहायता मिलेगी किन्तु इन देशों की परिस्थितियाँ भिन्न होने के कारण वहाँ क्रान्ति न हो सकी और सोवियत संघ को अपने ही पैरों पर खड़ा रहना पड़ा।

१९२१ के अकाल से प्रायः २८० लाख व्यक्ति मर गए। धीरे-धीरे यह विश्वास दृढ़ होने लगा कि क्रान्ति के तुरंत बाद साम्यवादी सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है। आंशिक रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया। किसानों को व्यक्तिगत रूप से या सहकारी संघ बना कर (जैसा भी उन्हें

स्वीकार हो) खेती करने की स्वतंत्रता दे दी गई। अतिरिक्त उपज लेने के बजाय भूमि पर कर लगाया गया। किसानों को उपज बेचने का अधिकार मिला। जगह-जगह सरकार ने आदर्श फार्म बनाये जहाँ खेती के उन्नत तरीकों के प्रदर्शन और शिक्षा की व्यवस्था थी।

१९२५ में भूमि बंधक बैंकों की व्यवस्था की गई। गरीब किसानों को कर्ज और सहायता के रूप में पर्याप्त धन बाँटा गया और कर माफ किये गये। गाँव की सरकारी समितियों को ८ वर्ष का मिथादी कर्ज दिया गया। धीरे-धीरे कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और १९२६—२७ में युद्ध पूर्व स्थिति तक पहुँच गया।

वर्ष	कृषि उत्पादन	
	लाख रूबल	प्रतिशत
१९१३	१,२३,८००	१००
१९२१-२२	६२,६००	६५.०
१९२२-२३	८७,०००	७०.३
१९२३-२४	९१,४००	७३.८
१९२४-२५	९१,५००	७३.९
१९२५-२६	१,१३,०००	९१.३

कृषकों ने अपनी पुरानी विचार धारा और मान्यताएँ न छोड़ी थीं। उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रकार पुराना ही थी। प्रायः ९७% खेत किसानों के अपने थे और ३% सरकार के।

कृषि योग्य भूमि का पूरा उपयोग किया जा रहा था। १९२१-२२ में केवल आधी भूमि पर खेती की जा रही थी। १९२४-२५ में ७३.९% और १९२५-२६ में ९२% भूमि पर कृषि की जाने लगी थी।

सोवियत संघ के औद्योगिक विकास की प्रमुख विशेषता समय की मांग को पहचानना और तदनुकूल आचरण करना है। पहले लक्ष्य निर्धारित करना फिर उसकी ओर बढ़ना, कठिनाइयों का धैर्य के साथ सामना करना और भूल ज्ञात हो जाने पर उसे स्वीकार करके समस्या सुलभता लेना, समष्टि में यही उनके विकास की सही व्याख्या है।

१९१७-२१ तक के ५ वर्ष प्रयोग का युग हैं। इस काल के प्रायः सभी प्रयास मानव स्वभाव न परख पाने के परिणाम हैं किन्तु अपने विश्वास की नींव हिलती देखकर जिस साहस और लगन के साथ उन्होंने अपनी राह बदली अनुकरणीय है। १९१३ की अपेक्षा १९२६-२७ में भारी उद्योगों की दशा काफी अच्छी थी—

दस लाख रूबल में

वर्ष	१९१३	१९२१	१९२२	१९२३
कुल बड़े उद्योग	१०,२५१	१,६२५	२,५१२	३,८२६
उत्पादन के साधनों का उत्पादन	४,२६०	८१४	१,०६०	१,७८५
उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	५,६६१	१,१११	१,४२२	२,०४४
वर्ष	१९२४	१९२५	१९२६	१९२७
कुल बड़े उद्योग	४,४६६	७,४३६	१०,२७७	१२,०५१
उत्पादन के साधनों का उत्पादन	१,६५६	३,१२१	४,३०४	५,३७२
उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन	२,५१०	४,३१५	५,९७३	६,६७६

विदेशी विद्वानों को विश्वास हो चला था कि सोवियत संघ के विकास के भावी चरण साम्यवाद की ओर न जा सकेंगे। लेनिन युग के उत्तरार्द्ध की स्थिति बहुत कुछ इसी प्रकार की थी भी। एक कनेडियन विद्वान के शब्दों में साम्यवाद को तिलांजलि दे दी गई थी। ६०% श्रमिक उत्पादन के अनुसार मजदूरी पाते थे। मजदूरों को आरंभ में ४५ रूबल और कुशलता प्राप्त कर लेने पर १३० रूबल दिया जाता था। अधिकतम मजदूरी २२५ रूबल थी। यंत्र विशेषज्ञों को ३०० रूबल मिलते थे। इस सत्य को अस्वीकार नहीं

✽The development of the Soviet Economic System

By Alexander Baykov. PP, 121

किया जा सकता कि मजदूरी का इतना अधिक अन्तर साम्यवाद के प्रतिकूल है।

१९२५ के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि देश शीघ्रता से राष्ट्रीयकरण की ओर उन्मुख हो रहा था। सोवियत संघ का लक्ष्य साम्यवाद था। पग डगमगा रहे थे।

❀	कुल औद्योगिक उत्पादन प्रतिशतों में %		
	१९२५-२६	१९२६-२७	१९२७-२८
राजकीय उद्योग			
कुल उद्योग	७१.६	७३.६	७६.१
(अ) बड़े उद्योग	८६.६	९१.३	९०.६
(ब) छोटे उद्योग	१.७	२.०	२.२
सहकारी उद्योग			
कुल उद्योग	८.२	८.६	११.२
(अ) बड़े उद्योग	६.४	६.५	७.४
(ब) छोटे उद्योग	१५.४	१६.०	३०.२
निजी उद्योग			
कुल उद्योग	१६.६	६.२	११.२
(अ) बड़े उद्योग	४.०	२.२	१.७
(ब) छोटे उद्योग	८.२६	७६.०	६७.६

❀ The development of the Soviet Economic System.
By Alexander Baykov PP. 124.

मूल्य में असंतुलन

१९२२ के मध्य में कृषि उत्पादन के मूल्य गिरे और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य इसके ठीक विपरीत बढ़े। यह असंतुलन ८८८ कृषि और २७५.७ उद्योग (आधार वर्ष १९१३) तक पहुँच चुका था।

उद्योग आरंभिक अवस्था में थे। उनका उत्पादन व्यय अधिक था। वे विगत वर्षों की अस्थिरता के युग में पर्याप्त घाटा उठा चुके थे। अनुकूल परिस्थिति देखकर वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। राजकीय नियंत्रण के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा भी न थी। आन्तरिक व्यापार में उनका एक प्रकार से एकाधिकार सा था। स्वाभाविक था कि औद्योगिक उत्पादन का मूल्य अधिक हो।

व्यापारी कृषकों की विवशताओं से लाभ उठाते थे। वे औद्योगिक उत्पाद महंगे दामों में प्रायः उस समय बेचते थे जब फसल तैयार होती थी और उसका मूल्य कम होता था।

कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा शीघ्रता से बढ़ा। गृह-युद्ध के समय अकाल पड़ा, अतिरिक्त खाद्यान्न छीन लिए गए, औरजार नष्ट कर दिए गए, बहुत बड़ी संख्या में पशु मार डाले गए—सब कुछ हुआ पर कृषि के सैद्धान्तिक तौर तरीके में कोई अंतर नहीं आया, राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी नहीं। उत्पादन पहले से अधिक था, सरकारी नीति के फलस्वरूप कृषि उत्पाद बाहर नहीं जा सकता था, देश में ही उसे खपाना पड़ता था।

दोनों मूल्यों में संतुलन स्थापित करना टेढ़ी खीर थी। कृषि उत्पादन बाहर नहीं भेजा जा सकता था और औद्योगिक उत्पादन का मूल्य कम होने से पूँजी पर बन आती।

१९२४ की १३ वीं बैठक में निश्चय हुआ कि व्यक्तिगत व्यापार को हतोत्साहित किया जाय जिससे सहकारी और राजकीय व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके और मूल्यों में संतुलन आए। इसी वर्ष आन्तरिक व्यापार समिति की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय आर्थिक योजना

(National Economic Planing N, E. P.)

साम्यवाद को घोषणा के साथ ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था किन्तु उद्योगों को चलाने के लिए उनके पास कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी। देश की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। परिस्थिति पर नियंत्रण पाने लिए राष्ट्रीय आर्थिक योजना (N. E. P.) बनाई गई जिसके उद्देश्य निम्न थे :—

१—उत्पादन जैसे भी हो सके बढ़ाया जाय।

२—राजनीतिक मतभेद समाप्त करके कृषकों का सरकार के प्रति विश्वास अर्जित किया जाय।

३—आर्थिक व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित किया जाय। परिस्थिति देखते हुए साम्यवादी दर्शन का अक्षरशः पालन संभव न था।

आरंभिक दो वर्षों में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली।

मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध लगाना सम्भव न था अतः मुक्त व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध क्रमशः उठा लिए गए और पहले जैसी स्थिति को पुनः प्रोत्साहन दिया गया। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में पहले वर्ष से ही आशा जनक प्रगति आरंभ हो गई। राष्ट्रीयकरण के भय से लोगों ने संचित माल लागत या उससे भी कम मूल्य पर बेचना आरंभ किया फलतः सक्रिय पूँजी का विस्तार हुआ। राजकीय व्यापार असङ्गठित होते हुए भी सहकारी और निजी व्यापार के साथ अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता रहा।

७ अप्रैल १९२१ को सहकारी व्यापारिक संस्थाएँ स्वतंत्र घोषित कर दी गईं।

२० अक्टूबर १९२१ को सहकारी व्यापारिक संस्थाओं की सम्पत्ति और संग्रह जिनका पहले राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था उन्हें लौटा दिया गया। बैंकों ने भी इन संस्थाओं की सहायता की। इतना होने पर भी सहकारी व्यापार

बहुत धीरे-धीरे बढ़ा। १९२३ ई० तक ये संस्थाएँ राजकीय और व्यक्तिगत उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय का प्रबंध करती थीं।

न्यास (Trust) तथा अभिषद् (Syndicate)

परिस्थिति अनुकूल देखकर अनेक न्यास तथा अभिषद् बनाये गए। स्मरणीय है कि सोवियत सङ्घ के न्यास जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यास से भिन्न थे। इनका सङ्घटन केवल लाभ अर्जित करने के लिए नहीं किया गया था।

सोवियत सङ्घ के न्यास केवल प्रारूप में अन्य देशों के समान थे। इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था किन्तु सरकार इनके घाटे का उत्तरदायित्व ले भी सकती थी और नहीं भी। न्यास अपनी चल पूँजी का मन चाहा उपयोग कर सकते थे किन्तु अचल पूँजी के मनमाने उपयोग का उन्हें अधिकार न था। अचल पूँजी को घटाने बढ़ाने का अधिकार श्रम तथा सुरक्षा समिति (Council of labour and defence, S. T. O.) को था। यह समिति न्यास और उसकी अचल पूँजी की स्विकृति देती थी। न्यास को विघटित करने और उत्पादन को मान्यता देने का भी इस समिति को अधिकार था। न्यास के डाइरेक्टरों और जांच समिति की नियुक्ति का अधिकार सरकारी परिषद् S. E. C. को था।

इनका कार्य औद्योगिक उत्पादन का वितरण था। ये उद्योगों के स्पर्द्धा नहीं, सहायक थे। विक्रेताओं की स्पर्द्धा कम करने में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली। १९२२-२३ के बीच इनके द्वारा धातु, चमड़ा, वस्त्र, तेल, नामक और दियासलाई आदि का व्यापार किया जाता था। न्यास थोक वितरण का कार्य करते थे। व्यक्तिगत तथा सहकारी संस्थाएँ फुटकर वितरण का कार्य करती थीं। प्रायः ५-७ मध्यस्थों से होकर माल उपभोक्ता तक पहुँचता था।

आरंभ में बैंकों का सहयोग कम मिला। राज्य व्यापार और सहकारी व्यापार क्रमशः १४.४ और १०.३ व्यापार अपने हाथ में लिए थे शेष ७५.३% व्यापार व्यक्तिगत और न्यास पूँजी द्वारा किया जाता था।

१९२७ की स्टेटमैन वार्षिक पुस्तक के अनुसार सोवियत सङ्घ में बड़े और मध्यम कोटि के ५०० न्यास थे। इनके द्वारा ७५% उत्पादन बेचा जाता था।

उद्योग के प्रकार	उत्पादन लाख रूबल में		
१—राजकीय उद्योग	१६२२-२३	१६२४-२५	१६२५-२६
वृहत् स्तर उद्योग	२३,८३०	३७,४००	५३,०६०
लघुस्तर और कुटीर उद्योग	१७०	२१०	२४०
२ - सहकारी उद्योग			
वृहत् स्तर उद्योग	१,०८०	१,५४०	२,४७०
लघुस्तर और कुटीर उद्योग	६४०	७६०	९१०
३—व्यक्तिगत और राजकीय सहायता प्राप्त उद्योग			
वृहत् स्तर उद्योग	१,३६०	१,६७०	२,४१०
लघुस्तर और कुटीर उद्योग	७,०६०	८,७६१	१०,११०
कुल जोड़			
वृहत् स्तर उद्योग	२६,२७०	४०,६१०	५७,९७०
लघुस्तर और कुटीर उद्योग	७,८७०	९,७६०	११,२६०
	<u>३४,१४०</u>	<u>५०,४००</u>	<u>६९,२३०</u>

१९२१ ई० तक प्रायः सभी महत्वपूर्ण उद्योग सरकार के नियंत्रण में लिए जा चुके थे।

देश की आवश्यकता के अनुसार योजनाबद्ध उत्पादन कराने के उद्देश्य से सर्वोच्च आर्थिक समिति (S. E. C) की स्थापना की गई। कलकारखाने सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति या संस्थायें ही चला सकती थीं।

नवम्बर १९२० में जिन उद्योगों के राष्ट्रीय करण की विधि पूरी हो चुकी थी किन्तु वस्तुविक राष्ट्रीयकरण न हो सका था उन्हें उनके पूर्व स्वामियों को लौटा दिया गया। जिन उद्योगों में २० से कम श्रमिक काम करते थे उनके प्रति भी यही दृष्टि कोण अपनाया गया।

बड़े और प्रमुख उद्योग राज्य के आधीन थे। कुछ उद्योगों को विदेशी पूँजीपतियों को लीज पर दे दिया गया और कुछ राज्य और व्यक्तिगत पूँजी के आधार पर चलाए जाने लगे। कुल १,६५,७८१ उद्योग थे जिनमें ८८.५% व्यक्तिगत, ८.५% राजकीय और ३.८% सहकारी थे। व्यक्तिगत उद्योग संख्या में अधिक होते हुए भी उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े थे। व्यक्तिगत उद्योगों में १२.४% और राजकीय उद्योगों में ८४.१% श्रमिक कार्य करते थे।

S. E. C. के न्यास सम्बन्धी अधिकारों का यथास्थान उल्लेख किया जा चुका है।

उद्योगों को साख प्रदान करने तथा उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए S. E. C. के अन्तर्गत दो प्रमुख विभाग खोले गए—

१—मुख्य आर्थिक प्रशासन (ग्लेवनोपइकोनोमिचैस्की उप्राब्लेनी G. E. U.)

२—राज्य उद्योगों का केन्द्रीय प्रशासन (स्तेन्त्रल्नी उप्राब्लेनी गोसुर्दास्त्वेनोय प्रोमेश्हेलेनोत्सी Ts. U. G. P)

राज्य उद्योगों के केन्द्रीय प्रशासन की समिति को उद्योगों की चल पूँजी की जाँच तथा राजकीय उद्योगों और न्यास के कार्यों की जाँच कर सकने योग्य अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार था। न्यास उत्पादन और बाजार में सम्बन्ध स्थापित करता था।

श्रमिक

१९२२ में श्रमिक कानून में सुधार किया गया। अधिक से अधिक उनसे ८ घंटा काम लिया जा सकता था। भारी काम करने वाले श्रमिक केवल ६ घंटे काम करते थे। १८ वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक खान के भीतर काम करने के लिए नहीं रखे जा सकते थे। सबको काम देने की व्यवस्था की गई। बेरोजगारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु, गर्भावस्था में पेंशन की व्यवस्था की गई। श्रमिक रोटी की समस्या से पूर्णतया मुक्त थे। श्रमिकों के पारस्परिक झगड़ों को सुलझाने के लिए श्रमिक पंचायतों की स्थापना की गई।

१९२६ में सभी व्यापारिक सङ्घों का केन्द्रीय सङ्घ बना। इस सङ्घ का

काम लागत, नियंत्रण, आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की किस्म आदि की देख-भाल करना था। ट्रेड यूनियन के द्वैत उत्तरदायित्व थे एक ओर तो वह श्रमिकों के हित की चिन्ता करता था, दूसरी ओर उत्पादन की देख-रेख करता था। वेतन तथा जीवनोपयोगी अन्य सुविधाओं की-उपस्थिति में मजदूर कारखानों की ओर आकर्षित हुए। क्रमशः मजदूरों की संख्या और उत्पादन बढ़ता गया—

	१९१३	१९२१	१९२२	१९२३	१९२४
कुल उत्पादन—उद्योग में (दस लाख रूबल में) १९२६-२७	१०,२५१	१,९२४	२,५१२	३,८२६	४,४६६
कुल श्रमिक (हजार में)	२,६००	१,१८५	१,०६६	१,३५२	१,५५३
	१९२५	१९२६	१९२७	१९२८	१९२९
कुल उत्पादन—उद्योग में (दास लाख रूबल में) १९२६-२७	७,४३६	१०,२७६	१२,०५१	१४,७५४	१८,३३७
कुल श्रमिक (हजार में)	१,६३६	२,२७२	२,३६२	२,५६८	२,८६०

व्यापार

विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार था। इसका परिणाम देश के लिए शुभ हुआ। देश के हित को ध्यान में रखकर विदेशों से समभौता करने, व्यापार और मूल्य पर नियंत्रण करने तथा योजना के अनुसार काम करने में सुविधा हुई। राजकीय एकाधिकार का सामाजिक और आर्थिक महत्व भी कुछ कम न था !

सोवियत सङ्घ का व्यापारिक संतुलन उसके पक्ष में न था। मार्च १९२१ में आस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों से समभौते की बात की गई पर विशेष सफलता न मिली। धीरे-धीरे परिस्थिति अनुकूल होती गई।

वर्ष	लाख रूबल में		सन्तुलन
	निर्यात	आयात	
१९१३	१५२०१	१३७४	+ १४६१
१९२०-२१	१४	२८७	- २६३
१९२१-२२	२०२	२०८२	- १८८१
१९२२-२३	८१६	२६६८	- १८८२
१९२३-२४	३७३२	२३३५	+ १३९७
१९२४-२५	५५८६	७२३५	- १६४९
१९२५-२६	६७६६	७७५३	- ६९७
१९२६-२७	७८०२	७१३६	+ ६६६
१९२७-२८	७७७८	९४५५	- १६७७
१९२८-२९	८७७६	८३६३	+ ४१३
१९२९-३०	१००२३	१०६८६	- ६६३

देश की आवश्यकताएँ और पिछले युग का अवसाद देखते हुए अन्तर-देशीय व्यापार औसत दर्जे का था। इस युग में प्रायः पँच गुनी प्रगति हुई थी। अधिकांश व्यापारिक संस्थायें निजी पूँजी और व्यवस्था द्वारा परिचालित थीं। १९२३ ई० में कुल ५४,६६१ व्यापारिक संस्थायें थीं जिनमें ६१.१% व्यक्तिगत थीं। कालान्तर में व्यक्तिगत संस्थाओं का स्थान राजकीय और सहकारी सङ्घ लेने लगे। १९२७ में ६,४३,२२३ व्यापारिक संस्थाओं में ७७.८% व्यक्तिगत थीं।

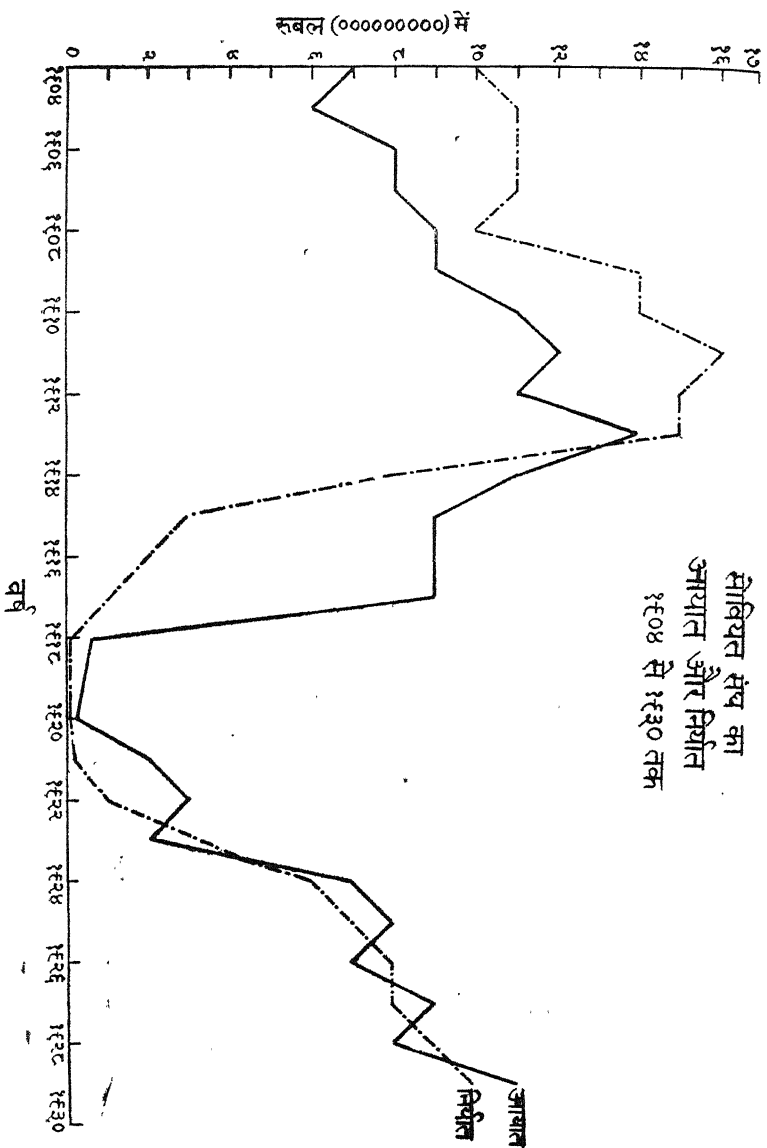
फुटकर व्यापार का पूरा ब्यौरा अधोलिखित है :-

संस्थाओं द्वारा संचालित
(लाख रूबल में)

वर्ष	राज्य	सहकारी	व्यक्तिगत	योग
१९२२-२३	५,१२०	३,६८०	२६,८००	३५,६००
१९२७-२८	२४,०८८	९३,४१२	३४,०६६	१५१,५६६

सोवियत संघ का आर्थिक विकास

५२



सोवियत संघ का
आयात और निर्यात
१९०४ से १९३० तक

आर्थिक पुनर्गठन और कैंची संकट

युद्धत साम्यवाद (War Communism) के अन्तिम वर्षों में देश के भाग्याकाश से निराशा का कुहासा धीरे-धीरे छूटने लगा था। हमारा यह आशय नहीं है कि परिस्थितियाँ अनुकूल हो गईं या देश में समृद्धि की लहर दौड़ गई अथवा ईंधन और कच्चे माल का अभाव न रहा। १९१७ का आर्थिक संकट १९२२ तक बना रहा। इतना अवश्य हुआ कि देश और विदेश में इस भावना ने घर कर लिया कि साम्यवाद की जड़ें गहरी हैं और उसमें किसी भी संकट का साहसपूर्वक सामना करने की क्षमता है। देशवासी इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि बोलशेविक दल के हाथ से किसी भी प्रकार सत्ता का हस्तान्तरण नहीं हो सकता। गैर कम्युनिस्ट विचार धारा के समर्थकों ने चुपचाप पराजय स्वीकार कर लेने में ही अपनी भलाई समझी। समष्टि में आर्थिक पुनर्गठन के काल का भावनात्मक मूल्य उसके न्यायव्यवहारिक मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है।

१९२१ तक अभाव दूर न हो सका था। कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन केन्द्र कम हो गए थे। तुर्किस्तान की सुरक्षित रूई केवल तुर्किस्तान के उद्योगों के लिये ही १ वर्ष के लिए पर्याप्त थी। सीमेन्ट का उत्पादन क्रान्ति पूर्व युग का केवल १% था। ईंधन अपर्याप्त था। इस युग में कोयले की खानों के कुछ नये क्षेत्र भी ढूँढे गए। यूराल की खानों में लगभग १ अरब पौद (१ पौद = १६ सेर) धातु का पता लग जाने के कारण धातु उद्योग के विकास की आशा बंधी।

औद्योगीकरण के दो प्रमुख बाधक तत्व थे—

१— सक्रिय पूँजी की कमी

२— थके हुए अनैतिक अकुशल श्रमिक

नवनिर्मित न्यासों (Trusts) से बाजार नियंत्रित करने का प्रयत्न किया किन्तु पण्यों (Commodities) की कमी के कारण लोग शीघ्रता से माल बेचने लगे और मूल्य बढ़ गए। सरकार द्वारा उत्पादन जब्त कर लेने की नीति के कारण आस्थिता थी गाँवों में फेरी वाले दूकानदार जाकर कच्चे माल के बदले औद्योगिक उत्पादन बेचते थे। विस्तृत बाजार के अभाव, बेचने में शीघ्रता (समय संकोच) और स्पर्द्धा के कारण उत्पादकों को अपेक्षित मूल्य न मिल पाता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। ३० लाख पुद् चीनी उत्पन्न की गई थी जिसका अधिकांश भाग चुकन्दर के बदले में बेच दिया गया। कभी-कभी कच्चे माल की प्राप्ति से पहले ही पक्का माल बेच देना पड़ता था। उत्पादकों का न तो मांग पर नियंत्रण था और न पूर्ति पर। व्यवसाय कांटा लगाकर मछली फँसाने जैसा हो गया था। कांटे में रोहू या सिधरी कोई भी मछली फँस सकती थी। लाभ या हानि अचरस पर निर्भर था। व्यवसायी की सहिष्णुता कार्यत्री प्रतिभा या व्यवसाय निपुणता के लिये अवकाश न था।

N. E. P. को भी अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल रही थी। मंहगाई के कारण किसानों और नागरिकों की आय घट गई थी। संक्रमण काल सबसे लिए चिन्ता का विषय था।

कोशिश की गई कि वाणिज्य अभिषद (Commercial Syndicate) बनाकर उत्पादन पर नियंत्रण किया जाय और अतिरिक्त स्टॉक (Surplus Stock) का निर्यात होने से रोका जाय। इस प्रकार के अभिषदों का निबंधन (Registration) कराना आवश्यक था। इस प्रकार के अभिषद सामान्य तथा शेयर पूँजी के आधार पर बनाए गए।

न्यूनतम बाजार मूल्य पर क्रय-विक्रय करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। पहला अभिषद टेक्सटाइल अभिषद (Textiel Syndicate) था जिसका बसंखा द्वारा निबंधन हुआ था। इस अभिषद की संरक्षित पूँजी कुछ पूर्व वर्षों की मुद्रा के आधार पर २ करोड़ रूबल थी जो १०,००० हिस्सों में बंटी थी। वैयक्तिक और सहकारी उत्पादक तथा राजकीय उद्योग भी इसमें भाग ले

सकते थे। हिस्सेदारों की प्रति छठवें मास साधारण सभा होती थी। हिस्सेदार ही इसकी कार्यकारिणी समिति और अध्यक्ष का निर्वाचन करते थे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न थे :—

- १—व्यापारिक कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करना।
- २—कमी और क्रय के सम्बन्ध में एक रूपता (unification) लाना।
- ३—वित्त सम्बन्धी कार्यों में सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना।

अन्य अभिषद

टेक्सटाइल अभिषद के अतिरिक्त ३ अन्य अभिषद भी बनाए गए :—

- १—दाक्षणी क्षेत्र का यूगो धातु अभिषद
- २—यूराल धातु अभिषद।
- ३—कृषि यंत्र अभिषद।

ये अभिषद कमीशन के आधार पर न्यासों को माल देते थे और उनसे आंशिक नकद और आंशिक पर्य के रूप में दाम लेते थे।

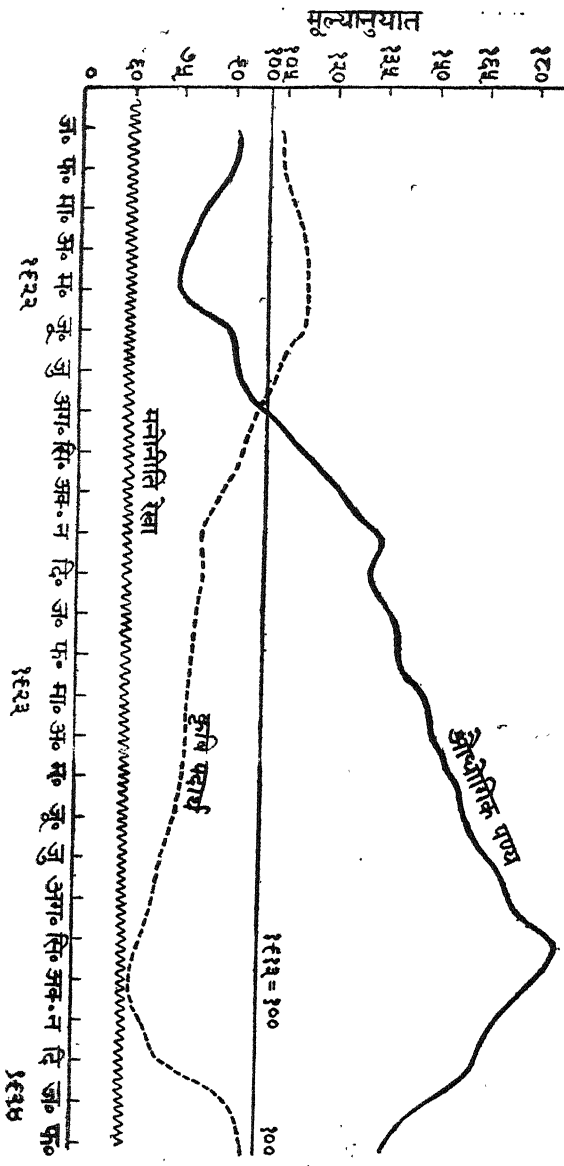
१९२२ में इस प्रकार के १७ अभिषद थे जिनका सम्बन्ध १७६ न्यासों से था।

आशा की किरण

युद्धत साम्यवाद के समय फैली आर्थिक अस्थिरता की भावना धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। औद्योगिक उत्पादन जो क्रान्ति पूर्व वर्षों का केवल १८% रह गया था। १९२१-२२ में २७% और १९२२-२३ में ३५% हो गया। औद्योगिक ईंधन (fuel) उद्योग में १०% वृद्धि हुई। सबसे अधिक उन्नति धातु उद्योग (Metal Industries) की हुई (७०% वृद्धि)। शस्य भूमि (Sown area) में १९१६ से भी कमी हुई। लोग खेत बिना जोते बोये छोड़ देते थे। १९२३ में १६ की अपेक्षा ८०% भूमि पर खेती हुई किन्तु कृषि उत्पादन १७% अधिक हुआ। १९२३ का कृषि उत्पादन प्रायः युद्ध पूर्व स्तर के निकट था।

व्यापार उद्योगों के पक्ष में था और कृषि के विपक्ष में।

मूल्य का सापेक्ष परिवर्तन



वर्ष	कृषि पदार्थ का मूल्य	औद्योगिक पर्यो का मूल्य
	१९१३	१००
जनवरी	१९२२	१०४
फरवरी	"	१०५
मार्च	"	१०६
अप्रैल	"	१११
मई	"	११३
जून	"	१०६
जुलाई	"	१०४
अगस्त	"	१००.५
सितम्बर	"	९४
अक्तूबर	"	८८
नवम्बर	"	८२
दिसम्बर	"	८३
जनवरी	१९२३	८१
फरवरी	"	८१
मार्च	"	७९
अप्रैल	"	७९
मई	"	७८
जून	"	७५
जुलाई	"	७१
अगस्त	"	६९
सितम्बर	"	६५
अक्तूबर	"	५९
नवम्बर	"	६६
दिसम्बर	"	७२
जनवरी	१९२४	८१
फरवरी	"	८५
मार्च	"	८७
		१००
		९२
		९०
		८२
		७७
		७४
		८९
		९२
		९९
		११२
		१२३
		१३५
		१३१
		१३९
		१४०
		१५०
		१५०
		१५२
		१५८
		१६०
		१६९
		१७४
		१८९
		१८०
		१६०
		१५०
		२ ४१
		४ ३२

चर्बोनेत्ज पत्र मुद्रा

पत्र मुद्रा का मूल्य घट गया था। कालान्तर में उत्पादन बढ़ने पर मुद्रा के मूल्य में कुछ परिवर्तन हुआ। मुद्रा के इतिहास में १९२३ ई० का विशिष्ट महत्व है १.। इसी वर्ष राज्य बैंक द्वारा चर्बोनेत्ज नोट चलाए गए। मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई थी। मुद्रा प्रसार के कारण ग्रेशम नियम के अनुसार अच्छी मुद्रा चलन से उठ गई और चर्बोनेत्ज प्रयुक्त होने लगा।

कैंची संकट (Scissors Crisis)

मारिस डाब ने जनवरी १९२२ से मार्च १९२४ के २७ महीनों के आर्थिक असंतुलन के काल को कैंची संकट की संज्ञा दी है। कैंची संकट से डाब का आशय कृषि और औद्योगिक मूल्य की असंगति से हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त अपरिचित नहीं हैं। कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य में एक अनुपात, एक संतुलन, अपेक्षित है। यही संतुलन (equilibrium) अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। जब तक यह संतुलन बना रहता है समृद्धि रहती है। संतुलन बिगड़ते ही अवसाद आ जाता है। इन २७ महीनों के काल में मूल्यों में असंतुलन था।

जनवरी से जुलाई (१९२२) तक कृषि उत्पादन के मूल्य ऊर्ध्वमुखी थे और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य अधोमुखी। अगस्त १९२२ से मार्च १९२४ तक मूल्यों की प्रवृत्ति इसके ठीक विपरीत थी। कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों का उतार-चढ़ाव कैंची के दोनों फलों जैसा होने के कारण ही डाब ने इसे कैंची संकट की संज्ञा दी है।

1. The year 1923 accordingly became notable in monetary history for the interesting experience of two untraded paper currencies, the one of strictly limited issue and prized as a means for holding values in stable form, the other still subject to inflationary depreciation.

Maurice Dobb—'Soviet Economic Development since 1917'

मुद्रा प्रसार और उपज की कमी के कारण १९२२ के आरम्भिक महीनों में कृषि उत्पादन के मूल्य बढ़े। दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन के मूल्य निरन्तर गिरते जा रहे थे। होना यह चाहिये था कि कृषक खुशहाल रहते किन्तु उनकी दशा सर्वाधिक दयनीय थी। अपनी आय का अधिकांश भाग उन्हें कर के रूप में दे देना पड़ता था। कृषि उपज की मांग और मूल्य की प्रवृत्ति ऊर्ध्व मुखी थी।

कृषि उपज का मूल्य तो मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार बढ़ रहा था। भूमि और पशुओं के स्वामित्व की अनिश्चिता के कारण कृषक प्रायः खाने भर को ही अन्न पैदा करते थे। आवश्यक औद्योगिक उत्पादन सामग्रियों के लिए थोड़ा बहुत खाद्येतर अनाज भी पैदा कर लेते थे। कृषि उपज की मांग पूर्ति से अधिक थी। कृषकों का अतिरिक्त उत्पादन सरकार ले लेती थी। ऐसी दशा में कृषि उत्पादन के मूल्य बढ़ने निश्चित थे।

औद्योगिक उत्पादन के मूल्य की गिरावट में मांग और पूर्ति के सिद्धान्त का विशेष महत्व न था औद्योगिक उत्पादन क्रान्ति पूर्व वर्षों की अपेक्षा बहुत कम हो रहा था। नागर मजदूरों और जनता को खाद्य सामग्री के लिए ही अपनी आय का अधिकांश भाग दे देना पड़ता था। औद्योगिक उत्पादन खरीदने के लिए उनके पास धन ही नहीं बचता था। औद्योगिक संस्थानों के पास कार्यशाला पूँजी बहुत कम थी। उत्पादन बेचकर ही वे कच्चा माल खरीद सकते थे। बेचने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करना उनके बस की बात नहीं फलतः जल्दी में बेचने के कारण उन्हें मूल्य कम मिलते थे। औद्योगिक क्षेत्र में अवसाद की सभी प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी।

वस्तु स्थिति यह थी कि मूल्यों की असंगति किसी स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण नहीं थी। वह भूलों और प्रयोगों का युग था; जैसे नौसिखुआ पियानों पर गाए और सुर न मिले किन्तु गाने की उत्कट अभिलाषा के कारण वह औचित्य का विचार किए बिना पियानो के बटन दबाता जाय और उससे जैसा-तैसा सुर निकलता रहे।

औद्योगिक उत्पादन के मूल्य की चिन्ताजनक गिरावट को रोकने के लिए

तरह-तरह के सुभावं रखे गए। कुछ लोगों ने उत्पादन कम करने की सलाह दी किन्तु यह संभव न था, इससे बेकारी बढ़ती। पड़ोसी देशों से अनबन और साव के अभाव में निर्यात भी न हो सकता था। राष्ट्रीय योजना आयोग (gosplan) ने उद्योगों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की जो सरकार को मान्य हुई।

कार्य शील पूँजी की समस्या सुलभ जाने पर औद्योगिक उत्पादन के मूल्य बढ़ने लगे। दूसरी ओर अनुकूल परिस्थिति पाकर कृषकों ने परती जमीन में भी खेती प्रारम्भ कर दी। कृषि उपज अच्छी हुई। स्वाभाविक था कि उपज के दाम गिरते हुआ भी ऐसा ही। मई १९२२ से मूल्य-स्तर संतुलन की ओर मुकने लगा। अगस्त तक स्थिति सामान्य हो गई।

सितम्बर १९२२ में संतुलन फिर बिगड़ने लगा। इस बार विपत्ति कृषकों के सिर थी। वातावरण बदल गया। कृषि उपज के मूल्य की प्रवृत्ति अधोमुखी हो गई और औद्योगिक उत्पादन की ऊर्ध्वमुखी।

खाद्यतर अनाज की बढ़ी हुई मांग का लाभ कृषक न उठा सके। उद्योगों को अपेक्षित कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में मिल जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण किसी भी मूल्य पर औद्योगिक उत्पादन खरीदने के लिए कृषक बाध्य थे। मुसीबत तो यह थी कि औद्योगिक उत्पादन की भांति कृषि उत्पादन का संचय नहीं किया जा सकता था। किसानों की इस विवशता का उद्योगपतियों ने भरपूर लाभ उठाया। मांस और नमक बराबर बिकने लगे। किसान निरीह थे। या तो वे न दिसियातिन् उपज के बदले जूता पहने या नंगे पांव बरफ पर चलें। स्फीति का अधिकांश भार किसानों के दुर्बल कंधों पर था। मजे की बात तो यह है कि स्फीति मुद्रा प्रसार के कारण न थी; किन्निम थी।

सितम्बर १९२३ में मूल्यों का असंतुलन बहुत बढ़ गया। इससे पहले कि 'कैची संकट' अर्थव्यवस्था काट कर नष्ट कर देता उस पर नियंत्रण पा लिया गया। राज्य ने क्रय, विक्रय, वितरण तथा मूल्य-स्तर कम करने के लिए बसंखा के अन्तर्गत केन्द्रीय वाणिज्य विभाग, प्रान्तीय सरकार की व्यापारिक कम्पनियाँ, नारकम्पोद, कृषि और स्वास्थ्य आयोग आदि संस्थाएँ बनाईं।

अभिषद और न्यासों पर औद्योगिक मूल्य कम करने के लिए ३ प्रकार से दबाव डाला गया ।

१—राज्य बैंक को आदेश दिया गया कि वह उद्योगों को कम ऋण दें ।

२—अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए आन्तरिक व्यापार कमेटी (कोम्बुतोर्ग) बनाई गई ।

३—विदेशों से आयात कर सस्ते मूल्य पर वस्तुएँ बेची जायं किन्तु ऐसा एक सीमा के भीतर ही किया जा सकता था । आयात को प्रोत्साहन देने पर अविकसित उद्योगों के नष्ट हो जाने की आशंका थी ।

१९२४ के मध्य तक स्थिति सामान्य हो गई । कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य में संतुलन स्थापित हो गया ।

१९२८ में नियोजित अर्थ-व्यवस्था अपना लेने के कारण भविष्य में कमी इस प्रकार के संकट की सम्भावना न रही ।

कैंची या दरार

श्री मारिस डाब ने इस संकट को 'कैंची संकट' (Scissors Crisis) कहा है । आपका उपमान मूल्य स्तर के रेखा-चित्र पर आधारित है । इसे यदि हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य की दरार कहें तो अधिक उपयुक्त होगा । वस्तुतः मूल्य स्तर का असन्तुलन कुछ वैसा ही था जैसे दलदल का पानी सूख कर दरार पड़ जाय और वह बढ़ती जाय; फिर उसे पाटकर असुविधा जनक स्थिति समाप्त कर दी जाय । इस दृष्टिकोण से रेखा-चित्र एक बार फिर देखिए ।

देश की सभी आर्थिक नीतियों—चलन मुद्रा की स्थिरता और साख नीति, राज्य बैंक के विभागीय प्रश्न, प्रॉम बैंक (Prom Bank), राष्ट्रीय योजना आयोग (Gosplan) और नारकोमफिन (Norcomfin)—परस्पर सम्बद्ध थीं । १९२४ में एक नई आर्थिक नीति को जन्म दिया गया । उद्योगों की एकाधिकारिक प्रवृत्ति समाप्त कर दी गई । यदि ऐसा न हुआ होता तो सोवियत सङ्घ का पराभव निश्चित था । अर्थ-व्यवस्था की दीवार में असमय में ही दरार पड़ गई थी । तीन वर्षों की अल्प अवधि में इतनी बड़ी खाईं पाट देना लेनिन जैसे शिल्पी का ही काम था ।

स्तालिन युग

(१९२४—५४)

अध्याय ८

योजना प्रणाली का संगठन

सोवियत सङ्घ की सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन भारतीय विद्यार्थी जितनी सरलता से और जितने सही ढंग से कर सकते हैं उतना अन्य देशों के विद्यार्थी नहीं। भारत की ही भांति सोवियत भूमि में भी सामन्तवाद के ठीक बाद लोकतांत्रिक अर्थ-व्यवस्था आ गई। दोनों देश अपनी मंजिल तक बिना रुके, एक लम्बी छलांग भर कर पहुँचे। पश्चिमी देशों को सामन्तवाद से लोक-तंत्र तक आने के लिए पूँजीवाद से होकर आना पड़ा। दूसरे शब्दों में हमारा विकास ऋजु रेखा में हुआ और पश्चिमी देशों का त्रिकोणात्मक। सोवियत सङ्घ के आर्थिक विकास के अध्ययन में यह बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वहाँ पूँजीवाद को कभी प्रश्रय नहीं मिला।

पश्चिमी देशों के औद्योगीकरण में पूँजी का विशिष्ट स्थान रहा है। सोवियत देश ने कभी पूँजी के विषय में सोचा भी नहीं, सोचने की आवश्यकता भी न थी। पूँजी की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व दिया गया। पश्चिमी देशों में औद्योगीकरण के लिए बचत (Saving) बढ़ाना आवश्यक था और बचत को प्रोत्साहित करने लिए विनियोग (Investment) की दर बढ़ाई गई। उत्पादन मुद्रा नहीं करती, श्रम करता है। सोवियत सङ्घ में अतिरिक्त कृषि श्रम को उत्पादन में लगा दिया गया। योजना काल में पूँजी (Capital) और विनियोग (Investment) बिना किसी ब्याज या बाजार (जहाँ उत्पादन बैंचकर मुद्रा प्राप्त की जा सके) की सहायता के केन्द्र द्वारा ही प्राप्त किया गया।

औद्योगीकरण की कठिनाइयाँ

औद्योगीकरण के मार्ग में तीन प्रमुख कठिनाइयाँ थी :—

- १—विदेशी सहायता नहीं मिली।
- २—सरकार का ध्यान सहकारी कार्यों और सहकारी उद्योगों की ओर अधिक था। सहकारिता के प्रति जनता की आस्था प्राप्त करनी थी।
- ३—युद्ध के कारण सुरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ा।

विशिष्टीकरण (Specialisation)

गरीब देश उत्पादन का जुआ नहीं खेल सकता। उत्पादन में निश्चयात्मक वृत्ति अपेक्षित है। प्रयोग और भूल के लिए अवकाश नहीं होता।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में सुविधा-पूर्वक विशिष्टीकरण (Specialisation) किया जा सकता है पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में स्वतंत्र स्पर्धा के कारण हानि का भय बराबर बना रहता है। विशिष्टीकरण का प्रयोग केवल बृहत् स्तर उत्पादन में ही किया जा सकता है। स्वतंत्र स्पर्धा में यदि उत्पादन जनरुचि के अनुकूल न हुआ तो नहीं बिक सकता किन्तु जहाँ उत्पादन पर नियंत्रण है वहाँ जन-रुचि का प्रश्न ही नहीं उठता। जूतों के उदाहरण से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। स्वतंत्र स्पर्धा में जूतों के विभिन्न उत्पादक तरह-तरह की डिजाइनों के जूते बनाते हैं। मानी हुई बात है कि जूते संख्या में कुल जूतों की मांग से अधिक बनते हैं पर जनता उनमें से कुछ डिजाइनों को ही पसंद करती है। मांग और पूर्ति का सन्तुलन कुल पूर्ति से न होकर आंशिक पूर्ति से होता है। अतिरिक्त उत्पादन और जनरुचि के प्रतिकूल उत्पादन या तो नष्ट कर दिया जाता है या कम दाम (Reduction Price) पर बेचा जाता है। स्पष्ट है कि स्वतंत्र स्पर्धा में जनरुचि की भिन्नता के कारण बृहत् स्तर उत्पादन नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अनुपात में नहीं हो सकता।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन, उपयोगिता और आवश्यकता में भारतीय पुराण पंथी दम्पति की भांति गठबन्धन होता है। जूतों का आधारिक महत्व पैरों की रक्षा करना है उनकी डिजाइने चाहे कैसी भी हो। सोवियत सङ्घ की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में केवल ३ प्रकार के मोटर हल (ट्रेक्टर)

बनाये गए थे। दूसरी योजना में ४ प्रकार के मोटर हल बनाए जाने लगे जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय ८० प्रकार के ट्रेक्टर प्रचलित थे। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि विशिष्टीकरण का प्रयोग कहीं अधिक सुविधाजनक है और सोवियत उद्योग क्यों अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव आकस्मिक नहीं था। आरम्भ से ही वहां आर्थिक जीवन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाने लगा जो समय के साथ बराबर बढ़ता गया।

युद्धत साम्यवाद के युग में ही राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जाने लगा। राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष उत्पादन पर अधिकार कर लिया गया यद्यपि उस समय राज्य को अपेक्षित सफलता न मिल सकी।

मार्च १९१६ में सारे देश के लिए सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था की चर्चा आरम्भ हो गई थी। सर्वोच्च आर्थिक परिषद् (बेसंख्ता Supreme Economic Council) ने उत्पादन की योजना बनाई। उस समय उद्योगों में सहयोग की भावना न थी। कालान्तर में सहयोग की भावना का विकास हुआ।

१९१८-२० में अनेक योजनाओं के प्रारूप बनाए गए किन्तु उन्हें कार्यान्वित न किया जा सका।

विद्युत शक्ति के बिना साम्यवाद की स्थापना असम्भव था। मार्च १९२० में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए गोएलरो (GOELRO, State Commission for electrification) योजना बनाई गई। डा० क्रज़िज़नोव्स्की (G. Krzhizhanovsky) द्वारा पांचवीं कांग्रेस में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए श्री मारिस डाब ने इस योजना के सम्बन्ध में जनता के दृष्टिकोण का उल्लेख इन शब्दों में किया है :—
People said that it was not a plan of electrification but of 'electric-fiction', they said it was poetry, an imaginative creation, far from reality.'

गोएलरो योजना अपने तथाकथित दोषों के कारण दीर्घ जीवी न हो सकी। दो महीने बाद ही राष्ट्रीय योजना आयोग (Gosplan) में इसका विलयन कर दिया गया। कार्यकारिणी सम्बन्धी अधिकारों से यह संस्था वंचित थी। ये अधिकार S.T.O. को दिए गए थे। इसके कार्य ६ भागों में बँटे थे और एक विभाग का दूसरे विभाग से कोई सम्बन्ध न था। राष्ट्रीय योजना आयोग का ध्यान छोटी-छोटी योजनाओं पर था। कोयला, लकड़ी, तेल आदि से सम्बन्धित अनेक छोटी-मोटी योजनाएँ इसने बनाईं। आगे चलकर राष्ट्रीय योजना आयोग का कार्य क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। १९२५-२८ तक प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का प्रारूप इसी ने तैयार किया। (Control figures) के निर्माण में भी इसी का हाथ था (१९२५)। मोस्की इसे साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रतिकूल समझते थे।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के लक्ष्य और कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में सुविज्ञ विद्वानों, सङ्घ सरकार के आर्थिक आयोग (Economic commissariat) और उद्योगों के संचालकों का मत और प्रतिक्रिया जानने के लिए योजना का प्रारूप उनके पास भेजा गया। योजना की मूलभूत भावना से प्रायः सभी सहमत थे। योजना के प्रारूप के विषय में, मुख्यतः आंकड़ों के विषय में ही मतभेद था। योजना के प्रारूप में पर्याप्त परिष्कार किया गया किन्तु इतने पर भी यह सर्वांगपूर्ण न बन सकी। साधनों की न्यूनता पर विचार किए बिना ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया। योजना के आलोचकों की कमी नहीं है किन्तु योजना निर्माताओं के साहस की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी।

योजना आयोग का काम केवल योजना बनाना मात्र नहीं था वरन् उसे पूरा करना भी था। उसे अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का समाधान तो प्रस्तुत करना ही पड़ता था सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन कर नए विचारों द्वारा जनमत को अपने अनुकूल बनाना पड़ता था।

अध्याय ६

प्रथम पंचवर्षीय योजना

(१९२८—३२)

पूँजीवाद को जड़ मूल से लखाड़ कर कम्यूनिस्ट व्यवस्था स्थापित करने के अभिप्राय से १ अक्टूबर १९२८ से प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के कार्यान्वय का निश्चय हुआ। योजना बनाकर विकास करने का विश्व के इतिहास में यह प्रथम सुनियोजित प्रयास था। विदेशी पूँजी आकर्षित करने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होने पर सोवियत सङ्घ ने पूँजीवादी देशों से पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद कर लेने का निश्चय किया। योजना का मूल उद्देश्य उद्योग और कृषि का पुनर्गठन था।

औद्योगिक क्षेत्र में योजना निर्माताओं का ध्यान कोयला, तेल, विद्युत तथा रसायनिक उद्योग की ओर अधिक था। कृषि के क्षेत्र में वे राजकीय और सामूहिक कृषि फार्मों का पुनर्गठन कर कृषि उत्पाद बढ़ाना चाहते थे।

योजना के निर्माण से पूर्व आशांका थी कि कृषि उत्पादन और नीचे गिरेगा। उत्पादन, मुख्यतः कृषि उत्पादन की किस्म में गिरावट हो रही थी। पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध न होने के कारण सुरक्षा पर अधिक व्यय अपेक्षित था किन्तु योजना बनाते समय इसके ठीक विपरीत सोचा गया। श्री अलेक्सेन्द्र बेकोव के शब्दों में योजना के पहले प्रारूप का ही आधार ठीक था।

योजना के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में १५.६% वार्षिक और अन्तिम वर्ष २१.४% वृद्धि सोची गई थी। S. E. C. से सम्बन्धित बड़े उद्योगों में प्रति वर्ष २१.४% और अन्तिम वर्ष २५.४% की आशा की गई थी। विश्वास था कि १९२८ की अपेक्षा १९३२ का औद्योगिक उत्पादन २३५.६% और S. E. C. के उद्योग २७६.२% हो जायेंगे। उत्पादन कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों की भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

उपभोग की वस्तुओं की अपेक्षा उत्पादन साधनों (यंत्र आदि) के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। औद्योगिक उत्पादन में ३०% कम ईंधन व्यय करने और लागत में ३५% की कमी करने का निश्चय हुआ। कोयले के स्थान में ईंधन के रूप में विद्युत शक्ति का प्रयोग करना कम खर्चीला था। विद्युत पर विगत वर्षों की अपेक्षा ५ गुना अधिक व्यय करने का निश्चय हुआ। योजना के अंत तक श्रमिकों की कार्य क्षमता में ११०% वृद्धि और थोक मूल्य में २४% कमी की आशा की गई।

योजना का आधारीक कोष १६.१ अरब रूबल था।

जिसमें उत्पादन के साधनों के निर्माण पर १४.७ अरब रूबल। और शेष उपभोग की वस्तुओं के निर्माण पर। व्यय किया जाने वाला था। विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली धन राशि का प्रतिशत विवरण निम्न था—

उद्योग ३१.४ (धातु, मशीन और निर्माण), ईंधन १७.६,
रसायन १०.४, कारखानों के लिए घर ७.१।

देश में कुशल श्रमिकों की कमी थी। इसे दूर करने के लिए स्थान-स्थान पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। योजना के अन्तिम वर्ष तक २५०० इंजियरों को प्रशिक्षित कर लेने का निश्चय हुआ।

प्रथम प्रयास होने के कारण योजना का अक्षरशः पालन न हो सका। लघुस्तर उद्योगों में ३०% और बृहत् स्तर उद्योगों में ४५% अधिक व्यय हुआ। इतना ही नहीं व्यय किए जाने वाले अनुपात में भी स्थिरता न रह सकी। बड़े उद्योगों में ८६% अधिक खर्च हुआ।

उद्योग

परिणाम देश के लिए शुभ हुआ। अधिकांश क्षेत्रों में आशातीत सफलता मिली। नियत समय से पहले निर्धारित लक्ष्य से २३.७% अधिक वृद्धि और लागत में ४.२% कमी हुई।

१९२६-३० में देश का कुल उत्पादन ३२.१% बढ़ा। श्रमिक नगरों की ओर आकर्षित हुये और मिल मजदूरी की संख्या में वृद्धि हुई। श्रमिकों की

पदोन्नति हुई। १९३० में औद्योगिक उत्पादन की किस्म को उन्नत बनाने के लिये मास्को में एक गोष्ठी हुई जिसमें उत्पादन की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्ष किया गया।

१९३२ के औद्योगिक परिणाम त्रिगत साठे तीन वर्षों की अपेक्षा कम सन्तोष जनक थे। बड़े उद्योगों का उत्पादन ८% और अन्य उद्योगों का उत्पादन ११% बढ़ा अथवा किन्तु उत्पादन व्यय कम न होकर बढ़ गया।

व्यक्तिगत रूप से चलाए जाने वाले लघुस्तर उद्योगों के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

योजना के प्रति सरकार की इतनी आस्था थी कि उसके विरोध में वह एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार न थी। योजना के मार्ग में आने वाली प्रत्येक रुकावट को किसी भी मूल्य पर हटा देने के लिए वे कटिबद्ध थे। योजना के विरोधी या अपना कार्य ठीक से न करने वाले कुशल श्रमिक दण्डित किए गए। ४ मई १९२६ को O. G. P. U. ने दो रेल विशेषज्ञों को गोली से उड़ा देने की आज्ञा दी। १८ जनवरी १९२६ को त्रोत्स्की को देश निकाला दिया गया। २ जून १९२६ को त्रोत्स्की को मजदूर संघ से स्तीफा देने को बाध्य किया गया। श्री बुखेरिन और श्रम तथा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष रेक्वोस को कम्युनिस्ट दल से निष्कासित किया गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि योजना कार्यान्वित करने में कितनी कड़ाई बरती गई थी।

आरम्भ में सरकार ने निजी उद्योगों की अपेक्षा की। सरकार का ध्यान राजकीय और सहाकारी उद्योगों की ओर अधिक था।

कालान्तर में १९३१-३२ में निजी उद्योगों को प्रोत्सहन देने के लिए कई धारार्ये बनाई गईं।

जनवरी १९३२ में S. E. C. का पुनर्गठन हुआ। एक साथ अनेक कार्य करने के कारण सुचारु रूप से S.E.C. का कार्य नहीं हो पा रहा था। आवश्यकता इस बात की थी कि S. E. C. के विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व बांट दिया जाय। S. E. C. के तीन विभाग किए गए —

१—भारी उद्योग आयोग (नारकोम्यजंप्रोम All-union Commissariat of Heavy Industry)

इसका कार्य बृहत् स्तर उद्योगों की देख-रेख करना और उनकी समस्याएँ सुलझाना था ।

२—हलका उद्योग लोक आयोग (नारकोमलीग प्रोम The People's Commissariat of light Industry).

३—काष्ठ उद्योग लोक आयोग (नारकोमर्लस The People's Commissariat of Timber and Wood-working Industry).

इन दो आयोगों का कार्य तत्सम्बन्धी उद्योगों की देख-रेख करना और आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता देना था ।

कृषि

कृषि उत्पादन में ३५% वृद्धि की आशा थी । बड़े खेतों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया । बाजार का ३६% कृषि उत्पादन बड़े फार्मों से उत्पन्न किया जाने वाला था ।

क्रान्ति के बाद भूमि पर नें व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर देने का विधान बनाया गया जिसे उस समय कार्यान्वित न किया जा सका । जनवरी १९३० से व्यक्तिगत खेतों को तोड़कर सामूहिक खेत बनाये जाने प्रारम्भ हुए । एक वर्ष बाद देश में १ लाख बड़े सामूहिक खेत (कोलरवोचेस Collective farm १२० बड़े राज्य खेत (सोवरवोजेस state farm) जिनका क्षेत्रफल ५० लाख हेक्टर था हो गए ।

सामूहिक खेत सरकार और जनता की सम्पत्ति थे । स्थायी रूप से किसानों को जमीन दे दी गई थी किन्तु उसे बेचने का उन्हें अधिकार नहीं था । भूमि का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिया जाता था । कृषि उत्पादन प्रत्येक सदस्य को उसके परिश्रम के अनुसार मिलता था । उत्पादन का एक निश्चित भाग सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर सरकार के हाथ बेचना पड़ता

था। फार्म की सार्धारण सभा के दो तिहाई बहुमत से ही कोई सदस्य निकाला जा सकता था।

जार-परिवार तथा चर्च की ज्वत की गई भूमि तथा साफ करके कृषि योग्य बनाये गये जंगल और मरुस्थल राज्य खेत थे।

धनी किसानों से जमीन छीन ली गई। बिना दूध देने वाले जानवर, कृषि यंत्र, बीज, चारा तथा सामूहिक खेतों में सहायक हो सकने वाले सभी बड़े मकानों का समाजीकरण कर लिया गया। आरम्भ में इससे बड़ी अव्यवस्था पैली। कृषि उत्पादन में वृद्धि होना दूर, उलटे कमी हुई। कृषि उत्पादन में हास होने के अनेक कारण थे—

१—अमीर किसानों द्वारा जानवरों की हत्या।

२—चारे की कमी।

३—भूमि और पशुओं के स्वामित्व के प्रश्न पर अनिश्चितता की भावना।

४—वैज्ञानिक साधनों का अभाव।

५—कृषकों की कार्य क्षमता में हास।

६—निजी खेती करने वाले कृषक सामूहिक खेतों पर अपेक्षित ध्यान न दे पाते थे।

सरकार ने इन दोषों को दूर करने का यथासाध्य प्रयास किया। निश्चय किया गया कि पशु हत्य करने वाले किसान मृत पशु का मूल्य सरकारी खजाने में जमा करने तक सामूहिक खेतों की सदस्यता से वंचित कर दिए जायेंगे। सामूहिक खेतों के उत्पादन और देख-रेख के लिए कठोर नियम बनाये गये। अधिक संख्या में अच्छे कृषि-यंत्रों का निर्माण किया जाने लगा। बहुत बड़े-बड़े खेतों को छोटे-छोटे फार्मों में विभक्त किया गया। स्वामित्व सम्बन्धी समस्याओं के निदान के लिए साम्यवाद के प्रति आस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया।

१९३२ तक स्थिति पर थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सका था। कृषि उत्पादन लगभग १९१४ के निकट था।

प्रथम योजना की कृषि सम्बन्धी प्रगति निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगी—

AGRICULTURE TABLE 27

	1927-8		1932-3	
	Million roubles	%	Million roubles	%
Gross Agricultural productions :				
1 State farms	170	1.2	690	3.2
2 Collective farms	88	0.6	2,480	11.5
Total 1+2	258	1.8	3,170	14.7
3 Individual peasant farming	13,722	98.2	18,459	85.3
Total 1+2+3	13,930	100.0	21,629	100.0
Marketable surplus :				
1 State Farms	104	3.6	570	8.6
2 Collective farms	24	0.8	1,060	16.7
Total 1+2	128	4.4	1,610	25.3
3 Individual peasant farming	2,772	95.6	4,754	74.7
Total 1+2+3	2,900	100.0	6,364	100.0
Total sown area (million hectares)	115.6	100.0	141.3	100.0
Individual peasant farming	113.3	98.0	122.4	86.6
Collective farms	1.1	0.9	14.5	10.3
State farms	1.2	1.1	4.4	3.1
Gross yield of grain crops (million quintals)	731.2	100.0	1,051.8	100.0
Individual peasant farming	715.3	97.8	895.8	84.6
Collective farms	7.2	1.0	119.5	11.3
State farms	8.7	1.1	43.5	4.1

* The Development of the Soviet Economic System PP. 19)
By Alexander Baykov

श्रम

इस समय देश में बुरी तरह बेकारी फैली थी। अधियोजन विभाग की सूची में प्रायः ८,११,००० बेकार थे जिनमें २,६६,६०० अकुशल श्रमिक थे। सरकार ने बेकारी दूर करने का यथाशक्ति प्रयास किया। श्रमिकों को ७ घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। १९२८ में विद्यालयों में विज्ञान और प्रशिक्षण के विभाग खोले गये। कामकरों की संख्या में बराबर वृद्धि होती रही। १९३०-३५ तक कामकरों की संख्या में क्रमशः २६, ६५, ६८, ७१, ७३, और ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आन्तरिक व्यापार

देश का आन्तरिक व्यापार दो भागों में विभक्त था—

१—वे वस्तुएँ जो बाजार में नहीं भेजी जाती थीं। यथा, औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुएँ, शस्त्रास्त्र।

२—बाजार में भेजी जाने वाली वस्तुएँ—

(क) नियोजित उत्पादन,

(ख) राजकीय उद्योगों के उत्पादन,

आन्तरिक व्यापार की वृद्धि के लिए उपभोग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उत्पादन और उत्पादन का योजनात्मक ढंग से वितरण किया जाता था। सुविधा की दृष्टि से राशनिंग पद्धति अपनाई गई थी। बचत की ओर सरकार का विशेष ध्यान था। सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे।

कृषि उत्पादन के वितरण की व्यवस्था के लिए राजकीय क्रम संगठन का निर्माण किया गया। व्यावहारिक रूप से सरकार द्वारा निर्धारित, मूल्य पर बेचा जाने वाला सारा कृषि उत्पादन सरकार के हाथ बेच देना पड़ता था। १९२८-२९ में ७२% क्रय किया गया था, योजना के अन्तिम वर्षों में ६५.४% अतिरिक्त कृषि उत्पादन खरीद लिया गया था। कृषि के क्षेत्र में निजी व्यापार क्रमशः समाप्त कर दिया गया। निजी व्यापार १९२९ में १३.५%, १९३० में ५.६% और १९३१ में प्रायः समाप्त हो गया था।

सिंहावलोकन

प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाने में बड़ी शीघ्रता की गई थी। प्रथम प्रयास होने के कारण अनुभव, कार्य क्षमता और शक्ति के साधनों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया गया था। यद्यपि वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत थी। कुशल श्रम का देश में नितान्त अभाव था, जो थे भी वे जारशाही के समर्थक थे। पारम्परिक संदेह चरम सीमा पर था। अक्सर उपलब्ध होते ही बड़े से बड़े अधिकारी दूध की मक्खी की तरह फेंक दिये जाते थे। बन्धुत्व और सहयोग की भावना (जो साम्यवाद की आधार शिला है) के स्थान पर संदेह और अविश्वास ने घर कर लिया था।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के बाद दूसरी पञ्चवर्षीय योजना कर्णान्वित की जाने लगी थी। विदेशी ऋण की संभावना की अनुपस्थिति में दूसरी योजना के लिए आधारित पूँजी सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक था। १९३२ में राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग बचा लिया गया। फलतः देशवासियों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तरसना पड़ा। पूँजी के संचय के लिए पहले तो नगरवासियों से ही औद्योगिक कर्ज लिया गया। आगे चलकर अर्थाभाव होने पर देहात की जनता से भी कर्ज लिया गया।

योजना संतुलित नहीं थी। औद्योगीकरण को इतना अधिक महत्त्व दिया गया कि कृषि उपेक्षित हो गई। विद्युत शक्ति इतनी अधिक उत्पन्न हुई कि उसका सम्यक उपयोग न हो सका। औद्योगिक उत्पादन की किस्म बहुत गिर गई थी।

ग्राम जनता की साम्यवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था न थी। सरकार ने जनमत तैयार किये बिना ही साम्यवादी सिद्धान्तों का कार्यान्वय प्रारम्भ कर दिया था। सरकार के राष्ट्रीयकरण (Nationalization) और समूहीकरण (Collectivization) की नीति की विरोध में कृषकों ने अपने उपभोग भर का ही उत्पादन करने का निश्चय किया। खाद्य पदार्थों की कमी और भूमि का स्वामित्व छिन जाने के कारण देहाती शहरों की ओर आकर्षित हुए। नगरों की जनसंख्या बढ़ी किन्तु खाद्य सामग्री की समस्या विकट हो गई। स्पष्ट

है कि जब भूमि का बहुत बड़ा भाग बिना बोये छोड़ दिया जाय, पशु राष्ट्रीयकरण के भय से मार कर खा डाले जाय, किसान केवल अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं भर को अन्न पैदा करें तो गौर कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले कैसे पेट भरेंगे ? और वह भी तब, जब मुद्रा स्फीति के कारण वास्तविक आय में कमी हो गई हो ।

आलोचना करते समय यह कभी न भूलना चाहिए कि सोवियत सङ्घ का प्रथम पञ्चवर्षीय योजना योजनार्थक आर्थिक विकास का प्रथम ऐतिहासिक प्रयत्न था । उसकी कमियाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसकी विफलताएँ मानव स्वभाव की कमियाँ कमजोरियाँ और विफलताएँ थीं । मनुष्य का स्व उसके सामाजिक होने में बाधक है । सिद्धान्ततः साम्यवाद का समर्थन करते हुए लोग अपना स्व नहीं छोड़ पाते ।

सारी कठिनाइयों के बावजूद भी देश आगे बढ़ा । योजना निर्माताओं का ध्यान केवल वर्तमान की ओर ही न था वे उज्वल भविष्य की कल्पना कर रहे थे । यदि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया होता तो तात्कालिक सफलता अधिक मिलती किन्तु विकास की भावी गति मंद पड़ जाती । प्रथम योजना वैसी ही थी जैसे कोई माली खाना पीना भूलकर वृक्ष लगाये, माली के कार्य का मूल्यांकन वृक्ष के फल से नहीं उसके रचना कौशल और लगन से किया जाना चाहिए ।

सोवियत सङ्घ की प्रथम पंचवर्षीय योजना साम्यवाद के प्रासाद की पहली ईंट थी ।

अध्याय १०

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना

(१९३२—३७)

सत्रहवीं पार्टी कांग्रेस की २६ जनवरी - १० फरवरी १९३४ की बैठक में द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का प्रारूप निर्धारित हुआ था। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना प्रथम योजना से अधिक व्यावहारिक थी। इसमें प्रथम योजना की भूलों और अवास्तविकताओं का परिष्कार किया गया।

प्रथम योजना में उत्पादन के साधनों के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया था। औद्योगिक दृष्टि से देश के पिछड़े होने के कारण ऐसा उचित भी था। दूसरी योजना के लागू होने तक परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी थीं। देश आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहा था। वास्तविक आय में क्रमशः वृद्धि होने पर आवश्यकताएँ बढ़ रही थीं। दूसरी योजना में उपभोग की वस्तुओं के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया गया।

उत्पादन की क्षेत्रीय इकाइयों को व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार दे दिए गए। मिश्रण (Combination) की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया गया और उसके स्थान पर क्षेत्रीय उत्पादन सिद्धान्त पर आधारित मुख्य प्रशासन को व्यवस्था की गई, उदाहरणार्थ—मास्को का मुख्य प्रशासन, लेनिनग्राद का रूई उद्योग प्रशासन आदि। प्रशासन के ३ मुख्य कार्य थे—

१—निरीक्षण और सुभाव।

२—कार्य-प्रणाली का निर्धारण।

३—अर्थ-व्यवस्था।

युद्ध की आशंका के कारण उद्योगों का केन्द्रीकरण संभव न था। युद्ध छिड़ने पर सब उद्योग एक साथ नष्ट हो जाते। उद्योगों को युद्ध के नाश से बचाने के लिए आवश्यक था कि उद्योग का विकेन्द्रीकरण किया जाय। द्वितीय

योजना में उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया गया। फलतः मूल उद्योगों के साथ पूरक उद्योग भी जगह-जगह फैले। छोटे-छोटे कस्बे शहरों का रूप ग्रहण करने लगे। श्रम की गति शीलता और कार्य-क्षमता बढ़ने लगी।

पार्टी कांग्रेस द्वारा पर्याप्त कटौती किए जाने पर भी योजना के प्रारूप के अनुसार काम न हो सका। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के कार्य ही अधूरे पड़े थे। योजना के तीसरे वर्ष से कार्य प्रारम्भ हो सका। द्वितीय योजना के ही धन से प्रथम योजना के अधूरे कार्यों को पूरा किया गया। सोचा गया था कि यदि द्वितीय योजना का ६ अरब रूबल प्रथम योजना के कार्यों पर लगा दिया जायगा तो वे पूरे हो जायेंगे पर कालान्तर में स्पष्ट हो गया कि प्रथम योजना द्रोपदी की चीर थी। १७ अरब रूबल व्यय कर चुकने पर भी प्रथम योजना के कार्य पूरे न हो सके।

द्वितीय योजना में ६४.७ अरब रूबल विभिन्न मर्दों में व्यय करने का निश्चय किया था। नव-निर्माण के कार्यों के लिए ३८.१ अरब रूबल व्यय करने का निश्चय किया था किन्तु इसके लिए २१ अरब रूबल से अधिक न व्यय किया जा सका क्योंकि १७.१ अरब रूबल प्रथम योजना के नव-निर्माण सम्बन्धी अधूरे कार्यों को पूरा करने में खर्च हो गया और जो शेष बचा उसे पुनिर्माण और मरम्मत में खर्च किया गया।

यह योजना पूर्व योजना की अपेक्षा अधिक तर्क संगत थी। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन की लागत में २६% की कमी और कार्य क्षमता में ६३% की वृद्धि का निश्चय किया था जो पहली योजना की अपेक्षा कहीं अधिक व्यावहारिक था। प्रथम योजना में इनका प्रतिशत क्रमशः ३५ और ११० था।

आय के साधन (मिलियार्ड (अरब) रुबल में)

	प्रथम पञ्चवर्षीय योजना		द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
समाजीकृत वित्त का एकत्रीकरण जिसका :—				
लाभ	७३.६	६१.३	३३२.२	७६.३
	१६.१	१५.६	७६.७	१६.०
उत्पादन कर	४२.३	३५.२	२१८.५	५२.२
अचल पूँजी की कटौती जनता से प्राप्त ऋण (मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण) विविधि आय	६.३	५.२	२०.०	५.७
	२१.५	१७.६	४६.१	१३.२
	१८.७	१५.५	२०.५	५.६
कुल आय	१२०.१	१००.०	३४८.८	१००.०

	द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के काल में	१९३७ का ३२ की अपेक्षा प्रतिशत
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था जिसका पूँजी लगाई जायेगी सक्रिय पूँजी में वृद्धि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में किया जाने वाला व्यय प्रशासन और सुरक्षा राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण विविधि व्यय	२०८.२ ११४.२ २६.४ ७५.४ १६.० १०.० २१.२	१४७.० १२५.० १४१.५ २१४.६ १७२.० २८०.० २५३.८
योग	३३३.८	१७१.७
राज्य द्वारा सुरक्षित धन	१५.०	—
कुल योग	३४८.८	१८३.०

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का प्रारूप और वास्तविक उत्पादन निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा—

	द्वितीय योजना का निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
कुल औद्योगिक उत्पादन (मिलियार्ड रूबल में १९२६-२७ के निर्धारित मूल्य के अनुसार)	६२.४	६५.५
जिसका :—		
क वर्ग		
उत्पादन के साधनों का उत्पादन	४५.५	५५.२
ख वर्ग		
उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	४७.२	४०.३
समेत:—		
जिला शक्ति केन्द्रों में विद्युत का उत्पादन (दस लाख किलोवाट में)	२४.५	२५.४
कोयला (दस लाख टन में)	१५२.५	१२८.०
बिना साफ किया तेल और गैस (दस लाख टन में)	४६.८	३०.५
कच्चा लोहा (दस लाख टन में)	१६.०	१४.५
इस्पात " "	१७.०	१७.७
ढाली हुई धातु " "	१३.०	१३.०
रासायनिक उद्योग (१९२६-७ के निर्धारित मूल्य—मिलियार्ड रूबल में)	५.०	५.६
धातु उद्योग " "	१६.५	२७.५
सूत्री वस्त्र (दस लाख मीटर में)	५,१००.०	३४४७.७
लिनेन " "	६००.२	२८५.२
जूता (दस लाख जोड़ा)	११८०	२०५.६

दिसम्बर १९३३ में नियम बना कि उत्पादन की अव्यवस्था और किस्म की गिरावट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायगी। एक बार फिर लोग न्यायालय के कठघरे में खड़े किए गए। श्रमिकों को पूर्ण अनुशासित बनाने के लिए प्रत्येक सम्भव तरीके का प्रयोग किया गया।

१९३४ ई० में अनेक क्षेत्रों से राशनिंग उठा ली गई किन्तु इससे मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन न हुआ, इसका कारण उत्पादन व्यय और क्रयशक्ति की स्थिरता थी।

कुल मिला कर योजना का प्रभाव देश के आर्थिक विकास के लिए शुभ हुआ। १९३६ तक बड़े उद्योगों में ३०.३, लघु उद्योग में ३० और सहकारी उद्योगों में ४१.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुछ उद्योगों में निर्धारित लक्ष्य से माल अधिक और कुछ में कम उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन का ८०% नव-निर्मित कारखानों में बना। श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में ८२% की वृद्धि हुई। वस्त्रोद्योग और स्वचालित यंत्रों से चलने वाले उद्योगों की आशातीत उन्नति हुई। पाव रोटी का उत्पादन जो १९३३ में केवल ६० लाख टन था १९३७ में बढ़कर १६० लाख टन हो गया। चीनी और पेट्रोल के उत्पादन में तिगुना, कोयले के उत्पादन में चौगुना और बिजली के उत्पादन में अठगुनी वृद्धि हुई।

औद्योगिक दृष्टि से अविकसित क्षेत्रों में नए कारखाने खोले गए। आर्कटिक के बर्फीले मैदान में राई, बाली तथा गेहूँ उपजाने की योजना सफल रही। सिंचाई तथा यातायात की सुविधा के लिए अनेक नहरें बनाई गईं। जिनमें दो नहरें विशेष रू से उल्लेखनीय हैं—

१ — श्वेत (white) औ बाल्टिक (Baltic) समुद्रों को मिलाने वाली नहर १९३३ में बनाई जानी प्रारम्भ हुई। इसे कैदी मजदूर बना रहे थे। प्रायः दो वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ।

२ — मास्को और वोल्गा नदी को मिलाने वाली नहर ८० मील लम्बी थी।

प्रथम योजना के अनुभवों से स्पष्ट हो गया था कि साम्यवादी सिद्धान्तों के लिए अभी देश तैयार नहीं है। साम्यवाद के अनुकूल वातावरण बनाये बिना

उसके सिद्धान्तों का कार्यान्वय नहीं किया जा सकता था। 'योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन' अथवा 'जिनके हाथ खुरदरे न हो उन्हें खाने का अधिकार नहीं है (तालस्तॉय)' का सिद्धान्त अव्यावहारिक था। इससे श्रम की कुशलता पर आ बनी थी। द्वितीय योजना में योग्यता और काम के अनुसार मजदूरी दी जाने लगी। स्वामित्व सम्बन्धी विचार-धारा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सामूहिक फार्मों (Collective farms) में स्वामित्व सम्बन्धी परिवर्तन हुए। व्यक्तिगत स्वामित्व को एक सीमा तक स्वीकार कर लिया गया। सामूहिक फार्मों के सदस्य परिवारों को एक घर, घर के पास व्यक्तिगत उपभोग के लिए खेत, कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु, एक दूध देने वाला पशु तथा इच्छानुसार सुर्गियों व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रखने और मन चाहा उपभोग करने की छूट दी गई। आर्टेल (Artel) के सदस्यों को प्रतिमास और औद्योगिक फसलें उत्पन्न करने वालों को प्रति सप्ताह काम के अनुसार पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई।

लोग काम में रुचि लेने लगे। सामूहिक फार्मों का उत्पादन योजना के अन्तिम वर्ष तक साढ़े तीन गुना बढ़ गया।

अध्याय ११

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना

(१९३८-४२)

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का ही विकसित रूप था। इसका प्रारूप १७ वीं पार्टी कांग्रेस में दूसरी योजना के साथ ही बना लिया गया था। १९३८ में इस योजना की घोषणा हुई। इस योजना में यंत्रों के अधिकाधिक उपयोग, उत्पादन की किस्म उन्नत करने, कार्य क्षमता में वृद्धि तथा लागत में कमी करने का निश्चय किया गया। युद्ध की संभावना बढ़ रही थी अतः बढ़े उद्योगों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक था। इस योजना में प्रथम योजना की भांति क वर्ग (उत्पादन के साधनों का उत्पादन) के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया और उपभोग के बहुत से अनावश्यक पदार्थों का उत्पादन कुछ समय तक स्थगित कर दिया गया।

सोवियत सरकार युद्ध से आशंकित अवश्य थी किन्तु वह वर्ष भर बाद ही प्रारम्भ हो जायगा इसका उन्हें आभास भी नहीं था। संभवतः वे युद्ध से विरत रहना चाहते थे। कहा नहीं जा सकता कि उनके पास कितनी युद्ध सामग्री थी किन्तु इतना स्पष्ट है कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। सोवियत नेताओं ने कई बार इस तथ्य को दुहराया था कि उनका देश उत्पादन के क्षेत्र में पूँजीवादी देशों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा था। वे युद्ध की लपटों से बचे रहकर पूँजीवादी देशों के समकक्ष आना चाहते थे। अपनी आशा के प्रतिकूल विवश होकर उन्हें १९४० में युद्ध में योग देना पड़ा।

तीसरी योजना का निर्माण कार्य बर्बर हथों द्वारा बलात् दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। खाद की जगह गोलियां बनाई जाने लगीं। आर्थिक विकास की दिशा में मूल योजना का अध्ययन महत्वहीन है। बात साफ है, जब योजना कार्यान्वित की ही नहीं जा सकी तो उसका प्रारूप जानने से कुछ

बनता-बिगड़ता नहीं किन्तु योजना बद्ध विकास के अध्ययन की कड़ी न टूटने देने के लिए यह आवश्यक है कि मूल योजना प्रारूप से भी हम परिचित रहे।

मूल योजना

तीसरी पञ्चवर्षीय योजना में उत्पत्ति के साधनों के उत्पादन पर पुनः जोर दिया गया। १९३९ के अनुमनित मूर्त्तियों के अनुसार योजना में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए १९२ अरब रूबल व्यय किया जाने वाला था। औद्योगिक विकास के लिए १११'९ अरब रूबल व्यय किया जाने को था। दूसरी योजना में यह धन राशि ५८'६ रूबल थी। १११'९ अरब रूबल की धन राशि में क वर्ग (उत्पादन के साधनों के उत्पादन) के उत्पादन पर ९३'९ अरब रूबल (दूसरी योजना में केवल ४९'८ अरब रूबल था) और उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन (ख वर्ग) पर १८ अरब रूबल (दूसरी योजना में केवल ८'८ अरब रूबल था) व्यय किया जाने वाला था। क वर्ग के लिए व्यय की जाने वाली धन राशि में से ३७'३ अरब रूबल यातायात पर व्यय होने को था।

तीसरी योजना में उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर दूसरी योजना की अपेक्षा दूने से अधिक खर्च किया जाने वाला था किन्तु व्यय की जाने वाली कुल धन-राशि के अनुपात में यह अपर्याप्त थी। योजना निर्माताओं का ध्यान वर्तमान आवश्यकताओं की ओर उतना नहीं था जितना भविष्य की आवश्यकताओं की ओर था। किसी प्रकार जीवन यापन कर शीघ्र से शीघ्र पश्चिमी जगत के स्तर तक वे आना चाहते थे। योजना का प्रारूप अधोलिखित है—

तालिका*

	१९३७	१९४२	१९४२ का प्रतिशत ३७ की अपेक्षा
सभी उद्योगों का कुल उत्पादन अरब रूबल में			
(१९२६-२७ के मूल्य के अनुसार)	९५'५	१८४'३	१९२
उत्पादन के साधनों का उत्पादन	५५'२	११४'५	२०७

*The development of the Soviet Economic System.

By Alexander Baykov PP. 289.

उपभोग वस्तुओं का उत्पादन	४०.३	५६.५	१७२
मशीन निर्माण तथा धातु उद्योग	२७.५	६३.०	२२६
रसायन उद्योग	५.६	१४.०	२३७
विद्युत शक्ति (अरब किलोवाट में)	३६.४	७५.०	२०६
कोयला (दस लाख टन में)	१२७.३	२४३.०	१६०
बिना साफ किया तेल और गैस (दस लाख टन में)	३०.५	५४.०	१७७
कच्चा लोहा , ,	१४.५	२२.०	१५२
इस्पात , ,	१७.७	२८.०	१५८
ढली हुई धातु, ,	१२.६	२१.०	१६२
अल्युमिनियम , ,	४६.८	१६२.०	३४६
सीमेंट , ,	५.४	११.०	२०२
सूती वस्त्र (दस लाख मीटर में)	३४४०.२	४६००.०	१४२
ऊनी , ,	१०५.१	१७७.०	१६७
चमड़े के जूते (दस लाख जोड़े)	१६४.२	२५८.०	१४३
चीनी (हजार टन में)	२,४२१.०	३,५००.०	१४४
फलों के मुरब्बे (दस लाख डिब्बों में)	८६३.०	१,८००.०	२०६

कोयला, लोहा, धातु, रसायन, यंत्र, सीमेंट, लट्टा, आदि उद्योगों को राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी गई। लाभांश के उचित वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए मुख्य प्रशासक और मुख्य शाखा प्रशासक की नियुक्ति की गई। १९३८ में युद्ध सामग्री के उत्पादन की अन्य उद्योगों से पृथक व्यवस्था की गई।

केवल साढ़े तीन वर्ष तक ही योजना पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाई जा सकी। इन साढ़े तीन वर्षों की औद्योगिक प्रगति का विवरण निम्न है

	१९३७	१९३८	१९३९	१९४०	१९४१
कुल औद्योगिक उत्पादन अरब					
रुबल में १९२६-२७ के					
मूल्य के अनुसार	६५.५	१०६.८	१२३.९	१३३.५	१६२.०
जिसमें—					
(Capital goods)	५५.२	६२.६	७३.७	८३.९	१०३.६
उपभोग वस्तुएँ	१०.३	४४.२	५०.२	५३.६	५८.४
कोयले का उत्पादन					
(दस लाख टन में)	१२७.९	१३२.९	१४३.९	१६४.६	१९१.०
तेल " " "	३०.५	३६.२	४१.२	३४.२	३८.०
कच्चा लोहा " "	१४.५	१४.६	—	१४.९	१८.०
इस्पात " "	१७.७	१८	—	१८.४	२२.४
ढली हुई धातु " "	१३	१३.३	—	१३.४	१५.८
अल्युमिनियम (हजार मन में)	४८.८	५६.८	—	५९.९	६६.४
ताँबा " "	६६.८	१०३.२	—	१६४.७	२१५.७

ऋणकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

§ अनुमानित

पूरब के अविकसित प्रदेश में खानों से धातुएँ निकालने और उसे साफ करने के उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था की गई । बोलगा तथा यूराल के क्षेत्र में मिट्टी के तेल निकालने और साफ करके पेट्रोल आदि बनाने की व्यवस्था थी । उद्योगों के स्थानीय करण की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों बनी रही । यातायात सम्बन्धी असुविधाओं को देखते हुए निश्चय किया गया कि कच्चे माल के क्षेत्रों के समीप ही उनसे सम्बन्धित उद्योग स्थापित किए जाय ।

शान्ति काल के साढ़े तीन वर्षों में पर्याप्त प्रगति हुई । प्रायः १३% वार्षिक औद्योगिक उत्पादन की प्रगति हुई । भारी उद्योगों का विकास आशातीत था । कालान्तर में युद्ध छिड़ने पर जिस शीघ्रता के साथ उद्योग धन्धे दूर पूर्व साइबेरिया के प्रदेश में ले जाए गए उसकी भूमिका तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों

में ही बन चुकी। बोल्गा प्रदेश, यूराल, कजारवस्तान, मध्य एशिया और साइबेरिया का औद्योगिक विकास प्रायः ब्योढ़ा हो चुका था। इन क्षेत्रों में प्रायः ४००० नए कल वारखाने स्थापित किए गए। यदि युद्ध न छिड़ता तब भी एशियाई प्रदेश का औद्योगीकरण होता हों, उसकी गति इतनी द्रुत न होती।

आश्चर्य तो इस बात का है कि औद्योगिक विकास के इस युग में अत्यधिक महत्व पूर्ण लोहा और इस्पात उद्योग में कोई वृद्धि न हो सकी। १९३८-१९४० के २ वर्षों में केवल २ लाख टन अधिक उत्पादन किया जा सका। कोयला तथा मिट्टी के तेल उद्योग की दशा चिन्ताजनक थी।

	१९३८	१९३९	१९४०
लोहा लाख टन में	१४७	१४५	१४९
इस्पात ,, ,,	१८१	१७६	१८३
कोयला ,, ,,	१,३३३	१,४६२	१,६५९
मिट्टी का तेल ,,	३२२	३०३	३११

ऐसे उद्योग जिनकी प्रगति निराशा जनक थी संख्या में स्वल्प थे। अधिकांश उद्योगों की प्रगति अच्छी थी।

अध्याय १२ : द्वितीय ' विश्व युद्ध

२२ जून १९४१ को जर्मनी ने बिना पूर्व घोषणा के सोवियत सङ्घ पर आक्रमण कर दिया। औद्योगिक दृष्टि से सोवियत देश जर्मनी की अपेक्षा पिछड़ा हुआ था १९४१ के अधोलिखित आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो जायगी—

	जर्मनी	सोवियत सङ्घ
कोयला	१८६० लाख टन	१३३० लाख टन
कच्चा लोहा	१८० ,, ,,	१४ ,, ,,
इस्पात	२३० ,, ,,	१८० ,, ,,

जर्मनी औद्योगिक उत्पादन और कच्चे माल की उपलब्धि की दृष्टि से न केवल सोवियत संघ वरन् सभी मित्र राष्ट्रों से आगे था।

जर्मनी जैसा शक्ति सम्पन्न और समृद्धि शाली देश कोई न था। हाँ, सबकी शक्ति के सम्मिलित योग की तुलना में वह कुछ नहीं था। सबको एक साथ चुनौती देकर उसने भूल की थी।

श्री डाब के मतानुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण सोवियत सङ्घ ने युद्ध में देर से भाग लिया।^१ हम श्री डाब से सहमत नहीं हैं। कोई

It was also the consciousness of German 'economic superiority in certain crucial respects that no doubt influenced the Soviet Government in attaching paramount importance to the strategy of the long-delayed second front in the west and in "buying time with space" while they were building the war potential further east that was to drive the Wehrmacht fifteen hundred miles from the Volga to beyond Oder.

The Economic Development since 1917—Maurice Dobb
M. A., P. 295

भी विकासोन्मुख राष्ट्र युद्ध को जान-बूझकर आमंत्रण नहीं देता। युद्ध के नाश, आंतरिक अशान्ति और अराजकता से सोवियत सरकार और नागरिक परिचित थे। जारशाही से मुक्ति पाने के २० वर्ष के अल्प समय में ही प्रथम विश्व युद्ध और युद्धत साम्यवाद के असहनीय कष्ट वे भेले चुके थे। उन्हें मित्र और शत्रु की पहचान थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीसवीं शती के युद्ध का परिणाम विगत युद्धों से भिन्न था। अब लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रसार के कारण उपनिवेश के लिए अवकाश नहीं था। युद्ध में विजय हो या पराजय परिणाम प्रायः समान था। हाथ लगता केवल नाश ही। ऐसी स्थिति में युद्ध से विरत रहना तो प्रत्येक समझदार राष्ट्र चाहेगा।

सोवियत सङ्घ के पास सभी युद्धोपयोगी वस्तुओं का भण्डार था। तेल, पेट्रोल, इस्पात, बरूद, मैगनीज, फास्फेट, जस्ता, क्रोम, पोटैस, एस्बेस्टार्स (ताप नियंत्रक Asbestors) और कृत्रिम रबर बनाने के उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। दूसरी योजना के आरम्भ से ही निर्माण कार्यों में इनका उपयोग किया जा रहा था। युद्ध में सम्मिलित होते ही योजना के अनुभवों के आधार पर निर्माण का ढांचा बदल दिया गया।

तीसरी योजना का उत्तराद्ध

२२ जून १९४१ को जब सोवियत नागरिक शान्ति पूर्ण निर्माण कार्यों में व्यस्त थे जर्मनी के बम वर्षक वायुयानों द्वारा उनका आकाश अशान्त हो उठा। श्री मोलोटोव ने अल्यूमिनियम, जस्ता, निकल, सीसा और तांबा के उत्पादन पर जोर दिया। केमेन्स्क (यूराल) में अल्यूमिनियम का कारखाना खोला गया। बोल्गा और यूराल के बीच में मिट्टी का तेल निकालने और साफ करने के अनेक केन्द्र खोले गए। इनकी क्षमता ७० लाख टन वार्षिक थी।

विद्युत शक्ति और यातायात के साधनों में प्रगति हुई। दूसरी योजना में २,५०० मील लम्बी नई रेल लाइन बनाई गई थी। तीसरी योजना में ७,००० मील लम्बी नई रेल लाइन बनाने की व्यवस्था थी। युद्ध में भाग लेने से पहले निर्माण कार्य पूर्व निश्चित योजनानुसार हो रहा था। योजसा में व्यय

की जाने वाली धन-राशि का १५% उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला था। यह धन-राशि पहली योजना के बराबर थी। बड़े उद्योगों की ओर सरकार का ध्यान अपेक्षया अधिक था। स्त्री वस्त्र उद्योग पर कम जोर दिया गया था फिर भी दूसरी योजना की अपेक्षा १० लाख मीटर कपड़ा अधिक बनाया जाने वाला था।

तीसरी योजना के आरम्भिक ३ वर्षों में देश काफी आगे बढ़ा। चमड़ा ४३%, चीनी, ४४%, कागज और डिब्बे में बन्द खाद्य पदार्थ ५६% अधिक उत्पन्न किये जाने लगे। स्मरणीय है बड़े उद्योगों की वृद्धि का अनुपात छोटे उद्योगों का तिगुना था। बड़े उद्योगों में ५०% वृद्धि हुई थी किन्तु हाथ करवा जैसे लघुस्तर उद्योगों में १२% से अधिक वृद्धि न हो सकी थी। १९५० में १८३ लाख टन इस्पात उत्पन्न किया गया था जो १९३८ से केवल ३ लाख टन अधिक था। समष्टि में उपभोग के पदार्थों में ३३%, कुल उत्पादन में ४४%, पूँजी-व्यवसाय में ५०% और कुल राष्ट्रीय आय में ३०% की वृद्धि हुई। तीन वर्षों की प्रगति के आंकड़े देखते हुए कहना पड़ता है कि यदि युद्ध न हुआ होता तो ये लोग शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते।

युद्ध जनित क्षति

प्रायः सभी विकासोन्मुख देश आजादी के बाद भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की उपेक्षा कर उन्हीं क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल देते हैं जहाँ पहले से उत्पादन कार्य होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में पहले तो उद्योग धन्धों का स्थानीयकरण होता है फिर धीरे-धीरे अनेक पुरक उद्योग भी उन्हीं क्षेत्रों में पनप उठते हैं। फलतः उस क्षेत्र विशेष के छोटे शहर कालान्तर में बड़े शहरों का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। देश के दूसरे भागों की जनसंख्या और पूँजी का उसी क्षेत्र में स्थानान्तर होता है। यदि क्षेत्रीय सर्कीरता की भावना राष्ट्रीय भावनाओं पर हावी न हो जाय और शान्ति का वातावरण बना रहे तो उद्योगों का स्थानीयकरण बुरा नहीं है किन्तु ऐसा होता नहीं है।

जार युग में यूरोपीय भाग औद्योगिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ा था। क्रान्ति के बाद भी यूरोपीय प्रदेश के उद्योग धन्धों पर विशेष बल दिया।

धीरे-धीरे देश की समृद्धि इसी ओर खिंच आई। जर्मनी के आक्रमण से पूर्व स्थानीयकरण की बुराइयों की ओर देश का ध्यान ही नहीं गया था। जब जर्मन सेनायें तूफानी वेग से आगे बढ़ने लगीं तब सोवियत सरकार को वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ। युद्ध के आरम्भक वर्षों में औद्योगिक महत्व के प्रायः सभी स्थान खोकर देश की अर्थ-व्यवस्था पंगु होते होते बची।

स्तालिनग्राद, वेलोरेशिया, उक्रेन जर्मन सेना के अधिकार में चला गया। देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों पर जर्मनी का अधिकार हो गया।

लेनिनग्राद पट्टुचकर जर्मनी की प्रगति मंद पड़ गई क्योंकि उस समय तक सोवियत सरकार ने अपने को काफी संभाल लिया था। उक्रेन, दानेत्स, दान, उत्तरी काकेशिया, क्रिमिया और स्तालिनग्राद के औद्योगिक क्षेत्र युद्ध की लपटों में भुलस गए।

कोयले के उत्पादन में ६०% और इस्पात के उत्पादन में ५०% की कमी हो गई। ४०% कृषि क्षेत्र, २२% इंजीनियरिंग उद्योग, ६०% चीनी के क्षेत्र, ३ अल्युमिनियम उद्योग और आधे सूअर जर्मनी के अधिकार में चले गए। मिट्टी के तेल के अधिकांश क्षेत्र सोवियत सङ्घ के ही पास थे पर युद्ध जनित कठिनाइयों के कारण तेल निकाला नहीं जा सकता था। युद्ध के वर्षों में मिट्टी के तेल का उत्पादन युद्ध पूर्व वर्षों का प्रायः आधा हो गया।

सबसे अधिक परेशानी यातायात के साधनों की न्यूनता के कारण थी। सैनिक आवश्यकताएँ तो थीं ही उद्योग धन्धों और जनसंख्या को भी स्थानान्तरित करना पड़ रहा था। एशियाई रूस में सड़कों तथा आवागमन के साधनों का नितान्त अभाव था। चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना से पहले स्थिति नहीं सुधारी जा सकी थी।

युद्ध से सोवियत सङ्घ के २,००० शहर, ७०,००० गांव और ४० लाख व्यक्तियों की जीविका के साधन उद्योग नष्ट हो गए। ढाई करोड़ व्यक्ति गृह हीन हो गए थे। लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्ति देश के काम आए। युद्ध के

कारण शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की गणना नहीं की गई है। स्मरणीय है सम्पूर्ण यूरोप में इसका आधा ही नष्ट हुआ था।

योजना का नया मोड़

जैसा पहले कहा जा चुका है युद्ध छिड़ते ही तीसरी योजना समाप्त कर दी गई। जिस शीघ्रता, साहस और आत्मविश्वास के साथ योजना का प्रारूप बदला गया वह इतिहास में अपनी मिसाल नहीं रखता।

१—सैनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई। युद्ध सामग्री का उत्पादन द्रुत गति से होने लगा। वस्त्र खाद्यान्न पहले सैनिक शिविरों में भेजे जाते थे। युद्ध काल तक जनता के जीवन मापन की चिन्ता से सरकार ने अपने को मुक्त कर लिया।

२—वार्षिक योजनाओं के अतिरिक्त अनेक अर्द्ध वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक योजनायें कार्यान्वित की गईं।

३—प्रायः सभी क्षेत्रों में केन्द्रीकरण की पद्धति अपनाई गई। प्रशासन का ढांचा लगभग तानाशासी जैसा था।

४—उत्पादन बढ़ाने के लिए समाजवादी प्रतिस्पर्धा (Socialist Competition) की नीति अपनाई गई। निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन करने वाले कारखानों, प्रबन्धकों और मजदूरों को अत्यधिक आर्थिक पुरस्कार दिया गया। उत्पादन के किस्म की गिरावट रोकने के लिए दण्ड की भी व्यवस्था की गई। १९४० ई० में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार जान-बूझकर कम उत्पादन करने वाले और खराब किस्म का माल बनाने वालों को ५-८ वर्ष तक कारावास की सजा दी जा सकती थी। सुरक्षा के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में खराब उत्पादन की बड़ी शिकायत थी।

दण्ड और पुरस्कार की नीति के कारण श्रमिकों की उत्पादकता में ६५% वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन ८८५ करोड़ रूबल अधिक हुआ।

५—सबसे अद्भुत बात थी उद्योग धन्धों और जनसंख्या का एशियाई रूस में स्थानान्तरण। जर्मनी के आक्रमण के बाद निरन्तर बढ़ती जर्मनी

सेनाओं के भीषण शस्त्रास्त्रों के बीच से एक वर्ष के अल्प समय में ही प्रायः डेढ़ हजार मोटर, वायुयान और इंजन आदि बनाने वाले बड़े कारखाने एक हजार मील पूरब उठा लाए गए। वितरण के प्रश्न की उपेक्षा कर देश प्रेम का दम भरने वालों के आगे सोविन्नत कारखानों का स्थानान्तरण और पुनर्स्थापन एक अभूतपूर्व उदाहरण है। अपनत्व की भावना के अभाव में ऐसा होना संभव नहीं है।

युद्ध कालीन अर्थ व्यवस्था

युद्ध के आरम्भिक वर्षों में सोवियत अर्थ व्यवस्था भयंकर भंभावात के बीच पाम के वृद्ध के समान थी। तूफान का कौन भोंका उसे समूल उखाड़ देगा यही जानने की सबको जिज्ञासा थी। सोवियत सङ्घ की भौगोलिक स्थिति भी कुछ इस प्रकार की थी कि मित्र राष्ट्रों से उसे पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। युद्ध के आरम्भिक दो वर्षों में कृषि उत्पादन में ४३% और औद्योगिक उत्पादन में २७% की कमी हो गई।

विस्थापितों के आवास और कारखानों की इमारत की समस्या लकड़ी से सुलभ ली गई। काठ के घरों का भारी संख्या में निर्माण हुआ। पूर्वी प्रदेशों में काम चलाऊ कच्ची सड़कें बहुतायत से बनाई गईं। नए क्षेत्रों में मुख्यतः साइबेरिया में जीवन यापन कठिन था। प्रायः सभी कुशल श्रमिक सैनिक बना लिये गए। कारखाने चलाने के लिये श्रमिकों के अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। अल्प समय में ही नये श्रमिकों ने अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया।

मास्को के निकट तोप के गोले, गोलियां, बम, बारूद तथा रासायनिक पदार्थयुक्त अन्य आवश्यक युद्ध सामग्री बनाने का कारखाना खोला गया। यूराल पर्वत पर टैंक और मोटरों आदि बनाई जाने लगी।

वोला, यूराल और दूर पूर्व साइबेरिया में जर्मन अधिकृत प्रदेशों के निवासी और कारखाने ले जाए गए। वोल्गा प्रदेश में हलके उद्योग के कारखाने खोले गए। इस्पात उद्योग पर अधिक ध्यान दिया गया। युद्ध काल में १६३७ की अपेक्षा ५०% अधिक इस्पात का उत्पादन किया जाने लगा।

१९४२ की ग्रीष्म ऋतु में स्थिति अनुकूल हो गई। जर्मन सेनाएँ लाख प्रयत्न के बावजूद भी आगे न बढ़ सकी। १९४३ ई० में यहाँ वायुयान और टैंक जर्मनी से अधिक बनाया जाने लगा था।

इस बीच जर्मनी ने प्रायः सम्पूर्ण मध्य यूरोप और उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। इतने बड़े प्रदेश पर युद्ध काल में शासन करना मुट्टी भर जर्मनों के बस की बात नहीं थी। महाड़ से सिर टकराने का जो परिणाम होता है उनका भी हुआ। जर्मनी की विवशता से मित्र राष्ट्रों ने लाभ उठाया। मान से खदेड़े हुए खरगोश की तरह जर्मन सेनाएँ असहाय हो गईं।

अब युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी की हार पर हार हो रही थी। जैसे जैसे लाल सेनाएँ आगे बढ़ती गईं पुनिर्माण कार्य होता गया। साइबेरिया और त्रांसवाल क्षेत्र में गेहूँ उत्पन्न किया जाने लगा। कजाकरतान में चुकन्दर की चीनी बनाई जाने लगी। सोवियत सङ्घ के १९४४ का उत्पादन १९४० की अपेक्षा १४% अधिक था। १९४५ तक युद्ध पूर्व वर्षों की तुलना में यहाँ आ चुकी थी।

अध्याय १३

चतुर्थ, पंच वर्षीय योजना

द्वितीय विश्व युद्ध की परिसमाप्ति के बाद विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त उलट-फेर हुआ पराजित राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पंगु होकर निरीह हो ही गए थे विजेताओं की भी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। युद्ध से लौटे सैनिकों को पुनिर्माण कार्यों में लगाना टेढ़ी खीर थी। यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति समान योग्यता से अनेक कार्य कर सके। सैनिकों को किसी अन्य काम पर लगाने से पहले उन्हें प्राशिक्षित करना आवश्यक था किन्तु इस कार्य के लिए न धन था, न समय। औद्योगिक दृष्टि से परावलम्बी राष्ट्रों को विदेशों से कच्चा माल और खाद्यान्न मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक था जिसका समाधान उनके नष्ट प्राय उद्योगों के पास न था। प्रायः सभी देशों में युद्ध के बाद अनिवार्य रूप से आने वाले अवसाद की स्थिति थी; प्रत्येक देश औद्योगिक थकान का अनुभव कर रहा था।

सोवियत सङ्घ भी दशा अन्य देशों से भिन्न थी। नियोजित अर्थ व्यवस्था की दिशा में वह तीन बड़े पग रख चुका था। उद्योग और कृषि के क्षेत्र में पूँजीपति और जमींदार समाप्त किए जा चुके थे व्यापार के क्षेत्र से निजी व्यवसायी और सट्टेबाज हटा दिये गए थे। युद्ध के ठीक बाद की संक्रमण कालिक परिस्थिति उसके लिए नहीं थी, स्वतंत्रता के शैशव में ही वह इन परिस्थितियों को झेल चुका था। चतुर्थ योजना की गर्वोक्तियों में आत्म विश्वास का भी योग है। आजादी के कुछ वर्षों में ही सोवियत सङ्घ उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जहां टैंकों और विमानों का बनाना नहीं सा था वहां द्वितीय विश्व युद्ध में प्रतिवर्ष ३० हजार टैंक, स्वयं चालित तोपें और ४० हजार विमान बनाए जाने लगे थे। युद्ध बीत जाने पर अब देश को युद्ध की अर्थ नीति से शान्ति के आर्थिक विकास के काल में प्रवेश करना था। श्री स्तालिन के शब्दों में “सोवियत जनता के अब काम हैं—

१—अधिकृत स्थानों को दृढ़ करना ।

२—फिर नई आर्थिक सफलताओं की ओर बढ़ना ।”

युद्ध में सोवियत सङ्घ की साख युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा बहुत बढ़ गई । देश के पूर्वी भाग में उद्योग धन्धों का प्रसार होने के कारण उसकी अर्थ-व्यवस्था में भी सन्तुलन आया । क्रान्ति पूर्व वर्षों में देश भर में ३३ अरब रूबल का वृहद् स्तर उत्पादन होता था जो १९४२-४४ में ग्यारह गुना बढ़ गया (३,६१ अरब रूबल) । देश के औद्योगिक विकास की पृष्ठ भूमि बन चुकी थी आवश्यकता थी युद्ध कालीन उत्पादन को शान्तिपूर्ण अर्थ व्यवस्था की दिशा में मोड़ देने की । इसी मूल उद्देश्य की सिद्धि के लिए चतुर्थ पंचम वर्षीय योजना बनाई गई थी ।

राज योजना कमीशन के प्रधान न० अ० वोज्नेशन्स्की ने १५ मार्च १९४६ को सोवियत पार्लियामेंट के सम्मुख चतुर्थ योजना का प्रारूप रखा जो तीन दिन के विचार विमर्श के बाद १८ मार्च को स्वीकार कर ली गई ।

योजना के उद्देश्य

१—औद्योगिक उत्पादन को युद्ध पूर्व वर्षों का डेढ़ गुना बढ़ाना । युद्ध सामग्री उत्पन्न करने वाले औद्योगिक संस्थाओं का शान्ति कालोपयोगी उत्पादन में लगाना और भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल देना ।

१—भारी उद्योग - भारी उद्योग से आशय आधारित उद्योग से है । ऐसे उद्योग जिनके अभाव में उत्पादन हो ही न सके । उदाहरणार्थ लोहा कोयला इस्पात आदि का उत्पादन तथा ऊन की लच्छियां और कपड़ा बनाने अथवा चमड़ा भिभाने वाली मशीने बनाने के कारखाने भारी उद्योग हैं ।

हलके उद्योग -- भारी उद्योग से उत्पन्न सामग्री तथा मशीन के द्वारा उत्पादन करने वाले उद्योग हलके उद्योग हैं । उदाहरणार्थ कपड़ा बनाने वाली मशीन बनाने का कारखाना भारी उद्योग होगा और उस मशीन से कपड़ा बुनने का कारखाना हलका उद्योग । स्मरणीय है ये शब्द वृहद्-स्तर और लघु स्तर उत्पादन के पर्याय नहीं हैं ।

२—सोवियत नागरिकों के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाने के लिए

उपभोग सामग्रियों को प्रचुर मात्रा और परिमाण में उत्पन्न करना और रूबल का मूल्य स्थिर रखना ।

३—उत्पादन और कार्य क्षमता की वृद्धि के लिये टेकनिकल प्रगति आवश्यक है । उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग किया जाय ।

४—समाजवादी पूँजी का संचय और इस अधिकृत पूँजी में १२% वार्षिक की वृद्धि ।

ध्वस्त कारखानों के पुनिर्माण के लिये २५० अरब रूबल और २३४ अरब रूबल नये कारखानों के निर्माण में लगाया जाय ।

५—अधुनातन हथियारों से सेना को सुसज्जित करना ।

६—वर्गहीन समाजवादी समाज का निर्माण और क्रमशः समाजवाद के साम्यवाद में परिवर्तन ।

७—नये भवनों का पुनिर्माण और नव निर्माण । मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों की आर्थिक सहायता प्रदान करना । मजदूरों के अतिरिक्त लाभार्थ का अनुपात बढ़ाना ।

८—काम के अधिकतम ८ घण्टे । मिहनत के कार्यों से मशीनों का आधिकाधिक प्रयोग

९—प्रारम्भिक माध्यमिक उच्च तथा शिल्प विद्यालयों का निर्माण ।

उद्योग

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (१९५०) औद्योगिक उत्पादन का कुल योग २०५ अरब (१९२६-२७) के मूल्य के अनुसार निश्चित हुआ जो १९४८ के कुल उत्पादन के मूल्य से ४८% अधिक था ।

१९५० में कुछ प्रमुख उद्योगों का उत्पादनस्तर अधोलिखित होगा—

२ लोहा-फौलाद आदि

२- १९५० में उद्योग की प्रधान-प्रधान शाखाओं का उत्पादन-तल निम्न प्रकार होगा ।

(क) लोहा-फौलाद

लोहा (टन)	१.९५,००,०००
फौलाद (टन)	२,९४,००,०००

रोल क्रिया माल (टन)	१,७८,००,०००
---------------------	-------------

(ख) ईंधन और विजली

कोयला (टन)	२,५०,०००,०००
पेट्रोल (टन)	३,५४,००,०००
कोयला-शेल-गैस (घनमीटर)	१,६०,००,००,०००
स्वाभाविक गैस (घनमीटर)	८,४०,००,००,०००
विजली (किलोवाट)	८२,००,००,०००

(ग) रेल-यातध्यात

दूरगामी भाप-इंजन	२,२००
” डीजल-इंजन	३००
” विजली-इंजन	२२०
माल-डब्बा (दो धुर वाले डब्बे में)	१,४६,०००
मुसाफिर-गाड़ी के डब्बे	२,६००

(घ) मोटर गाड़ियाँ

ट्रक	६,२८,०००
पसिंजरकार	६५,६००
मोटर-बस	६,४००

(ङ) फैक्ट्री का सामान

लोहा फौलाद मिलों का सामान (टन)	१,००,६००
भाप-टर्बाइन (किलोवाट)	३६,०६,०००
जल-टर्बाइन, बड़ी (किलोवाट)	३,७२,०००
” मझोली (”)	१,५०,०००
” छोटी (किलोवाट)	५,००,०००
विजली मोटर (१०० किलोवाट तक)	६,२४,०००
” (१०० किलोवाट से ऊपर)	६,०००
घातु के काम वाली मशीन	७४,०००

कताई फ्रेम (तकुआ)	१४,००,०००
कर्घा	२५,०००

(च) कृषि-मशीन

ट्रेक्टर	१,१२,०००
ट्रेक्टर से खींचा हल	१,१०,०००
” जोतक	८२,३००
” बंधक	८३,३००
स्वयंचालित दाँवक	१८,३००

(छ) रसायनिक और खनिजक खाद

कास्टिक सोडा (टन)	३,६०,०००
कलकाइन सोडा (टन)	८,००,०००
खनिज खाद (महाफास्फोर्स, निट्रेट, पोटास) (टन)	५१,००,०००
कृत्रिम रंग (टन)	४३,०००

(ज) काष्ठ और गृह-सामग्री

कटा काष्ठ (घन-मीटर)	२८,००,००,०००
चिरा काष्ठ ”	३,६०,००,०००
सीमेंट (टन)	१,०५,००,०००
स्लेट (पटिया)	४१,००,००,०००
खिड़की का कांच (वर्गमीटर)	८,००,००,०००

(झ) कपड़ा और हलका उद्योग

सूती कपड़ा (मीटर)	४,६८,६०,००,०००
ऊनी कपड़ा ”	१५,६४,००,०००
चमड़े का जूता (जोड़ा)	२४,००,००,०००
रबर का जूत ”	८,८६,००,०००
मोजा ”	१८,००,००,०००

(ब) खाद्य-सामग्री

मांस (टन),	१३,००,०००
मक्खन (टन)	२,७५,०००
तेल (टन)	८,८०,०००
मछली (टन)	२२,००,०००
चीनी (टन)	२४,००,०००
आटा (टन)	१,६०,००,०००
शराब (१० लीटर)	१०,०८०,०००
साबुन (टन)	८,७०,०००

३. उत्पादन की वृद्धि की योजना के अनुसार १९४६-५० में सोवियत सङ्घ के उद्योग-वन्धे के निर्माण में १ खरब ५७ अरब ५० करोड़ रूबल (१९४५ के मूल्य से) पूँजी लगोगी।

लोहा और इस्पात

लोहा और इस्पात आधारीक उद्योग है। युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा इसमें ३५% वृद्धि होगी।

१९५० तक लोहे और इस्पात की भट्टियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। १६२ लाख टन क्षमता वाले ६० बिजली के भट्टे, १८० लाख टन क्षमता वाले ४५ धौंकनी के भट्टे, १६५ खुले भट्टे, १५ परिवर्तक, १६१ लाख टन क्षमता वाले कोकवैट्री काम करेंगी। इनमें से कुछ का परिष्कार किया जायगा और कुछ बिलकुल नए सिरे से बनाई जायेंगी। सब भट्टियों का सम्मिलित उत्पादन ३,५४ लाख टन वार्षिक होगा।

गुर्जा, कजाक स्तान, आज़ुबाइजान और लेनिन-ग्राद में १-१ लोहे के नये कारखाने खोले जायेंगे। लोहे की नई खानों की शोध की जायगी। दक्षिणी क्षेत्र में लोहे की चदरें बनाई जायेंगी। उच्च तापमान तथा दबाव वाले ग्वाय-लरों तथा टर्बाइनों के लिये अच्छे किस्म का इस्पात बनाया जायगा।

१९५०वर्षीय पञ्चवर्षीय योजना के आंकड़ों के लिये हम श्री राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक सोवियत भूमि के आभारी हैं।

लौहैतर धातु उद्योग

अधुनातन वैज्ञानिक साधनों द्वारा अलुमिना तथा बहुमूल्य धातुओं (सोना आदि) के उत्पादन में वृद्धि की जायगी। योजना के अंत में तांबे के उत्पादन में १.६ गुना, अल्युमिनियम में दो गुना, निकल में १.६ गुना, सीसा में २.६ गुना, रांगा में २.२५ गुना, टिन में २.७ गुना वृद्धि होगी।

तांबे के कारखानों की कार्य-क्षमता बढ़ाई जायगी। कजाकस्तान और दक्षिणी उराल में तांबे के एक-एक कारखाने बनाये जायेंगे।

पश्चिमी क्षेत्र की दो ध्वस्त-अल्युमिनियम मिट्टी (बाक्साइट) की खाने, दो अल्युमिनियम कारखाने और एक अल्युमिनियम प्लांट के ध्वंसावशेष को फिर से बनाया जायगा। कुजनेत्स बेसिन, उत्तरी उराल के कारखानों की कार्य-क्षमता बढ़ाई जायगी। अल्युमिनियम के कारखानों में काम आने वाले कच्चा माल निकेलिन और अलुनाइट के कारखानों की स्थापना की जायगी।

उत्तरी काकेशस में वोल-फ्रम् और मोलिब्डेनम् का कारखाना खोला जायगा। ताँबा, शीशा, बाक्साइट, निकल, वोलफ्रम्, मोलिब्डेनम् के धातु पाषाणों के कच्चे माल का उत्पादन और संचय बढ़ाया जायगा।

कोयला

कोयले का उत्पादन युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा ५१% बढ़ जायगा। दोनेत्स कुजनेत्स्क करगन्दा, किजिल, पेचोरा, त्कूर, त्कचर्चेली आदि कोयला क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाकर ५७७ लाख टन कर दिया जायगा। दोनबास में १६५० तक ८८० लाख टन कोयला निकाला जायगा। क्षेत्रीय उद्योगों के लिये बाहर से कोयला न मंगाने की कोशिश की जायगी जिससे उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कोयले से ही काम लिया जाय।

कोयले की खानों में खुदाई का काम अस्वास्थ्य कर है। भारी मिहनत के कामों के लिये मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जायगा। मशीनों का प्रयोग प्रायः तिगुना या चौगुना होने लगा। मशीनों की कमी को पूरा करने के लिये मशीन निर्माण के १३ नये कारखाने खोले जायेंगे और १६ पुराने कारखानों

का काम बढ़ाया जायगा। १ करोड़ टन वार्षिक क्षमता वाले नये कोयला ब्रिकेट प्लांट बनाये जाएंगे।

पीट

१९५० में पीट का उत्पादन ४,४३ लाख टन होगा जो युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा २६% अधिक होगा। पीट निकालने और उसके टेकनोलाजिकल और रासायनिक क्रिया को यंत्र द्वारा ही करने का प्रयत्न किया जायगा।

गैस

कारखानों में शक्ति के रूप में गैस का प्रयोग किया जायगा। स्वाभाविक गैस तथा कोयला, पीट और शेल की विशिष्ट रासायनिक प्रकृतियों द्वारा बनाई गई गैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जायगा। १९५० तक स्वाभाविक गैस का उत्पादन ८,४० करोड़ घन मीटर और शेल गैस का उत्पादन १,६० करोड़ घनमीटर बढ़ा दिया जायेगा। गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

पेट्रोल और मिट्टी का तेल

पेट्रोल और मिट्टी का तेल निकालने और साफ करने का काम १९४६ तक युद्ध पूर्व स्तर तक पहुँच जायगा और १९५० में आगे बढ़ जायगा। नये क्षेत्रों की तलाश के लिए भूगर्भीय सर्वे और प्रारम्भिक काम किये जायेंगे। पेट्रोल निकालने, संचित करने और स्थानान्तरित करने के लिये वायु शून्य पाइपों का प्रयोग किया जायगा। मोटर और बस में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल, ट्रैक्टर के किरासिन और डीजल इंजन के तेल का उत्पादन बढ़ाया जायगा। तेल साफ करने के लिए ४ तेल शोधक प्लांट और १६ तेल शोधानियां बनाई जाएगी।

बिजली

युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा ७०% बिजली अधिक पैदा की जाएगी। युद्ध में ध्वस्त विद्युत शक्ति स्टेशनों को ठीक किया जायगा। और नये स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

योजना के अंत तक ३० नये जल-विद्युत केन्द्र काम कराने लगेंगे। उद्योगों के अतिरिक्त रेल और कृषि के क्षेत्र में भी बिजली का उपयोग किया जाएगा। कुछ नगर पालिकायें मकान गर्म करने के लिए भी जल-विद्युत का प्रयोग करेंगी।

मशीन निर्माण

मशीन निर्माण के क्षेत्र में युद्ध पूर्व वर्षों की दूनी प्रगति होगी। लोहा, इस्पात, कोयला, तेल के कुएँ और शक्ति उत्पादन केन्द्रों में प्रयुक्त मशीनों का निर्माण किया जायगा। मोटर, रेल, ट्रैक्टर के इंजन, दलाई की मशीनें, खानों में सर्वे के काम आने वाले यंत्र बनाए जायेंगे।

योजना काल समाप्त होते-होते, ४००० इंजन, २ लाख माल गाड़ी के डिब्बे, १,३१,००० टन लोहा इस्पात, मिल के सावन यंत्र ३७,७०,००० किलोवाट वाष्प युक्त टर्बाइने ५,४०,००० वर्ग मीटर गर्म करने के धरातल वाले वायलर १,३३,००० ट्रैक्टर, ६४,८०० मशीन टूल, ७.५ लाख मोटरें बनाई जाएगी।

मोटर गाड़ियों का उत्पादन क्रमशः बढ़ता-बढ़ता १९५० में ५ लाख वार्षिक हो जायगा। इसी प्रकार ट्रैक्टरों का उत्पादन १,१२,००० वार्षिक होने लगेगा। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले बोआई, कटाई, दवाई आदि के यंत्र बनाए जाएँगे।

रसायनिक उद्योग

रसायनिक उद्योग में डेढ़ गुने की वृद्धि होगी।

यूरोपीय सोवियत के ध्वस्त उद्योगों का पुनिर्माण किया जायगा। पहले नाईट्रेट, शोरा, फारफेट और रंग का उत्पादन होगा प्लास्टिक, एनीलाइन रंग बार्निश, पेंट, गन्धकी तेजाब, सोडा आदि का उत्पादन बढ़ाया जायगा।

रबर

१९५० में युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा कृत्रिम रबर का उत्पादन दूना, मोटर-टायर का तीन गुना, रबर के जूतों का १.३ गुना हो जायगा।

खाद्य पार्दर्थ

६२ चीनी की मिलों, १४४ शराब के कारखानों, २४ टिन बंदी के कारखानों और ६८ यंत्र चालित रोटी कारखानों को पूरी तरह फिर से स्थापित किया जाएगा और १० नये चीनी के कारखानों, ७ शराब के कारखानों ६ टिन बंदी कारखानों और ३६ यंत्रचालित रोटी के कारखानों को बनाया जायगा ४१ मांस के टिन बंदी कारखानों, २६ बरफ में रखने के कारखानों, २२ नगर की दूध तैयार करने वाली फैक्ट्रियों और ८ दूध को टिन में बन्द करने वाली फैक्ट्रियों को नये सिरे से तैयार किया जायगा । ३६ नये मांस पैक करने वाले प्लान्टों, ३८ बरफ में रखने वाले कारखानों, ४८ दूध तैयार करने वाली फैक्ट्रियों १३ दूध को डिब्बे में बन्द करने वाली और १२०० मक्खन और पनीर की यंत्र चालित फैक्ट्रियों को बनाया जायगा । नमक १४ लाख टन वार्षिक बनाया जायगा । उक्रइन्, उराल, कजाकस्तान अल्ताई प्रदेश और इकुत्स्क जिले के नमक के कारखानों की कार्य-क्षमता दूनी कर दी जायेगी । मछली मारने के १५० जहाज बनाए जायगे । १६५० के अन्त तक देश की आटा मिलें प्रतिदिन २०,००० टन अधिक आटा पीसने लगेंगी ।

योजना के ५ वर्षों में उद्योग धन्वों के निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ते चरण निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेंगे :—

(आधार वर्ष १६४० = १००)

वर्ष	सम्पूर्ण उद्योग	भारी उद्योग	हलके उद्योग और उपभोग्य वस्तुएँ
१६४०	१००	१००	१००
१६४५	६२	११२	५६
१६४६	७७	८२	६७
१६४७	६३	१०१	८२
१६४८	११०	१३०	६६
१६४९	१४१	१६३	१०७
१६५०	१७३	२०५	१२३

सोवियत सङ्घ उत्पादन का संतुलन बनाए रखने की दिशा में सर्वदा प्रयत्नशील रहा। १९४६-४७ में भारी उद्योगों के हास का यही कारण है। इन दो वर्षों में वह उपभोग वस्तुओं की कमी पूरा करता रहा।

कृषि

बरसाती नदी के समान प्रबल वेग से निर्वाध आगे बढ़ने वाली जर्मन सेना से बचाकर आधे तीहे उद्योग मध्य और पूर्वी भाग में जैसे तैसे ले जाए गए किन्तु कृषि की बड़ी क्षति हुई। जर्मनी के अधिकार में ८ लाख वर्ग भूमि चले जाने से सोवियत सङ्घ कृषि उत्पादन की दिशा में लगभग पंगु हो गया। भीषण गोलाबारी के कारण भूमि की उर्वरा नष्ट शक्ति हो गई। १० लाख सामुदायिक फार्म, १५ लाख ट्रैक्टर और ५० हजार हारवेस्टर मशीनें पूर्णतः नष्ट हो गईं। सबसे अधिक क्षति पशुओं की हुई।

चतुर्थ योजना में इतनी हानि सह चुकने के बाद भी इसे पूरा कर योजना के अन्त तक २७% की वृद्धि का निश्चय किया गया। २० अरब रूबल की धन राशि कृषि के विकास के लिए सुरक्षित रखी गई। गेहूं, चावल और फल की उपज पर विशेष ध्यान दिया गया। अन्तिम वर्ष की वार्षिक उपज १२,७० लाख टन और प्रति हेक्टर उपज १२ सेन्तनेर हीगी।

औद्योगिक फसलों का उत्पादन निम्न होगा:—

फसल	प्रति हेक्टर उत्पादन	कुल उत्पादन
चुकन्दर की चीनी	१६० मीटरिक सेन्तनेर	२,६० लाख टन
कच्ची कपास	१८.४ सेन्तनेर	४१ ”
फ्लेक्स का सन	४ ”	८ ”
सूर्यमुखी का बीज	१० ”	४७ ”

हेम्प (एक प्रकार का जूट) तेलहन और तम्बाकू के क्षेत्रों का पुनिर्माण और परिष्कार किया जायगा।

पशु पालन

योजना के ५ वर्षों में घोड़ों में ४६%, गायों में ३६%, भेड़ बकरियां ७५%

और सूअरों में ३००% की वृद्धि होगी। मुर्गी पालने वाले फार्मों में बड़ी संख्या में अंडा सेने की मशीनों (इन्क्यूबेटर) की व्यवस्था की जायगी। डेरी फार्मों की गाए ६७% अधिक दूध देंगी। भेड़ों के औसत ऊन में ३०% की वृद्धि होगी।

मारने से पहले पशुओं को विशिष्ट चारा और मोटा करने की गोलियाँ दी जायेंगी कल्चरवोजी किसानों, व्यक्तिगत किसानों फैक्टरी और आफिस के कर्मचारियों को यथेष्ट मात्रा में मुर्गी और खरगोश पालने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा।

यातायात

सोवियत संघ के यातायात का प्रमुख साधन रेल और नदियाँ हैं। यूरोपीय सोवियत का यातायात युद्ध काल में समाप्त हो गया था। चतुर्थ योजना में सभी टूटे और विशृंखलित यातायात के साधनों को मिलाया गया। यूरोपीय क्षेत्र में यातायात युद्ध पूर्व वर्षों के स्तर तक लाने और एशियाई भाग में वृद्धि करने की योजना बनाई गई।

रेल

१९५० में १,१५,००० रेल के चार वाहक डिब्बे प्रतिदिन कार्य करेंगे और उनसे ५,३२ अरब टन माल उस वर्ष ढोया जायगा।

प्रायः सभी मुख रेलों को आधुनातन वैज्ञानिक साधनों से सुसजित किया जायगा। रेल के इंजनों में ईंधन के रूप में बिजली और डीजल का प्रयोग होगा। रेलों के विक.स में ५,१० करोड़ रूबल की पूंजी लगाई जायगी।

रेल के साधनों में ६१६५ दूरगामी वाष्प इंजनों, ५५५ दूर गामी बिजली इंजनों, ८६५ दूरगामी डीजल इंजनों, ४७२,५००० माल के डिब्बों की और ६२० सवारी के डिब्बों की वृद्धि की जाएगी। क्षति ग्रस्त रेल के डिब्बों की मरम्मत की जाएगी। १९४८ तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाने वाली रेल की लाइनों का पुनिर्माण किया जा चुका था और जहाँ रेल की लाइने नहीं थी, नई बना दी गई थी। १५०० रेलवे स्टेशन, १३०० इंजन-घर और

१२८ डिब्बा मरम्मत करने के कारखाने या तो मरम्मत किये गए या नए सिरे से बनाए गए। रेलवे कमकरो को रहने के लिए ५० लाख वर्ग मीटर फर्श के मकान बनाए गए।

जल यातायात

आन्तरिक जल यातायात में ३८% की वृद्धि होगी।

जर्मनी द्वारा विजित प्रदेश का जल यातायात युद्ध पूर्व वर्षों जैसा कर दिया जायगा। १९४८ तक दिनमेपर, प्रिपेन, दोन, कूबन, नीमन पश्चिमी द्वीना और स्विर् नदियों और लदोगा तथा ओनेगा भीलों के सारे स्टीमर बन्दरगाह पहले की तरह बना दिए गए।

नदियों के वर्तमान घाटों को पहले से अच्छा बनाया गया। नावों और जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने का ७५% काम मशीनों द्वारा किया जाने लगा।

आन्तरिक जल यातायात के जहाजों में ३ लाख अश्व शक्ति की वृद्धि होगी। जहाज बनाने के ५ कारखाने खोले जायेंगे।

समुद्र में माल की ढुलाई युद्ध पूर्व वर्षों की २.२ गुनी हो जायगी। व्यापारिक जल पोतों में ६ लाख टन की वृद्धि होगी। अजोफ, काला और बाल्तिक सागर के ध्वस्त बन्दरगाह युद्ध पूर्व अवस्था में लाए जाएंगे। मोटर गाड़ियां युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा दूनी हो जायगी। बड़े पैमाने पर डीजल इंजन, उच्च कम्प्रेशन गेसोलिन, गैस रिजर्वायर और गैस जेनरेटरो का प्रयोग होगा। ११,५०० किलोमीटर नए ढङ्ग की पूर्णतः नई सड़कें बनाई जाएगी।

वायुयान

वायु पथ का जाल १,७५ लाख किलोमीटर तक बढ़ा दिया जायगा। मुख्य वायु पथों पर यांत्रिक सुविधाओं के कारण रात को भी काम हो सकेगा। १६ हवाई अड्डों और २० मुसाफिरखानों का निर्माण होगा। सवारी और माल ढोने के अतिरिक्त खेती या जंगल के हानिकारक कीड़ों को मारने और भूधातवीय सर्वे के लिए भी वायुयानों का प्रयोग होगा।

योजना की सफलता

योजना काल में उत्पादन, मुख्यतः उत्पादक साधनों और भारी उद्योग के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली। औद्योगीकरण की दिशा में देश पूँजी-वादी देशों के स्तर तक पहुँचने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहा। हाँ, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि जिस अनुपात में उत्पादन अथवा राष्ट्रीय समृद्धि बढ़ी उस अनुपात में व्यक्तिगत (आय) अथवा उपभोग्य सामग्रियों की वृद्धि नहीं हुई। निर्धारित समय से पहले ही योजना का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। योजना की सफलता निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगी :—

आधार वर्ष १९४०	योजना का लक्ष्य	वास्तविक पूर्ति
राष्ट्रीय आय (१९२६-२७ के १००	१३८	१६४
मूल्य के अनुसार)		
मजदूर तथा कर्मचारी १००	—	१२६
औद्योगिक उत्पादन १००	१४८	१७३
रेल यातायात १००	१२८	१४६
विद्युत उत्पादन १००	१७०	१८६

अध्याय १४

पंचम पंचवर्षीय योजना

[१९५१-५५]

[यद्यपि सोवियत संघ के अधिनायक श्री स्तालिन की योजना काल में ही मृत्यु हो गई किन्तु इस आकस्मिक दुर्घटना का योजना के प्रारूप पर कोई विशिष्ट प्रभाव न पड़ा। सभी कार्य पूर्ववत् चलते रहे। पंचम पंचवर्षीय योजना का अध्ययन स्तालिन युग के अंतर्गत पूर्वमान्यताओं को ध्यान में रखते हुए करना अधिक न्याय संगत प्रतीत होता है।]

पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कोई नवीनता नहीं है। विगत योजनाओं की मान्यताएं ही इस बार भी दुहराई गईं। चतुर्थ योजना का अभि-प्रेत समाजवादी समाज की स्थापना था। हम देख आये हैं कि चतुर्थ योजना को लक्ष्य से अधिक सफलता मिली। दूसरे शब्दों में चतुर्थ योजना की परिसमाप्ति तक वे समाजवादी समाज स्थापित कर चुके थे। अब वे साम्यवाद की मंजिल की ओर जा रहे थे।

पांचवी योजना के आंकड़ों को देखने से विदित होता है कि वे १९५५ तक उस स्तर तक पहुँच जाना चाहते थे जहाँ यदि युद्ध न होता तो वे पहुँचते। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए अथक परिश्रम, लक्ष्य के प्रति आस्था और कष्ट सहिष्णुता की प्रवृत्ति अपेक्षित हैं। इस योजना में भी उत्पादक साधनों के उत्पादन और भारी उद्योगों पर पुनः बल दिया गया। इस योजना में कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों के व्यावहारिक पहलू के कार्यान्वयन का प्रयत्न हुआ।

अक्टूबर १९५२ की १९ वीं कांग्रेस की बैठक से पहले पांचवी योजना का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त न हो सका था। इस योजना का दो दृष्टियों से अधिक महत्व है :—

१ - औद्योगिक उत्पादन में विगत योजनाओं से कम (केवल ७२%) वृद्धि का निश्चय।

२—पूँजी के साधनों (Capital goods उत्पादन साधनों का उत्पादन) और उपभोग की वस्तुओं की दरार भरने का निश्चय हुआ। इस योजना में दोनों की प्रतिशत वृद्धि क्रमशः ८०% और ६५% थी।

योजना के निर्माताओं ने औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष १२% वृद्धि का अनुमान किया था। इस प्रकार १९५१-५५ तक देश का औद्योगिक उत्पादन ७२% बढ़ जाता किन्तु योजना को लक्ष्य से अधिक सफलता मिली। योजना के अन्तिम वर्ष तक ८५% वृद्धि हुई। पूँजी के साधनों (Capital goods) की वार्षिक वृद्धि का अनुमान १३% था। ५ वर्ष बाद कुल वृद्धि ८०% होने को थी पर वस्तुतः वृद्धि हुई ९१% की। इसी प्रकार उपभोग सामग्री का उत्पादन ११% वार्षिक अथवा योजना काल पूरा होने पर ६५% होने को था पर हुआ ७६%। पांचवी योजना में सुरक्षा के खर्च और कम हो गए थे। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी सोवियत सङ्घ के अनुकूल थीं।

१९५५ तक औद्योगीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े अधोलिखित हैं।

पदार्थ	प्रतिशत वृद्धि
१ - धातुएँ	
कच्चा लोहा	७६
इस्पता	६२
अलौह (Nonferrous Metal)	६४
जिस में :—	
तांबा	९०
सीसा	१७०
अल्युमिनियम	१६०
जस्ता	१५०
निकल	५३
टिन	८०

२—शक्ति

विद्युत	८०
जल-विद्युत	६८०
भाप के इंजन	१३०
वाष्प यंत्र	१७०

३—अन्य औद्योगिक पदार्थ

कोयला	४३
मिट्टी का तेल	१५०
सोडा भस्म	८४
कार्बोनाट सोडा	७६
खनिज खाद	८८
कृत्रिम रबर	८२
सीमेंट	१२०
लकड़ों	५६

४—उपभोग की वस्तुएँ

क—खाद्य पदार्थ	४०—५०
जिसमें :—	
चाय	७८
चीनी	८०
सूखी तरकारो	२५०
हरी तरकारी और फल	४०
दूध का पाउडर	१००

अन्य दूग्ध पदार्थ	६०
मक्खन	७२
मास	६२
मछली	५८
पनीर	११०
आलू, सूर्य मुर्खी के बाज	६५
ख—अन्ध	
सूती वस्त्र	६१
ऊना वस्त्र	५४
क्रित्रिम वस्त्र	३७०
जूता	५५
तम्बाकू	६०
भूसा	६०
हरा चारा	२००-३००

उत्पादन व्यय कम करने के लिये आवश्यक था कि औद्योगिक ईंधन के रूप में जल-विद्युत का यथासाध्य प्रयोग किया जाय। पांचवी योजना में जल-विद्युत क उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। पुराने जल-विद्युत केन्द्रों में अपेक्षित सुधार किया गया जिससे वे अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो सकें। अनेक नये जल-विद्युत शक्ति केन्द्र खोले गए। क्विवेशेवेव (Kuibyshev) जल-विद्युत केन्द्र की क्षमता २१ लाख किलोवाट थी। इसी प्रकार कामा, गोकर्ण, मिंगचार, उस्त कामेनोगोस्कर् आदि शक्ति केन्द्रों में प्रत्येक की क्षमता लगभग २० लाख किलोवाट थी।

मशीन निर्माण में यथेष्ट प्रगति की योजना थी। धातु मुख्यतः लोहा और इस्पात के बड़े-बड़े चक्के, धातुएँ बेलने, ढालने, गढ़ने अथवा पत्र बनाने के यंत्रों का विकास हुआ। रासायनिक पदार्थों में तेल की गैस, कृत्रिम रबर,

कृत्रिम अलकोहल, सल्फरिक एसिड, अमोनिया सल्फेड, सल्फरिक क्षार आदि की प्रगति उल्लेखनीय है।

विभिन्न उद्योगों में होने वाली वार्षिक वृद्धि के आंकड़े निम्न हैं —

	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
लोहा (लाख टन)	२१६	२५१	२७४	३००	३३३
इस्पात ,,	३१४	३४५	३८१	४१४	४१३
अलौह ,,	२४०	२६४	२६४	२२१	३५३
कोयला ,,	२,८१६	३,००६	३,२०४	३,४७१	३,६१०
तेल ,,	४२३	४७३	५२८	५६३	७०८
शक्ति (हजार किलोवाट)	१३.७	१४.६	१६.२	१८.६	३२.१

कृषि

कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए प्रायः सभी आवश्यक बातें दुहराई गईं जिनमें भूमि की उर्वरता में वृद्धि, खाद्यान्न तथा दूध से बनने वाले पदार्थों में वृद्धि, कृषि कार्य में यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग आदि प्रमुख हैं। किन्तु १९५३ तक कृषि की दशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति न हो सकी। चारे के अभाव के कारण गायों की संख्या तथा दूध और मांस के उत्पादन में भारी कमी हुई। भैंड़ और सुअर केवल १० और १८ प्रतिशत ही बढ़ सके। १९५०, ५१, ५२ में उत्पादन बढ़ा नहीं; औसत वृद्धि ३-४ प्रतिशत से अधिक न हो सकी।

सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। कुलन्दा के घास के मैदान तथा कुन्दा और काले में अनेक नहरें और बांध बनाए गए।

कृषि की दशा सुधारने के लिए १९५४ में कम्यूनिस्ट पार्टी ने साढ़े तीन लाख नवयुवकों को खेती के काम पर और लगाया। आगामी दो वर्षों में २ लाख ट्रैक्टरों की सहायता से ३३० लाख ट्रैक्टर भूमि जो पूर्णतः बंजर थी खेती के योग्य हो गई। साइबेरिया और कजाखस्तान में ७०० लाख एकड़ भूमि तोड़ कर खेती के योग्य बनाई गई। फलतः १९५५-५६ में कृषि उत्पादन में २६% वृद्धि हुई।

पशु पालन

(दस लाख पशुओं में)

	१९२८	१९४०	१९४५	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
	अन्त तक	अन्त तक	अन्त तक	अन्त तक	अन्त तक	अन्त तक	अकम्बल	अकम्बल	अकम्बल
पशुएँ	६६.८	५४.५	४५.३	५७.२	५८.८	५६.६	६३.०	६४.९	६७.१
गाएँ	३३.२	२७.८	—	२४.२	२४.३	२४.३	२७.०	२७.५	२९.२
सूअर	२७.४	२७.५	३.५	३४.१	२६.७	२८.५	४७.६	५१.१	५२.१
भेड़ और बकरियाँ	११४.६	९१.६	५६.०	९९.०	१०७.५	१०९.९	११४.९	११७.५	१२४.९
घोड़े	३६.१	२०.५	९.१	१३.७	१४.६	१५.३	—	—	—

उन्नत जन-जीवन

विगत चार योजनाओं में पूँजी के साधनों का पर्याप्त उत्पादन हो चुका था। पाँचवीं योजना में जनता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने और उसे सब प्रकार की भौतिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गई। शहरों में राजकीय सहायता और ऋण से नए घर बनाए जाने लगे। सरकार ने १०५० लाख वर्ग मीटर जमीन में नए घर बनवाने की घोषणा की थी। योजना काल समाप्त होते-होते १५४० लाख वर्ग मीटर भूमि पर नए घर बने।

१९५३ की एक घोषणा द्वारा रूबल की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए खाद्यान्नों के मूल्य में भारी कमी की गई और कर भी कम लगाए गए। यह पहला अवसर था जब योजना के मध्य में उपभोग सामग्री के पक्ष में परिवर्द्धन अथवा टैक्स में परिवर्द्धन किया गया हो। खाद्यान्न के उत्पादन में इस वर्ष १४% वृद्धि हुई।

उपभोग सामग्री के उत्पादन के लिए ३०० नए उद्योग खोले गए। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में उपभोग वस्तुओं की बिक्री के लिए ६,००० नई दूकानें खुली। फलतः १९५३ के फुटकर क्रय-विक्रय में विगत वर्ष की अपेक्षा १५% की वृद्धि हुई। २३ अक्टूबर १९५३ की एक घोषणा के अनुसार आगामी ३ वर्षों में ४०,००० नई दूकानें और ११,००० जलपान गृह खोलने का निश्चय किया गया।

योजना की सफलता

पाँचवीं योजना औद्योगिक विकास की दिशा में एक साहसिक कदम था। इस योजना की पूँजी का विनियोग ६८६*७ अरब रूबल था। योजना के लक्ष्य की प्राप्ति समय से पहले (सवा चार वर्ष) में ही हो गई थी। १९५५ के औद्योगिक विकास के आंकड़े निम्न हैं।

	योजना	वास्तविक वृद्धि
राष्ट्रीय आय	१६०	१६८
रोजगार	११५	१२०
औद्योगिक उत्पादन	११७	१८५
भारी उद्योग	१८०	१९१

हलके तथा अन्य उद्योग	१६५	१७६
विद्युत शक्ति	१८०	१८७
कार्य क्षमता में वृद्धि		
१—उद्योग	१५०	१४४
२—कृषि	१४०	१४७
अन्य क्षेत्रों में	१५५	१४५

योजना के अंतिम वर्ष में अनेक अपेक्षित सुधार किए गए । श्रम की उत्पादकता (Incentives) पर विशेष ध्यान दिया गया । योजना के तौर तरीकों में भी कई उल्लेखनीय सुधार हुए । कठोर केन्द्रीय प्रशासन के स्थान पर जनतंत्रों को महत्व पूर्ण अधिकार मिले । विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई गई ।

राष्ट्रीय योजना (गोसप्लान) के कार्यों पर भी प्रतिबन्ध लगा । उसके अधिकार में कमी हुई और केवल राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था सुधारने तक ही उसका कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया गया ।

मई १९५५ में इसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया ।

१—वह संस्था जो अल्पकालीन योजनाओं को तैयार करा सके और उसको कार्यावयन्त कर सके ।

२—वह संस्था जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन योजनाओं को बनाना और तदनुसार कार्य कराना हो ।

पूर्ण साम्य की ओर

अध्याय १५

षष्टमं पञ्चवर्षीय योजना

पांचवी योजना की सफलता के बाद सोवियत सङ्घ सुसंठित समाजवादी अर्थ-व्यवस्था अपना चुका था और अब छठी योजना में अधिक दृढ़ता-पूर्वक साम्यवाद की दिशा में उन्मुख हुआ। कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में योजना का प्रारूप स्वीकृत हुआ। घोषणा की गई कि छठी योजना के अन्तिम वर्षों में सोवियत सङ्घ साम्यवाद के पूर्वाद्घ में पहुँच जायगा और सातवीं योजना में सर्वांग रूपेण साम्यवादी समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। साम्यवाद के मूल-भूत आदर्शों की मंजिल १० वर्ष में कोई तय कर लेगा—विश्वास नहीं होता। हुआ भी यही। अन्य योजनाओं का वास्तविक उत्पादन जहाँ लक्ष्य से अधिक होता था वहाँ छठी योजना में लक्ष्य से कम हुआ। प्रशासन का ढांचा देखते हुए आज भी यह अनुमान करता कठिन है कि सोवियत सङ्घ में कभी राज्य विहीन समाज की स्थापना हो सकेगी।

जब किसी राष्ट्र पर से किसी महान् व्यक्तित्व का साया उठ जाता है तो कुछ समय के लिए अंधकार सा छा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज डूबने पर होता है। अनगिनत दीप शिखार्ये और तारे सूरज का अ्रवकाश भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं पर उनमें वह बात नहीं होती। छठवीं योजना स्तालिन की ही परम्परा का अनुसरण करते हुए बनाई गई थी। योजना के प्रारूप में कोई कमी नहीं दिखाई देती। विगत योजनाओं में इससे अधिक के लक्ष्य पूरे किए जा चुके थे। योजना की विफलता का यदि कारण हो सकता है तो वह प्रशासन की ढिलाई है। संभव है नेताओं का मतभेद भी असफलता का एक कारण रहा हो। किन्तु किसी विश्वस्थ सूचना के अभाव में अनुमान

के आधार पर निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। सत्य इतना ही है कि योजना के कार्यान्वयन के साथ ही इसे अव्यावहारिक समझा जाने लगा था और साल भर बाद १९५७ में इसका प्रथम संशोधन हुआ। संशोधित योजना अन्त तक न चल सकी। संशोधन के वर्ष भर बाद ही १९५८ में इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सप्तवर्षीय योजना चलाई गई।

छुटी पञ्चवर्षीय योजना अपनी विफलताओं के बावजूद भी दो दृष्टियों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं :—

१.—स्वचालित (Automation) यंत्रों का यथा साध्य प्रयोग।

२.—उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर अत्यधिक बल।

सोवियत सङ्घ के योजना बद्ध आर्थिक विकास के इतिहास में पहली बार निकिता ख्रुश्चेव ने उपभोग की सामग्रियों के उत्पादन पर बल दिया उत्पादन की वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में केवल १०% का अन्तर रखा गया। दोनों उत्पादनों की वृद्धि का अनुपात क्रमशः ७०% और ६०% रखा गया था। सोवियत नागरिकों का दैनिक जीवन बेहतर हो और वे अधिक से अधिक आराम दायक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें यही इस योजना की विशेषता थी। विगत योजनाओं में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति पर कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया गया था।

मूल योजना

१९५५ ई० में सोवियत सङ्घ का औद्योगिक उत्पादन १९२८ की अपेक्षा २० गुना अधिक था। उत्पादन यंत्रों में ३६ गुना और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में ६ गुने की वृद्धि हुई थी। पांचवीं योजना के अन्तिम वर्षों में सोवियत सङ्घ केवल अमेरिका से औद्योगीकरण की दृष्टि में पिछड़ा था। छुटी योजना का उद्देश्य न केवल औद्योगिक उत्पादन को और बढ़ाना था वरन् सामाजिक स्थिति को भी बढ़ाना था। निश्चय किया गया कि पुराने सामाजिक ढांचे के स्थान पर नये समाज की स्थापना की जाय जिससे २० करोड़ सोवियत नागरिक अन्य औद्योगिक समृद्धि सम्पन्न देशों से बेहतर जीवन बिता सकें।

बड़े उद्योग

बड़े उद्योगों में १९५५ की अपेक्षा ७०% वृद्धि होगी।

१९६० में सोवियत संघ ६८३ लाख टन इस्पात पैदा करेगा जो १९५५ से २३० लाख टन अधिक होगा।

इस्पात गलाने और उससे मन कीर्षी वस्तुएँ ढालने के लिए अनेक भट्टियाँ बनाई जायेंगी। सबसे बड़ी भट्टी १,३८६ घन मीटन की होगी। पूर्वी साइबेरिया में कई धातु उत्पादक केन्द्र खोले जायेंगे जो आगामी १० वर्षों में १५०-२०० लाख टन कच्चा लोहा पैदा करेंगे। साथ ही अनेक स्वचालित बड़ा भट्टियाँ बनाई जाएँगी। योजना काल में ४० रोलिंग और पाइप रोलिंग मिलों का निर्माण किया जायगा।

जेट, राकेट, इंजिनियरिंग रसायन, रेडियो आदि की प्रगति के लिए मिश्रित धातुओं के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कोयला

१९६० में ५६३० लाख टन कोयला निकाला जायगा जो १९५५ का डबोड़ा होगा।

कोयले की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों में दोनेत्स बेसिन जिसकी वार्षिक क्षमता २१२० लाख टन होगी का महत्वपूर्ण स्थान होगा। देश की खानों में अरबों टन कोयला है। द्नीप्रोपेत्रोवास्क क्षेत्र में कोयले की नई खान का पता लगा है। १९६० तक १५० नई खानों से कोयला निकाला जाने लगेगा।

तेल और गैस

तेल और गैस के अनेक नए क्षेत्रों का पता लग जाने से इनका उत्पादन १९५५ की अपेक्षा २५ गुना बढ़ जायगा। १९६० में १३५० लाख टन तेल प्राप्त हो सकेगा।

पहले बाकू और ग्रेजनी के तेल से ही काम चल जाता था। छुट्टी योजना में औद्योगीकरण के समानान्तर ही तेल की मांग बढ़ जायगी। योजना काल में तातारिया, स्तार्लिन ग्राद, उक्रेइन, तुर्कमानिस्तान, खिगीर्जिस्तान, कजाखस्तान आदि की खानों से विकसित वैज्ञानिक साधनों द्वारा तेल निकाला जायगा।

तेल निकालने वाली मशीनों को और उन्नत बनाया जायगा तथा उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। १९५५ में ४८,००० टन भार की मशीने बनाई गई थी, १९६० में १२०,००० टन की विभिन्न मशीने बनाई जाएंगी। तेल साफ करने की शक्ति में ३-५ गुने तक वृद्धि होगी। अद्यतन ईंधन गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ६,००० किलोमीटर पाइप लाइने बनाई जाएंगी। यूरोप की सबसे बड़ी पाइप लाइन स्टाब्रोपोल—मास्को १३० नगरों को गैस देगी। गैस का उत्पादन चौगुना हो जाएगा। १९६० तक ४०,००० लाख किलोवाट वार्षिक गैस उत्पादन की जाने लगेगी। गैस का प्रयोग ईंधन (fuel) और रासायनिक कच्चे पदार्थ के रूप में किया जायगा।

स्वचालित मशीने (Automatic Machine)

१९५५ में मशीन निर्माण का उद्योग युद्ध पूर्व वर्षों का ५.७ गुना था। अनेक प्रकार के स्वचालित यंत्र मुख्यतः भारी मशीने, बड़ी मट्टियां तथा रोलिंग मिलों का निर्माण किया जाने लगा। छुठी योजना में औद्योगिक स्वचालित यंत्रों का प्रचलन बहुत बढ़ जायगा। लगभग २२० नए स्वचालित यंत्रों का निर्माण होने लगेगा।

१९६० में १९५५ की अपेक्षा ८०% की वृद्धि होगी। यह संख्या युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा ८ गुनी है।

१९६० में २ लाख मशीन टूल बनाए जायेंगे।

कृषि, यातायात, पशुपालन, रसायन, कागज, चमड़े के जूते, काष्ठ आदि उद्योगों में काम आने वाली नए ढंग की मशीने बनाई जाएंगी। इन मशीनों में अधिकांश बिजली से चलने वाली होंगी।

दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले रूई, ऊन, सिल्क, लीनेन आदि उद्योगों से सम्बन्धित मशीने तीन पाली (shift) में काम करेगी। पांचवी योजना की सफलता के बाद ७६% औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था जो १९६० में युद्ध पूर्व वर्षों का दूना हो जायगा। उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए प्रतिदिन १ नया उद्योग खोला जायगा। १९६० तक १६०० नए उद्योग उत्पादन कार्य में लग जाएंगे।

ऊनी कपड़े का उत्पादन ५०% और सिल्क का उत्पादन १००% अधिक होने लगेगा। ४५५० लाख जोड़े जूते बनाए जाएंगे। चीनी के उत्पादन में ६५,३०,००० टन की वृद्धि होगी जो विगत वर्षों की अपेक्षा दूनी होगी।

विद्युत शक्ति

१९२८ में ५०,००० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती थी। १९५५ में १७,००,००० लाख किलोवाट पैदा की जाने लगी। छठवीं योजना में ३४,००,००० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की व्यवस्था की गई जो पांचवी योजना की ३ गुनी है।

जल विद्युत के अधिक उत्पादन पर अधिक जोर दिया जायगा। १९६० तक कुवेशे तथा स्तालिन ग्राद के जल विद्युत केन्द्र बन जाएंगे। इनकी उत्पादन शक्ति ४,४०,००० किलोवाट होगी। देश की प्रायः सभी प्रमुख नदियों से जल विद्युत उत्पन्न की जाएगी। साइबेरिया की विभिन्न नदियों से उत्पन्न जल विद्युत केन्द्रों में प्रत्येक ३२ लाख किलोवाट जमता के होंगे।

भाप के चलने वाले शक्ति गृहों की भी अपेक्षा नहीं की गई। २७ जून १९५४ को अणु शक्ति को उद्योगों में प्रयुक्त करने का निश्चय हुआ। १४० भाप से चलने वाले उद्योगों की स्थापना की गई। केन्द्रीय साइबेरिया में शक्ति केन्द्र बनाया जायगा और उसका सीधा सम्बन्ध यूरोपीय प्रदेश से कर दिया जायगा।

अणु शक्ति के उपयोग का निश्चय किया गया। योजना काल में ऐसे कारखाने खोले जायेंगे जो ४—६ लाख किलोवाट अणु शक्ति का उपयोग कर सकें। अणु शक्ति का प्रयोग केवल विद्युत के स्थान पर ही नहीं किया जायगा वरन् बीमारियों के इलाज, यातायात, बरफ काटने और खेतों को उपजाऊ बनाने आदि मानवीय सेवाओं के लिए भी अणु शक्ति का उपयोग होगा।

कृषि

योजना के आरम्भिक वर्षों में ८५,७०० सामूहिक फार्म ५००० राजकीय फार्म ६००० मशीन और ट्रैक्टर के गोदाम थे। अनुमानतः १९६० में गेहूँ का उत्पादन १८ करोड़ होने वाला था।

कुस्तनाय चारागाह जो पहले बेकार पड़ा था १६५८ में खेती योग्य हो जायगा। देश की इसी प्रकार की बेकार पड़ी भूमि पर चार बड़े राजकीय फार्म खोले जाएंगे और इस नई भूमि से ३२० लाख टन का अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जायगा।

बहुत से सहकारी फार्म ३ से २.६ टन प्रति हेक्टर और कुल ५ से ६ टन प्रति हेक्टर तक खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे। उजबेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकस्तान, ताजकिस्तान आदि क्षेत्रों में पैदा होने वाली रूई की उपज में ८२% वृद्धि होगी। १६५५ ई० में २२ लाख हेक्टर भूमि पर रूई पैदा की जाती थी। छठी योजना पूरी होने पर ५६% और बढ़ जाती। अन्य कृषि उत्पादन जैसे चीनी ५४%, रेशेदार पदार्थ (flax) ३३%, आलू ८५% अधिक उत्पन्न होते।

१६५५ में कृषि फार्मों में प्रयुक्त होने वाले पशुओं की संख्या २६१० लाख थी। छठी योजना के अन्त में इस संख्या में ३५% की वृद्धि होती।

१६५५ में १५ अश्व शक्ति के १४,३६,००० ट्रैक्टर थे। १६६० में ये १६,५०,००० हो जाते।

१६६० में नहर सिंचित भूमि २१ लाख हेक्टर होती।

नये उद्योग

१६२६-५५ तक २६००० छोटे-बड़े नये उद्योग स्थापित किए गए। इन नये उद्योगों में व्यय की जाने वाली धन राशि अधोलिखित थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना - ६१.६ अरब रुबल

” ” ” १४१.४ ” ”

तृतीय ” ” १३८.७ ” ” साढ़े तीन वर्षों में

चतुर्थ ” ” ३२६.६ ” ”

पंचम ” ” ६२५.३ ” ”

षष्ठम् ” ” ६६० ” ”

नये मकान बनाने के लिए २०,५० लाख वर्ग मीटर भूमि स्वीकृत हुई और २८० लाख घन मीटर मकान बनाने के सामान बनाए जाने वाले थे।

स्वास्थ्य और संस्कृति

१९५५ के पहलू के दस वर्षों में स्वास्थ्य और संस्कृति पर ३ लाख रूबल खर्च हुआ था। छठी योजना के अन्तिम वर्षों में देश भर में ४००० खेल के मैदान, ३,३४,००० डाक्टर, ५ लाख सिनेदर्शकों की सीट, १२ दूर दर्शक केन्द्र (Television centre) ३,६२,००० पुस्तकालय, और १३५१० लाख पुस्तकें हो जाएगी। श्रमिकों को प्रतिदिन ७ घंटे काम करना पड़ेगा।

योजना की विफलता

छठी पञ्चवर्षीय योजना सफल न हो सकी। योजना की विफलता को यूरोपीय गैर कम्यूनिस्ट आलोचक शंका की दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है। कि उत्पादन के सही आंकड़े और योजना की विफलता के कारण छिपाए गए हैं। योजना अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रही—

	योजना का वार्षिक लक्ष्य (प्रतिशत वृद्धि)	१९५७-५८ में (पूर्ति) (प्रतिशत वृद्धि)
कोयला	८.६	२.८
पेट्रोल	१३.६	६.४
गैस	३१.०	१६.४
विजली	१३.५	६.७
कच्चा लोहा	१०.०	५.३
इस्पात	८.५	५.३
सीमेंट	१६.५	८.३
चीनी	१४.०	५.१
ऊनी कपड़ा	७.७	५.२
चमड़े के जूते	८.७	४.६

सुनियोजित अर्थ व्यवस्था की दिशा में सोवियत चरण क्रमशः शिथिल पड़ते जा रहे थे। १९५५ से ५७ तक के उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यदि छठी योजना समाप्त न कर दी गई होती तो साम्यवादी समाज का सपना-सपना ही रह जाता :—

	वास्तविक	वृद्धि	
	१९५५	१९५६	१९५७
लोहा (लाख टन)	३३	२५	१२
इस्पात ,,	३६	३३	२४
दली धातु ,,	३२	२५	२४
कोयला ,,	४३६	२८०	१६८
मिट्टी का तेल ,,	११५	१३०	१४५
सीमेंट ,, खरब	३५	२४	४०
विद्युत शक्ति (दस खरब किलोवाट)	१६.५	२१.६	१७.५
गैस (दस खरब घन मीटर)	०.३	३.३	६.५
सूती वस्त्र ,,	०.३	०.४	०.१
ऊनी वस्त्र ,,	६.१	१५.४	१४.३
जूते (लाख जोड़े)	१६.५	१५.५	२५.२
चीनी (लाख टन)	८	६	४

प्रवदा के २७ सितम्बर १९५७ के अंक में 'प्रेरणादायक भविष्य' के प्रति आस्था प्रकट करते हुए योजना के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया था। देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक ईंधन और धातुएं इतनी प्रचुर परिणाम में मिली थी कि छठी योजना के अन्तर्गत उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। उक्रइन के औद्योगिक क्षेत्र के निकट कुर्स्क में लोहा, टिटानियम तथा जरकोजियम की खान कजाखस्तान में टंग्स्टन और मालेबडूम दूर पूर्व में टिन यूराल में अलौह धातुएं और अणु शक्ति के लिये आवश्यक नए औद्योगिक ईंधन तथा लोहा मिल जाने से देश के विकास की दिशा बदल गई। फलतः छठी योजना समाप्त कर सति वर्षीय योजना बनाई गई। आशा प्रकट की गयी की आगामी १५ वर्षों में सोवियत संघ अपने लक्ष तक अवश्य पहुंच जायगा।

अध्याय १६

सप्त वर्षीय योजना

पञ्चवर्षीय योजनाओं की आशातीत सफलता के बावजूद भी सोवियत सरकार की दृष्टि में देश की आर्थिक प्रगति संतोषजनक नहीं थी। सोवियत सङ्घ के साम्यवादी दल (C.P.S.U) की २१ वीं विशेष बैठक में सप्तवर्षीय योजना के कार्यान्वय का निश्चय किया गया। योजना के निर्माण में राज्य मंत्रियों, वैज्ञानिकों तथा अन्य अनुभवशील व्यक्तियों ने योग दिया है और देश की जनता इसकी सफलता के लिए सचेष्ट है।

सुप्रीम सोवियत की ४० वीं बैठक में योजना का आदर्श निश्चित किया गया। इस आयोग ने यह तय किया कि आगामी १५ वर्षों में उद्योग-धन्धों का उत्पादन वर्तमान उत्पादन का दूना या तिगुना कर दिया जाय।

१९५७ की अपेक्षा कच्चे माल का उत्पादन ३.५ गुना, तेल ४ गुना, गैस १३ से १५ गुना, कच्चा लोहा और इस्पात ४.३ गुना, विद्युत शक्ति ४ गुना, सीमेंट आदि गृह निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं में ४ गुने अधिक की वृद्धि की जायगी। प्रस्तुत सप्त वर्षीय योजना इसी पंचदश वर्षीय योजना का एक भाग है।

श्री खुश्चेव के मतानुसार योजना के आरंभिक सात वर्ष साम्यवाद और पूँजीवाद के होड़ का समय है। आपका विश्वास है कि इस अग्नि परीक्षा में साम्यवाद खरे सोने की भाँति दमक उठेगा। ४ फरवरी १९६० को दिल्ली की विशाल सभा में आपने पूँजीवादी राष्ट्रों को विध्वंसकारी शस्त्रास्त्रों के क्षेत्र में होड़ न करके निर्माण कार्य में सोवियत सङ्घ से स्पर्धा करने की चुनौती दी है।

सोवियत सङ्घ की योजनाओं की प्रमुख विशेषता उपभोग सामग्रियों के निर्माण की अपेक्षा उत्पादन के साधनों का निर्माण रहा है। प्रस्तुत योजना

में भी इसी आदर्श का पालन किया गया है किन्तु परिस्थिति अनुकूल हो जाने के कारण जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए उपभोग सामग्रियों के निर्माण पर बल दिया जाने लगा है और ऐसी बहुत सी चीजें जो पहले विलासिता की समझी जाती थीं अब आराम दायक आवश्यकता मान ली गई हैं ।

कृषि और उद्योगों का उत्पादन स्तर उठाने के लिए विज्ञान और औद्योगिकी (Technology) को सब प्रकार से उन्नतिशील बनाया जा रहा है । उत्पादन के मूल आधार में परिवर्तन करके लक्ष्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे ।

१—उद्योग धन्धों में प्रयुक्त होने वाली धातुओं का उत्पादन बढ़ाया जायगा ।

२—रासायन उद्योग, विशेष रूप से, कृत्रिम और रासायनिक रेशे (Synthetic Fibre) प्लास्टिक के सामान, नाइलान (Nylone) तथा अन्य रासायनिक वस्तुओं के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जायगा । स्मरणीय है ये सभी सामान उपभोग के होंगे ।

३—गैस और तेल के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी ।

४—बड़े-बड़े जल विद्युत केन्द्र बनाए जायें और उनके पास ही उद्योगों की स्थापना की जायगी । इसके दो लाभ स्पष्ट हैं उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होगा और उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध होगी ।

५—तेल से चलने वाले इंजनों और विद्युत से चलने वाली रेलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ।

६—कृषि उत्पादन बढ़ाया जायगा जिससे खाद्य पदार्थ की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके ।

७—बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपयोग के घर बनाए जायेंगे ।

देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का उपयोग

देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए कच्चे माल के समीप ही उद्योग धन्धों की स्थापना की जाएगी ।

पूर्वी भाग के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जायगा ।

साइबेरिया और कजाकस्तान की लोहे की खानों के पास लोहे का सामान बनाने वाले कारखाने स्थापित किए जाएंगे ।

कजाकस्तान, मध्यवर्ती एशिया, यूतल तथा बेकाल क्षेत्र में लोहेतर धातु के उद्योग स्थापित किए जाएंगे ।

साइबेरिया में सस्ते कोयले से शक्ति उत्पन्न की जाएगी ।

वोल्गा, यूराल और उजबकिस्तान में गैस उद्योग खोले जाएंगे ।

रासायनिक उद्योग को बढ़ाने के लिए पूर्वी क्षेत्रों और मध्यवर्ती एशिया में कारखाने खोले जाएंगे ।

टैगा तथा अन्य लकड़ी उत्पादक क्षेत्रों में काष्ठ उद्योग खोले जायेंगे ।

देश के यूरोपीय भाग में निम्न बातों पर अधिक जोर दिया जायगा—

१—यूक्रेन तथा कुस्क क्षेत्रों के लोहे की खानों के प्रयोग से स्पात उत्पादन की वृद्धि की जायगी ।

२—कोलापेन सुला क्षेत्र में लोहेतर (Non-ferrous) धातु उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

३—उत्तरी काकेशस एवं यूक्रेन के क्षेत्रों में गैस और मिट्टी के तेल के कुओं का उपयोग किया जायगा ।

४—तेल और गैस के क्षेत्रों में रासायनिक उद्योग खोले जायेंगे ।

५—भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाएगी ।

प्रावैधिक विकास (Technical development)

योजना के आरम्भिक सात वर्षों में प्रावैधिक और प्रौद्योगिक उन्नति की जायगी जिससे मशीन निर्माण, रेडियो, विद्युत शक्ति, इंजीनियरिंग, तेल, रसायन, धातु और गैस का देश की आवश्यकता भर का उत्पादन हो सके ।

श्रमिकों की उत्पादन क्षमता और रहन-सहन के स्तर का विकास किया जायगा ।

समाजवादी उद्योग धन्धों का विकास

सोवियत संघ का विश्वास है कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में सर्व हारा वर्ग का शोषण होता है। विशापन जनित अनावश्यक किन्तु अनिवार्य खर्चों के कारण लागत व्यय बहुत बढ़ जाता है। पारस्परिक प्रति स्पर्द्धा न तो पर्यय के गुण में हास होने देती है न मूल्य में वृद्धि। इसका परिणाम मजदूरों को भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत संतुलित समाजवादी अर्थ व्यवस्था में सामाजिक और वैयक्तिक उद्योगों में प्रति द्रन्दिता नहीं होती। उत्पादन के साधनों और मूल्य नियंत्रण पर समाज का अधिकार होता है।

प्रस्तुत योजना में उत्पादन के दो वर्ग किए गए हैं।

क वर्ग—उत्पादन के साधनों का उत्पादन (Production of the means of production)।

ख वर्ग—उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन (Production of the consumer goods)।

१९६५ में १९५८ की तुलना में औद्योगिक उत्पादन ८०% बढ़ जायगा जिसमें क वर्ग का उत्पादन ८५ से ८८% और ख वर्ग का उत्पादन ६२ से ६५% बढ़ जाएगा। १९५९-६५ की वार्षिक अनुमानित प्रगति ८.६% (क वर्ग ९.३%, ख वर्ग ७.३%) होगी।

आगामी सात वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन १३,५०,००० लाख रूबल का होगा जो विगत सात वर्षों में ९,००,००० लाख रूबल ही था।

क वर्ग

बड़े उद्योग

लोहा और इस्पात उद्योग—आधुनिक युग में लोहे और इस्पात का महत्व बढ़ गया है। प्रायः सभी यंत्रों में किसी न किसी रूप में इनका उपयोग अवश्य होता है। १९६५ तक ६५०—७०० लाख टन कच्चे लोहे के उत्पादन की योजना है जो १९५८ की तुलना में ६५-७७ प्रतिशत अधिक होगा। वेल्डित धातु (rolled metal) ६५०-७०० लाख टन अथवा ५२-६४

प्रतिशत अधिक और संरेखित लौह (dressed iron) १५००-१६०० लाख टन उत्पादन करने का निश्चय किया गया है। कच्चा लोहा, इस्पात, वेल्डिंग धातु और संरेखित लौह का औसत वार्षिक उत्पादन क्रमशः ३६-४४, ४४-५१, ३२-३६, ६०-१०३ लाख टन होगा। १९५२-५८ में इनका उत्पादन क्रमशः २५, ३४, २७, ६२ लाख टन था।

सोवियत संघ के लोहे और इस्पात उद्योग का प्रावैधिक स्तर (technical level) उठाया जायगा। अणु शक्ति से चलने वाली शक्ति शाली मशीनों के निर्माण में अधुनातन वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के साधनों का प्रयोग किया जायगा।

लोहेतर धातु उद्योग (Non-ferrous metals industry)

निकल, मैगनीशियम, ताँबा, टिटैनियम, जरमैनियम सिलिकन आदि लोहे-तर धातु उद्योग में २८ गुने की वृद्धि की जायेगी। अल्युमिनियम धातु हल्की, सस्ती और मजबूत होती है। इसके उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अनुमान है १९६५ तक उसके उत्पादन में १.६ गुने की वृद्धि हो जायेगी। अल्युमिनियम से विभिन्न मशीनें, ट्रैक्टर, मोटरो के पुर्जे, वायुयान जलपोत तथा दैनिक उपयोग की अन्य अनेकानेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्रॉसनोयास्क के क्षेत्र में अल्युमिनियम का बहुत बड़ा कारखाना खोला जा रहा है। स्मरणीय है इस क्षेत्र में क्रोयला तथा नीफेलीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ-साथ हीरे की खानों को भी बढ़ाया जायगा जो १९५८ की अपेक्षा १४ गुना अधिक होगा।

रसायनिक उद्योग (Chemical Industry)

रसायनिक उत्पादन को ३ गुना बढ़ाया जायगा। उत्पादन संश्लिष्ट धातुओं (Synthetic materials) के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी। रसायनिक तन्तुओं (Chemical fibres) में ३८-४ गुनी वृद्धि होगी जिसमें बहुमूल्य संश्लिष्ट तन्तु (Synthetic fibres) में १२-१४ गुने और प्लास्टिक तथा संश्लिष्ट उद्यास (Synthetic resins) में ६.७ गुने की वृद्धि होगी।

संश्लिष्ट रबर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली तेल गैस के उत्पादन के लिए १३ अरब रूबल और भूमिक उर्वरक (Nitric fertilisers) के उत्पादन के लिए ४० अरब रूबल की लागत के कारखाने खोले जाएँगे।

देश भर में लगभग १४० वृहत् स्तर के नये रसायनिक केन्द्र खोले जायेंगे और १३० उद्योग केन्द्रों का नव निर्माण किया जायगा।

ईंधन उद्योग (Fuel industry)

तेल और गैस का कुल उत्पादन ५१% बढ़ेगा और कोयले का खर्च ५६% से घट कर ४३% रह जायगा। १९६५ में तेल का उत्पादन २३-२४ करोड़ टन होगा। तेल साफ करने की क्षमता में २* गुने की वृद्धि होगी। गैस का उत्पादन १५,००,००० लाख घन मीटर होगा जो १९५८ का ५ गुना है।

कोयले का उत्पादन ५,९६०—६,०६० लाख टन होगा जो वर्तमान उत्पादन से २०-२३ प्रतिशत अधिक है।

विद्युत शक्ति (Electrification)

१९६५ में वर्तमान विद्युत शक्ति में २-२* गुने की वृद्धि होगी। योजना के अनुसार ५०,००,०००—५२,००,००० लाख किलोवाट बिजली पैदा की जायगी। प्रायः २०,००० Km. बिजली रेल यातायात के काम आएगी।

स्तालिनग्राद, ब्रात्स्क, क्रैमेनचुंग, वोल्किन्स्क, बुखतरमा तथा अन्य दूसरे स्थानों में हाइड्रोएलेक्ट्रिक केन्द्र खोले जायेंगे।

आगामी सात वर्षों में अणु शक्ति के शान्ति पूर्ण प्रयोग की दिशा में विशेष ध्यान दिया जायगा और अनेक आणुविक विद्युत शक्ति केन्द्र (Atomic electric power station) खोले जायेंगे।

मशीन बनाने के उद्योग

मशीन बनाने के उद्योगों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। आशा है १९६५ तक आवश्यकता से अधिक मशीनें बन जायेंगी। मशीन निर्माण के

उद्योग में अणु शक्ति का भी सहारा लिया जायगा। निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

१—अधुनातन उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों और इस्पात के कारखानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

२—मशीनों के निर्माण में विशेषतः रेडियो वैद्युदण्विकी (radio-electronics) अधि-संवाहिता (super-conductivity) अधि-ध्वनि (super-sound), अर्ध संवाहक (semi-conductor) न्युट्रि-ऊर्जा (nuclear energy) आदि के निर्माण और प्रारूप में अधुनातन वैज्ञानिक शोधों का उपयोग किया जायगा।

३—इन मशीनों द्वारा उत्पादन शक्ति और कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जायगा।

४—उद्योग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। वृहत् स्तर उत्पादन १९५६ की अपेक्षा दूने से अधिक होगा।

लट्टा, कागज तथा काष्ठ उद्योग

लकड़ी के लट्टे का उत्पादन ३२२० लाख घन मीटर (१९५८) से बढ़कर ३७८० लाख घन मीटर (१९६५) हो जायगा। देश के उत्तरी भाग एवं साइबेरिया में लकड़ी के उद्योग में डेढ़ गुने की वृद्धि हो जायेगी। लकड़ी के बने सामान का मूल्य १,८०,००० लाख रूबल होगा। यह संख्या १९५८ की तुलना में २.४ गुनी अधिक है।

योजना के अन्तिम वर्षों में ३५ लाख टन कागज बनाया जाने लगेगा यह संख्या १९५६ की अपेक्षा १.६ गुनी अधिक होगी। कार्ड बोर्ड के उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी।

प्रमुख उद्योगों पर अनुमानित व्यय और १९५८ की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि अधोलिखित है—

१९५८—६५	उद्योग	अनुमानित व्यय लाख रुबल में	वृद्धि
" "	लोहा और इस्पात	१०,००,०००	२'४ गुना
" "	रसायनिक उद्योग	१०,००,०००—१०,५०,०००	—
" "	तेल और उद्योग	१७,००,०००—१७,३०,०००	२'३—२'४
			गैस में ४'२ गुना
" "	कोयला	७,५०,००—७,८०,०००	२२—२७%
" "	विद्युत शक्ति तथा अन्य सम्बन्धित शक्ति श्रोत	१२,५०,०००—१२,६०,०००	१'७ गुना
" "	लट्टे, कागज एवं लकड़ी के उद्योग	६,००,०००	२ गुना

ख वर्ग

उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन

आशा की जाती है कि आगामी सात वर्षों में उपभोग की सामग्रियों में १'५ गुने की वृद्धि हो जायगी। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त, रेडियो, घड़ी आदि का भी बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है।

उपभोग की वस्तुओं के निर्माण का प्रारूप अबोलिखित है—

परय	१९५८	१९६५	१९५८ की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
सूती वस्त्र करोड़ मीटर में	५,८०	७,७०—८,००	१३३—१३८
ऊनी वस्त्र "	३०	५०	१६७
लीनेन "	४८	६३'५	१३२
सिल्क "	८१'४	१,४८'५	१८२
होजरी (Hosiery)	८२'२	१२५	१४२

बुने हुए अन्डरवीयर करोड़ में	३६*२	७८	१६६
बुने हुए गारमेन्ट ”	६*५	१६	१६८
चमड़े के जूते करोड़ जोड़े	३५*५	१५*५	१४५

१९६५ तक चमड़े के जूते बनाने में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर हो जायेगा। १५६ नये लघुस्तर उद्योग खोले जायेंगे और पुरानी फैक्टरियों का परिष्कार किया जायेगा।

खाद्य उद्योग (Food industry)

मुख्या खाद्य वस्तुओं के आंकड़े अधोलिखत हैं—

	१९५८	१९६५	प्रतिशत वृद्धि
	हजार टनों में		
मांस	२,८३०	६,१३०	२१७
मक्खन	६२७	१,००६	१६०
दूध	६,०१७	१३,५४६	२२५
सुकन्दर की चीनी	५,१५६	६,२५०-१०,०००	१८०-१६४
वनस्पति तेल	१,२२१	१,६७५	१६२
मछली	२,८५०	४,६२६	१६२
अलकोहल (अच्छी शराब)	१५८*८	२०२*८	१२४
साधारण अलकोहल	१११*७	१००	६०

आगामी ७ वर्षों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ जायगा। केवल सोवियत सङ्घ ही ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। स्पष्ट है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों की वृद्धि की ओर उन्हें अधिक ध्यान देना होगा। मांस साफ करने के २००, दूध साफ करने के १००० तथा चीनी और दूसरी वस्तुओं के २०० नये कारखाने खोले जायेंगे।

घरेलू उद्योग की वस्तुओं का उत्पादन

लगभग ८८ अरब रूबल की घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाई जायेंगी। इनमें घर की सफाई करने वाली मशीनें, रेडियो, दूरदर्शक (Television),

सिलाई की मशीन, बेतार का तार, सायकिल, घड़ी, कैमरा, मोटर सायकिल आदि प्रमुख हैं।

उत्पादन बढ़ाने और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए यातायात उद्योग, इंजीनियरिंग और कृषि पर विशेष बल दिया जा रहा है। सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में सोवियत संघ सचेष्ट है। अनुमान है कि १९६५ तक श्रमिकों की कार्यक्षमता में ४५—५०% वृद्धि और लागत में ११.५% कमी हो जायेगी।

१९६५ तक ८,०००—८,५०० करोड़ रूबल के खाद्यपदार्थ और ३७,५००—३८,००० करोड़ रूबल की घरेलू उपयोग की वस्तुएँ बनाई जायेंगी।

समाजवादी कृषि का विकास

प्रचुर मात्रा में अपेक्षित स्वास्थ्यवर्द्धक पदार्थों की उपलब्धि के लिए बड़े-बड़े सामूहिक फार्मों के संगठन और कोष का प्रबन्ध किया जायगा। अनाज के शीत ताप नियंत्रित गोदाम बनाये जायेंगे। कृषक परिवारों के लिए विद्यालय, अस्पताल, मनोरंजन गृह, उद्यान और खेल के मैदान बनाए जायेंगे।

राजकीय फार्मों की संख्या, उत्पादन क्षमता और महत्व की वृद्धि की जायेगी।

योजना का लक्ष्य

फलों के उत्पादन में दूनी वृद्धि होगी। पशुओं से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री में प्रायः ज्योड़ी से अधिक वृद्धि होगी यथा—मांस १.६ और दूध १०—१०.५ करोड़ टन तथा ३७ अरब अंडों का उत्पादन होगा।

फसलों का उत्पादन

आगामी सात वर्षों में फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी और अनाज की किस्म भी अच्छी होगी। राजकीय फार्मों और सहकारी फार्मों पर विशेष ध्यान दिया जायगा। राजकीय फार्मों में साइबेरिया के फार्म, यूराल के मैदान, वोल्गा क्षेत्र, यूक्रेन, कजकाह, मध्यवर्ती काली मिट्टी वाले क्षेत्र

तथा उत्तरी काकेशस मुख्य हैं। लेतेविया, लिथुयानिया, एसतोनिया आदि क्षेत्रों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किया जायेगा।

कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए खाद बनाने के अनेक कारखाने खोले जायेंगे। अनुमान है १९६५ तक ३,१०,००,००० टन खाद बना ली जायेगी।

पशु पालन

मांस, दूध, चमड़ा आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं की संख्या में वृद्धि होनी आवश्यक है। देश के पशु धन में ३.२ गुने की वृद्धि होगी जिसमें गायें २.२ और भेड़ें २ गुनी हो जायेंगी। सूअर और मुर्गी की नस्ल में सुधार किया जायगा।

पशुओं के लिये चारे का भी प्रबन्ध करना होगा। ८.५-९ करोड़ टन चारा उत्पन्न करने की योजना है। पशुओं के लिये मक्का सर्वाधिक उपयुक्त चारा है। अन्य पशुओं को खिलाने के लिए १.८—२ करोड़ टन अतिरिक्त चारे की व्यवस्था की जायगी।

कृषि उत्पादन

अनुमान है कि खेती से १९६५ में अधोलिखित उपजें होंगी—

	१९६५ हजार टन में	१९५७ की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
रूई	५,७००—६,१००	१३५—१४५
चुकन्दर की चीनी	७०,०००—७८,०००	१८०—२००
तिलहन	३,५६०	१८०
आलू	११,७२०	१४८
फ्लेक्स (flex) रेशा	५३०	१३७
मांस	११,०५०	२.२ गुना
दूध	४०,६१०	२ गुना
ऊन	५४०	१.९ ,,
अंडा	१०,०००	२.३ ,,

कृषि उत्पाद की अधिकता के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

राजकीय फार्मों का विकास

आगामी ७ वर्षों में राजकीय फार्मों में पशुओं और देख-रेख करने वालों के लिए नये घर बनाये जायेंगे। देहाती क्षेत्रों में बनाये जाने वाले घरों की संख्या अधिक होगी।

उत्पादन में वृद्धि और लागत व्यय में कमी करने का निश्चय किया गया है। १९५७ की अपेक्षा अनाज के लागत व्यय में कम से कम ३० प्रतिशत, माँस २० प्रतिशत, दूध २३ प्रतिशत, ऊन ८ प्रतिशत, रूई २० प्रतिशत की कमी होगी।

कृषि के विकास में विद्युत शक्ति का प्रयोग

कृषि क्षेत्र में अधुनातन वैज्ञानिक साधनों और शोधों का प्रयोग किया जायगा। १० लाख ट्रैक्टर, ४०,००,००० अनाज काटने की मशीने तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य अनेक छोटे बड़े यंत्र बनाये जायेंगे। जिन फार्मों में बिजली उपलब्ध है उनमें ४ गुनी अतिरिक्त विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जायेगा।

जंगल

जंगलों का कुल क्षेत्रफल २६२० लाख हेक्टर है। इनके सुरक्षा की व्यवस्था की जायगी। सामूहिक फार्मों का उत्पादन प्रायः दूना हो जायगा। राजकीय फार्मों का उत्पादन ५५—६० प्रतिशत अधिक हो जायगा। फार्मों के विकास के लिए ५०,००० करोड़ रूबल खर्च किया जायगा।

यातायात और परिवहन के साधनों का विकास

आगामी सात वर्षों में सोवियत संघ के यातायात और परिवहन के साधनों में विशेषतः रेल और वायुयान में अत्यधिक प्राविधिक प्रगति होगी।

भार की सामग्री रेलों से ढोई जायेगी। यह संख्या विगत वर्षों से ४०-५० प्रतिशत अधिक है। ८५-८७ प्रतिशत माल बिजली से चलने वाली रेलों से ढोया जायेगा।

निम्नलिखित स्थानों को मिलाने वाली रेल गाड़ियाँ विद्युत शक्ति से चलेंगी—

मास्को—क्यूवेशेव—इरकूत्स्क (दूर पूर्व), मास्को—गोर्की—स्वेरदोव्स्क, मास्को—कजन—स्वेरदोव्स्क, करगन्दा—माग्नितोगोव्स—उफा, दवरकोव—रोस्तोव—मेनेराल्नी वोदी और दूसरी अन्य रेलें ।

इसके अतिरिक्त ६००० किलोमीटर मुख्य लाइने और ८००० किलोमीटर शाखा लाइने नई खोलीं जाएँगी ।

दक्षिणी साइबेरिया और मध्य साइबेरिया ट्रंक लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कजाकस्तान, यूराल और वोल्गा क्षेत्र में अनेक नई लाइने बन रही हैं । वन्य प्रदेश में २,७०० किलोमीटर लाइने बनाई जाने वाली हैं ।

१८—२० हजार किलोमीटर रेलों में स्वचालित इंजनों का और ७० हजार किलोमीटर दूरी में भारी इंजनों का प्रयोग किया जायगा ।

सामुद्रिक यातायात

सामुद्रिक यातायात प्रायः दूना हो जायगा । देश के आयात निर्यात में वृद्धि होगी । बन्दरगाहों के डाक इतने अच्छे बनाये जायेंगे कि जहाजों पर ६०—७०% और अधिक भार सरलतापूर्वक चढ़ाया उतारा जा सकेगा ।

नदी यातायात

वोल्गा—बाल्टिक नहर का उपयोग किया जाने लगेगा । साइबेरिया की नदियों में यातायात की सुविधाएँ बढ़ाई जायेंगी । अनुमानतः ये सुविधाएँ १.६ गुनी अधिक होंगी ।

तेल

एक स्थान से दूसरे स्थान को तेल से जाने के लिए तेल के पाइप बिछाये जायेंगे । पाइपों की संख्या में ५.६ गुनी वृद्धि होगी ।

स्थल यातायात

मोटरो की संख्या में १.७ गुनी वृद्धि होगी । मोटर चलाने योग्य सड़कों

में २८ गुनी वृद्धि होगी। जिन स्थानों में अब तक आवागमन का प्रबन्ध नहीं था वहाँ सड़कें बनाई जायेंगी।

वायुयान

द्रुतगामी और बड़े टर्बो-जेट (turbo-jet) और टर्बो-प्राप वायुयानों के कारण वायुपथ के यातायात में ६ गुने की वृद्धि होगी।

यातायात सम्बन्धी खर्च बहुत बढ़ जायेंगे। रेलों की उन्नति के लिए ११,०००—११,५०० करोड़ रूबल खर्च किया जायगा। विगत सात वर्षों की अपेक्षा यह संख्या ८२—६२% अधिक है। इसी प्रकार रेलों को विद्युत शक्ति से चलाने में २७ गुना अधिक खर्च होगा।

योजना में व्यय की जाने वाली धन राशि

इतनी महान योजना जिसकी सफलता से देश का कायाकल्प हो जायगा कम खर्चीली है। व्यय इतना कम है कि निरपेक्ष दर्शक भ्रम में पड़ जाता है कि कहीं योजना के निर्माताओं के हाथ 'अलादीन का जादुई चिराग' तो नहीं लग गया। विगत सात वर्षों में जितना धन व्यय किया गया है उसका १८ गुना अधिक धन आगामी सात वर्षों में व्यय होगा।

विभिन्न मदों में व्यय की जाने वाली धनराशि निम्न है।

अरब रूबल में	प्रतिशत वृद्धि
१६५२—५८	१६५६—६५

योजना में व्यय की जाने वाली

कुल धन राशि	१,०७२	१६४०—१६७०	१८१—१८४
-------------	-------	-----------	---------

समेत :—

बड़े उद्योग	८२१	१,४८८—१,५१३	१८१—१८४
गृह निर्माण और जन सुविधा	२०८	३७५—३८०	१८०—१८३
शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कृति	४३	७७	१७६

अनावश्यक खर्च को रोकने और यथा साध्य कफायत सारी बरतने का प्रयत्न किया जायगा। गृह निर्माण के लिये ११,०००—११,२०० करोड़ रूबल खर्च किया जायगा। गृह निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सीमेन्ट,

स्लेट, कान्क्रीट, शीशा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न होगा।

सिंहावलोकन

योजना का उद्देश्य समाजवादी अर्थ व्यवस्था को क्रियात्मक रूप देना है। सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता समाजवादी विचार धारा की विजय थी। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा में देश पूँजीवादी देशों के सामने गर्व से सिर उठा सके, निवासियों के रहन-सहन का स्तर, दैनिक जीवन की आवश्यक सुविधाएँ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सकें यही योजना का लक्ष्य है। उनका विश्वास है कि १९६५ में सोवियत संघ की प्रतिव्यक्ति आय ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की अपेक्षा अधिक होगी और कुछ मुख्य कृषि उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक हो जायेंगे। १९१७ के पूर्व विश्व के औद्योगिक उत्पादन में उनका भाग केवल ३% था जो क्रमशः बढ़ता-बढ़ता १९३७ में १०%, १९५८ में २०% हो गया। १९६५ में वे विश्व के औद्योगिक उत्पादन का आधे से अधिक भाग पैदा करेंगे।

देश के विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। १९४० में ४० देशों से उनका व्यापार होता था। १९६० में इनकी संख्या ७० हो गई है। विकासोन्मुख (underdeveloped) देशों से सोवियत संघ के सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण रहेंगे। पूँजीवादी देशों से भी वे व्यापार करने को इच्छुक हैं।

योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि युद्ध न हो।

सप्तवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अमेरिकी दृष्टिकोण

अमेरिकी अर्थ शास्त्रियों का विश्वास है कि १९७० तक भी सोवियत संघ की प्रतिव्यक्ति आय, उत्पादन और रहन-सहन का स्तर वर्तमान अमेरिका जैसा नहीं हो पायेगा। सोवियत संघ की प्रगति के सम्बन्ध में की जाने वाली सरकारी घोषणायें वास्तविकता से दूर हैं। १९५०-५७ में सोवियत संघ की कुल वार्षिक राष्ट्रीय आय में सरकारी घोषणा के अनुसार ११% वृद्धि हुई जब कि वास्तविक वृद्धि ६-७ प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं थी। औद्योगिक उत्पादन में १२% वार्षिक वृद्धि हुई किन्तु वास्तविक वृद्धि ८-१०% वार्षिक से अधिक नहीं थी।

W. K. Bunce, counsellor of Embassy for Public Affairs ने American Embassy News Letter की १७ फरवरी १९६० की बुलेटिन में लिखा है :-

Here, in brief, are several of the more important objectives of the Soviet Seven-Year Plan, to be achieved by 1965, as compared with the current annual rate of U.S. output, in 1959 :

Steel : 83 million metric tons (USSR 1965 target).
The U. S. now is turning out steel at the rate of 125 million metric tons a year and has a current capacity of 135 million metric tons.

Oil : 140 million metric tons (USSR 1965 target).
U. S. production is now generating 355.5 million metric tons.

Electricity : 520,000 units (USSR 1965 target).
The U. S. is now generating 724,000 million kilowatt hours.

Automobiles : 170,000 units (USSR 1965 target).
The U. S. is now turning out 6 million and can turn out 8 million or more if necessary.

अनुमान और तथ्य

वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। सोवियत संघ की सरकारी घोषणा के अनुसार वर्ष समाप्त होने के ३ महीने पहले ही उसने वर्ष का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उनकी घोषणा को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दीखता। चाँद पर अग्निबाण उतार कर उन्होंने अपने विरोधियों के मुँह बन्द कर दिये हैं।

किन्तु इस विकास का एक और पहलू भी है। प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े भ्रामक होते हैं। विकासोन्मुख देशों की वास्तविक प्रगति का अनुमान तो इन

आंकड़ों से नहीं ही क्रिया जा सकता। सोवियत संघ के आंकड़े प्रायः प्रतिशत वृद्धि के हैं। यदि हम वर्तमान आंकड़ों से प्रतिशत वृद्धि का भाग देते हुये पीछे की ओर लौटें तो इन्कलाब के पहले सम्भवतः शून्य हाथ लगेगा। इन्कलाब के पहले भी वहाँ आदमी रहते थे—उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ थीं—जो पूरी होती ही रही होंगी।

सप्तवर्षीय योजना गवोंकितियों से भरी है। देश विकासोन्मुख है, उसके प्रगति की गति तीव्र है। यह मानने में हमें आपत्ति नहीं है। यदि वे योजना के अन्तिम वर्षों में चॉद या मंगल पर कारखाने खोलने की बात कहते या अपने देश से वहाँ तक सड़क बनाने की योजना बनाते तब भी हमें अविश्वास न होता पर इस बात पर कैसे विश्वास किया जाय कि सारी दुनियाँ के औद्योगिक उत्पादन का आधे से अधिक वे ही पैदा करेंगे। क्या अन्य देश अपने हाथ में दही लगाकर प्रगति की दौड़ के लगाएगें नये रङ्गें ?

अमेरिका का दावा है कि उसके विकास की गति सोवियत संघ १९७० में भी न प्राप्त कर सकेगा। दूसरे शब्दों में यदि सोवियत संघ विश्व के औद्योगिक उत्पादन का ५०% उत्पन्न करेगा तो अमेरिका कम से कम ७५%। हम किसी पर अविश्वास नहीं करते—अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है; हमारी कठिनाई यह है कि दोनों की प्रगति का योग १०० से अधिक हो जाता है और दुनियाँ में केवल ये ही दो देश नहीं हैं; और भी हैं।

अपनी सुनियोजित अर्थ व्यवस्था पर सोवियत संघ को गर्व है किन्तु सब कुछ उसकी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ही होगा इसकी क्या गारंटी है ? उनका आत्म विश्वास सराहनीय है किन्तु यदि देश की मुर्गियाँ पूर्व निश्चित योजना के अनुसार १९६५ तक ३७ अरब अण्डे न दे सकें तो क्या होगा ?

जो हो, सोवियत संघ की प्रगति निःसंदिग्ध है। एक नितान्त नये पथ का अवलम्बन कर अपनी मिहनत और त्याग के सहारे उसने जो प्रगति की है, अनुकरणीय है। इन्कलाब से पहले और उसके बाद भी वह निरंतर बाहरी और भीतरी कलह से आक्रांत रहा है। दोनों महायुद्धों में उसने सक्रिय भाग लिया है। युद्ध का उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। युद्ध उसके लिए घाटे का

सौदा है। योजना की सफलता युद्ध की अनुपस्थिति पर निर्भर है। आइन्स्टीन ने एक बार कहा था 'तीसरे युद्ध की बात मैं नहीं जानता। चौथा युद्ध ईंट-पत्थरों से लड़ा जायगा।' वस्तु स्थिति यही है। नाश के इतने अधिक साधन उपलब्ध हैं कि तनिक सी असाबंधानी या राष्ट्रों की गलत-फहमी न केवल अपने और शत्रु को वरन् मित्रों और निरपेक्ष देशों को भी मृत्यु के मुख में ले जा सकती है। सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में विचाराधीन है। सोवियत संघ ने १२००० सैनिकों की छुटनी कर अपने प्रस्ताव का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है।

अमेरिकी टोह विमान यूरे के सोवियत क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी इधर काफी बढ़ गई है। भविष्य के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता। सप्तवर्षीय योजना की सफलता विश्वशान्ति पर निर्भर है। मानव जाति को नाश से बचाने के लिए आवश्यक है कि उन्नत राष्ट्र गुटबन्दी और आपसी मतभेद को तिलांजलि देकर स्वयं जीयें और दूसरों को जीने दें। गले में पत्थर बाँधकर डूब मरने की तैयारी पागलपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। युद्ध राक्षसी के डिनर की प्लेटें अशक्त राष्ट्रों के रक्त-मांस से सजाई जाएंगी।

अध्याय १७

उद्योग

क्रान्ति पूर्व वर्षों में हलके उद्योग भारी उद्योगों की अनुपात में बहुत अधिक भौगोलिक दृष्टिकोण से भारी उद्योग बहुत असंगठित और असंतुलित थे। अधिकांश उद्योग यूरोपीय भाग ही थे। औद्योगीकरण की दिशा में यह देश ब्रिटेन का चौथाई जर्मनी का पँचाई और संयुक्त राज्य अमेरिका का दसाई था। आर्थिक और टेकनिकल कमियों के कारण जार शाही के युग में अधिकांश मशीनों के लिए विदेशों का मुँह देखना पड़ता था। भारी उद्योगों की प्रायः सभी मुख्य शाखाएं विदेशी पूँजीपतियों के हाथ थीं। फलतः औद्योगीकरण की दिशा में अवरोध आ गया था। अक्टूबर की महान् क्रान्ति ने नई आशाओं, नई परिस्थितियों और नई व्यवस्था को जन्म दिया।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् सोवियत जन समूह ने अपनी स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था को सुरक्षित रखकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सोवियत संघ के औद्योगिक इतिहास में वह समय आपत्ति काल का था। ईंधन, धातु और कच्चे माल की बेहद कमी थी। अधिकांश कारखाने और प्लांट या तो अस्तित्व में ही न थे या बन्द पड़े थे। कोयले और लोहे की बहुतेरी खाने अनजानी थीं जिनका पता था भी उन्हें साधनों के अभाव में उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। जीवन इतना संकुल था कि भोजन और वस्त्र के लाले पड़े थे। युद्ध साम्यवाद के युग में आर्थिक अवस्था और चिन्त्य हो गई।

नई आर्थिक योजना के निर्माण काल में स्पष्ट हो गया कि विदेशी सहायता के अभाव में ही देश को आगे बढ़ना है। इस योजना की सफलता के बाद औद्योगिक उत्पादन युद्ध पूर्व स्तर तक पहुँच चुका था किन्तु सुदृढ़ समाज और औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर होने वाले राष्ट्र के लिए इस प्रगति का कोई महत्व न था। उन्हें औद्योगीकरण के लिए कृषि युग से औद्योगिक युग में प्रवेश करना था। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थापना और निवासियों को सामाजिक सुरक्षा की हर संभव सुविधाएं देना कम्यूनिस्ट पार्टी का उद्देश्य था। लेनिन के शब्दों में, “भारी उद्योगों के अभाव में देश की स्वतंत्रता सुरक्षित न रखी जा सकेगी, सोवियत व्यवस्था नष्ट हो जायगी। इसीलिए हमारे देश की कम्यूनिस्ट पार्टी ने औद्योगीकरण के सर्व मान्य पथ को छोड़कर भारी उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया है।”

आरंभिक योजनाओं में भारी उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल देकर सोवियत सरकार अपनी अर्थ व्यवस्था की नींव दृढ़ करती रही। पूँजी का संकलन देश के ही विभिन्न साधनों से किया गया। विदेशी और उत्तर राज्य व्यापार पर राज्य का ही नियंत्रण था। नियंत्रण और अनुशासन की कठोरता तथा उपभोग वस्तुओं की कमी के कारण द्वितीय योजना की परिसमाप्ति तक सामाज्य जन जीवन पर देश के औद्योगिक विकास का कोई प्रभाव परिलक्षित न हो सका।

N.E.P और .S.E.L. के युग में देखा गया कि निजी उद्योगों की उपस्थिति में योजनाएं पूरी तरह लागू नहीं की जा सकती। किसी एक उद्योग को दूसरे की खाद बनकर नष्ट हो जाना पड़ेगा। सहकारी और सरकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा। क्रमशः उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीय करण कर लिया गया।

प्रथम योजना शीघ्रता में बनाई गई थी। उत्पादन तो अचर्य बड़ा किन्तु उसकी किस्म अच्छी न हो सकी। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन की किस्म और लागत व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अभाव में स्पर्द्धा में उत्पादक टिक ही नहीं सकता। उपभोक्ता को वस्तु से काम है उसे कोई बनाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्रा पर अधिक ध्यान दिया गया। दूसरी योजना में किस्म पर ध्यान दिया जाने लगा। तीसरी योजना से माल अच्छा बनने लगा था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों के लिए भारी मशीनें बनाई गईं। धीरे धीरे देश भर में उद्योग और शक्तिगृह फैल गए। खोरकोव और स्तालिनग्राद में ट्रैक्टर, मास्को और निजनीनोवग्राद में स्वचालित यंत्र मैगनितोभोरस्क और कुजनेत्सक में रसायनिक तथा अन्य उद्योग स्थापित किए गए। प्रथम योजना ने सोवियत की आर्थिक प्रगति के द्वार खोल दिए। हूसिया वाले हाथ हथौड़ा और पेंचकस की ओर बढ़ने लगे।

द्वितीय योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करना था। समय से पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई। योजना में हलके उद्योगों की स्थापना की भी व्यवस्था थी। १९३७ तक १९१३ की अपेक्षा बड़े उद्योगों ने ८ गुनी प्रगति की। पूँजीवादी निजी व्यवस्था अन्तिम सल्ले ले रही थी और समाजवादी अर्थ व्यवस्था की जड़ें मजबूत होने लगी थीं।

तृतीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन की किस्म उन्नत करना तथा प्रति एकड़ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। १९३८ तक की औद्योगिक प्रगति अधोलिखित हैं—

❀ उत्पादन

	१९१३	१९२९	१९३३	१९३७	१९३८
इन्जीनीयरिंग एवं घाट उद्योग (मिलीयाई)					
रुबल १९२६—२७ के मूल्य पर)					
इंजन	१,४४६	३,०५४	१,८२२	२७,५१९	३३,६१३
माल डोने वाले ट्रैक	४१८	६०२	९४१	१५८१	१,६२६
मोटरकार (हजार में)	१४८	१५.९	१८.२	६६.१	४९.१
बिजली (मिलीयाई कि० वाट)	—	१.४	४९.७	२००.०	२११.४
क्रोयला (दस लाख टन में)	१.९	६.२	१६.४	३६.४	३९.६
तेल (दस लाख टनों में)	२९.१	४०.१	७६.३	१२७.९	१३२.९
मेगनीज (हजार टनों में)	९.२	१३.८	२२.५	३०.५	३२.२
कच्चा लोहा (दस लाख टनों में)	१,२४५	७०२	१,०२१	२,७५२	२,२७३
स्यात (दस लाख टनों में)	४.२	४.०	७.१	१४.५	१४.६
ताँबा (हजारों टन में)	४.२	४.९	६.९	१७.७	१८.०
एलमूनियम (हजार टनों में)	—	३५.५	४४.५	९९.८	१०३.२
सीमेंट (मिलीयन टनों में)	—	—	७.०	३७.७	५६.८
रुई के कपड़े (१० लाख मीटर में)	१.५	२.२	२.७	५.५	५.७
ऊनी कपड़े (१० लाख मीटर में)	२,२२७	३,०६८	२,४२२	३,४४७	३,४९१
	९५	१००.६	८६.१	१०८.३	११४.०

❀ The development of the Soviet Economic System By Alexander Baykov PP. 307.

उद्योग

३५

प्रथम विश्व युद्ध ने तीसरी योजना का उद्देश्य पूरा न होने दिया। युद्ध से पहले की इन योजनाओं ने अपेक्षित सफलता प्राप्त की। बड़े बड़े राजकीय उद्योग स्थापित हुए जिनमें मैगनितोगार्क्स और कुजनेत्स्क के लोहा और फौलाद के कारखाने प्रमुख हैं। १९४० में इस देश में १५० लाख टन कच्चा लोहा (१९१३ का चार गुना), १८३ लाख टन फौलाद (१९१३ से साढ़े चार गुना), ३१० लाख टन तेल (१९१३ से साढ़े तीन गुना) निकाला।

इन योजनाओं द्वारा यूराल और सिबेरिया के औद्योगिक क्षेत्रों को प्रगतिशील बनाया। १९४० तक स्थिति अनुकूल हो चुकी थी। इस समय १९१३ की अपेक्षा वृहद् स्तर उद्योग १२ गुना, मशीन निर्माण ५० गुना हो गया था। आयात तो बंद हो ही चुका था। आटोमोबाइल आदि का निर्यात भी होने लगा था।

युद्ध काल में नाजियों के विध्वंसात्मक कार्यों द्वारा देश को काफी क्षति उठानी पड़ी। दक्षिणी भाग के ६८% कच्चा लोहा और ५८% लोहा के क्षेत्र जर्मनी के अधिकार में जा चुके थे। ३१८५० बड़े उद्योग और खाने आदि नष्ट हो गईं थी। युद्ध काल में ही १३०० बड़े उद्योग यूराल और सिबेरिया में स्थानान्तरित किए गए जो १९४२ से पुनः कार्य करने लगे। युद्ध में ६७६०००० लाख रूबल की क्षति हुई। युद्ध के दो शुभ परिणाम सामने आए—

१—औद्योगिक देशों ने सोवियत संघ की साख मान ली।

२—भौगोलिक दृष्टि से सोवियत उद्योगों में संतुलन आया।

१९५० में २६०० लाख टन कोयला निकाला गया। तेल उद्योग युद्ध पूर्व स्तर तक पहुँच गया।

छठी योजना में ६००० नए भारी उद्योगों की स्थापना की गई। १९५५ का औद्योगिक उत्पादन १९४० को तुलना में सवा तीन गुना अधिक था।

भारी उद्योग

धातु

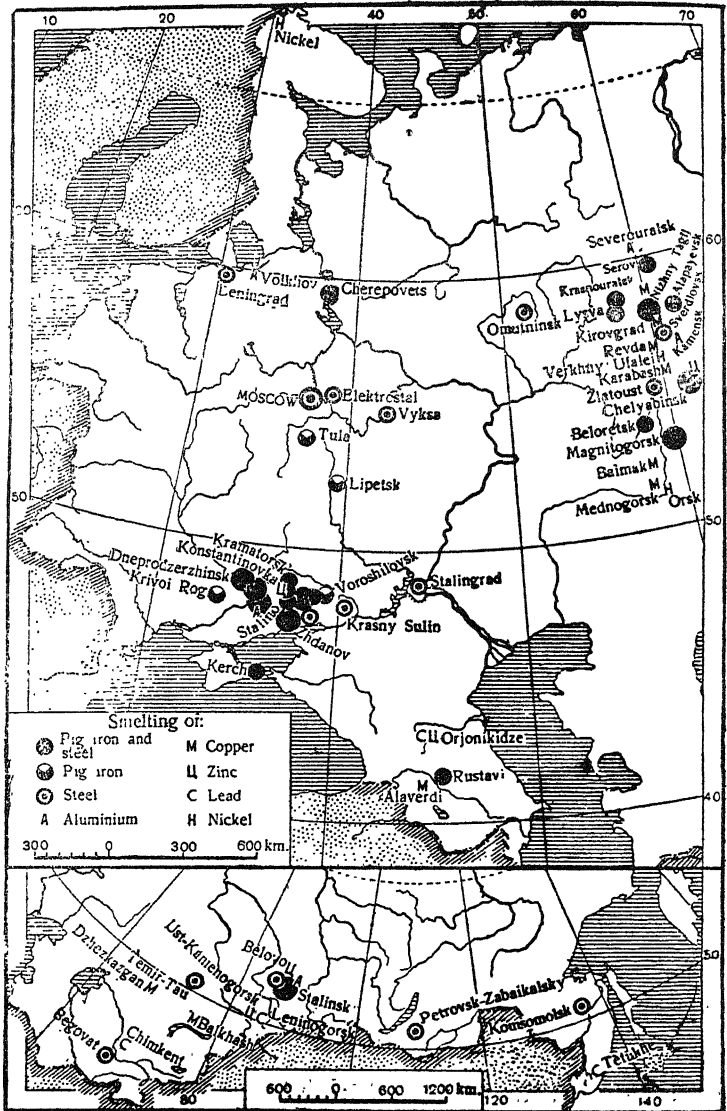
क्रान्ति से पहले उक्रेन खनिज क्षेत्र था। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा इसे नये सिरे से परिष्कृत किया गया। आज यह पहले से कुछ गुना अधिक कोयला, कच्चा लोहा और फौलाद देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूराल, कुजबास और कजाखस्तान की खानों में खुदाई होने लगी। युद्ध से पहले ये खाने छुई भी न गई थीं। अक्रेले यूराल की खानों में कोयला और तेल इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों को कहीं दूसरी जगह से खनिज पदार्थ मंगाने की आवश्यकता नहीं है। उक्रेन, बेलोरूसी, मोल्दाविया, लिथोनिया, लतविया, इस्तोनिया, करेलियन जनतंत्र और मध्य के क्षेत्रों को यह धातुएं भेजता है।

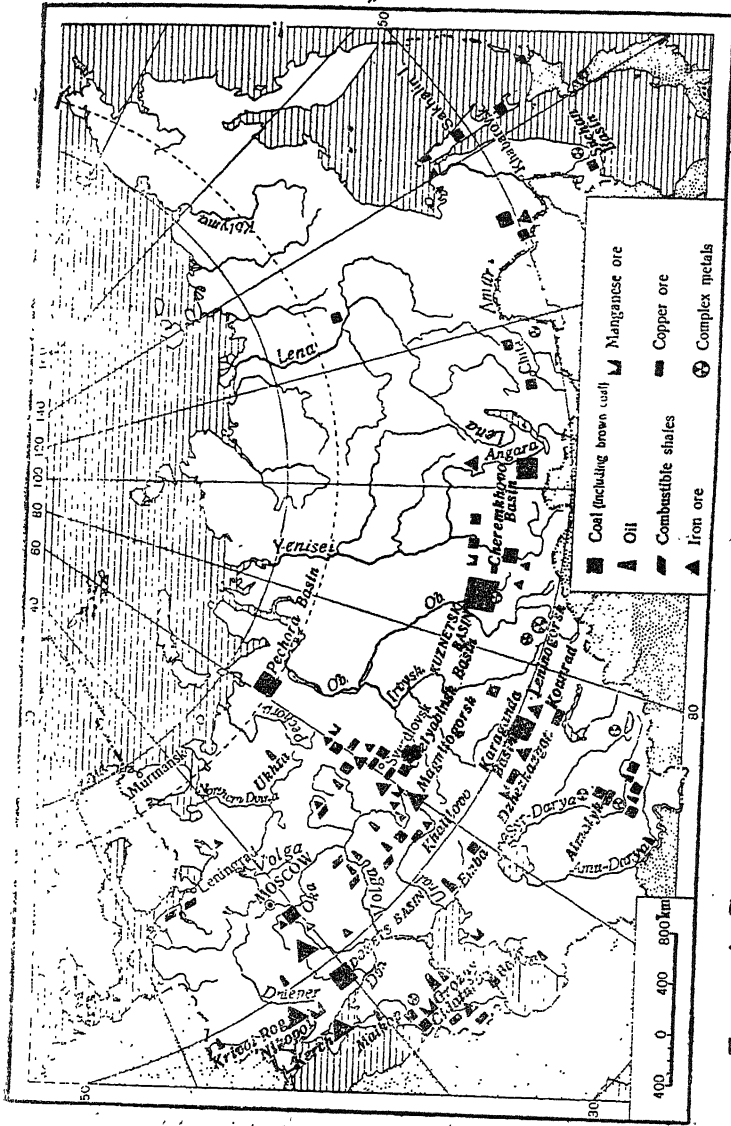
द्वितीय विश्व युद्ध के समय देश के पूर्वी क्षेत्र में कोयले की खाने, कच्ची धातु (ore) की खाने, शक्ति गृह, खनिज तथा मशीन निर्माण के उद्योग खोले गए।

१९३० से कुजनेत्स्क के इस्पात के कारखाने का निर्माण प्रारंभ हुआ और १९३२ में इसका एक भाग बनकर तैयार हो गया। इसका वार्षिक उत्पादन १९१३ के सम्पूर्ण रूस के वार्षिक उत्पादन के बराबर था। इस कारखाने की अपनी रेल, रसायनिक उत्पादन का क्षेत्र, खान, दूकान आदि हैं। यह कारखाना स्वयंपूर्ण है। पहले १२०० टन यूराल की खान से कच्चा लोहा मंगाया जाता था। अब निकट वर्ती क्षेत्र से ही प्राप्त है। उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है।

मैगनीतोगोरस्क लोहा और फौलाद उद्योग दक्षिण यूराल में स्थित है, चेल्येबिंस्क क्षेत्र पूर्वी भाग का दूसरा औद्योगिक संस्थान है। १९५५ में यूराल और पश्चिमी सिबेरिया की खानों में १४० लाख टन कच्चा लोहा निकाला गया था। यद्यपि इस खान की क्षमता ब्रिटेन से अधिक है किन्तु इतने माल से पूर्वी क्षेत्र का काम नहीं चलता, यूरोपीय क्षेत्र से कच्चा लोहा मंगाना पड़ता है। १९६२ तक सिबेरिया में १५०—१२० लाख टन वार्षिक क्षमता वाली खान कच्चा लोहा उत्पन्न करने लगेगी।

Economic Geography of U.S.S.R. लेखक — श्री यन० यन नारायणसक्की — पृष्ठ ४१ से सामानर





Economic Geography of U.S.S.R. लेखक - बन० यन० वारानसकी - से सामार - पृष्ठ २६

निकट भविष्य में मध्य और पश्चिमी भाग कच्चे लोहे की दृष्टि से आत्म निर्भर हो जायगा। कुर्क के आस-पास कच्चे लोहे के बहुत बड़े भंडार का पता चला है। अनुमान है कि विश्व का लगभग आधा लोहा इन खानों के भीतर है। लोहा निकालने की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यहाँ लोहा बालू के नीचे है।

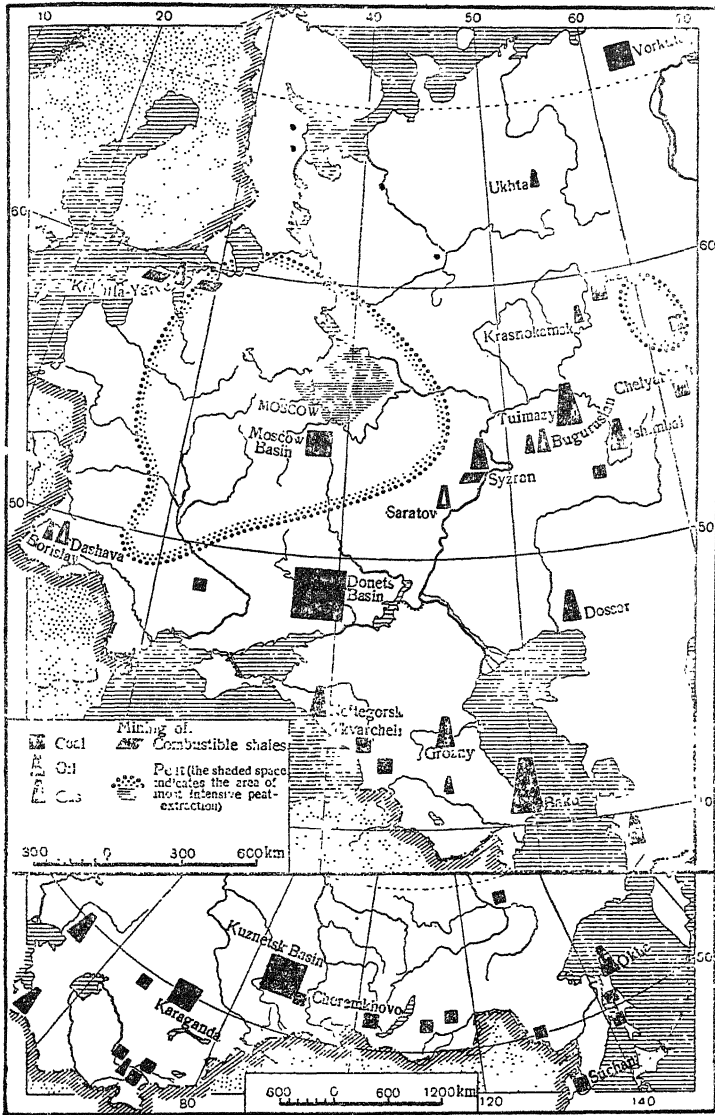
१९३३ की तुलना में अब ११ गुना फौलाद बनाया जाने लगा है। १९५५ में सोवियत संघ ने ४५३ लाख टन इस्पात बनाया था। जब कि ब्रिटेन फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी का कुल फौलाद उत्पादन ५४० लाख टन था। स्मरणीय है १९३७ में ये देश सोवियत संघ का दूना फौलाद बनाते थे।

छुठी योजना का लक्ष्य ५३० लाख टन कच्चा लोहा, ६८३ लाख टन इस्पात, ५२७ लाख टन दलुई धातुएं हैं। सप्तवर्षीय योजना में तो लक्ष्य तथा उत्पादन और बढ़ गया है।

औद्योगिक ईंधन (Fuel)

१९५६ में सोवियत संघ ने ४२६० लाख टन कोयला उत्पन्न किया था। यह संख्या १९१३ की ग्यारह गुनी थी।

पहले काकेशिया और मध्यवर्ती क्षेत्रों में ही तेल का उत्पादन होता था कालान्तर में देश के अन्य भागों में भी तेल का पता चला। १९५६ में ८४० लाख टन तेल निकाला गया था। तातार में तेल का उत्पादन सर्वाधिक है। बश्किया मध्यवर्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त अब सिबेरिया को भी तेल देने लगा है। ओमस्क में तेल साफ करने का कारखाना खोला गया है। जहाँ बश्किया का तेल साफ किया जाता है। यह तेल ८२७ मील लम्बी पाइप लुइमाजा ओमस्क द्वारा इस कारखाने में लाया जाता है। १९६० तक यह पाइप लाइन इरकुत्स तक (२३०० मील लम्बी) कर दी जायगी।



Economic Geography of U.S.S.R. लेखक - श्री यन० यन० भारद्वाज - पृष्ठ ३२ से सामान

प्राकृतिक गैस

प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सरतोब के प्राकृतिक गैस के भंडार को विकसित किया जा रहा है। ५२२ मील लम्बी पाइप द्वारा यहाँ से प्राकृतिक गैस मास्को ले जाई जाएगी। स्तब्रोपोल क्षेत्र में नए प्राकृतिक गैस के भंडार का पता चला है। यहाँ से मास्को को ८०७ मील लम्बी पाइप लाइन द्वारा मिला दिया गया। यह यूरोप की सबसे लम्बी गैस लाइन होगी और इसका दूसरा भाग पूरा होने पर मास्को को पहले की अपेक्षा २० गुना गैस मिलेगी।

एस्तानियाँ में एक शेल गैस कम्पनी बनाई गई है जो लेनिन ग्राद के क्षेत्र को गैस पहुँचाती है।

मशीन निर्माण

१९५५ का मशीन निर्माण १९१३ की अपेक्षा २७ गुना था।

मास्को गोरी और मिनिस्क में स्वचालित यंत्रों (Automobile) के कारखाने हैं जहाँ प्रतिदिन हजारों कारें बनाई जाती हैं। मास्को आटो वर्क्स (Moscow Auto Works) जन-वाहक गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गोर्की स्थित मोलोतोव आटो वर्क्स वोल्गा जनवाहक गाड़ियाँ बनाता है।

स्तालिन ग्राद खारकोव, अल्ताई, ब्लादिमिर, लिप्सतस्क आदि क्षेत्रों में ट्रेक्टर बनाए जाते हैं। देश भर में १५ अश्व शक्ति के ३ लाख ट्रेक्टर प्रति वर्ष बनते हैं। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली अन्य बड़ी मशीनें रोस्तोव, ब्यूेल और ताशकंद में बनाई जाता है। छुट्टी योजना में रेडियों इंजिनियरिंग यातायात और कृषि मशीनों के बड़ी संख्या में निर्माण की व्यवस्था थी।

इस समय देश भर में अनुमानत साढ़े छः लाख स्वचालित यंत्र प्रति वर्ष बन रहे हैं।

रसायनिक उद्योग (Chemical Industry)

पिछले २५ वर्षों में सोवियत संघ ने रसायनिक उद्योगों का नये सिरे से

निर्माण किया। अन्य उद्योगों की नींव जारशाही में ही रखी जा चुकी थी किन्तु रसायनिक उद्योग अपेक्षया नया है। बेरेजिंस्की, बाब्रिकोवो आदि नगरों के रसायनिक प्लान्ट देश की रसायनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं।

लगभग २ करोड़ टन कृषि उत्पादन बढ़ाने भर को खाद प्रति वर्ष बनाई जाती है। कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, अलकोहल आदि बनाने के अनेक कारखाने जहाँ तहाँ बिखरे हैं।

विद्युत शक्ति (Electric Power)

१९५६ में १९२०००० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती थी। १९६० के अन्त तक ३२० अरब किलोवाट घंटा बिजली पैदा की जाएगी।

देश में कोयला-विद्युत केन्द्र (Thermal Power Station) भी हैं। इस ओर अपेक्षया कम ध्यान दिया जा रहा है। कोयले से शक्ति उत्पन्न करने की प्रकृया अस्वास्थ्यकर और खर्चीली है। नये शक्ति गृह जब काम करने लगेंगे तो उनमें से प्रत्येक की क्षमता १-१.५ लाख किलोवाट टरवाइन होगी।

दस लाख किलोवाट से अधिक की क्षमता वाले तामयूनिस्क, त्रौयत्स्क दक्षिणी यूराल स्त्रोवेशेय (उक्रेन) और नाजारोव (सिबेरिया) कोयला विद्युत केन्द्र बनाए गए हैं।

सोवियत नदियों से ३००० लाख किलोवाट जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। यदि देश भर की जल शक्ति का उपयोग किया जा सके तो १५ खरब किलोवाट-घंटा बिजली उत्पन्न होगी। सबसे पहले १९३२ में द्नीपर नदी पर वोल्कोत जल-विद्युत केन्द्र बना था। इसकी क्षमता ५,५८,००० किलोवाट थी। सेरदार्या नदी पर स्थित केरकुम (मध्य एशिया) जल विद्युत केन्द्र सबसे बड़ा है। यह ताजकिस्तान, उजबकिस्तान, कजाखस्तान, और किरगीज को शक्ति देता है। १९५६ से इकुत्स्क जल-विद्युत केन्द्र ६,६०,००० किलोवाट वार्षिक पैदा कर रहा है। सातवीं योजना का लक्ष्य बहुत ऊँचा है।

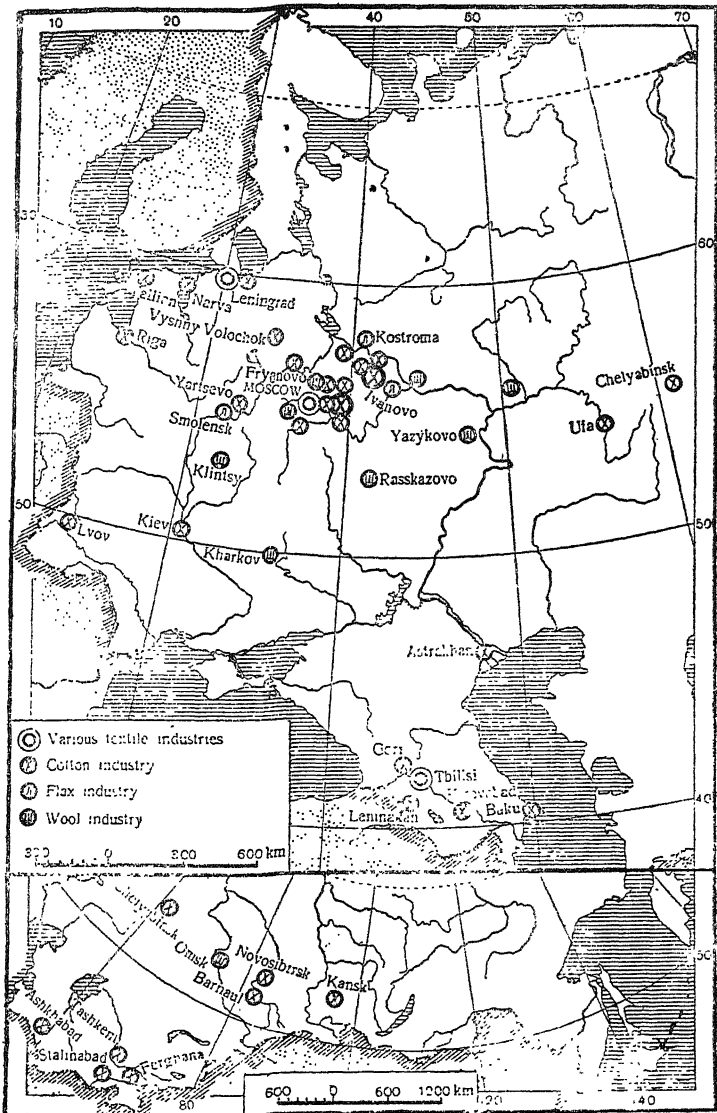
उपभोग की वस्तुएँ

जार शाही के युग में उत्तरी भाग में बुने हुए वस्त्र (Textile) बनते थे। इनका परिमाण संख्या में अत्यन्त स्वल्प था। क्रमशः मध्यवर्ती पश्चिमी सिबेरिया उक्रेईन, बेलो रूसी तथा बाल्तिक्क जनतंत्र में जूता मोजा आदि बनने लगे।

सोवियत शासन के आरंभिक बीस वर्षों में खाद्य पदार्थ ४४ गुना, बुने वस्त्र ३२ गुना कारखानों में निर्मित जूते २० गुना उत्पादित हुए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में (१९३७) में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन ६५ गुना १९१३ की अपेक्षा बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक वर्षों में फरनीचर, कपड़े तथा घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुओं का उत्पादन प्रायः पश्चिमी यूरोप के स्तर तक पहुँच चुका था। युद्ध के कारण उद्योगों को बहुत क्षति उठानी पड़ी किन्तु चौथी योजना की सफलता के बाद सोवियत उद्योग युद्ध पूर्व (१९४०) स्तर से आगे बढ़ गया।

१९५० में हलके उद्योगों का उत्पादन १९५० की अपेक्षा बहुत अधिक था। युद्ध काल में और उसके बाद भी यूराल सिबेरिया, माल्देविया, वोल्गा और दूर पूर्व प्रदेशों में नये उद्योग प्रारम्भ किये गए। कमेसी टेक्सटाइल कम्बाइन (Kamyshin Textile Combine) जो वोल्गा तट पर स्थित है ११ लाख गज कपड़ा प्रति वर्ष तैयार करता है। नव-निर्मित पोल्तावा मांस केन्द्र और कोकंद, लिस्की, कर्शी और खवरोवस्क आदि में अनेक चीनी साफ करने के कारखाने हैं। अल्मा अता (कजाखस्तान) में डेढ़ लाख डिब्बा (can) मांस प्रति दिन तैयार होता है। वर्ष भर में लगभग ६ अरब गज सूती कपड़ा, लगभग ३ करोड़ गज ऊनी कपड़ा, ३१४ करोड़ जोड़े जूते, ४३५ लाख टन चीनी, २३६८ टन मांस और १७३ लाख टन दुग्ध सामग्री उत्पन्न की जाती है। इस समय १९५६ की अपेक्षा १५% अधिक उपभोग की वस्तुएँ बन रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद २५००० नई मशीनें, ४०० स्वचालित यंत्र उत्पादन केन्द्र और ३००० अर्द्ध स्वचालित मशीनें नई बनाई गईं। सिल्क वस्त्र १९१३ की अपेक्षा १७ गुना अधिक बनाया जा रहा है।

Economic Geography of the U.S.S.R. — लेखक — यन० यन० बापानसकी से संपादन — पुष्ट — ५५



खाद्य उद्योग (Food Industry)

१९१३ में खाद्य पदार्थों का बुरी तरह अभाव था। यह बात अरि है कि देश में एक ऐसा भी वर्ग था जो खाद्य पदार्थों का अपव्यय कर रहा था किन्तु खाद्य पदार्थों की औसत उपलब्धि प्रति व्यक्ति १० किलोग्राम चीनी, ३ कि० ग्रा० तेल, ६ टिन बन्द भोजन प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं थी। चीनी का उत्पादन इतना कम था कि निवासियों को बिना चीनी की चाय पीनी पड़ती थी। युद्धत साम्यवाद के समय तो अवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी।

देश की खाद्य समस्या सुलभाने के लिए आवश्यक है कि—

- १—देश शक्ति सम्पन्न हो,
- २—उद्योग मुख्यतः भारी उद्योग उन्नत हों,
- ३—घाट्ट, शक्ति (Power) औद्योगिक ईंधन (Fuel) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों,

४—भूमि उर्वर हों और

५—जनसंख्या और उत्पादन का संतुलन बना रहे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमाने के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। खाद्य पदार्थों के उत्पादन संस्थान केन्द्रीय यूनियन द्वारा संचालित होने लगे। तीन विभिन्न मंत्रालयों की स्थापना हुई—

१ - खाद्य और उद्योग मंत्रालय

२—मत्स्य

३—मांस और पशु पालन

खाद्य उद्योग के संगठन के लिए विशिष्टीकरण की नीति अपनाई गई है। २२००० बड़े खाद्य उद्योग ३० विभिन्न शाखाओं में विभक्त कर दिए गए हैं।

रेलों की आय का दसवां भाग खाद्य पदार्थों का किराया है। मौसम में प्रायः ६००० बैगन चुकन्दर प्रतिदिन ढोया जाता है। २५० बैगन पशु (इसमें मुर्गियाँ भी शामिल हैं) प्रतिदिन रेलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ले जाए जाते हैं। वर्ष भर में प्रायः १३० लाख टन औद्योगिक ईंधन ढोया जाता है।

खाद्य उद्योग में अणु शक्ति के प्रयोग के कारण सोवियत संघ की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई है। इस समय वह अपने नागरिकों को विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मक्खन देता है।

• चीनी

चीनी को रूसी भाषा में सक्कर कहते हैं। कहना न होगा कि रूसी सक्कर संस्कृत शर्करा और हिन्दी शक्कर के अंग्रेजी शुगर की अपेक्षा अधिक निकट है। द्वितीय युद्ध काल में सोवियत शक्कर उद्योग की बड़ी क्षति पहुँची थी। २११ शक्कर उद्योग केन्द्रों में १६६ नष्ट हो गए थे। किन्तु १९५० तक वह युद्ध पूर्ण स्तर तक पहुँच चुका था। शक्कर उद्योग का क्रमिक विकास निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है—

वर्ष	उत्पादन
१९१३	१३,४७,०००० टन
१९५५	३५,००,००० टन
१९६०	६५,००,००० टन अनुमानित

जनता को आज युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा ७०% अधिक चीनी उपलब्ध है।

मांस

सोवियत संघ में डिब्बों में मांस बन्द करने के ४७५ कारखाने हैं। इन कारखानों को विभिन्न मांस की दूकानों तक माल पहुँचाना पड़ता है। १९६० तक ४० लाख टन मांस प्रति दिन तैयार होगा।

सोवियत मांस उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता मृत पशु का कोई अंग बेकार न होने देना है। मृत पशु के खून से शज्स नामक एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। चमड़े की जरूरी, हड्डियों की बटन और कंधी, गिल्डियों (glands) की दवाएँ, आतों से वायलिन और गेटार के तार-समष्टि में चीलों के लिए कुछ नहीं बचता है।

पशु धन से प्राप्त खाद्य पदार्थ उत्पादन की समाजवादी प्रणाली द्वारा उपलब्ध हैं। १९५८ में सरकार की कुल खरीद का ८६% दूध, ८४% मांस ६०% ऊन सामूहिक और सरकारी फार्मों से खरीदा गया था।

विगत ५ वर्षों में सोवियत संघ के पशु धन की वृद्धि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है—

	१९५३	१९५८
पशु	५.५८ करोड़	७.०८ करोड़
जिसमें—	'	
गाएँ	२.५२ "	३.३३ "
सूअर	३.३३ "	४.८७ "
भैंड़	६.६८ "	१२.६६ "

पशु धन की वृद्धि के फलस्वरूप पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। १९५४-५८ तक के ५ वर्षों में दूध ६१%, मांस ३२% अंडा ४४% और ऊन ३६% बढ़ा।

दूध

दूध के अनेक प्रयोग हैं—जमाया हुआ दूध (Condensed Milk) पाउडर, मक्खन (Cream) आदि। १९५४ में मक्खन बनाने वाले कारखाने केवल १८० थे जो २ वर्ष बाद बढ़कर ४०० हो गए; १९६१ तक इनकी संख्या १५०० हो जायगी। इस वर्ष सोवियत संघ की उत्पादन क्षमता ६ लाख लिटर प्रतिदिन है।

मछलियाँ

सोवियत संघ के ३ समुद्रों, १२ भीलों और सैकड़ों नदियों द्वारा वर्ष भर में ४२ लाख मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। विज्ञान के अधुनातम साधनों के कारण अब ३००-४०० मीटर गहरे समुद्रों में भी मछलियाँ सरलता से पकड़ी जा सकती हैं। पानी के भीतर एक विशिष्ट बल्ब जला कर मछलियों को आकर्षित किया जाता है जहाँ आकर वे जाल में फँस जाती हैं। कहीं-कहीं ध्वनि से भी मछलियों को आकर्षित किया जाता है। मछली सुरक्षित रखने के ६००० कारखाने हैं।

टिन और वितन्तु तरंग

शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को पहले धूप में सुखा कर वर्ष में दबा कर सुरक्षित रखा जाता था। अब इस कार्य के लिए वितन्तु तरंग (Radio

wave) विद्युत धारा (Electronic currents) और आणविक शक्ति (Atomic energy) का प्रयोग किया जाता है। ये साधन अपेक्षया महंगे हैं और वृहद् स्तर के संग्रह पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

सोवियत संघ में इस समय ५०० विभिन्न प्रकार के डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ बनते हैं। डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों की वृद्धि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है—

१९४०—७२७० लाख, १९५०—१०,००० लाख, १९६०—५,५००० लाख डिब्बे।

वनस्पति तेल

वनस्पति तेल के लिए ३५ प्रकार की विभिन्न फसलें पैदा की जाती हैं जिनमें सूरज मुखी, अलसी और सोयाबीन प्रमुख हैं। १९१३ में सूरजमुखी और अलसी का क्षेत्रफल १३,७१,००० हेक्टर (१ हेक्टर = २.४७ एकड़) था जो १९५८ में बढ़कर ५१,४६,००० हेक्टर हो गया। १९५४ से ५८ तक के ५ वर्षों में वनस्पति तेल का उत्पादन ५४% बढ़ा है।

१९६० में वनस्पति तेल (Vegetable Oil) का वार्षिक उत्पादन १८.४ लाख टन वार्षिक था।

सूर्यमुखी (Sun flower) बड़ा उपादेय पौदा है। यह खाने और तेल निकालने के काम आता है। इसकी भूसी पहले जलाई जाती थी अब इससे शराब बनाई जाती है।

अध्याय १६

यातायात

विश्व के छठवें भाग पर फैले इस विशाल देश की एक सूत्रता के लिए यातायात के उन्नत साधन अत्यन्त आवश्यक हैं। देश की जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। अधिकांश जनसंख्या देश के यूरोपीय भाग और पश्चिमी एशिया में ही निवास करती है। औद्योगिक दृष्टि से भी ये ही प्रदेश महत्वपूर्ण हैं। दोनेत्स घाटी, कजनेत्स घाटी, वाकू और यूराल के खनिज पदार्थों का उपयोग मास्को के उद्योग करते हैं। स्पष्ट है कि २००० किलोमीटर और इससे भी अधिक दूरी को परिवाहन के उन्नत साधनों के अभाव में मिलाया नहीं जा सकता।

रेल

फ्रान्सीसी इंजीनियारों और पूँजी के सहयोग से १८३६ में पहले रेल बनी किन्तु क्रिमिया युद्ध से पहले इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। १८४० में केवल २६ किलोमीटर रेल की पटरी थी। क्रमशः रेलों का विस्तार होता रहा। अधोलिखित आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो जायगी—

रेल यातायात (हजार किलोमीटर में)

वर्ष	१८४०	१८५०	१८६०	१८७०
रेल की पटरियां	०.२६	६.०१	१.५८६	११.२४३
वर्ष	१८८०	१८९०	१९००	१९१०
रेल की पटरियां	२३.८५७	३०.९५७	४८.१०७	५९.५५६
वर्ष	१९१३	१९१४	१९२५-२६	१९२६
रेल की पटरियां	५८.५	६२.२	७४.४	७७
वर्ष	१९३५	१९३७		
रेल की पटरियां	८३.८	८५		

यद्यपि प्रत्येक योजना में रेलों के निर्माण और परिष्कार पर पहले से अधिक धन व्यय किया जाता रहा है किन्तु योजना के कुल विनियोग में उसका प्रतिशत निरन्तर कम होता रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों की मद में २३.८% धन खर्चाया गया और सप्तवर्षीय योजना में केवल ५.५%

१९५५ में ७५,००० मील लम्बी रेल की लाइने थीं। रेल यातायात को दृष्टि से सोवियत संघ का स्थान विश्व में दूसरा (प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका) है।

तुर्क सिब (Turkestan—Siberian Railway) रेलवे का निर्माण कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है। यह रेल ४,२५० मील लम्बी है। इस रेल द्वारा मध्य एशिया के रूस के क्षेत्र, कुजवःस की कोयले तथा धातु की खानें, अस्ताई, कजाखस्तान तथा सिबेरिया के औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाएगी।

जार युग में विद्युत चालित रेलें नहीं थीं। क्रान्ति के बाद कई रेलें विजली से चलने लगीं। प्रौद्योगिकी योजना में १४०० मील रेल लाइन पर विजली का उपयोग किया जाने लगा।

१९६२ तक २००० से अधिक विद्युत इंजन, टाई हजार डीजल के नए इंजन ५०३० मील लम्बी नई लाइनें बन जाएगी। डीजल वाली रेल गाड़ियों में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इस समय डीजल का प्रयोग ४,४०० मील किया जाता है सप्तवर्षीय योजना के बाद १५,५०० मील पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जायगा। सप्तवर्षीय योजना में ४००० मील लम्बी नई लाइनें बनेगीं।

पड़ोसी देशों के साथ भी रेलों द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया है। पीकिंग, वियना, हेलसिंकी, बर्लिन, वारसा, प्रोग, सोफिया, बुदापेस्त, बुचरेस्त, बेलग्राद आदि से सोवियत संघ का सीधा यातायात है।

रेलों का वितरण

देश भर में रेलों का वितरण एक जैसा नहीं है। अधिकांश रेलें

काकेशस और यूरोपीय क्षेत्र में हैं। सिबेरिया और मध्य एशिया में अपेक्षाकृत कम रेलें हैं। सिबेरिया के उत्तरी भाग में तो रेलें नहीं ही हैं।

मध्यवर्ती एशिया यूरोपीय भाग की दो बड़ी रेलों से सम्बन्धित हैं—

१—चेलकोव से ताश कंद तक

२—क्रान्सनोवोदस्क से समर कंद तक

देश के यूरोपीय भाग में भी रेलों का वितरण बड़ा असमान है। वोल्गा से स्तालिनग्राद, लेनिग्राद से शेर्चर नको और स्तालिनग्राद से रोस्तोव की तीन मुख्य लाइनों को छोड़कर सभी का विस्तार असमान है। रेलों के विस्तार औद्योगिक दृष्टि कोण प्रधान है। सबसे अधिक रेलें उक्रैन में हैं।

रेलों से प्राप्त होने वाली आय क्रमशः बढ़ती जा रही है। रेलों की निरन्तर बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए दोहरी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। पाँचवीं योजना में रेलों के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया था। नये आराम देह डिब्बे, नई पटरियाँ, विभिन्न प्रकार के नए इंजन, ६,५०० किलोमीटर नई लाइनें और ६,६०० किलोमीटर दोहरी लाइनें बनाई गईं।

जल यातायात

सोवियत संघ में तीन बड़ी नदियाँ हैं—अमूर, लीना, अंगारा के साथ यनसी अतिशय के साथ ओबी और वोल्गा। यूरोपीय क्षेत्र में दान, दूनीपर, पश्चिमी देविना और वोल्गा नदियाँ हैं जो काला वास्तिक और कैस्पियन समुद्रों में गिरती हैं। काकेशस और मध्य एशिया की नदियाँ यातायात की दृष्टि से कम महत्व रखती हैं। आर्थिक दृष्टि से इन नदियों पर कम खर्च में यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। शीत ऋतु में बरफ जम जाने से अधिकांश समय में यद्यपि ये नदियाँ उपलब्ध नहीं होतीं—इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता। ग्रीष्म में बरफ पिघलने के बाद इनके द्वारा काठ (Timber) खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ, तेल आदि देश के अन्य भागों में भेजा जाता है।

वोल्गा नदी की आय सब नदियों के अधिक है। वोल्गा नदी की हम रूस की गंगा कह सकते हैं। उस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता है ही औद्योगिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। इसका कारण जन संख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास है। खाद्य पदार्थ, मछली, नमक क्रित्रिम खाद और कच्ची धातुएं इसी नदी से भेजी जाती हैं। मास्को, अस्तर खान, स्तालिन ग्राद, सारातोव, बिबिश्नोव, कजान, गोर्की, यारोस्लोव, शेर्चेव कोव आदि नगरों की समृद्धि बहुत कुछ वोल्गा पर निर्भर है।

मास्को लेनिन ग्राद नहर, लेनिन वोल्गादान नहर, ट्नीपर बक नहर, कार्ल्तक नहर तथा अन्य छोटी मोटी नहरें यातायात, व्यापार और सिंचाई के क्रम में अती हैं।

मजदूर, मजदूर सङ्घ और मजदूरी

मानवीय भावनाएं आर्थिक नियमों में नहीं बंधती। सोवियत संघ के परिवर्तन, उसकी कार्य प्रणाली—कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज है, नहीं कहा जा सकता। वहां समस्याएँ सुलभाईं गईं घसीटी नहीं गईं। काम करने में गलतियाँ तो होती ही हैं, सुधारी भी जाती हैं। परिवर्तनों ने आर्थिक व्यवस्था के नए पहलू की मांग की। इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। सोवियत अर्थ नीति और राजनीति के आमूल परिवर्तनों की उपादेयता पर मतभेद तो सकता है किन्तु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रान्स और सोवियत की क्रान्ति ने मजदूर को गर्व से-सिर उठाकर चलना सिखा दिया, मजदूर के मनमें यह विश्वास भर दिया कि वह उत्पादन यंत्र का शीघ्रता से नष्ट होने वाला एक निरीह पुर्जा मात्र नहीं है, एक अपरिहार्य अंग है, एक महत्वपूर्ण इकाई है।

सोवियत मजदूर संघों का अध्ययन करते समय जो बात हमारा ध्यान सबसे पहले आकर्षित करती है वह यह है कि गैर कम्युनिष्ट देशों के मजदूर संघों को जितना अधिकार देना कम्युनिष्ट आवश्यक समझते हैं उसका शतांश भी सोवियत संघ में नहीं है। बात चौंकाने वाली है किन्तु इसके मर्म तक पहुँचने के लिए साम्यवादी दर्शन का निरपेक्ष चिन्तन आवश्यक है। सिद्धान्तः उत्पत्ति के साधनों पर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के पश्चात् मजदूरों और प्रबन्ध संचालकों के बीच किसी प्रकार के असंतोष और मतभेद के लिए अवकाश नहीं रहता। घड़ी के पुर्जों की तरह उत्पत्ति के सभी साधन परस्पर संबंधित होते हैं। किसी एक के रुकने से पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। वहाँ उत्पादन की योजना के साथ ही मजदूरों निश्चित हो जाती है—काम शुरू हो जाने पर दबाव डालना व्यर्थ होता है।

श्रमिकों के सम्बन्ध में दो बातें विशेष महत्व पूर्ण हैं—

१—संघटन

२—काम करने का प्रोत्साहन ।

मजदूरी का उत्पादन निर्धारण के अनुसार होता है। लालाभांश में मजदूरों को हिस्सा नहीं मिलता। उत्पादन और कार्य सामूहिक होते हैं।

सोवियत मजदूर सङ्घ कारखाने के संघटन की आधारीक इकाई होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र केवल उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। ये एक प्रकार की शिक्षण संस्थायें भी हैं। यहां कुशलता और कार्य क्षमता की वृद्धि का प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है यदि श्रमिक प्रतिभा सम्पन्न हुआ तो इसके माध्यम से राजनीति में भी प्रवेश कर सकता है। इस दिशा में दानवास की कोयले की खान के मजदूर निकाली ममाई का उल्लेख किया जा सकता है जो १९५८ में सर्वोच्च सोवित के सदस्य चुने गए हैं।

मजदूर संघ का उद्देश्य सामूहिक उत्पादन और सामूहिक कार्य है। ये कारखाने के संगठन की आधारीक इकाई हैं। इनके प्रमुख कार्य हैं—

१—उत्पादन बढ़ाना

२—लागत कम करना

३—मजदूरों और उत्पादकों में सहयोग की भावना लाना।

मजदूर सङ्घ राज्य से स्वतंत्र सङ्घटन हैं। मजदूर सङ्घ के पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। यदि ये मजदूरसङ्घ की केन्द्रीय कार्य समिति (Central Council of Trade Union) से सम्बन्ध जोड़ना चाहें तो इन्हें वैधानिक स्वीकृति भी मिल सकती है। इनकी सदस्यता और चंदा एच्छिक तथा वैयक्तिक है। ये मजदूरों को काम दिला सकते हैं और दिलाते हैं किन्तु इसके लिए ये बाध्य नहीं हैं। इनका कार्यालय और व्यवस्था अपनी होती है। किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक भेद भाव के कोई भी व्यक्ति इनका सदस्य हो सकता है।

मजदूर संघ के कार्य

१—मजदूरी के निर्धारण और काम दिलाने में सक्रिय भाग लेते हैं।

२—समाजवादी प्रतिस्पर्धा कायम करके उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन व्यय घटाने और मजदूरों की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं।

३—श्रमिकों को आपसी तथा उत्पादकों के बीच आए दिन उठने वाले मत भेद दूर करते हैं।

४—वीमा गृहनिर्माण, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

५—राजकीय आयोग तथा समितियों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मजदूर संघ का सङ्गठन

मजदूर सङ्घ की आधारीक इकाइयां विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं।

सोवियत मजदूर सङ्घ का क्रमिक विकास

क्रान्त पूर्व वर्षों में मजदूर संघ गुप्त और क्रांतिकारी संस्थाएं थीं। विगत अर्धशताब्दी में यथा स्थान इनका विवेचन हो चुका है। उस समय इनका राजनीतिक महत्व था जो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है।

क्रान्ति के बाद मजदूर संघ की विचार धारा और कार्य प्रणाली में परिवर्तन हुआ। मजदूर संघ प्रायः दो विचार धारा के थे :—

१—तेरिडकलिस्ट विचार धारा के समर्थकों ने छोटे छोटे संघ बनाए। १९१८ के पूर्व इनका बड़ा जोर था।

२—मजदूरी विचार धारा के लोग मजदूर संघटन को राज्य का अंग बनाकर रखना चाहते थे। उनका मत था कि इनका राज्य से पृथक् स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आगे चलकर यही विचार धारा स्वीकृति हुई और मजदूर सङ्घ का राष्ट्रीयकरण हुआ।

क्रोत्की मजदूर सङ्घ की स्वतंत्रता का विरोधी था। लेनिन के विचार इस सम्बन्ध में उदार थे। वह इन्हे शिक्षा, सङ्घटन और कम्युनिज्म की पाठशाला मानते थे। कुछ लोग मध्यम मार्गी भी थे। उनका विचार था कि मजदूर सङ्घ के द्वारा न तो उद्योगों पर नियंत्रण हो और न इनका राष्ट्रीयकरण ही किया जाय। कार्यकर्त्तियों का मनोनयन न करके उनका चुनाव विशा ज्ञाय। मजदूर प्रतिनिधि उद्योगों के नियंत्रण में सलाह दें।

लैलिन के जीवन काल में मजदूर सङ्घ को आंशिक स्वतंत्रता मिली कालान्तर में त्रोट्स्की की नीति धीरे धीरे कार्य रूप में परिणत की जाने लगी ।

इस युग में कार्यकर्त्ताओं का निर्वाचन होता था और मजदूर प्रतिनिधि उद्योगों के नियंत्रण में सलाह देते थे ।

संक्रमण काल (Transition Period) में वैक्की बहुत अधिक बढ़ गई थी । मजदूरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी । मजदूरों में असन्तोष ने घर लिया था ।

आरंभिक दिनों में 'योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन' के साम्यवादी सिद्धान्त ने मजदूरों की कुशलता और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला । सुद्धत साम्यवाद के युग में नीति बदल दी गई और 'समान काम के लिए समान वेतन' तथा 'कार्य के अनुसार वेतन' का सिद्धान्त अपनाया गया । N. E. P. ने मजदूरों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया ।

१९२२ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मजदूर सङ्घ के कार्य और प्रस्थिति (Status) के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए कहा, "मजदूर संघ मजदूरों के हित के लिए काम करने वाली संस्था है । इसका प्रमुख कार्य अधिकारियों और प्रबंधकों के सम्मुख मजदूरों की कठिनाइयों और समस्याओं को उपस्थित करना और उनसे राहत दिलाना है ।

१९२२ में लेबर कोड बनाया गया जिसमें मजदूरों के लिए

१—सामाजिक बीमा

२—सामाजिक स्वास्थ्य

३—बुढ़ापे की पेंशन

की व्यवस्था की गई । सामाजिक बीमा विभाग एक सामाजिक बीमा कमेटी के नियंत्रण में था । ३०० रुबल मासिक से कम पाने वालों के लिए बीमा की विशिष्ट सुविधाएँ थीं । ट्रेड यूनियन के सदस्यों का वेतन तथा अन्य सुविधाएँ अन्य मजदूरों से अधिक थीं । ६० वर्ष से अधिक

आयु के पुरुषों और ५० वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों की बुढ़ापे की पेंशन मिलती थी।

१९२२ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मजदूर संघ के कार्य और व्यवस्था के सम्बन्ध में घोषणा की :—

‘मजदूर संघ मजदूरों के लाभ के लिए काम करने वाली संस्था है। श्रमिकों की और से उनकी कठिनाइयां प्रबंधकों के सम्मुख रखना इसका प्रमुख कार्य है। अन्य कार्य :—

१—श्रम और श्रमिकों के सम्बन्ध में बनने वाले विधान पर सलाह देना।

२—श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने में राज्य की सहायता

प्रबंधकों को हिंदायत दी गई कि वे मजदूर सङ्घ के सदस्यों और पदाधिकारियों को परेशान न करें मजदूर संघ के कार्यालय के लिए कारखाने में एक कमरा देना अनिवार्य था।

रूसहरे में मजदूर संघ की रजिष्ट्री करानी पड़ती थी।

संघ अवैधानिक ढंग से निकाले गए श्रमिकों के मुकदमों की पैरवी करता था। न्यायाधीश बेंच के तीन व्यक्तियों में १ मजदूर प्रतिनिधि भी होता था।

हड़ताल

आरंभ में वैधानिक थी। १९२५ तक आयः ५०० हड़तालें हुईं जिनमें १,५४,००० व्यक्तियों ने भाग लिया और ३,२२,००० दिन व्यर्थ नष्ट हुए।

समय और शक्ति की अकारण वरबादी सरकार को सह्य न हुई और उसने हड़ताल सेकने की दिशा में सहस्र पूर्ण कदम उठाए। धीरे धीरे हड़तालें कम होती गईं और १९३० तक प्रायः समाप्त हो गईं। वस्तुस्थिति यह थी कि इस समय सोवियत संघ में योजना वृद्ध निर्माण कार्य हो रहा था। उत्पादन की योजना बनते समय ही मजदूरी तय हो जाती थी। काम प्रारंभ हो जाने पर दबाव डालकर मजदूरी बढ़ाई नहीं जा सकती थी।

मजदूर सङ्घ की केन्द्रीय समिति

C. C. T. U. न बहुत अवेक अस्तोर होन पर ही हड़ताल की अनुमति दीं। कोशिश यही था कि सम्झौते द्वारा मतभेद निबटा लिए जाय।

मजदूर सङ्घ की सदस्यता के लाभ—

१—बीमा की सुवधाएँ—सदस्यों को विशेष सुविधाएँ।

२—मजदूरों की शिकायतें सङ्घ द्वारा व्यवस्थाकों के सम्मुख रखी जा सकती हैं।

३—राष्ट्रीय आर्थिक योजना (N.E.P.) को स्थापना के बाद सङ्घ की सदस्य सबके लिए सुलभ।

४—अनुशासन हीनता के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध के कारण सदस्यों की सदस्यता से पृथक नहीं किया जा सकता था।

५—आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क वैधानिक परामर्श (Legal advice) मिलता है।

६—सङ्घ के सुरक्षित कोष से आवश्यकतानुसार ऋण और सहायता मिलती है।

देश में वेतन भोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। १९२२ में ६० लाख वेतन भोगी थे, १९३० में इन्की संख्या बढ़कर ३ करोड़ हो गई। ८४% वेतन भोगी मजदूर सङ्घ के सदस्य थे।

तामस्की जो इस समय C. C. T. U. का सभापति (Chairman) था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हिमायती था। उसने उत्पादन बढ़ाने और वेतन भोगियों की शिकायतें सामने रखने का सुझाव दिया। सेरिडकलिस्ट विचार धारा का समर्थक होने के कारण उसको बड़ी आलोचना हुई और वह पद से पृथक कर दिया गया।

१९६८-२६ में मजदूरों की अनुशासन हीनता बहुत बढ़ गई थी। देर से शान। और काम से जो चुराना सामान्य बात थी।

मजदूरों को शिक्षायत थी कि सङ्घ उनके वेतन स्तर और निवास (Housing) की असुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। मजदूर सङ्घ के अधिकारियों की धांधली और पक्ष-पात पूर्ण नीति से श्रमिक अप्रसन्न थे। (१९३०)

१९३२ में फैक्टरी में कमकरो की समित (Workers of factory committee) को C. C. T. U. ने आदेश दिया कि :-

- १—अधिक से अधिक काम किया जाय ।
- ६—मजदूरी (Progressive premiums) में दी जाय ।
- ३—फजूल खर्ची रोक़ी जाय ।

C. C. T. U. के आदेशों का प्रालन किया गया ।

१९३३ में ट्रेड यूनियन द्वारा बनाया गया श्रम आयोग (Commissariat of Labour) भंग कर दिया गया । इस आयोग के सदस्य रुद्ध द्वारा मनोनीत किए जाते थे । श्रम आयोग के दो प्रमुख कार्य थे :-

१—समाज कल्याण की व्यवस्था—स्वास्थ्य, बीमा तथा वृद्धावस्था की पेंशन से अतिरिक्त और सभी बातें उदाहरणार्थ कारखानों की देख रेख, कार्य क्षमता की वृद्धि, अनुशासन की भावना आदि । ये सभी काम C. C. T. U. ने अपने हाथ में ले लिए ।

२—वेतन निर्धारण—सरकार और मजदूरों के मध्यस्थ के रूप में वेतन का निर्धारण करता था । मजदूरों और कार्य में सम्बन्ध स्थापित किए बिना मजदूरों का असन्तोष दूर नहीं किया जा सकता था ।

योजना निर्माताओं ने मजदूरी की दर पहले ही निर्धारित कर दी थी । मजदूरी की दर में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए अवकाश न था । आयोग का यह कार्य महत्व हीन था ।

१९३६ में फैक्टरी और मजदूरों के झगड़ों के समाधान के लिए सोवियत कन्ट्रोल कमीशन (Soviet Control commission) बनाया गया । यह तत्सम्बन्धी शिकायतें और अपीलें सुनता था ।

रोटी का राशनिंग समाप्त हो जाने का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव अच्छा पड़ा । सबसे महत्वपूर्ण इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा । लोग समझने लगे कि अब संक्रमण काल बीत चुका है ।

१९३५ में श्री स्तेनखोव ने ६ घंटा प्रतिदिन काम करके १०२ टन कोयला उत्पादित कर उत्पादन क सभी पुराने रेकार्ड ताड़ दिए । उन्हें २२५ रूबल की अतिरिक्त आय हुई । कालान्तर में समाजवादी प्रसिस्पर्द्धा को और प्रश्रय

मिला। १९५६ में दानवास खान के मजदूर निकाली ममाई (जो आजकल सोवियत सर्वोच्च के निर्वाचित सदस्य हैं) ने इस आन्दोलन को गति दी। अब सोवियत श्रमिक लक्ष्य के अधिक आने-जाने लगा है।

वेतन स्तर की भिन्नता कम करने की दिशा में सरकार बराबर सचेष्ट रही। मजदूरी की व्यवस्था में कई बुराइयाँ थीं—

१—मजदूरी की दर में भिन्नता।

२—कई तरह के बोनस दिए जाते थे। फलतः कुछ कुशल श्रमिक इंजीनियर और फोरमैन से अधिक वेतन पाते थे*।

३—समय मजदूरी और वेतन उत्पादन मजदूरी, मजदूरी देने के दो प्रकार थे। प्रायः एक ही कार्य के लिए प्रकार भेद के कारण मजदूरी कम या अधिक हो जाती थी। समय मजदूरी पाने वाले मजदूर दूसरे को अपेक्षा कम मजदूरी पाते थे।

दिसम्बर १९३८ में काम १ घंटा और बढ़ा दिया गया। अब मिलों में काम करने वाले मजदूरों को ७ घंटा और कार्यालय के मजदूरों को ८ घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता था। अनुशासन में भी कड़ाई बरती गई। जो मजदूर जो काम कर रहा है। वही उसे करना पड़ता था। सरलता से इच्छा-नुसार कार्य बदला नहीं जा सकता था।

१९३८-४० में वेतन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आधारिक उद्योगों (लोहा, इस्पात, कोयला, तेल आदि) में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई।

१९४० में विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन निर्धारण के लिए वेतन आयोग (Wages commission) की स्थापना की गई। इंजीनियर और टेकनिकल मजदूरों का वेतन १४००-२००० रुबल मासिक तक कर दिया गया।

१९४७ में पेंशन की अधिक दर निर्धारित की गई।

१९५६ में राज्य में राज्य बीमा का नया कानून (The new law on state pensions) बना जिसके अनुसार १२०० रुबल मासिक पाने वालों को भी बीमा का सुविधाएँ दी गईं।

अध्याय २०

कृषि

कृषि समस्या के महत्व पूर्ण पहलू भूमिका विस्तार, उसकी उर्वरता और कृषि उत्पादन के प्रकार हैं किन्तु इनसे भी महत्व पूर्ण है भूमि का स्वामित्व। वस्तुतः स्वामित्व और वर्ग भेद से पूर्व कृषि समस्या थी ही नहीं।

१८६१ से पूर्व कृषि की दो प्रणालियाँ थीं—

१—जमींदार अपने खेतों में अर्द्ध दासों से काम कराते थे। अथवा—

२—उत्तरी भागों में जहाँ कृषि लाभ प्रद न थी कृत पर किसानों को जमीन दे दी जाती थी। इस प्रणाली के अनुसार भूमि का स्वामित्व जमींदार के पास था। किसान उस पर खेती करता था और फसल के अंत में पहले से निर्धारित गल्ला या धन जमींदार को देता था। इस प्रणाली को रूसी भाषा में ओब्रोक् कहते हैं। यह शब्द ओब्रे चेन से निकला है जिसका अर्थ दण्डित या देने को विवश होता है। अधिकांश किसानों को भूमि से अब्रोक् अदा कर सकने भरको भी आनाज नहीं होता था इसे पूरा करने के लिए उन्हें दूसरे काम करने पड़ते थे।

बेगारी (बाश्चना)

सामन्ती अर्द्ध दास प्रथा के युग में शोषण के अनेक रूप थे जिसमें सबसे प्रमुख बाश्चना (बेगारी) था। किसान जमींदार के यहाँ सप्ताह में कम से कम तीन दिन काम करने को बाध्य था। कमी-कमी ऐसा भी होता था कि किसान की छः दिन जमींदार के खेत पर बेगारी करनी पड़ती थी और अपने खेत पर ठीक से एक दिन भी काम नहीं कर पाता था। स्वाभाविक था कि ऐसे उत्पादन के प्रति कृषि मजदूर निरपेक्ष रहते जिनके उपयोग का उन्हें अधिकार न था और ऐसे काम के प्रति उनकी कोई दिलचस्पी न होती जिसके

बदले में उन्हें कुछ न मिलता था। फलतः कृषि उत्पादन बहुत कम होता था। गरीबी, विवशता और खेती ने मिलकर एक ऐसी अर्थ व्यवस्था को जन्म दिया था जिसमें कृषि स्वतः पूर्ण थी और औद्योगिक उत्पादन के लिए अवकाश न था। देश का आर्थिक खोखलापन क्रिमिया युद्ध (१८५३-५६) की पराजय में उभड़ कर सामने आया। •

दास प्रथा का उन्मूलन

सामन्ती अर्थ व्यवस्था के प्रति असन्तोष की जो आग किसानों के अन्तर्गत में सुलग रही थी। जारशाही उससे अपरिचित न थी। जार यह भी जानता था कि मुट्टी भर बड़े सामन्त और जमींदार किसानों के विद्रोह की आँधी में टिक न सकेंगे। इससे पहले कि असन्तोष विद्रोह का रूप लेता। जार ने १६ फरवरी १८६१ के घोषणा पत्र द्वारा किसान को स्वतंत्र व्यक्ति मान मान लिया। घोषणा पत्र के अनुसार 'जमींदार किसानों को न बेच सकता है, न खरीद सकता है, न उसका विनिमय कर सकता है। किसान को विवाह करने से न वह रोक सकता है और न वह उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है।'

यह घोषणा पत्र जार शाही की परिवर्तित उदारता पूर्ण नीति का परिचायक नहीं है। किसान मजदूर आन्दोलन को समय से पूर्व कुचल देने के लिए अनुदार सरकारें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विवश होकर उदार बन जाती हैं पर शासन का भीतरी ढाँचा ज्यों का त्यों रहता है। भारत में भी समय-समय पर ऐसा ही रुख अपनाया जाता रहा है पर उसका मूल उद्देश्य क्रान्ति को अनिश्चित काल तक के लिए टालना भर था।

किसान की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक थी। आर्थिक दृष्टि से वह अब भी परतंत्र था। किसान पहले जितनी जमीन पर खेती करता था उसका लग भग पाँचवा भाग ओत्रेज्की (कटौती) के रूप में जमींदार के अधिकार में चला गया। शेष जमीन किसान को मिली अवश्य पर मुआवजे के रूप में उन्हें जमीन के वास्तविक मूल्य से अधिक जमींदार को देना पड़ा। किसानों द्वारा

अधिकृत भूमिका कुल मूल्य ६५ करोड़ रूबल था पर इसके लिए किसानों को २ अरब रूबल से अधिक देना पड़ा ।

कृषि की समस्याएँ

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कृषि को समस्या का सबसे महत्व पूर्ण पहलू भूमि का स्वामित्व है । जारशाही कृषि-पूँजी और उसके लाभांश के वितरण में संतुलन स्थापित करने के पक्ष में नहीं थी । समस्या के मूल के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण अपना कर उसने जो भी किया वह पुराने कपड़े में पेबन्द भर था ।

उर्बर धरती जमींदारों के अधिकार में थी किन्तु वे कृषि को सही अर्थ में जीविका का साधन नहीं मानते थे । मिहनत कश किसान जिनके लिए कृषि जीवन मरण का प्रश्न थी घटिया जमीन के मालिक थे । किसानों के खेत परिमाण में अत्यंत कम थे जो थे भी वे छोटे और छिटे थे किसी भी प्रकार उन पर वृहत् स्तर उत्पादन की योजनाएँ लागू नहीं की जा सकती थी । किसानों के खेतों के बीच में जमींदारों के खेत आ गए थे । जमींदारों के खेतों पर पशु आदि के जाने के लिए किसानों को भारी कर देना पड़ता था । अपने खेत ठीक से जोतने-बोने के लिए बहुधा जमींदारों के खेतों को कठिन शर्तों पर लेना पड़ता था क्योंकि जमींदारों के खेत उनके खेतों को कभी-कभी दो ऐसे हिस्सों में बाँट देते थे कि वे उन्हें परस्पर सम्बन्धित नहीं कर सकते थे । मुआवजे और लगान के रूप में दी जाने वाली धन राशि इतनी अधिक थी कि बिना हाथ पैर हिलाए जमींदार केवल इन्हीं की आय से विलासिता पूर्ण जीवन बिता सकते थे ।

१८६१-१९०६ तक के ४५ वर्षों में किसानों ने मुआवजे और लगान के रूप में १६५० करोड़ सोने के रूबल जमींदारों को दिए ।

भूमि के स्वामित्व का विवरण निम्न है—

६९६ बड़े जमींदारों के पास २,०७,९८,५०४ देसियातिन^१ भूमि (औसत

१—देसियातिन—क्रान्ति पूर्व रूसी भूमि का एक नाप जो १*०३ हेक्टर या २*७ एकड़ के बराबर थी ।

३०,००० देसियातिन) थी और इनसे छोटे जमींदारों के पास औसतन २३३३ देसियातिन भूमि थी। किसानों की स्थिति इसके ठीक विपरीत थी १५% किसान भूमि हीन थे, ३०% के पास खेत जोतने के लिए घोड़ा नहीं था और ३४% के पास किसी प्रकार के कृषि-औजार नहीं थे। केवल ५० लाख किसानों के पास औसतन २ देसियातिन भूमि थी। .

समष्टि में जार युग का किसान उस पालतू बगुले जैसा था जिसके गले में मुंदरी पहना दी जाती है, जो मछली पकड़ता है। इसीलिए कि यह उसका स्वभाव है और इसके अतिरिक्त वह और कुछ कर नहीं सकता किन्तु अपनी निज की भूख के लिए उसे स्वामी की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। जमीन की चिर अतृप्त भूख, उन्मीड़न, बरदास्त के बाहर कर, घुटन और कुंठा ये ही रंग हैं जिनसे तत्कालीन कृषक समाज का चित्र बनाया जा सकता है।

जार और जमींदारों के विरुद्ध किसानों के मन में निरन्तर सुलगने वाली आग अनुकूल वातावरण पाकर उमड़ उठती थी सरकार उस आग पर मिट्टी डालकर फैलने से रोकने में प्रयत्नशील थी पर यह समस्या का उचित समाधान न था। अक्सर मिलते ही किसान जमींदारों की जमीन और पशु छीन कर आपस में बाँट लेते थे जमींदार भूमि और कृषि साधनों पर येनकेन प्रकारेण अपना अधिकार बनाए रखने की दिशा में सचेष्ट थे। जार शाही ने निर्ममता पूर्वक किसान आन्दोलन को कुचला। विद्रोहियों को नाना प्रकार की यातनाएँ दी गईं। 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दबा की।' १९०५-०७ में किसान-विद्रोह और उग्र हो उठा। देश के आधे से अधिक उयेज्दों (जिलों) में आन्दोलन फैल गया। औद्योगिक मजदूर किसानों के कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़े। यह क्रान्ति यद्यपि विफल रही किन्तु इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसके अभाव में १९१७ की सफलतन्त्र क्रान्ति असंभव थी।

१९०५ की क्रान्ति की विफलता के बाद जारशाही सरकार ने गाँवों के पूँजीवादी फार्मों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके मालिकों को अच्छी जमीनें, कृषि-साधन तथा ऋण आदि दिया। किसानों को अपनी जमीन कुल को [धनी किसान जो क्रान्ति पूर्व कृषकों की कुल संख्या के १५ प्रतिशत थे]

के हाथ नाम मात्र के मूल्य पर बँच देनी पड़ी। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व घेरा बन्दी आन्दोलन के कारण इंग्लैण्ड में भी ऐसा हुआ था। रूस के सीमान्त प्रदेश मुख्यतः मध्य एशिया के गैर रूसी आबादी वाले इलाकों में जमींदारों की स्वेच्छा चारिता और बढ़ गई थी। प्रथम विश्व महायुद्ध (१९१४-१९१८) के समय किसानों की दशा और भी बदतर हो गई थी। खेती का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा बहुत अधिक घट गया था, स्वस्थ किसान बलात् सैनिक बना लिए गए और सैनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि मजदूर और साधन दोनों भारी संख्या में नष्ट हुए।

फरवरी (१९१७) क्रान्ति के बाद राजनीतिक सत्ता अस्थायी सरकार के हाथ में जाने पर आशा की गई कि परिस्थिति में परिवर्तन होगा। अस्थायी सरकार से सम्बन्धित व्यक्ति मार्क्सवादी थे। किन्तु वे जार, पूँजीपतियों, जमींदारों, किसानों अथवा मजदूरों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे।

अस्थायी सरकार का किसान आन्दोलन पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। संवर्ष चलता रहा। किसानों और कृषि मजदूरों के सङ्गठन क्रियाशील रहे। किसान प्रतिनिधियों की कौंसिलें, किसान कमेटियों, भूमि हीन किसानों की यूनियनें बिना फसल वाली जमीन के किसानों की कौंसिलें, कृषि-मजदूर यूनियनों की शाखाएँ देश भर में बनाई गई और कृषि क्षेत्र में उनका उत्साह पूर्वक स्वागत हुआ।

आरम्भ में किसानों का असंतोष जमींदारों की रियासत का एक हिस्सा छीन लेने, जंगलों के पेड़ काट लेने अथवा उनके खेतों और चारागाहों में अपने जानवर छोड़ कर चरा लेने के रूप में व्यक्त हुआ। अस्थायी सरकार के अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार किसानों की ये कार्रवाइयाँ मई १९१७ में ४११ से बढ़ कर जून में ६८६, जुलाई में १५०६, अगस्त में ११३१ और सितम्बर में १५८७ हो गई। किसान आन्दोलन की उग्रता के साथ-साथ अस्थायी सरकार की दमन नीति की बर्बरता भी बढ़ती गई। विद्रोही गावों को दण्ड देने के लिए सैनिक दस्ते भेजे गए।^१

१-६० स० कोल्पाकोव—सोवियत सङ्घ में कृषि समस्या किस तरह हल की गई।

कटु अनुभवों के कारण मेहनत कश जनता अस्थायी सरकार पर से अपना विश्वास खो बैठी। जनता के लिए रोटी, शान्ति और जमीन में से किसी की भी व्यवस्था न हो सकी। लेलिन के नेतृत्व में लाल रक्त दल सक्रिय था। ८ महीने के अन्दर ही अस्थायी सरकार का पतन हो गया।

अक्तूबर क्रान्ति

२५ अक्तूबर (नई तिथि के अनुसार ७ नम्बर) १९१७ को लाल रक्त दल क्रान्तिकारी सैनिकों के साथ मिल कर अस्थायी सरकार को उलट दिया।

२६ अक्तूबर (८ नम्बर) को सोवियतों की कांग्रेस ने जमीन सम्बन्धी अध्यादेश पास किए। बिना किसी क्षति पूर्ति के जमींदारी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि अब राष्ट्र की (समग्र जनता की) सम्पत्ति हो गई। जमीन न बेची जा सकती थी न खरीदी।

जमींदारों, राज घराने और गिरजा घरों की जमीन मेहनत कश किसानों को मुफ्त दे दी गई। जमींदारों से छीनी हुई, जिस जमीन का उपयोग सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में किया जाता था किसानों से वापस नहीं ली गई। अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि 'साधारण किसानों और साधारण कजाकों की जमीन जब्त नहीं की जायगी।

क्रान्ति पूर्व वर्षों १३½ करोड़ देसियातिन जमीन किसानों के प्रयोग में थी भूमि सम्बन्धी अध्यादेश के अन्तर्गत उन्हें १५ करोड़ देसियातिन जमीन और मिल गई। भूमि का पट्टा बदलवाने या खरीदने पर जो खर्च पड़ता था उससे भी किसानों को मुक्ति मिल गई। यह धन ७० करोड़ स्वर्ण रूबल के लगभग था। इतना ही नहीं १३० करोड़ रूबल ऋण से भी किसान मुक्त हो गए। जमींदारों से छीने हुए कृषि यंत्र, पशु, मकान प्राकृतिक सम्पदा (खान, जंगल और नदियाँ) जनता की सम्पत्ति बन गई। अध्यादेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि सारी जमीन पूरी जनता की सम्पत्ति हो जाय और उसे जोतने वाले उसका प्रयोग करें और जमीन के बटवारे का नियंत्रण

स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारी संस्थाएँ करें।^१ उन सहकारी संस्थाओं और कम्यूनों को भी कुछ जमीन दी गई जो क्रान्ति के बाद देश के विभिन्न भागों में पेत्रोग्राद, मास्को, नोवोग्रोद, वात्का, रूयाजान, वारोनेज, खारकोव और दूसरी गुबर्नियाओं में अपने-आप बनते जा रहे थे।

जमींदारों ने नई व्यवस्था का विरोध किया। जब उन्होंने देखा कि लाल तूफान से वे अपनी सम्पत्ति की रक्षा न कर सकेंगे तो उन्होंने खाद्यान्न जलाना, कृषि साधनों को नष्ट करना और पशुओं की हत्या आरम्भ की। किसानों ने जमींदारों की इस नीति का प्रतिकार किया कुछ स्थानों में २४ घंटे के भीतर ही जमींदारों को अपनी रियासत छोड़ कर भाग जाना पड़ा।

कुलक (बड़े पूंजीवादी किसान) अधिक खतनरनाक साबित हुए। जमींदारों की रियासतें जन्त होने पर इन्होंने भी उनकी जमीन हड़प ली फलतः ये अधिक शक्तिशाली हो गए। स्थानीय सोवियतों में भी इन्होंने स्वयं या इनके दलाल सक्रिय भाग लेने लगे। मध्यम किसानों को अपने साथ मिलाकर गरीब किसानों का शोषण करने की भी इन्होंने कोशिश की।

जून १९१८ की एक घोषणा के अनुसार किसान कमेटियों में पुराने जमींदारों कुलकों तथा दूसरे शोषकों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। ५ करोड़ हेक्टर जमीन और कृषि यंत्र कुलकों से छीन कर गरीब किसानों को बाँट दिए गए।

१९१८ की गर्मियों में देश में खाद्य संकट गम्भीर हो गया। औद्योगिक मजदूरों को ५० से १०० ग्राम तक ही दैनिक राशन मिल पाता था।

स्वाधीनता के पहले चरण

विश्व-युद्ध और यह युद्ध के सात वर्षों में सोवियत अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा १९२० में देश का औद्योगिक उत्पादन सातवाँ और कृषि उत्पादन आधा रह गया था।

भूमि के स्वामित्व परिवर्तन का प्रभाव मध्यम और निम्न वर्ग के किसानों पर अच्छा पड़ा। वे प्राण-प्रण से जुट कर कृषि के विकास में सचेष्ट हुए। जमींदारों और कुलकों से उन्हें केवल भूमि ही मिली थी। पशु और कृषि

यंत्र नष्ट किए जा चुके थे। १९१८-१९ में तो खेत बोए भी न जा सकते थे। न बीज था, न हल और न पशु। १९२६ तक स्थिति में इतना सुधार हुआ कि उत्पादन युद्ध पूर्व वर्षों की अपेक्षा आगे बढ़ गया।

१९१३ में चार करोड़ टन गल्ले की अपेक्षा १९२६-२७ में गरीब और मध्यम किसानों ने ६ करोड़ ६४ लाख टन ज्यादा गल्ला पैदा किया। क्रान्ति पूर्व वर्षों में घरेलू प्रयोग (खाना, बीज और चारा) के लिए उनके पास कठिनता से ३४९ लाख टन गल्ला बचता था जब कि १९२६-२७ में उनके पास ५८८ लाख टन बचा जो ६८ प्रतिशत अधिक था। गरीब और मध्यवित्त किसानों के जीवन में क्रान्ति के कारण पर्याप्त सुधार हुआ। इन दस वर्षों में गरीब किसानों का जीवन भाव मध्यवित्त किसानों के स्तर तक पहुँच गया था।^१

सहकारिता की आवश्यकता

प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसानों के छोटे-छोटे बिखरे हुए असंख्य परिवार थे। १९१३ में ऐसे परिवारों की संख्या केवल डेढ़ करोड़ थी। १९२६ में ये बढ़ कर ढाई करोड़ हो गए।

छोटे खेतों में न तो पूँजी लगाई जा सकती थी न वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग ही किया जा सकता था। ८० लाख किसान परिवार तो ऐसे थे जिनमें मशीन की बात तो दूर घोड़ा रखना भी लाभ प्रद नहीं था। १९२८ की ग्रीष्म ऋतु की जुताई में ९८% लकड़ी के पुराने हल से, ८९.२% घोड़े वाले हल से और केवल एक प्रतिशत हल मोटर (ट्रैक्टर) के जुताई हुई थी। चिन्ता की बात यह थी कि १९२६-२७ में जनसंख्या वृद्धि का वार्षिक औसत १.२३% था और कृषि उत्पादन ०.६% बढ़ा था। जनसंख्या वृद्धि की गति से पीछे का कृषि उत्पादन सोवियत विचारकों को कृषि के क्षेत्र में नई प्रणाली के सृजन का आह्वान कर रहा था।

लेनिन ने अपनी सहकारी योजना में कृषि के समाजवादी पुनर्गठन की योजना बनाई।

‘कोलखाज’ सहकारी खेती (Collective Farming)

सामूहिक खेती समाजवाद के सहकारी सिद्धान्त पर आधारित है। विखरे और छोटे खेतों में किसान यंत्रों का प्रयोग कर सकने में असमर्थ थे। यदि खेती बिलकुल व्यक्तिगत रूप से ही की जाती तो प्रत्येक परिवार खेत की उसी सीमित परिधि में क्रियाशील रहता चाहे उस पर कम श्रम ही अपेक्षित क्यों न हो। श्रम की बचत और धरती के सम्यक उपभोग के लिए यह आवश्यक था कि छोटे खेतों को मिलाकर बड़ा कर दिया जाय और श्रम और खेत के अनुपात में किसान को उत्पादन का उपयुक्त भाग प्राप्त हो।

रस्सी ढँठने से कष्ट अवश्य होता है पर उपयोगिता रस्सी की ही होती है—बिना बटे धागे की नहीं।

सामूहिक खेती के प्रकार

क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार किसानों ने तीन प्रकार की सामूहिक खेती गठित की—कम्यून, संयुक्त खेती समितियाँ और सहयोगी समितियाँ।

कम्यून

समष्टि में कम्यून भारतीय संयुक्त परिवारों जैसे थे। आवश्यकता के अनुसार सम्पत्ति के वितरण के सिद्धान्त पर इनका विश्वास था। कम्यून अधिकतर कुलकों और पुराने जमींदारों के भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों का संगठन था जिनके पास उत्पादन के निजी साधन न थे। पशु खेती और इमारतें आदि सार्वजनिक सम्पत्ति बना लिए गए। कम्यून के सदस्यों के पास व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी प्रकार के उत्पादक साधन न थे—सुर्गियों बतख भी नहीं। कम्यून की आय नगद या सामान उसके सदस्यों में खाने वालों की संख्या, परिवार या आवश्यकता के आधार पर बाँट दी जाती है।

कम्यून की आदर्शवादिता समयोचित नहीं थी। आवश्यकता के अनुसार सम्पत्ति के वितरण के सिद्धान्त का सदस्यों के श्रम के साथ सन्तुलन नहीं

स्थापित किया जा सना। सदस्यों के अधिक योगदान के लिए कम्यून में प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं थी। कम्यून की विफलता का कारण उसकी अव्यावहारिकता थी।

खेती की संयुक्त समितियाँ

संयुक्त समितियाँ सहयोग का सबसे आसान रूप थीं। ये एक प्रकार की साझेदारी (Association) थीं। फसल के लिये सबके खेत एक में मिला लिए जाते थे। खेती की अवधि में मेहनत, जमीन, कृषि उत्पादन के साधन आदि एक में संयुक्त की जाती हैं।

वितरण केवल श्रम के अनुसार ही नहीं होता साझेदार का पूंजी का भी ध्यान रखा जाता है। पूंजी में हल, बीज तथा कृषि के अन्य साधन शामिल है।

संयुक्त समितियों के सदस्यों की आमदनी का बटवारा साधारणतया इस प्रकार होता था आमदनी का एक भाग परिश्रम के आधार पर बाँटा जाता था और दूसरा भाग पूंजी के आधार पर। सदस्य ने कितना परिश्रम किया और उत्पादन के कितने साधन दिए इस आधार पर उसका लाभांश निश्चित होता था।

यह सिद्धान्त कम्यून की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक था किन्तु सफल न हो सका। गरीब किसानों का इससे अहित हुआ। क्रान्ति के पश्चात उनके पास उत्पादन के साधन बिलकुल नहीं थे। अधिकांश जमीन भी व्यक्तिगत परिवारों के कब्जे में थी।

१९२५ के आँकड़ों के अनुसार कम्यूनों में ६६.५% उत्पादन के साधन, सहयोगी समितियों में ६८% और संयुक्त कृषि समितियों में २७% सामाजिक सम्पत्ति बनाए गए थे। १९२४ में कम्यूनों के ६६.८% बाग बगीचे, सहयोगी समितियों के ६७.७% और संयुक्त समितियों के ५८.६% सामाजिक सम्पत्ति बनाए गए। लाभ की दृष्टि से संयुक्त समितियाँ श्रेयस्कर थीं।^१

सामूहिक खेती (Collective farming)

सामूहिक कार्य का मूल आधार सामूहिक श्रम है, जमीन और उत्पादन के मूल साधन (सभी श्रम, पशु और उत्पादक वस्तुओं का एक भाग, खेती की इमारतें और औजार) सामूहिक सम्पत्ति हैं।

एक प्रकार से सामूहिक फार्म कम्युन और संयुक्त समितियों के विकसित रूप हैं। सामूहिक फार्म की योजना में इनके दोषों पर ध्यान दिया गया। सामूहिक फार्म में काम करने वाले किसानों के पास एक सीमा तक व्यक्तिगत सम्पत्ति भी होती है। १९३५ की दूसरी कांग्रेस के निश्चय के अनुसार हर सामूहिक किसान परिवार को उस कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयोग के लिए २५ से १ हेक्टर तक भूमि मुफ्त मिलेगी और इसमें घर की जमीन शामिल नहीं होगी। इसके अतिरिक्त १ गाय, २ बछड़े, बच्चों समेत एक या दो सुअर, १० भेड़ें या बकरियाँ, मधु मक्खियों के २० छत्ते और इच्छानुसार मुर्गी, बतक या खरगोश तथा आवश्यक कृषि यंत्र भी व्यक्तिगत सम्पत्ति माने जाते हैं। व्यक्तिगत जमीन परिवार की आय का अतिरिक्त साधन होती है। पारिवारिक भोजन के लिये उसे अतिरिक्त मांस, घी, मक्खन, तरकारी और फल मिल जाता है। व्यक्तिगत खेतों पर वे लोग अवकाश के समय काम करते हैं। यदि वे चाहें तो इस अतिरिक्त उपज को सरकारी क्रम संस्थाओं, उपभोक्ता सहयोग समितियों अथवा सामूहिक खेत के बाजार में सीधे उपभोक्ता के हाथ बेच सकते हैं। १९५८ के एक विशेष आदेश के अनुसार सामूहिक किसान अपनी निजी गृहस्थी के उत्पादन को सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है। इस आदेश के कारण उसकी आय में और अधिक वृद्धि हो गई।

सामूहिक खेतों की आय का बँटवारा

सामूहिक खेतों की आय का बँटवारा समाजवादी सिद्धान्तों के आधार पर परिश्रम की मात्रा और गुण के अनुपात में होता है। परिश्रम के मात्र की इकाई दिन भर का काम माना जाता है। विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को

परिश्रम, जटिलता और सामूहिक खेती के लिए उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ६ भागों में बाँट दिया गया है। हर तरह के कार्य के लिए उत्पादन का एक निश्चित लक्ष्य रखा गया है। अपेक्षया साधारण कामों के लिए दैनिक उत्पादन की मात्रा एक दिन के काम की इकाई मानी जाती है और अन्य काम इसी अनुपात में कम या अधिक यथा १, ५, १७५, २२५, दिन भर के काम की इकाइयाँ। काम का प्रकार इकाइयों की संख्या कम अधिक करता है। जितना ही अधिक जटिल और महत्वपूर्ण काम होगा उतनी ही अधिक इकाइयाँ गिनी जाएँगी। किसान की आय उसके परिश्रम पर निर्भर होनी है। दीनभर काम करके वह एक दिन की इकाई का एक भाग भी पा सकता है और कई दिन की इकाइयाँ भी कमा सकता है।

दिन भर के काम की इकाई, सामूहिक खेत पर की गई मिहनत की मात्रा और गुण को मापने और उसके लिये पारिश्रामिक देने का आधार है, जो अधिक दिन कमाता है उसे अधिक मिलता है। इसके अतिरिक्त नियोजित व्यवस्था को पूरा करने के लिए, फसलों की पैदावार पर और पशुओं के उत्पादन पर बोनस भी दिए जाते हैं।

आमदनी कई किशतों में (नकद और जिन्सों में) निश्चित तारीख के दिन बाँटी जाती है। पहले पेशगी ली जाती है और वर्ष के अन्त में हिसाब हो जाने पर पूरी रकम मिलती है।

सामूहिक फार्मों का प्रबन्ध

सामूहिक फार्मों का प्रबन्ध जनतन्त्रवादी सिद्धान्तों के आधार पर होता है।

सामूहिक फार्म के सदस्यों की आम सभा सबसे ऊँची संस्था मानी जाती है। सदस्यों की सभा में सहयोगी समिति के नियमों पर विचार किया जाता है और उन्हें स्वीकार किया जाता है। उसका बोर्ड और सामूहिक फार्म का अध्यक्ष तथा हिसाब की जाँच करने के लिए एक कमीशन का निर्वाचन होता

है। उत्पादन की योजनाओं पर विचार होता है और बोर्ड तथा हिसाब जॉन्च कमीशन की रिपोर्ट सुनी जाती है। आम सदस्यों की सभाएँ साधारणतः साल में दो तीन बार होती हैं। प्रबन्ध बोर्ड की बैठक महीने में दो बार होती है।

बोर्ड सामूहिक फार्म के प्रचलित काम का निर्देश करता है। इसमें आर्थिक प्रबन्ध, कार्यकर्ताओं का चुनाव और नियुक्त, सामूहिक किसानों की सांस्कृतिक और पेशे सम्बन्धी शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और खेल की सुविधाओं की व्यवस्था, मनोरञ्जन, गाँव सुधार, किंडर गार्डन, शिशु शाला और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था आदि शामिल हैं।^१

१९३५ के सामूहिक कृषक कॉग्रेस में (Model rules of the Agriculture Artel) कानून बनाया गया। यह कानून सामूहिक खेती के कार्य सिद्धान्त तौर तरीके और वितरण के विषय में प्रकाश डालता है। तब से आज तक सामूहिक खेती प्रगतिशील होती रही। वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग होता रहा।

१९५६ के संशोधन के अनुसार सामूहिक फार्मों को और स्वतन्त्रता दी गई कि वे अपने सिद्धान्त और स्थिति के अनुसार अपने कार्यों में परिवर्तन कर सकें। इस नियम के अनुसार फार्म के स्वामी खेतिहर होते हैं। सभी सदस्यों को एक साधारण सभा होती है। साधारण सभा २ वर्ष के लिए एक सलाहकार चुनती है जो साधारण सभा में फार्म की प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करते हैं। खेतिहरों में आपसी मतभेद होने पर जिला कार्यकारिणी समिति (District Executive Committee) को अपील की जा सकती थी और भ्रगड़े का अन्तिम निर्णय कृषकों की साधारण सभा करती है।

सामूहिक खेती के कई रूप हो सकते हैं जिनमें फल उगाना, पशुपालन करना, मकान बनाना, आनाज उत्पादन करने वाले ब्रिगेड (Brigade)

के व्यक्तियों की नियुक्त एक बोर्ड के द्वारा की जाती है। बोर्ड इस ब्रिगेड के सबसे कुशल खेतिहरों को नियुक्त करता है। एक ब्रिगेड में ७ से १२ तक की टोलियाँ होती हैं। उदाहरणार्थ मात्रिकों गाँव में स्थित (सुवास्क संव) श्रीविदा सामूहिक खेत को लें। इस गाँव में ५०० कृषक परिवार हैं जिनकी जनसंख्या २४०० है। १९३० ई० में हम लोगों ने सामूहिक खेती आरम्भ की। इनमें १००० व्यक्ति खेतों पर तथा पशुपालन का कार्य करते हैं। इनके पास ३००० हेक्टर भूमि है। इस फार्म की मुख्य उपज आलू, सेम, गेहूँ, साग सब्जी आदि है। प्रायः २ टन प्रति हेक्टर ये पैदा करते हैं। सदस्यों में लामांश मुद्रा के रूप में बाँट दिया जाता है।

सामूहिक खेती ने कृषकों को क्या दिया ?

- १ - मशीनों का प्रयोग।
- २ - समय की बचत
- ३ - कार्य क्षमता में वृद्धि (३८ गुना)
- ४ - कृषि और पशु पालन में वृद्धि
- ५ - सार्वजनिक स्थानों का निर्माण—शिशु पाठशालाएँ, विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय आदि।
- ६—उपज बढ़ाने वाली शोध संस्थाओं का निर्माण।
- ७—श्रमिकों का प्रशिक्षण।
- ८—त्रिगत ५-६ वर्षों में ३६० लाख हेक्टर बंजर भूमि कृषि योग्य बनाई गई।
- ९—कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पुराने औजारों की जगह नए औजारों से काम लिया जाने लगा। १९५८ में कृषि यंत्रों से सम्बन्धित नए संस्थानों का पुनर्गठन किया गया।

किसानों की सम्पत्ति क्रमशः बढ़ती जा रही है ? १९५८ में अनाज उत्पादन ८१,००० लाख टन था। दूध का उत्पादन लगभग २००० किलोग्राम हो गया।

सत वर्षीय योजना में खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना अन्त तक १०-११ अरब प्रद (१६४०-१८०० लाख टन) अनाज प्रति वर्ष उत्पन्न होगा।

रूई के उत्पादन में ३० से ४०%, चीनी ४०-४५%, दूध ७०-८०%, मांस १००%, अण्डा ६०% वृद्धि होगी।

‘सोवखोज’ सरकारी खेती

(State Farm)

बड़े जमीदारों और कुलकों के जब्त किए खेत बंजर भूमि अथवा भाड़ियाँ और जंगल काटकर कृषि योग्य बनाई गई वह भूमि जिस पर सरकार का नियंत्रण हो सरकारी खेती के अन्तर्गत आता है। प्रारम्भ में थोड़े से खेत थे जिन पर खेती करना या नती घाटे का सौदा था या बहुत कम लाभ था। १९२१-२२ में ३३८५००० हेक्टर राज्य फार्म थे जो १९२६ में घटकर २३१६००० हेक्टर रह गए। १९२८ में जो भूमि किसानों की जोत में नहीं थी। राज्य फार्मों में मिला ली गई। इस प्रक्रिया में १५ मिलियार्ड रूबल खर्च हुआ।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में खेतों में ५ गुने और कृषि योग्य भूमि में ८ गुने की वृद्धि हुई। १९३७ में बड़े खेतों के भाग करके उन्हें छोटा कर दिया गया और अलाभकर खेतों पर खेती बन्द कर दी गई।

अधोलिखित आंकड़ों से सरकारी खेती के विकास के विभिन्न मोड़ स्पष्ट हो जाएँगे :—

The various phases in the development of *State Farms are illustrated by the following Figures—

	1928	1932	1938
No. of State Farms	1,400	4,337	3,992
Average No. of workers on them (thousand)	316.8	1,891	1,319.7
Basic Capital (balance estimates) (Million roubles)	451.5	4,030.6	7,716.1
Sown area (mile ha.)	1.7	13.4	124
Tractors (thousands)	6.7	64.0	850
Their Total h.p. (thousand h.p.)	77.6	1,043.0	1,751.8
Harvester combines (thousands)	—	12.3	26.6
Lorries (thousands)	0.7	8.2	30.0
Heads of livestock (mill heads)			
Cattla	0.18	3.2	3.7
Pigs	0.06	1.8	2.8
Sheep and goats	0.75	5.7	7.0
Gross production			
Grain (mill quintals)	11.3	—	87.6
Cotton (mill quintals)	0.1	—	1.4
Wool (ahcusand quintals)	21.0	—	186.0
Total gross production in fixed prices of 1926—7 (mill roubles)	229.7	—	1,630.6
Marketable production supplied to the State			
Grain (mill quintals)	3.9	15.9	36.4
Cotton (thousand quintals)	130.0	406.0	1,381.7
Meat, live weight (thousand quintals)	—	1,536.0	3,549.0
Milk (mill quintals)	1.2	6.9	16.2
Wool (thousand quintals)	20.0	125.0	201.0

*The development of the Soviet Economic System
By Alexander Baykov—p.p. 333.

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (Central Executive committee) ने राज्य फार्मों के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए थे ।

१—कृषि उत्पादन बढ़ाना जिससे श्रमिकों की उत्पादन शक्ति और बोई हुई भूमि में वृद्धि की जा सके ।

२—ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना कि कृषि पूर्णतः साम्यवादी स्वरूप ग्रहण कर ले ।

सरकार का ध्यान राज्य फार्मों की ओर आरम्भ से ही था । १९२०-२१ के बाद इसके पुनर्गठन का प्रयास हुआ । देश भर में कुल ४३१६ छोटे बड़े राज्य फार्म थे । जिनका कुल क्षेत्रफल ३३२४००० हेक्टर था । जुलाई १९२८ में इन फार्मों के संगठन का निश्चय हुआ और आशा की गई कि प्रथम योजना के ५ वर्षों में १० करोड़ पूंज अन्न इनसे प्राप्त होगा ।

राज्य फार्मों ने सामूहिक फार्मों की भी यथेष्ट सहायता की है । १५ लाख गाये, २ लाख सूअर, ५० लाख भैंड़, १ करोड़ मुर्गियाँ और चूजे प्रदान किए गए ।

समय-समय पर राज्य फार्मों के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता रहा । सरकार का ध्यान बृहत् स्तर उत्पादन की ओर था क्योंकि यह सुविधा जनक और कम खर्चीला था । १९३६ में सोवियत संघ में ३६६० राज्य फार्म थे जो संख्या की दृष्टि से १९२२ की अपेक्षा कम थे यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक थे । अनेक छोटे फार्म मिला कर बड़े फार्म बना दिए गए । इन राज्य फार्मों में ४७८ अनाज पैदा करने वाले, १८५० पशुओं की नस्ल सुधारने वाले और ३०८ औद्योगिक सामग्री उत्पन्न करने वाले थे ।

द्वितीय विश्व युद्ध से राज्य फार्मों को बड़ी क्षति पहुँची । १८००० फार्म नष्ट हो गए ।

राज्य फार्म के भेद

१—अनाज उत्पादक—उक्रेन, काकेशस, बोलगा प्रदेश के राज्य फार्म प्रायः खाद्यान उत्पन्न करते हैं । इनकी उत्पादन लागत अन्य क्षेत्रों के राज्य फार्मों से २५% कम पड़ती है । बड़े फार्म १५०००—२५००० हेक्टर

क्षेत्रफल के हैं। १६५८ में इन फार्मों की औसत उपज ३२.१ Centners प्रति हेक्टर थी।

२—गोशाला (Dairy farm)—शिशुओं और रोगियों के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था है। गायें औसतन ३०००-४००० किलोग्राम दूध देती हैं।

३—बूचड़ खाने—स्टेप्स में अधिक हैं। इस क्षेत्र में पशुओं के चारे की समस्या नहीं है। मांस के लिये सूअर और गायें काटी जाती हैं। पशु काटने खाल निकालने और मांस साफ करने का सारा कार्य मशीन द्वारा किया जाता है।

४—भेड़ प्रजनन शाला—यहाँ पशुओं के कृत्रिम गर्भावधान की भी व्यवस्था है। उत्तरी काकेशस, ट्रॉस काकेशस, स्टेप (Steppe) उक्रेन, पश्चिमी और पूर्वी साइबेरिया, कजाखस्तान में इनकी अधिकता है। १ फार्म में औसतन १५००० हेक्टर भूमि होती है और पशुओं में १६५०० भेड़ें, १३०० बकरियाँ, ३०० सूअर होते हैं।

५—मुर्गी पालन—एक फार्म में साधारणतया ३०,००० से १,२०,००० मुर्गियाँ होती हैं। अरेंज का फार्म प्रतिवर्ष ५ लाख मुर्गे और १,३० लाख अण्डे उत्पन्न करता है। इस फार्म का वार्षिक उत्पादन २ करोड़ रूबल है। गतवर्ष ७० लाख पक्षी प्रतिदिन खाए जाते थे।

६—तरकारी फार्म (Vegetable farm)—शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों के पास बनाए गए हैं। ये फार्म छोटे होते हैं। साधारणतः ६०००-८००० हेक्टर भूमि में। आलू, हरे शाक और दूध इनका प्रमुख उत्पादन है।

राज्य फार्मों का संगठन और कार्य प्रणाली

राज्य फार्म का उत्तरदायी अधिकारी डाइरेक्टर होता है। डाइरेक्टर की नियुक्त कृषि मन्त्री करता है। इसका मुख्य कार्य फार्म का निरीक्षण करना, आवश्यक निर्देश देना, श्रमिकों में अनुशासन बनाए रखना तथा कार्य और योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक देना होता है। राज्य फार्म में लाभ अवश्य होना चाहिए।

मजदूर विभिन्न टुकड़ियों में बँटे होते हैं। प्रत्येक टुकड़ी का एक नेता होता है। नेता के माध्यम से श्रमिकों को डाइरेक्टर द्वारा आवश्यक निर्देश मिलता है। मजदूरों में समाजवादी स्पर्धा होती है। नियत कार्य से अधिक काम करने पर पुरस्कार दिया जाता है। ट्रैक्टर चलाने वाले श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त बोनस भी मिलता है।

खाद्यान्न उद्योग (Food Industry)

खाद्यान्न उद्योग के अन्तर्गत अधोलिखित वस्तुएँ आती हैं—रोटी, दूध, मक्खन, मछली, केक, अण्डा, मांस, चीनी, चुकन्दर, चाय, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, चर्बी, तेल आदि। इस उद्योग में प्रायः ३० लाख व्यक्ति काम करते हैं। ३० प्रकार की विभिन्न शाखाओं वाले २२००० उद्योग इससे सम्बन्धित हैं। १९५७ के एक अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न उद्योग के प्रबन्ध का कार्य जिले की आर्थिक परिषदों को सौंप दिया गया है। १९५१ की अपेक्षा १९५५ में चीनी ३५%, बनस्पति तेल ५०% में शराब १००% अधिक उत्पन्न हुई। अनुमानतः १९६१ में दूध ३७५% और मांस ८५% अधिक उत्पन्न होगा। ४१० लाख टन खाद्य पदार्थ १९६० में उत्पन्न किए गए थे यह वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बहुत अधिक है। चीनी का उत्पादन आवश्यकता से कम है। १९१३ में चुकन्दर की चीनी १३,४७,००० टन हुई थी और १९५६ में ३५० लाख टन। देश भर में अनेक पाब रोटी बनाने वाली संस्थाएँ हैं। अकेला मार्क शो रोटी संस्थान प्रतिदिन २५० टन रोटी बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष भर में औसतन १०,००० लीटर दूध मिलता है। मछली और मांस का उत्पादन भी इधर बढ़ा है। १९६० में ४२ लाख टन समुद्री मछलियाँ पकड़ी गईं थीं। देश में २५० मुर्गाघर हैं और ४७५ संस्थाएँ डिब्बों में माँस बन्द करके बाजार में भेजती हैं।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

यंत्रिकरण (mechanization) खाद का उपयोग करने, बीज का चुनाव करने, सिंचाई, कृषि संगठन तथा शिक्षा के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई। प्रयत्न किया गया कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिकतम वैज्ञानिक यंत्रों का अधिकाधिक

प्रयोग हो। हल जोतने और बीज बोने का ६०% कार्य मशीनों से किया जा रहा है। फसल की कटाई में ६०-६५% मशीने ही व्यवहृत होती हैं। मशीनों का अधिक प्रयोग होने के कारण घोड़ों की संख्या कम हो रही है। निम्न आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो जायगी :—

वर्ष	ट्रैक्टर (अश्व शक्ति) दस लाख में	घोड़े
१९४०	१०.४	२०.५
१९५०	१३.४	१३.७
१९५२	१६.५	१४.६
१९५५	२०.१	१५.२

तेरेन्त्य सेम्योनोविच मलत्सेव ने कृषि भूमि और जलवायु के सम्बन्ध में शोध की थी। आपने बीज, मिट्टी तथा जुताई के तरीके पर विशेष प्रकाश डाला था १९३८ ई० में कई प्रयोगशालाओं (Experimental station) की स्थापना की गई जहाँ कृषि उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में सफल प्रयोग किए गए।

पुराने सोवियत विश्वास के अनुसार तीन फसली पद्धति (Travopoloye system) अपनाई गई थी। खेत में दो फसले पैदा कर लेने पर तीसरी बार खेत बिना बोए छोड़ दिया जाय और उनमें एक विशिष्ट घास उगा कर खेत जोत दिया जाय। घास सड़कर खाद बन जाएगी और खेत उर्वर हो जाएगा। भारत में ईख जैसे पौधे जो खेतों की अधिक उर्वरा शक्ति खींचते हैं, बोने से पहले इसी प्रकार सनई उगाकर खेत जोत दिए जाते हैं। लेकिन यह साधन महंगा पड़ता है। इस कार्य के लिए (Perennial grass) भी बोई जाती है। भूमि की उर्वरता बनाए रखने की दूसरी पद्धति फसलों को अदल-बदल कर बोना है।

* १९५० में मंत्रियों की बैठक (council of ministers) में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए :—

१—खेती के ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे अनाज की किरस उन्नत हो।

२—कृषि यंत्रों में आवश्यक परिवर्द्धन किया जाय और सब के लिए उसे उपलब्ध बनाया जाय।

३—खेतों में गहरी जुताई करके उन्हें छोड़ दिया जाय। जिससे वे स्वतः उर्वरता प्रहण कर लें।

बसंत ऋतु में अपने आप उग आने वाली घास गहरी जुताई करके निकाल ली जाती है और पटेला (Harrow) चलाकर खेत को पत्तियों से ढंक दिया जाता है। इस प्रकार खेत की नमी बनी रहती है।

निकेता खुरचेव का भाषण

२५ दिसम्बर १९५६ को कम्युनिस्ट पार्टी की साधारण सभा में निकेता खुरचेव ने कृषि के सम्बन्ध में जो भाषण दिया था उससे वहाँ की वर्तमान कृषि और भविष्य की सम्भावनाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। आपने कहा कि सप्तम योजना के पहले वर्ष में आशातीत सफलता मिली है। औद्योगिक उत्पादन में ११.३% वृद्धि हुई जब कि योजना में हमने ७.७% की ही आशा की थी। इस वर्ष २२ लाख आधुनिक प्लेट और ८,५०,००० नए घर गाँवों और फार्मों पर बनाए गए। खाद्यान्न का उत्पादन ३ अरब पूद हुआ। (योजना में २ अरब पूद की आशा की गई थी)। मांस के उत्पादन में ३२% और दूध के उत्पादन में १५% वृद्धि हुई। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ६ लाख टन चीनी अधिक साफ की गई। खाद्यान्न के उत्पादन में प्रतिवर्ष ८% वृद्धि होते-होते योजना के अन्तिम वर्ष तक १.७ गुना वृद्धि हो जाएगी। १९६५ में ११० लाख पूद खाद्यान्न पैदा होगा जो वर्तमान उत्पादन का ड्योढा होगा। अनाज की उपज प्रति हेक्टर २२६-३६० पूद होगी। प्रति व्यक्ति उत्पादन ८-९ सेन्टनर्स (centners) हो जायगा।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ३१० लाख टन उर्वरक (Fertilizers) का प्रति वर्ष प्रयोग किया जायगा। राजकीय और सामूहिक फार्मों में आधुनिकतम कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। मिट्टी के कीड़ों को नष्ट करने के लिए १ डाक्टरों की एक परिषद बनाई जाएगी, वायुयान से कीटाणु नाशक दवाइयों का छिड़काव होगा।

अध्याय २१

वित्त व्यवस्था : योजना और पद्धति मुद्रा और योजना

योजना का आधार पूँजी का निर्माण होता है। पूँजी योजना का आधारीक और अपरिहार्य तत्व होते हुए भी ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम न चल सके। योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुद्रा में भी अधिक महत्वपूर्ण है मानव-श्रम, साहस और अध्यवसाय—देश की वित्त व्यवस्था; इस बात का स्पष्ट निर्देश कि योजना की सफलता से पूँजी लगाने वाले लाभान्वित होंगे या पसीना बहाने वाले? योजना के विभिन्न अंग तीन हैं :—

१—साख योजना (Credit plan)

२—नकद योजना (Cash plan)

३—आय व्ययक (Budget)

मुद्रा के अभाव में भी योजना सफल हो सकती है। अक्तूबर क्रान्ति में मुद्रा को विनिमय का माध्यम न बनाए जाने का निश्चय किया गया। मुद्रा के स्थान पर टिकट दिए जाने की व्यवस्था की गई जिससे विभिन्न वस्तुएँ सुलभ हो सकें (१९१६)।

१९३० से पूर्व सोवियत अर्थशास्त्रियों की एक बहुत बड़ी संख्या मुद्रा प्रयोग की विरोधी थी। ऐसे विचारक अदल-बदल की प्रक्रिया के विश्वासी थे। वे योजना द्वारा साख की समाप्ति संभव मानते थे। स्वतंत्र स्पर्धा में मुद्रा अर्थ-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्व गौण हो जाता है। मुआवजे और मजदूरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

लेनिन और दूसरे विचारक इसके विरोधी थे।

मुद्रा स्फीति (१९१७-२४)

स्वाधीनता के प्रथम चरण में उत्पादन और बाजार निम्न कोटि का था। पुराने रूबल का मूल्य गिर रहा था और वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थीं। भुगतान प्रायः वस्तुओं (Commodity) में की जाती थी। सरकारी कर भी वस्तु में दिए जाते थे। दूसरी ओर मुद्रा का निरन्तर गिरता मूल्य भी चिन्ता का विषय था। लोग मुद्रा को अपने पास रखने की अपेक्षा बाजार में भेज देना ही श्रेयस्कार समझते थे। सुदृढ़ मुद्रा का निर्माण नई आर्थिक योजना के बाद ही संभव हो सका।

The statistical anatomy of the superinflation is shown by the data in Table 46, Volume of currency in circulation and Price level on selected Dates, 1918-24 in Soviet Rural Area.

Date (First of each month)	Million Rubles	Notes in circulation Index July 1, 1914=1	Price Index 1913=1
Jan. 1918	27,650	17.0	21
Jan. 1919	61,326	37.6	164
Jan. 1920	225,015	138.0	2,420
Jan. 1921	1,168,597	716.7	16,800
Jan. 1922	17,539,232	10,757.6	288,000
Jan. 1923	1,994,464,454	1,223,597.8	21,242,000
Jan. 1924	2,25,637,374,014	138,427,836.8	5,457,000,000
March 1924	809,526,216,667	496,702,886.9	61,920,000,000

Source : Arthur Z. Arnold. Banks credit and money in Soviet Russia (pp.76, 91, 128-29, 186-97.) Quoted By Hary Schwartz—Russia's Soviet Economy—pp. 47.

सरकार को दो बार रूबल का मूल्य घटाना पड़ा। ३ नवम्बर १९२१ को एक घोषणा के अनुसार १९२२ का १ रूबल पहले के १०,००० रूबल के बराबर होगा। २४ अक्टूबर १९२२ की एक घोषणा के अनुसार १९२३ का १०० रूबल १९२२ के १० लाख रूबल के बराबर होगा।

घाटे का बजट

सरकार का बजट अत्यधिक घाटे का था। इसके दो प्रमुख कारण थे :—

१—सरकार की आय के सभी पुराने साधन क्रान्ति के कारण प्रायः समाप्त हो चुके थे।

२—सरकार को युद्धत साम्यवाद के समय विदेशी आक्रमण और गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। नव निर्मित सरकार को आवश्यकताएँ जार की अपेक्षा अधिक थीं और उन्हें किसी भी प्रकार कम नहीं किया जा सकता था।

घाटा पूरा करने के लिए अधिक पत्र मुद्रा छापने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। १९२१ के आरंभिक काल में निश्चय किया गया कि देश में सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना की जाय। इस दिशा में १९२१-२४ तक सरकार ने पर्याप्त कार्य किया। राज्य उद्योग को राज्य आय व्ययक (बजट) से अलग कर दिया गया जिससे राज्य बजट राज्य उद्योग के हानि लाभ से प्रभावित न हो। सरकारी खर्च की नीति और सुदृढ़ हो गई।

मुद्रा की मांग में वृद्धि

व्यापार और उत्पादन में वृद्धि के साथ मुद्रा की मांग बढ़ी। १९२२ में राज्य बैंक को एक नई मुद्रा चलाने का अधिकार मिला। जार के १० रूबल के बराबर चेरवोनसे (Chervontsy) नामक सिक्का चलाया गया। मुद्रा कोष का २५% सोना तथा विदेशी मुद्रा में और ७५% अल्पकालिक नोट (Shor-term note) में था।

१ अक्टूबर १९२३ को कुल मुद्रा के मूल्य का ७५% राज्य बैंक द्वारा चलाए गए चेरवोनसे का था और शेष २५% सोवियत सरकार की मुद्रा सोव्जनाकी (SovZnaki) का, किन्तु चलन में सोव्जनाकी ही अधिक था।

सरकार ने विधि ग्राह्य मुद्रा के रूप में १, ३, ५ रूबल के सोने के सिक्के चलाए।

अप्रैल, मई, जून १९२४ तक अवमूल्यन चलता रहा। चांदी का आधा रूबल, चांदी और तांबे के १०, १५, २० कोपेक और तांबे के १, २, ३, ५, कोपेक जारी किए गए।

१९२४-२७ तक दो प्रकार की पत्र मुद्रा प्रचलित थी। १० रूबल की कीमत की चेरवोनत्से जो १, ३, ५, १० चेरवोनत्से नोटों में उपलब्ध था। ये नोट राज्य बैंक द्वारा जारी किए जाते थे और उन्हें साधारण बैंक नोट कहा जाता था। साधारण रूबल नोट खजाने द्वारा जारी किए जाते थे लेकिन उनका नियंत्रण राजकीय बैंक से होता था। सभी बैंक नोट सोना, विदेशी मुद्रा और अल्पकालिक नोट (Short term note) द्वारा सुरक्षित थे। ट्रेजरी द्वारा जारी किए गए रूबल नोट fiat currency थी। इसके अतिरिक्त १९४७ में Bronze और निकल के १, २, ३, ५, १०, १५, २० कोपेक के बराबर सिक्के चलाए गए। १०० कोपेक का १ रूबल होता था।

विदेशी मुद्रा से रूबल का सम्बन्ध

सोवियत राजनीतिज्ञों ने विदेशी मुद्रा से रूबल का सम्बन्ध स्वतः निर्धारित किया।

१ अमेरिकी डालर = १.६४३ रूबल

१ पाँड स्टर्लिंग = ६.४५३८ रूबल

१०० फ्रैंक = ७.६१६ रूबल

अन्य देशों की मुद्रा से रूबल के परिवर्तन की दर इसी अनुपात में थी।

इस मनमानी दर का प्रभाव हितकर नहीं हुआ। सोवियत संघ ने रूबल की क्रय शक्ति बहुत घटा दी थी। वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक आंकी गई। लोग सस्ते भाव में खरीद कर मंहगा बेचने लगे। रूबल का मूल्य बढ़ाने का परिणाम चोर बाजारियों के हित में रहा। विदेशों में बैंक नोट जाना बन्द सा होने लगा। विदेशी पर्यटकों को एक सीमा तक मुद्रा परिवर्तन का अधिकार था। सोवियत मुद्रा का विदेशी बाजार भी था।

२१ मार्च १९२८ को बाहर नोट जाना एकदम बन्द हो गया। रूबल केवल अन्तर्देशीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होता था। १९३०-४० तक रूबल की विदेशी मुद्रा से परिवर्तन की दर निश्चित होती रही। रूबल को आवश्यकता से अधिक महत्व देने के कारण विदेशी व्यापार को धक्का लगा। स्वर्ण मान पर आधारित देशों से अच्छा व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए रूबल का अवमूल्यन किया गया। १९३७ में संयुक्त राज्य का १ डालर = ५.३ रूबल निश्चित हुआ अन्य देशों की मुद्रा में डालर के अनुपात में ही परिवर्तन हुआ।

जनता की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए राशन पद्धति अपनाई गई।

मुद्रा का चलन और साख का विस्तार निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है^१

Currency in Circulation in the U. S. S. R. 1928-36

Date	Bank Notes	Treasury Notes and coins (Thousands of Rubles)	Total currency in circulation
Jan. 1, 1928	1002900	664900	1667800
Jan. 1, 1930	1501000	1272000	2773000
Jan. 1, 1932	2748413	2888897	5673310
Jan. 1, 1934	3342502	3429046	6771548
Apr. 1, 1935	3978041	3901366	7879407
Apr. 1, 1936	5934994	unavailable	unavailable

^१Russia's Soviet Economy—Harry Schwartz, Page 476

१९४२ में बजट का घाटा पूरा करने के लिए नोटों की संख्या २'४ गुनी बढ़ा दी गई। मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए राशन पद्धति चलाई गई।

वस्तुओं के मूल्य युद्ध पूर्व वर्षों के ही रखे गए। अधिक कर लगाए गए और वाण्ड बँचे गए।

कृषि उत्पादन के मूर्ज्य की बढ़ती का प्रभाव सामूहिक कार्यों पर पड़ा जहां सदस्य कृषक को अपनी अतिरिक्त उपज बेचने की पूरी स्वतंत्रता थी। वे अपना अतिरिक्त उत्पादन किसी भी मूल्य पर बेच सकते थे। यह कार्य वैधानिक था, इसे काला बाजार नहीं कहा जा सकता।

वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए थे—कुछ के सौ गुने या और अधिक। १९४३ में राशन की दूकान पर राई की रोटी १ रूबल की १ किलो ग्राम थी किन्तु बाजार में इसकी लागत १३० रूबल पड़ती थी। चीनी जो राशन स्टोर में अप्राप्य थी ५ रूबल प्रति किलोग्राम थी किन्तु बाजार में ११०० रूबल की दर से मिलती थी।

द्वितीय विश्व युद्ध ने अर्थ व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। सोवियत संघ के सम्मुख दो महत्व पूर्ण प्रश्न थे—

१—बढ़ती हुई जर्मन फौजों को रोकना और सैनिक आवश्यकता की पूर्ति करना।

२—उद्योग धन्धों को पूर्वी प्रदेश में स्थानान्तरित करना और पूर्वी क्षेत्र का कृषि उत्पादन इतना बढ़ाना कि नष्ट हुए पश्चिमी प्रदेश की क्षति पूर्ति की जा सके।

१९४४—४७ में सोवियत सरकार रूबल के मूल्य में स्थिरता लाने की दिशा में प्रयत्नशील रही। १९४४ में जहां तहां व्यापारिक भण्डार (commercial store) खोले गए जहां वस्तुएँ खरीदी जा सकती थीं। खाद्यान्न और उपयोग सामग्रियों के मूल्य।

१९४७ के मौद्रिक सुधार

युद्ध समाप्त होते ही सरकार का ध्यान देश की विश्रुंखल अर्थ व्यवस्था की ओर गया। मंत्रि मण्डल ने मुद्रा प्रसार में वृद्धि स्वीकार की। चलन में जाली नोट भी थे। वस्तुओं के मूल्य १० - १५ गुने बढ़ गए थे। सड़के बाजियों पर रोक लगाई गई।

वित्त व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने के लिए :—

१—राशन पद्धति समाप्त कर दी गई।

२—राज्य के नियंत्रण में भण्डारों की स्थापना की गई।

३—पुराने रूबल के स्थान पर १९४७ के नए रूबल को विधि ग्राह्य माना गया और आज्ञा प्रसारित की गई कि जनता १० पुराने रूबल के बदले १ नया रूबल ले। धनी मानी व्यक्ति और कुछ सीमा तक किसान भी इस अध्यादेश के कारण घाटे में रहे।

४—सरकारी बैंक में ३००० रूबल तक व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में धन जमा किया जा सकता था।

इस प्रकार एक ही तीर से सरकार ने कई शिकार किए। एक आज्ञा पत्र मात्र से नई मुद्रा का प्रचलन, राशनिंग (Rationing) की समाप्ति, तथा वितरण और मूल्य निर्धारण के अधिनियम को सुव्यवस्थित कर दिया गया।

स्वर्णमान रूबल (The Gold Standard Ruble)

५.३ रूबल = १ डालर

इसी अनुपात में अन्य देशों की मुद्रा से सम्बन्ध।

रूबल आयात निर्यात की भुगतान के उपयुक्त नहीं था। अन्य देशों के व्यापारिक समझौते डालर में ही व्यक्त होते थे। २८ फरवरी १९५० को एक घोषणा के अनुसार अन्यान्य उपयोग सामग्रियों और खाद्यान्न की कीमत कम की गई और रूबल का मूल्य बढ़ाया गया। डालर को सोवियत संघ में अस्थिर मुद्रा (unstable currency) घोषित किया गया।

मंत्रि मण्डल ने निश्चित किया कि :^१

१—प्रवदा १ मार्च १९५०

१—रुबल में ०.२२२१६८ ग्राम शुद्ध सोना हो।

२—सोवियत संघ का राज्य बैंक १ ग्राम शुद्ध सोना ४ रुबल ४५ कोपेक में खरीदे।

३—विनिमय की नई विधि ग्राह्य पर ४ रुबल = १ डालर

४—अन्य देशों की मुद्रा में रुबल का परिवर्तन डालर के अनुपात में हो।

दूसरे देश यदि सोवियत संघ से सोना खरीदना चाहें तो कितने रुबल देने होंगे इस दर का उल्लेख नहीं किया गया। मार्च १९५४ में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ जब सोवियत संघ में दांत बनवाने के लिए एक व्यक्ति ने ६० रुबल प्रति ग्राम के भाव से सोना खरीदा। इस प्रकार २८०० रुबल का १ औंस सोना हुआ जिसकी दर अमेरिका में ३५ डालर प्रति औंस थी। इस दृष्टिकोण से रुबल का मूल्य १.२५ अमेरिकी सेन्ट हुआ किन्तु सोवियत संघ ने एक रुबल का मूल्य २५ सेन्ट निश्चित किया था। न्यूयार्क टाइम्स ने अपने ७ मार्च १९५४ के अंक में रुबल की क्रय शक्ति के सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिखी है :—

“The Soviet claim that post war price cuts had raised the exchange value of the ruble above its previous exchange rate, ignored the fact that the Government had made no revision of the exchange rate during the entire preceding period—particularly during World War II—when this rate overvalued the ruble tremendously. More important the Government gave no evidence of the ruble’s supposed undervaluation.”

रुबल की विदेशी मुद्रा में क्रय शक्ति के संबंध में तब तक निश्चय पूर्वक कुछ नहीं जा सकता जब तक विश्व के विभिन्न देशों के बाजारों में सोवियत वस्तुएं भी इंग्लैंड और अमेरिका की वस्तुओं जैसी नहीं बिकने लगती। आत्म निर्भर देश होने के कारण रुबल अभी विदेशी मुद्रा के सम्पर्क में यथोचित रूप में नहीं आ पाया है। स्तालिन की मृत्यु के बाद स्वर्ण के आयात निर्यात पर से प्रतिबंध हटा और गैर कम्युनिस्ट देशों का ध्यान सोवियत संघ की ओर आकर्षित हुआ। कम्युनिस्ट देशों की मुद्रा रुबल पर ही आधारित है। पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों के साथ रुबल की विनिमय दर निम्नलिखित है—

Table 50. Official Ruble Foreign Exchange Rates. November, 1, 1949, March, 2, 1950 and February, 1, 1954.

Foreign Currency	Exchange value in Rubles		
	November, 1, 1949	March, 2, 1950	February, 1, 1954
U. S. Dollar	5.30	4.00	4.00
British Pound Sterling	14.84	11.20	11.20
Egyptian Pound	15.24	11.52	11.52
Canadian Dollar	4.82	3.63	4.12
100 Swedish Kroner	102.32	77.22	77.22
100 Swiss Francs	121.84	91.47	93.27
100 Indian Rupees	111.83	84.30	84.30
100 Pakistan Rupees	160.76	121.05	121.05
1000 French Francs	15.15	11.46	11.43
100 Czech Crowns	10.60	8.00	55.56
100 Afghan Afghani	31.35	23.66	19.05
1000 Italian Lire	8.34	6.40	6.42
2000 Rumanian Lei	35.33	26.74	666.70
100 Norwegian Kroner	74.20	56.00	56.00
1000 Polish Zlotys	13.25	10.00	1000.00

Sources Izvestia, November, 1, 1949. March, 2, 1950, February 2, 1954.

सोवियत आय व्ययक (Budget)

विश्व के अन्य देशों की भांति सोवियत आय व्ययक वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और प्रति वर्ष वित्त मंत्री सदन में उपस्थित करता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर भी साधारणतया वैसे ही होते हैं जैसे विश्व के अन्य देशों के। सोवियत बजट की भिन्नता शैद्धान्तिक पृष्ठ भूमि पर है।

भिन्नता

- १—सोवियत बजट जन जीवन में अधिक हस्तक्षेप करता है।
- २—नियोजित सामूहिक फार्मों के अतिरिक्त प्रायः सभी उत्पादन साधनों पर राजकीय नियंत्रण होने से आंकड़े अधिक स्पष्ट होते हैं। आय-व्यय के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाया जाता है वही अंतिम सत्य होता है।
- ३—सरकार की आय के जो स्वतन्त्र साधन हैं वह केवल कर पर आधारित नहीं हैं।
- ४—बजट अत्यधिक केन्द्रित और नियंत्रित होता है।
- ५—प्रायः अन्य देशों के बजट घाटे के होते हैं किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध काल को यदि अपवाद मान लें तो सोवियत बजट बराबर बचत का बजट रहता है।
- ६—कर वृद्धि का कभी विरोध नहीं होता।
- ७—सरकार मुद्रा की मात्रा बढ़ा कर, कर में वृद्धि करके या राजकीय बांड बेचकर अपनी आय बढ़ा सकती है।

आय के साधन

आय के दो प्रमुख साधन हैं—कर और बांड
सभी जीवनोपयोगी साधनों पर राजकीय नियंत्रण होने के कारण कर लगाने और उगाहने में सुविधा होती है। करों में उत्पादन कर, लाभ कर और आय कर प्रमुख है।

उत्पादन कर (Turnover Tax)

शान्ति काल में ६०% और युद्ध काल में ४०% आय उत्पादन कर द्वारा

प्राप्त होती है। उत्पादन कर को आय का अधिकांश भाग पूंजी विनियोग (Capital investment) में व्यय होता है।

उत्पादन कर को हम एक प्रकार का विक्रय कर कह सकते हैं जो उपभोग की वस्तुओं के ऊपर विभिन्न रूप में विभिन्न दरों के साथ लगाया जाता है। बड़े उद्योगों के उत्पादन पर प्रारम्भ में ही उत्पादन कर और बाजार में जाने पर विक्रय कर लगाया जाता है।

फ़ुटकर बिक्री पर उत्पादन कर की दरें निम्नलिखित हैं :—

आलू	—४८ से ६२%	फ़ुटकर मूल्य पर
मांस	—६७ से ७१%	” ”
ताजी मछली	—३५ से ५३%	” ”
मक्खन	—५६ से ६७%	” ”
चीनी	—७३%	” ”
बोडका	—८४%	” ”
पेय पदार्थ	—२०%	” ”
सिग्रेट	—७५-८८%	” ”

२ सितम्बर १९३० में पहली बार उत्पादन कर लगाया गया था। समय-समय पर अनेक सुधार होते रहे। विभिन्न उत्पादनों पर कर दरें भिन्न-भिन्न हैं। यह थोक और फ़ुटकर दोनों प्रकार की बिक्री पर लगता है।

इधर सरकार की प्रवृत्ति वस्तुओं के मूल्य घटाने की ओर है। इस कारण

उत्पादन कर में कमी की जा रही है। १९५३-५४ में उत्पादन कर के रूप में आय का केवल ४०% लिया गया था।

(लाभ कर Profit Tax)

उत्पादन कर के साथ लाभ कर भी विभिन्न उद्योगों पर विभिन्न दरों में लगाया जाता है। कुछ विशिष्ट उद्योगों पर इसकी दर निम्न है :—

पेट्रोल ३५%, लोहा और इस्पात २५%, टेक्सटाइल ६०%, खाद्यान्न ८४%, यातायात ५१%।

आय कर (Income Tax)

कारिगर, लेखक, सामूहिक अथवा निजी खेतिहरों पर एक निर्धारित दर के अनुसार आय कर लगाया जाता है। सरकार पूंजी के संचय की सैद्धान्तिक रूप से विरोधी है अतः अधिक आय वालों के आय कर की दर ऊँची है। २६० रूबल तक आय कर माफ है। २६० से १००० रूबल तक १५% और १००० रूबल से अधिक आय वालों से १३% आय कर लिया जाता है। तीन से अधिक बच्चों का पिता होने पर पूरे कर में ३% की छूट मिलती है।

स्तालिन की मृत्यु के बाद आय कर की दर में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया गया।

६० वर्ष से अधिक के पुरुष और ५५ वर्ष से अधिक आयु वाली स्त्रियों का यदि कोई सहायक न हो तो कर माफ हो जाता है। डाक्टर, अध्यापक, कृषिवेत्ता और ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके घर का कोई व्यक्ति जंगल या खान में काम करता है, से आय कर नहीं लिया जाता।

सामूहिक फार्मों में काम करने वाले सदस्यों से जो निर्धारित समय में काम पूरा नहीं कर पाते अथवा अनुशासनहीन होते हैं ५०% अतिरिक्त आय कर लिया जाता है।

सरकारी बाँड

१९२० ई० से सोवियत सरकार ने बाँड बेचने आरंभ किए। पहले छोटी रकमों के बाँड जारी किए गए और उसने सफलता मिलने पर बड़ी रकमों के बाँड भी जारी किए जाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाटरी बाँडों का प्रचलन हुआ। भारत में इस समय ५, १० ५०, और १०० रु० के ५ साला अवधि के लाटरी बाँड जारी किए जा रहे हैं।

सोवियत संघ में राजकीय बाँडों पर व्याज की दर १९२० में ११—१३% थी। लोग प्रायः साल में १ महीने की आय के बाँड खरीद लेते थे। १९४७ में बाँड पर व्याज की दर ४—२% कर दी गई। अब प्रायः २ सप्ताह की आय के बाँड खरीदे जाते हैं।

बैंक तथा अन्य संस्थाएँ भी बाँड खरीदती हैं। बाँडों की कुल आय का प्रायः चौथाई भाग बैंकों से प्राप्त होता है।

व्यय के प्रमुख श्रोत

सरकार की आय का अधिकांश भाग राष्ट्रीय योजनाओं पर खर्च होता है। रेल, मशीनें, बड़े उद्योगों पर खर्च अधिक है।

Trade 55. Budgetary Expenditures for Financing the National Economy in selected years¹

	(Billion Rubles)									
	1938	1940	1942	1944	1946	1948	1950	1953		
Total	51.7	58.3	31.6	53.7	106.2	147.5	164.4	192.5		
Industry	23.6	28.6	—	27.3	68.8	98.1	85.3	82.6		
Agriculture	11.4	12.2	5.1	7.0	12.3	20.5	36.6	39.9		
Transport & communication	7.4	6.1	—	7.7	10.0	14.4	15.0*	—		
Trade & Requisitions	—	2.0	—	1.2	3.2	4.1	9.3	—		
Municipalities & Housing	2.9	2.5	—	1.8	—	4.4	—	—		

१९४८ ई० में कुल पूंजी का ८६.२ बिलियन रुबल उद्योगों पर खर्च हुआ था जिसमें ५७.२ बिलियन रुबल की व्यवस्था बजट से की गई थी। मात्र कल बजट से चल पूंजी प्राप्त की जाती है।

1. Russia's Soviet Economy. Harry Schwartz—Pp. 502.

Table no. 56.

Budgetary Appropriations for Social and Cultural Measures
of the Soviet Government in selected years

	(In Billion Rubles)					
	1938	1940	1946	1948	1950	1953
Total	35.3	40.9	80.4	105.6	120.7	129.8
Education	18.7	22.5	38.1	55.1	59.6	62.8
Health	7.6	9.0	13.8	19.9	21.9	24.8
Social Insurance	6.0	5.4	4.3	8.7	—	
Aid to widows and mothers	—	1.2	3.6	2.5	4.0	42.9
Social Security	—	2.9	17.6	18.4	22.4	

Ibid—Pp. 503

बैंक

सोवियत संघ में वित्तीय व्यवस्था का सारा कार्य बैंकों द्वारा होता है। केन्द्रीय बैंक संस्था को गॉस बैंक (Gos Bank) कहते हैं जिसके ५,५०० कार्यालय देश भर में फैले हैं।

दीर्घ कालीन पूंजी लगाने के लिए ४ विशिष्ट बैंक हैं—

- १—औद्योगिक बैंक—प्राम बैंक (Industrial Bank)
- २—कृषि बैंक—सेलखोज बैंक (Agricultural Bank)
- ३—व्यापारिक बैंक—त्राग बैंक (Trade Bank)
- ४—म्युनिसिपल बैंक—स्केकोम बैंक। (Municipal Bank)

कुछ विदेशी व्यापारिक बैंक (Foreign Trade Bank) भी हैं जिन्हें व्नेतोर्ग बैंक कहा जाता है। ये बैंक विदेशी मुद्रा के भुगतान में सहायक होते हैं।

अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था राज्य बैंकों द्वारा की जाती है।

राज्य बैंक (State Bank)

राज्य बैंक सरकारी बैंक जैसा है। यह बैंक सभी उद्योगों के लिए अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था करता है। यह मुद्रा की चलन को नियंत्रित करता है और नगद योजनाओं के अनुसार मुद्रा की व्यवस्था करता है। सरकार के कर जमा करना और सरकार के भुगतान करने का दायित्व भी इस बैंक पर है।

१९३० ई० के सुधार के अनुसार राज्य बैंक को साख का दायित्व भी दे दिया गया है। अब यह साख सम्बन्धी प्रायः सभी कार्य करता है। इस बैंक को साख का दायित्व इसलिए सौंपा गया कि मुद्रा सम्बन्धी सामयिक अभावों की पूर्ति संभव हो सके। इस सुधार के द्वारा बड़े उद्योग भी इसकी सीमा में लाए गए। यह बड़े उद्योग की घन से मदद करता है।

१९४६ ई० में ७०% व्यापारिक संघटनों के क्रय का भुगतान राज्य बैंक द्वारा किया गया।

राज्य बैंक निश्चित अवधि और निश्चित कार्य के लिए उद्योगों और व्यवसायियों को ऋण देता है। ऋण दिए गए धन पर व्याज भी लगता है और अधिकतम सीमा साख योजना (Credit Plan) द्वारा निर्धारित की जाती है। गैर सरकारी उद्योगों को भी राज्य बैंक ऋण देता है।

यदि किसी अन्य बैंक में ऋणी का खाता हो और वह उसे राज्य बैंक में परिवर्तित करा दे तो ऋण भुगतान मान लिया जाता है। ऐसी अवस्था में राज्य बैंक उस उद्योग की उत्पादन व्यवस्था पर ध्यान देता है। इस प्रकार राज्य बैंक उद्योगों के संचालक का भी कार्य करता है।

राज्य बैंक कुछ दशाओं में वित्तीय परिवर्तक (Financial Transfer Agent) का भी कार्य करता है। एक बैंक के खाते का जमा धन दूसरे बैंक के खाते में सरलता से परिवर्तित हो सके इसके लिए क्लियरिंग ब्यूरो (Mutual Clearing Bureaus) खोले गए हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में बैंकों का हिसाब साफ करने में सहायक होते हैं।

अल्प बचत बैंक (Saving Bank)

धन बचाने और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्प बचत बैंक (State Labour Saving Bank) की स्थापना की गई है।

१९५१ में देश भर में सेविंग बैंकों की कुल ४७००० शाखाएँ थीं। अन्य विकसित देशों की तुलना में सोवियत संघ में अल्प बचत बैंक कम हैं। इसका कारण यह है कि सोवियत श्रमिकों का भविष्य अन्य देशों जैसा अनिश्चित नहीं है। सोवियत श्रमिकों के सामने बेकारी की कोई समस्या नहीं है। बुढ़ापे के पेंशन की व्यवस्था के कारण श्रमिक बचत की ओर से निश्चित रहते हैं।

१९४६ के आरंभ में अल्प बचत बैंकों का जमा धन ६ अरब रूबल था जो साल भर बाद १३ अरब रूबल हो गया किन्तु युद्ध काल वीत जाने पर जब वातावरण सामान्य हो गया तो इन बैंकों का जमा धन घटने लगा। यद्यपि अल्प बचत बैंक ३०% तक व्याज देते हैं (१९३०)। १९५३ में इनका जमा धन केवल ३८५ करोड़ रूबल था।

अध्याय २२ व्यापार (Trade)

क्रान्ति पूर्व के वर्षों में सोवियत वाणिज्य पूर्णतः स्वतंत्र स्पद्धियों के हाथ में था और वस्तुओं के मूल्य मांग और पूर्ति के संतुलन के अनुसार निर्धारित होते थे । क्रान्ति के बाद राजकीय नियंत्रण जैसे-जैसे बढ़ता गया निजी व्यापारी समाप्त होते गए । इस समय सोवियत संघ में व्यापार राजकीय और सहकारी स्तर पर होता है यद्यपि निजी व्यवसायी भी किसी न किसी रूप में अब भी हैं ।

सोवियत संघ में व्यापार के तीन स्वरूप उपलब्ध हैं—

१—राजकीय व्यापार (The State Trading net work)

२—सहकारी व्यापार (The Cooperative Trading net work)

३—स्वतंत्र स्पद्धी (Free farm market)

तीनों प्रकार के संगठनों का कार्य और वितरण समय-समय पर बदलता रहा है ।

राजकीय व्यापार

१९३०—३५ तक तथा १९४१ से दिसम्बर १९४७ तक देश में राशनिंग प्रथा थी । १९३० ई० के बाद देश में वस्तुओं की कमी थी जिससे विक्रेताओं को अधिक लाभ था ।

राजकीय और सहकारी विक्रय संस्थाएँ समाजवादी व्यापार का एक आवश्यक अंग समझी जाती हैं और वे वार्षिक योजनाओं द्वारा परिचलित होती हैं ।

खेतियों के बाजार शहरों में या रेल रोड के स्टेशनों पर लगते थे । इन बाजारों में सामूहिक फार्मों के कृषक अथवा निजी किसान सरकार को देने के बाद जो शेष अतिरिक्त उत्पादन बच रहता था, बेच सकते थे । इन बाजारों में कीमतें मांग और पूर्ति तथा नियोजित सरकारी प्रतिबन्ध द्वारा तय की जाती थी ।

१९४० ई० में कुल सामान की बिक्री का ६०% राजकीय वितरण

व्यवस्था द्वारा, २०% सहकारी भंडारों (Cooperative stores) के द्वारा और २०% फार्म बाजार द्वारा होता था ।

राजकीय व्यापार के अन्तर्गत अनेक प्रकार के थोक और फुटकर व्यापारिक स्तर पर अनेक संघटन हैं । ये शहरी जनता की प्रमुख रूप से तथा कुछ विशिष्ट वर्ग (सैनिक आदि) को मांग पूरी करते हैं ।

प्रमुख संघटन व्यापार मंत्रालय है पर अग्य मंत्रालय भी इस दिशा में क्रियाशील रहते हैं । सरकार प्रतिवर्ष इस बात को निश्चित कर लेती है कि किस मूल्य पर किन वस्तुओं की कितनी मात्रा जनता में वितरित की जाय । आन्तरिक व्यापार की रूप रेखा बनाते समय मूल्य और विक्रय योग्य वस्तुओं का निश्चय कर लिया जाता है राजकीय योजना समिति तथा मंत्रालय (Council of Ministers) द्वारा वितरण संस्थाओं की देख-रेख की जाती है ।

उत्पादकों के यहाँ के निर्मित माल एक जगह एकत्रित किया जाता है । इस प्रक्रिया को 'ग्राम्बजी' (Warehouses) कहते हैं । मिलों और सरकारी भण्डारों से प्राप्त माल राजकीय एवं सहकारी फुटकर व्यापारिक संगठनों को दे दिया जाता है । ये स्वतंत्र संगठक प्रशासन के अधीन है ।

त्राग

त्राग मुख्य फुटकर व्यापारिक इकाई है । प्रत्येक त्राग के प्रबन्ध और नियमन का दायित्व व्यापार मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति पर होता है । प्रत्येक त्राग में एक क्रय विभाग होता है जो ग्राम्बजी सहकारी फार्मों आदि से समान खरीदता है । प्रत्येक बड़े शहर में छोटे बड़े विभागीय भंडार (यूनिवर्सल Departmental store) भी है । १९५३ ई० में मास्को में एक बृहत् भंडार (Superdepartment store) का निर्माण किया गया जिसमें आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के फुटकर भंडार भी हैं जो तत्सम्बन्धी मंत्रालयों के अधीन हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दवा की दूकाने हैं ।

१९४६ ई० में डाक द्वारा भी वस्तुओं के क्रय विक्रय की व्यवस्था की गई है।

सहकारी व्यापार (Cooperative Trade)

देश भर में फैली उपभोक्ता सहकारी समितियाँ सहकारी व्यापार पर नियंत्रण करती हैं। १९३०—४६ ई० तक उपभोक्ता सहकारी व्यापार देश के ग्रामों में फैला हुआ था और राजकीय संगठन शहरों में सीमित थे। १९४६—४६ तक इसका विस्तार होता रहा और सहकारी संस्थाओं ने नगरों का बाजार भी कुछ हद तक अपनाया लेकिन १९४६ की ग्रीष्म ऋतु में उपभोक्ता सहकारी समितियों को शहरों से स्थानान्तरित कर देहातों तक में सीमित कर दिया गया। १९५३ में इसकी २,५४,००० शाखाएँ थीं जिसमें १० लाख व्यक्ति काम करते थे। सहकारी समितियों की सदस्य संख्या ३३० लाख थी।

सभी सहकारी संस्थाएँ एक केन्द्रीय संस्था त्सेन्त्रोसोबुज से सम्बन्धित हैं। इस संगठन की सबसे छोटी इकाई को स्लेपो कहते हैं। ये संगठन जनतांत्रिक आधार पर चलाए जाते हैं। इन पर सदस्यों का नियमन होता है लेकिन अन्तिम निर्णय कम्प्यूनिस्ट सिद्धान्तों के आधार पर होता है। सहकारी फार्मों का अतिरिक्त सामान भी इनमें बेचा जाता है। शहरों, कस्बों और स्टेशनों पर स्वतन्त्र व्यापारी अपना माल बेचते हैं। वस्तुतः यह असंगठित व्यापार है जहाँ मांग और पूर्ति द्वारा मूल्य निश्चित होता है।

१९५३ ई० में एक सुधार हुआ। सहकारी संस्थाओं से माल खरीदने पर क्रेताओं को मूल्य में कुछ छूट भी मिलने लगी। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि सहकारी दूकाने सामूहिक फार्मों का उत्पादन भी बेच सकें और इस प्रकार विक्रय कार्य में लगे ५ लाख सामूहिक फार्मों के कर्मचारी कोई अन्य उत्पादक कार्य करें।

मूल्य

वस्तुओं के मूल्य में एक रूपता का अभाव है। किसी वस्तु का मूल्य इस बात पर निर्भर है कि वह खरीदी कहाँ से गई है—राजकीय भंडार से,

सहकारी भंडार से अथवा स्वतंत्र बाजार से। राजकीय भंडार का मूल्य सरकार निर्धारित करती है। उसके अन्तर्गत उस वस्तु की उत्पादन लागत, वितरण लागत, उत्पादन कर, संयोजित मुनाफा आदि शामिल रहता है। खाद्यान्न सामग्री के लिए १९४७ ई० के बौद कीमतों के तीन क्षेत्र (zone) बने हैं—पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। मूल्य में परिवर्धन का व्यय भी शामिल रहता है।

राज्य भंडारों में तीन विभिन्न कीमतें रखी गई हैं—पहले भाग में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य व्यापार मंत्रालय, कम महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य मंत्रिमंडल (Council of Ministers) और सामान्य वस्तुओं को थोक कीमतें सरकार निश्चित करती है और फुटकर कीमतें व्यापारी।

सहकारी भंडारों से माल की जो कीमतें ली जाती हैं वे कुछ अंशों में सरकार द्वारा और कुछ अंश में मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। सहकारी भंडार सरकारी भंडारों से जो सामान खरीदते हैं उन पर मूल्य छूपा रहते हैं। सहकारी, सामूहिक अथवा व्यक्तिगत फार्मों अथवा व्यावसायिक संगठनों से जो सामान खरीदा जाता है उसका मूल्य मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाता है। स्वतन्त्र बाजार के मूल्य पूर्णतः मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं।

उपसंहार

सोवियत संघ की व्यापार नीति सरकार द्वारा नियोजित और नियंत्रित होती है। सरकार साम्यवाद के व्यावहारिक स्वरूप पर आधारित है। अतः अपूर्ण अथवा पूर्ण स्वर्द्धा वाले देशों के नागरिकों के लिए सोवियत विक्रय और मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त विचित्र हो सकते हैं। सोवियत संघ में उत्पादन आवश्यकता की तीव्रता और मूल्य निर्धारण उपभोक्ता के स्तर पर आधारित होते हैं। उत्पादन की मात्रा और मूल्य दोनों सरकार निश्चित करती है और किस उपभोक्ता को उत्पादन की कितनी इकाई मिलनी चाहिए इसका निर्णय भी सरकार ही करती है।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)-

विदेशी आर्थिक सम्बन्धों के अन्तर्गत विदेशी व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय

अध्याय २३

साम्यवाद

भविष्यत संघ को एक नई सभ्यता और एक नए समाज के निर्माण का श्रेय प्राप्त है जो मनुष्य की समता, भ्रातृत्व और पुरानी रूढ़ियों के त्याग पर आधारित है। साम्यवाद के मसीहा कार्ल मार्क्स का जर्मनी में जन्म हुआ, इंग्लैंड में उन्होंने इसकी सैद्धान्तिक रूप रेखा निर्धारित की और रूस में उनके दर्शन को व्यावहारिक रूप मिला। साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रणयण इंग्लैंड में ही हो सकता था और औद्योगिक क्रान्ति के बाद ही हो सकता था—कार्ल मार्क्स तो निमित्त मात्र थे। व्यक्ति और विचार इतिहास की परम्परा की एक लहर हैं, धारा नहीं।

कुछ देर के लिए हम मार्क्स और साम्यवाद को भूल जाय और इतिहास की धारा को देखें—

प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य का जीवन ऋजु था उत्पादन और उपभोग में सीधा सम्बन्ध था। कालान्तर में आवश्यकताएँ बढ़ने लगी और मानव जीवन जटिल होने लगा। धीरे-धीरे उत्पादन और उपभोग के बीच विनिमय और वितरण ने प्रवेश पा लिया। स्वाभाविक था कि ऐसी दशा में अधिकार का प्रश्न उठता। मानव धीरे-धीरे सभ्यता की मंजिले पार करता गया। कुटुम्ब, परिवार ग्राम—अपना, पराया—और यहाँ संचय वृत्ति को प्रोत्साहन मिला। कभी खराब न होने वाली एक चमकदार पीली धातु (स्वर्ण) को विनियम का माध्यम बना लेने पर संचय वृत्ति को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। संचय वृत्ति ने शोषण को जन्म दिया क्योंकि शोषण के अभाव में संचय हो ही नहीं सकता था।

यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज से अपना ही भाग चाहता तो कोई समस्या न थी किन्तु ऐसी अवस्था में केवल उपभोग होता, संचय न हो सकता था।

सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था में भूमि, श्रम और पूँजी उत्पत्ति के तीनों प्रमुख साधन सामन्तों के नियंत्रण में थे। मशीन के आविष्कार ने अर्थ-व्यवस्था को नया मोड़ दिया। मशीनों के प्रयोग के कारण श्रम का महत्व कम हो गया और मशीनें मंहगी होने से पूँजी का महत्व बढ़ गया। यहाँ पूँजीपतियों ने एक बुद्धिमानी की—श्रम को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया किन्तु पूँजी पर नियंत्रण रखा। वस्तु स्थिति यह थी कि पूँजी के अभाव में श्रम की स्वतंत्रता मात्र मरखौल थी।

स्पर्धीकरण के लिए एक उदाहरण लें। पहले कर्षे पर एक जुलाहा १० आदमियों के लिए कपड़ा बुनता था और अब १० आदमी जुलाहे को दूसरी आवश्यकताओं के सामान बनाते थे। समाज के ग्यारहों सदस्य सामन्तों के नियंत्रण में थे किन्तु उनमें से प्रत्येक को जीवनोपयोगी वस्तुएँ किसी न किसी प्रकार थोड़ी बहुत मात्रा में सुलभ हो जाती थीं और प्रत्येक एक दूसरे के लिए अनिवार्य था। मशीन का आविष्कार हो जाने पर उत्पादन की मात्रा बढ़ गई और उत्पादन लागत कम हो गई। अब जुलाहा १०० आदमियों के लिए कपड़ा बुनने लगा। उपरोक्त उदाहरण के अन्य १० सदस्य १००० व्यक्तियों की आवश्यकता के सामान बनाने लगे। स्वाभाविक था कि बेकारी बढ़ती और प्रतस्पर्द्धा में श्रम पीछे रह जाता। इतना ही नहीं अतिरिक्त बचत पुरे की पूरी उसके पास संचित होने लगी जो मशीन का मालिक था। गरीब और अमीरी की खाई दिनों दिन बढ़ती गई—

मशीनों का आविष्कार (औद्योगिक क्रान्ति) सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ इस कारण शोषण के विरुद्ध आवाज भी पहले पहल वहीं उठी।

प्रश्न है स्वामित्व का। लाभांश का वास्तविक अधिकारी कौन है—वह जो कर्षा चलाता है अथवा वह जिसका कर्षा है ?

मार्क्स कर्षे (उत्पादन के साधन) पर समाज का नियंत्रण चाहता था—उसने कहा—दुनियाँ के मजदूरों एक हो। तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं।

कार्ल मार्क्स—(१८१८—८३ ई०) कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के एक गरीब यहूदी वकील के घर में हुआ था। कालान्तर में मार्क्स ने इसाई

धर्म स्वीकार कर लिया। जर्मनी से फ्रांस और बेलजियम होते हुए आप इंग्लैंड पहुँचे और वहाँ रुई मिल के धनी मालिक के पुत्र फ्रेडरिक एंगेल्स के सम्पर्क में आए। श्री एंगेल्स आपका शुभ चिन्तक और बौद्धिक सहायक सिद्ध हुए। इंग्लैंड में ही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने कम्यूनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया (१८४८ ई०)।

कम्यूनिस्ट सिद्धान्त

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित तथा लेनिन और स्तालिन द्वारा व्यवहृत कम्यूनिज्म पहला प्रयास नहीं था। पुराने ग्रीक विचारक, बायबिल के संत-थामस मोर आदि ने बहुत पहले शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अनेक वैदिक और पौराणिक भारतीय मनीषियों के सिद्धान्त मिलते-जुलते हैं और अपने भौतिकतावादी विचारों में तो चार्वाक मार्क्स से भी दो डग आगे हैं। कार्ल मार्क्स को कम्यूनिस्ट दर्शन के यथातथ्य दिग्दर्शन और सम्यक विश्लेषण का श्रेय प्राप्त है।

पूँजी अथवा शक्ति के आधार पर कोई दूसरे के श्रम का उपभोग न करे और व्यर्थ के मध्यस्थ समाप्त हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति शक्ति भर काम करे और उसे आवश्यकता भर प्रतिदिन मिले—मार्क्स यही चाहते थे।

द्वन्द्व्वात्मक भौतिकवाद

कार्ल मार्क्स ने द्वन्द्व्वात्मक भौतिकवाद का दर्शन हीगल से लिया किन्तु मार्क्स का द्वन्द्ववाद हीगल का उलटा है। मार्क्स के शब्दों में 'हीगल सिर के बल खड़ा है। मैं उसे पैर के बल खड़ा कर रहा हूँ।' फ्रेडरिक एंगेल्स ने प्राणि मात्र के परिवर्तन की तीन प्रतिक्रियाएँ बनाई थीं। ये परिवर्तन विज्ञान की गति (motion) जैसे ही होते हैं। हीगल के अनुसार द्वन्द्ववाद की घात प्रतिघात और संघात तीन प्रक्रियाएँ हैं। मूल घात और प्रतिघात की देन है।

- फ्रेडरिक एंगेल्स ने इसे बीज गणित से समझाने का प्रयत्न किया है—
यदि (अ) मात्रा घात है
तो (—अ) प्रतिघात होगा

और संघात या अभाव का अभाव (Nigation of the nigation) की प्राप्ति

(-अ) × (-अ) = अ^२ होगा

हीगल के अनुसार मनुष्य के सोचने की क्रिया व्यक्तिगत और स्वतंत्र है। मार्क्स के विचार से केवल भौतिक संसार आदर्श है जो मानव मस्तिष्क द्वारा प्रकट होता है और विभिन्न विचारों के रूप में सामने आता है। एंगेल्स भौतिकवाद में प्रकृति को ही एक मात्र वास्तविक अस्तित्व स्वीकार करते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बाहर कुछ नहीं होता। उच्च जीव, स्वर्ग नरक और धार्मिक ग्रंथ-विश्वास मात्र मानवीय भ्रम हैं।

स्थूल संसार ही एक मात्र सत्य है—और इसका सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया घात, प्रतिघात और सघात में होती है।

साम्यवाद को लेनिन की देन

मार्क्स और एंगेल्स का साम्यवाद सैद्धान्तिक पृष्ठ भूमि पर आधारित था। लेनिन ने उसे व्यावहारिक रूप दिया। १९०० में साम्राज्यवाद पुस्तक में लेनिन ने लिखा था—चन्द व्यक्तियों के हाथ में उत्पादन के साधन आ जाने के कारण पूँजी का एकत्रीकरण होता है। संगठित वित्त व्यवस्था द्वारा उत्पादन व्यवस्था नियंत्रित कर ली गई और इस व्यवस्था ने मुद्रा के वितरण और साख की चलन को इस रूप से नियंत्रित कर लिया जिससे एक विशिष्ट वर्ग का लाभ हुआ। बैंकों द्वारा उद्योगों के प्रभावित होने के कारण साहसी और कर देने वाले दो नए वर्गों का समाज में जन्म हुआ। पूँजी पूँजीवादी देशों से ऐसे पिछड़े देशों की ओर जाने लगी जहाँ लाभ की अधिक संभावना थी। पूँजी के इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण का कारण यह था कि पिछड़े देशों में सस्ती भूमि, सस्ते मजदूर और सस्ता कच्चा माल सरलता से उपलब्ध थे। ऐसे अविकसित प्रदेशों की भूमि पर भी भूस्वामियों का ही अधिकार था, इस कारण भूमि की उन्नति होने पर लाभ उन्हीं को होता था।

लेनिन का विश्वास था कि बीसवीं सदी में सारा संसार दो बड़े पूँजीवादी वर्गों में विभक्त हो जाएगा—भूमि और बाजार की आधिपत्य के

लिए युद्ध होगा और इस नए साम्राज्यवाद में साम्राज्यवादी युद्ध की ज्वाला में सारा संसार जलने लगेगा ।

लेनिन का विश्वास था कि मजदूरों का उच्च वर्ग पूँजीपतियों से अधिक प्रभावित होता है और कामकरों का यही वर्ग सामाजिक व्यवस्था को बदलने में बाधक होता है । लेनिन ने उस भयानक क्रान्ति की परिकल्पना की थी जिसके बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व (Dictatorship of the Proletariat) स्थापित होगा ।—एक नए राज्य की परिकल्पना जिसमें पूँजीवाद समाप्त हो जायगा, न कोई शोषक होगा और न शोषित ।—और जब तक ऐसा आदर्श समाज बन नहीं जाता वर्ग संघर्ष होता रहेगा ।

लेनिन ने अपनी नीति में मार्क्स के सिद्धान्तों को अपनाने का अधिक प्रयास किया था । पूँजीवाद की समाप्ति के बाद उत्पादन के साधनों पर समाज और राज्य का नियंत्रण होगा ।

आन्तरिक व्यवस्था

पूँजीवाद में सभी को काम पाने, शिक्षा, यातायात, संदेश वाहन की सुविधा होती है । ऐसी दशा में सशस्त्र क्रान्ति सफल हो सकती है और नए समाज की स्थापना संभव है । साथ काम करने से मजदूरों में एकता की भावना आती है । जैसे जैसे पूँजीवाद का जाल बढ़ता जाता है मध्यस्थ समाप्त होते जाते हैं और मजदूरों का एका और उनकी शक्ति बढ़ती जाती है । जिस प्रकार एक बिच्छू दूसरे बिच्छू को जन्म देकर समाप्त हो जाता है उसी प्रकार एक पूँजीपति दूसरे पूँजीपति को जन्म देकर समाप्त हो जाता है । छोटी मछलियों को निगलते-निगलते बड़ी मछलियाँ और बड़ी होती जाती हैं ।

लेनिन का सिद्धान्त भ्रम रहित नहीं है । लेनिन ने सामाजिक व्यवस्था की परख ठीक नहीं की । कार्य की कठिनाइयों की ओर उसका ध्यान नहीं गया । मजदूर शक्ति का अनुमान भी उसने अधिक किया । यह युद्ध, विदेशी आक्रमण और समता के सिद्धान्त पर अत्यधिक आस्था भी व्यवहार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी । इतना होते हुए लेनिन की विचारधारा का मूलभूत तथ्य गलत नहीं है ।

स्तालिन

स्तालिन सैद्धान्तिक कम और क्रियाशील अधिक थे। स्तालिन की सफलता का श्रेय उनकी विद्वत्ता को नहीं, अनुभव और कार्य कुशलता को है। १९२० से ५३ तक वह सोवियत राजनीति पर छाया रहा। स्तालिन का व्यक्तित्व अतिशय जटिल और रहस्यमय व्यक्तित्व था। उन्होंने विचारकों के सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप दिया। सैद्धान्तिक अंध-विश्वास (Doctrinal Orthodoxy) उनमें बिलकुल नहीं थी। समय रहते मूल सुधार लेना उनकी निजी विशेषता थी।

१९५२ में आपने समाजवाद की आर्थिक समस्याएँ पुस्तक लिखी। उनका विश्वास था कि आर्थिक नियम बदले नहीं जा सकते, वे आदमी की इच्छा से नहीं स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, उत्पादन मुख्यतः उत्पादन साधनों का उत्पादन बढ़ाना, सामूहिक फार्मों को राजकीय सम्पत्ति बनाना, मुद्रा के द्वारा विनिमय समाप्त करना, सांस्कृतिक उत्थान और मजदूरों को विशेष सुविधाएँ देना स्तालिन का उद्देश्य था। उनकी मान्यता थी कि समाजवाद की स्थापना से ही युद्ध की समाप्ति हो सकती है किन्तु समाजवादी सिद्धान्तों के प्रसार के लिए उन्होंने कभी बल प्रयोग नहीं किया।

सोवियत संघ को जितना योग्य लेनिन का उत्तराधिकारी मिला उतना स्तालिन का नहीं। स्तालिन के देहावसान के बाद अनेक प्रतिभाएँ राजनीतिक मंच पर आईं पर कोई उनका स्थान न ले सकी।

खुश्चेव

इस समय सोवियत संघ की बागडोर श्री खुश्चेव के हाथ में है। आप लेनिन और स्तालिन के ही पद-चिन्हों पर चल रहे हैं। आपका दावा है कि आगामी कुछ वर्षों में सोवियत संघ पूर्ण साम्य तक पहुँच जाएगा।

BIBLIOGRAPHY

1. सोवियत भूमि —राहुल सांकृत्यायन
2. रूस की सैर —पं० जवाहरलाल नेहरू
3. कम्यूनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र. —कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स
4. साइबेरिया की जल-विद्युत योजनाएँ—म० सुत्स
5. सोवियत संघ की कृषि समस्या किस तरह हल की गयी —डॉ० एस० कोल्याकोव
6. The Development of the Soviet Economic System —By Alexander Baykov
7. Soviet Economic Development since 1917 —Dobb Maurice
8. Soviet Statistics —A. Yezhov
9. Soviet Industry —F. Koshelev
10. Industrialization without Foreign Loan —E. Frolov
11. Russia's Soviet Economy (second Edition) —Harry Schwartz
12. Forms of Rural Cooperation in the U. S. S. R. —Y. Borisov
13. The Soviet Food Industry —J. Volper
14. Kazakhstan and Seven year plan —D. Kunayer
15. A State Farm —T. Yurkin
16. Coal Industry of the U. S. S. R. —A Sudoplatov
17. Kolkhoz Collective Farming in the Soviet Union —P. Voitsekhovsky
18. New Soviet Seven Year Plan —Theses of N. S. Kruechehov's report to 21st. CPSCU Congress)

19. Glimpses of the U.S.S.R.—Nikolai Mikailov
 20. Economic Geography of the U. S. S. R. —N. N. Baransky
 21. Statistical Returns —Central Statistical Board of the U.S.S.R. Council of Ministers
 22. U. S. S. R. —Reference Book (The Information Department of the U.S.S.R. Embassy in India)
 23. The Development of Capitalism in Russia —V. I. Lenin
 24. Economic Development of Soviet Union —K. T. Shah
 25. Problems of Leninism —Stalin
 26. The Economics of Soviet Agriculture —Hubbard
 27. Capital —Karl Marx
 28. Pravda —Mouthpiece of Communist Party
 29. The U.S.S.R. in 1960 —M. Postolovesky
 30. Soviet Civil Law —Govski